छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा — अष्टम् सत्र

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026
(फाल्गुन 08, शक सम्वत् 1947)

[अंक 05]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए.)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी नहीं रहते तो नेता प्रतिपक्ष जी स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेते हैं । वे रहते हैं तो महंत जी आभाषी हो जाते हैं, वर्चुअल नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं । वे इनको दबा देते हैं । सदन के नेता प्रतिपक्ष को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी के साथ हैं । उनका दल उनके साथ अन्याय करता है । पुराने मुख्यमंत्री जी आकर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं ।

सभापति महोदय :- ऐसा कुछ नहीं है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति जी, हमारे नेता जी का कोई नहीं दबाता।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी नहीं रहते तो आप लोग चहकते हैं ।

श्री केदार कश्यप :- आपको कोई नहीं दबा सकता इसलिए आप उनसे डरिए मत।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, महंत जी वर्चुअल नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं, आभाषी हो जाते हैं ।

सभापति महोदय :- कोई वर्चुअल नहीं होते, नेता जी अच्छा काम कर रहे हैं ।

श्री केदार कश्यप :- वे वर्चुअल नहीं, एक्चुअल की ओर होने की कोशिश कर रहे हैं ।

फसल उत्पादन एवं परीक्षण कार्यक्रम में व्यय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

1. (*क्र. 747) श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में वर्ष 2023 से दिनांक 04/02/2026 तक किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नयी किस्म/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि करना/उपकरण/संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण आदि की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कहां-कहां आयोजित किये गये? आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय किस-किस योजना/मद से किया गया? प्रशिक्षण में कितने किसान/हितग्राही सम्मिलित हुए? प्रशिक्षणवार प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वालों की संख्या की वर्षवार जानकारी देवें? किस-किस प्रशिक्षण पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्ड मुंगेली एवं पथरिया में वर्ष 2023 से दिनांक 04/02/2026 तक किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नयी किस्म/हाई ब्रीड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि करना/उपकरण/संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण आदि की विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की योजनावार वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैंने कृषकों के लिए प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नयी किस्म/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि/उपकरण/संसाधन संरक्षण के संबंध

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में माननीय मंत्री जी से पूछा था। मैं आपके माध्यम से इस विषय पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी हेतु नई किस्म के फसल की जानकारी लोगों को दी जाये क्योंकि 900 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, इससे किसानों को क्या लाभ मिला? मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करें।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य जो कई बार विधान सभा के सदस्य भी रहे और लोकसभा में भी लगातार चार बार सदस्य रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ सदस्य ने कृषि के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में चिंता की है और किसानों का प्रशिक्षण कैसे हुआ, इस बारे में प्रश्न किया है । जहां तक आपने प्रशिक्षण के बाद के परिणाम की बात की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि जो अनेकानेक योजनाएं चलती हैं, उस योजना के तहत किसानों को किस तरह से अधिक उत्पादन अपने खेत में लेना चाहिए, इस लिहाज से विभाग की अनेकानेक योजनाएं हैं और इस प्रशिक्षण के बाद स्वाभाविक है कि उत्पादन बढ़ता भी है। जब उनका उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि किसानों का आर्थिक उन्नयन होगा। ऐसा सोचकर इस तरह की योजनाएं चलती हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा यह कहना है कि प्रदर्शनी और हाईब्रिड का भी प्रदर्शन और प्रशिक्षण दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि मात्र प्रशिक्षण ही दिया गया या हाईब्रीड बीज दी गई और नए किस्म के बीज के प्रदर्शन के लिए किसानों के खेत में बोने के लिए या उगाने के लिए बीज दी गई क्या, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो पुराने बीज वाले हैं। आप नये बीज में कहां से आ गए?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न में मैंने बताया कि कृषि विभाग के अनेकानेक योजनाएं चलती हैं। उस योजना के तहत प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे आत्मा योजना है, बीज ग्राम योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण योजना है, दलहन की योजना है। दलहन की खेती को हमें कैसे बढ़ावा देना है, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहां मिशन चांवल की जो योजना है और रेनफेड एरिया एवं डेव्हपलमेंट के लिए प्रशिक्षण चलता है कि इन क्षेत्रों में कैसे हम बढ़ावा दे सकें, उनके उपज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके। एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तरह से हमारे यहां जो आधार बीज होते हैं, उससे हम उत्पादन कैसे अधिक बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक फसल ले सकते हैं, हम लोग विभाग द्वारा इसी का प्रशिक्षण देते हैं।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग बीज देते हैं या नहीं? हर समय प्रशिक्षण होता है और किसानों को नि:शुल्क बीज दिया जाता है, मुझे उन बातों को बताने का कष्ट करें। दूसरा, प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी कौन-कौन थे? कितने किस-किस पद के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया, यह बताने का कष्ट करें?

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही जो प्रशिक्षण होता है, वहां उन्हें मिनी किट दिया जाता है, जिससे वे उत्पादन लेते हैं। उनको उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से दिया जाता है। दूसरा, प्रदर्शनी में उनका बीज लेते हैं, जिससे बाकी किसानों को अगले साल के लिए वितरण किया जा सके, इस तरह की भी योजना होती है।

माननीय सभापति महोदय, आपने जहां तक प्रशिक्षण के बारे पूछा है तो उस प्रशिक्षण में अलग-अलग संख्या के हिसाब से व्यय राशि को बताया है। जो प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी हैं, यदि उसके बारे में कहेंगे तो बता दूंगा। लेकिन लंबी सूची है। अगर आप जानना चाहेंगे तो एक-एक करके बताऊंगा। जैसे उन्नत कृषि के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना के तहत प्रशिक्षण हुआ। इस प्रशिक्षण में श्रीमती नेहा लहरे, डॉ. एस.के. लहरे, फसल प्रणाली आधारित जो प्रदर्शनी है..।

सभापति महोदय :- आप उनको सूची उपलब्ध करा देंगे। माननीय मंत्री जी, आप उनको सूची उपलब्ध करा दीजिये, पढ़ने में बहुत समय लगेगा।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हां, सूची बहुत लंबी है।

सभापति महोदय :- इसीलिए आप माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हां, सूची दे दूंगा।

सभापति महोदय :-आप एक अंतिम प्रश्न और कर लीजिये।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, क्या प्रशिक्षण के बाद प्रदर्शनी में किसानों को बीज देने के बाद नि:शुल्क खाद भी दिया जाता है और क्या उसका मूल्यांकन किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाता है? मूल्यांकन किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? या सिर्फ बीज दे दिए और चल दिए। आखिर किसानों को कितना लाभ मिला? यह बताने का कष्ट करें।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, उसकी बहुत बड़ी संख्या होती है। इसीलिए जितना मिनी किट वितरण करते हैं, वह बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए हम जितना मिनी किट वितरित करते हैं, नीचे से किसानों के नाम चयनित होकर आते हैं, जब उनको किट देते हैं तो इस अपेक्षा से देते हैं कि किसान उसका सही उपयोग करेगा। अधिकांश किसान उसका सही उपयोग करते हैं। यह बात सही है कि जिनको हम देते हैं उसका शत-प्रतिशत मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां इस तरह की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई है। फिर भी आपने इस ओर ध्यान दिलाया है, अगर कोई शिकायत हो, किसी प्रकार की कोई और बात हो तो आप बताईये, सुझाव दीजियेगा, निश्चित ही हम उसे जमीनी स्तर पर लागू करेंगे।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

<u>राज्य में घुमन्तू पशुओं के रख-रखाव/संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं</u>

[पशुधन विकास]

2. (*क्र. 797) श्री कुंवर सिंह निषाद: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) घुमन्तू पशुओं के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु राज्य शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं? जानकारी देवें? वर्तमान में घुमन्तू पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? जिलावार विवरण क्या है? जिला बालोद का विवरण विकासखण्डवार देवें? (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार राज्य में स्थापित गौठान/कांजी हाउस/पशु आश्रय स्थलों की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान क्षमता एवं उपयोग की स्थिति क्या है? विगत तीन वर्षों में घुमन्तू पशुओं के रख-रखाव हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि का व्यय, कहाँ-कहाँ किन-किन प्रयोजनों में की गई है? जिलावार विस्तृत जानकारी देवें? जिला बालोद का विवरण विकासखण्डवार देवें? (ग) क्या अनेक क्षेत्रों में घुमन्तू पशुओं के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कारण सड़क दुर्घटनाएँ एवं फसल क्षति की घटनाएँ बढ़ी हैं? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): (क) घुमन्तू पशुओं के सरंक्षण एवं रख-रखाव हेतु पशुधन विकास विभाग द्वारा गौधाम योजना संचालित की जा रही हे। 20वीं पशु संगणना अनुसार राज्य में घुमन्तू पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है। जिलावार विवरण तथा जिला बालोद का विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार राज्य में घुमन्तू पशुओं के सरंक्षण एवं रख-रखाव हेतु पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित गौधाम योजना अंतर्गत 11 गौठानों का गौधाम के रूप में पंजीयन किया गया है जिसकी कुल क्षमता 2200 पशु हैं। वर्तमान में 03 गौधाम संचालित है, जिसमें 620 पशुधन संरक्षित है। विभाग अंतर्गत कांजी हाऊस तथा पशु आश्रय स्थल स्थापित नही किया गया है। विगत तीन वर्षो में घुमन्तु पशुओं के रख-रखाव हेतु पशुधन विकास विभाग द्वारा स्वीकृत राशि निरंक है। (ग) गृह विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दो वर्षो में घुमन्तु पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है एवं कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार फसल क्षति के संबंध में कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। यद्यपि घुमन्तू पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना एवं फसल क्षति को रोकने के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा गौधाम योजना संचालित की जा रही है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय आदिम जाति विकास मंत्री से ये सवाल करे रहेव कि घुमन्तू पशु के सरंक्षण अउ रखरखाव बर कौन कौन से योजना सरकार संचालित करत हे ? वर्तमान में प्रदेश मा पशु के संख्या कतका हे?

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर में करीब-करीब सभी जानकारी दिया हूं। जहां तक आपने संख्या के बारे बात की है तो हमने इसमें संख्या भी बताया है कि घुमन्तू पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है। उसमें जिलेवार भी विवरण दिया हुआ है। आप परिशिष्ट को निकालकर देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से येही बात करहूं कि घुमन्तू पशु के सरंक्षण अउ रखरखाव बर पशुधन विभाग द्वारा का-का योजना चलत हे? सरकार ओखर रहे के व्यवस्था कोन प्रकार से करे हे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, पशुधन विभाग द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारा एक तो आदर्श गौधाम, गोकुल ग्राम, गौ अभ्यारण्य योजना है और गौशाला है। इस तरह से यह योजना अभी प्रदेश में चल रही है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैंने संख्या पूछा था कतका-कन गौधाम योजना के माध्यम से संचालित होथे और कतका पशु के रख-रखाव ओ योजना के माध्यम से गौधाम में चलत हे।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, जहां तक हमारे यहां गौधाम योजना है, यह योजना 06/08/2025 से संचालित है और इस प्रकार से प्रदेश में 11 गौधामों का पंजीयन कर 620 पशुधन संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 25 गौधामों के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जहां तक हमने बताया कि गौधाम में उनके संरक्षण के लिए, उनके रख-रखाव के लिए तमाम सारी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। बाकी अभी प्रक्रियाधीन है, बहुत सारी जगहों में जहां पर अभी स्वीकृति दिए हैं, लेकिन चालू नहीं हुआ है, उसे शीघ्र ही हम लोग चालू करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में घोषणा हुई थी कि हम पूरे प्रदेश में गौधाम योजना के माध्यम से पशुओं को संरक्षित करने का काम करेंगे। लेकिन अभी दो साल में 11 ठन गौधाम योजना चालू करे हो जेमा तीन ठोक संचालित हे। 11 में तीन संचालित हे और 600 पशु के आप व्यवस्था संचालित करत हो, संरक्षित करे हो। लेकिन मैं ये जानना चाहूं कि ओ जतका पशु हे, 620 ठन पशु हे ओकर रख-रखाव, चारा-पानी के व्यवस्था सरकार के डाहर ले होते कि काकर डाहर ले होते? काबर आपके जवाब के उत्तर में आए हे कि संरक्षित हे, लेकिन उनके रख-रखाव की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा राशि निरंक है। तो विभाग द्वारा ओकर रख-रखाव नहीं होत हे, विभाग द्वारा पैसा जारी नहीं होए तो वो 620 ठन जानवर हा हवा-पानी पी के जियत हे कि कैसे जियत हे?

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने बताया कि 36 गोठानों में गौधाम स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिसमें से 11 गौधाम का पंजीयन किया गया है। प्रति गौधाम 200 पशु रखे जाने के प्रावधान हैं, जिसमें से अभी उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है, वह सरकार से उन्हें अनुदान दिया जाता है। उसके लिए चारा-पानी, बाकी वहां पंजीयन के पश्चात् प्रति पशु प्रथम वर्ष में हम 10 रुपये, द्वितीय वर्ष में 20 रुपये, तृतीय वर्ष में 30

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूपये और चतुर्थ वर्ष में 35 रुपये प्रति पशु के हिसाब से उनके रख-रखाव, उनके चारा-पानी के लिए दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब यह राशि उनको दी जाती है, संबंधित जो पंजीकृत संस्थाएं हैं, उनके जिम्मे लगाया जाता है, तो इसका सही सदुपयोग करते हैं। इसलिए यह कहना कि वहां पर अव्यवस्था है, चारा-पानी नहीं मिल रहा है, तो कृपा करके इसे ऐसा ना कहें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह आपके विभाग का जवाब है कि स्वीकृत राशि निरंक है। तो ये कैसे टाइप के होही तेला आप समझ सकत हो, आपके विभाग के अधिकारी मन समझ सकत हे। लेकिन मैं कहना चाहूं कि जब 1,84,993 घुमंतू पशु में से 620 ला आप संरक्षित करत हो, बाकी मन के स्थिति का होही? ये बाद के बात हे। लेकिन आज गौमाता के नाम से जेन सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में बने हे, मैं तो सभापति महोदय, बस आपके माध्यम से निवेदन करत हौं कि आज ही सदन में घोषणा हो जाए कि गौमाता ला राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, जब अतका बड़े-बड़े बात करथन अऊ ओकर व्यवस्था के काम नई कर सकत हन, ता एखर कोई मतलब नई हे। साथ ही, मैं एक बात अउ कहत हौं कि जतका आवारा पशु है, जेकर कारण आज लगातार बहुतायत मात्रा में सड़क दुर्घटना होवत हे। मैं अपन विधान सभा क्षेत्र में लगातार देखत हौं कि रोज एक न एक दुर्घटना होते रइथे। लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मिलिस कि कोई दुर्घटना नई होवत हे अऊ न ही कोई फसल ला नुकसान होवत हे। जबकि आवारा जानवर के कारण आज पूरा छत्तीसगढ़ में जतका उन्हारी सियारी होथे, यहां लाखड़ी बोआई बंद होगे, राहर बोआई बंद होगे, उरीद बोआई बंद होगे, सब चीज के बोआई बंद हो गे हे। एकर बर अगर आप कोई व्यवस्था करिहौ ता आने वाला समय में भी किसान मन ला कम से कम अपन उन्हारी के फसल ले सकय। का सरकार के तरफ से अईसे कुछ व्यवस्था हो सकथे?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैंने निश्चित ही बताया कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो गौठान हैं, उन गौठानों में ही हम पशुओं को रखने का पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। वहां पर चारा-पानी से लेकर के बाकी सभी चीजों का समुचित व्यवस्था करेंगे। इसलिए सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। वहां हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा जो गौधाम योजना आया है, इस गौधाम योजना के माध्यम से प्रदेश में जितने भी घुमन्तू या जितने दुर्घटनाग्रस्त

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी पशु हैं, उसके रख-रखाव, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके चारे की चिंता, खाने की चिंता, इन सभी चीजों को वहां बेहतर करने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहत हौं कि आप जेन 11 ठन गौधाम के बात करे हौ, वो 11 ठन गौधाम कहाँ-कहाँ स्वीकृत होय हे? अऊ जेन 3 ठन गौधाम संचालित हे, वो कहाँ-कहाँ संचालित होवत हे, आप अतका ला बता देवौ?

श्री रामविचार नेताम :- देखिए, जहाँ तक गौधाम संचालन हो रहा है, उसमें तखतपुर, जिला बिलासपुर में गौधाम लखासार है। इसी प्रकार से जिला बिलासपुर में मस्तूरी ब्लॉक में गौधाम ओखर है। गौधाम केंवतरा, विकासखंड साजा, बेमेतरा में है। इस प्रकार से ये गौधाम यहाँ संचालित हैं। इसके अलावा हमने बताया कि जो पंजीकृत गौशाला हैं, उसे भी इसका दर्जा दे करके हम वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें बालोद जिले में चार गौधाम हैं। बालोद है, गुरूर है, डौण्डी है, लोहारा है। गौधाम में एक डौण्डी प्रस्तावित है। इसी प्रकार से आपने बाकी जो 11 गौधामों की जानकारी माँगी है। यह 11 गौधामों की सूची भी है, आप कहेंगे तो मैं इसे पूरा पढ़ देता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अभी आप पांच का नाम तो पढ़ ही लिये हैं, बाकी पांच को और पढ़ लीजिये।

सभापति महोदय :- आप उपलब्ध करा दीजिये न।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं बता देता हूं। माननीय सदस्य 11 गौधामों की जानकारी लेना चाहते हैं। उसमें जिला कोरबा में गौधाम सुहागपुर, विकासखंड करतला में है। दूसरा सराईपाली, ग्राम पंचायत भैंसदा, जिला कोरबा में है। तीसरा महोरा, पोड़ी-उपरोड़ा में है। चौथा लखासार, तखतपुर में है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी आपको सूची उपलब्ध करा देंगे। आप जो चाहते हैं, आप अंतिम प्रश्न पूछ लीजिये। 11 गौधामों की सूची है। मंत्री जी, बैठ जाईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामविचार नेताम :- पाँचवा ओखर में है, छठवाँ मरवाही में तरईगाँव में है, गौरेला में पड़वनिया में है, रायपुर में ग्राम धनेली, धरसींवा में है। महासमुंद, सरायपाली, कुम्हारी, पिथौरा, बेमेतरा, केंवतरा, साजा में है। इस तरह से 11 गौधाम हैं।

सभापति महोदय :- आप क्या चाहते हैं, वह पूछ लीजिये कि भविष्य में और बढ़ाने का इरादा है, उसको बढ़ाएंगे क्या? ऐसा पूछिये न।

श्री कुंविर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूँ कि दो साल में हमन 11 ठन गौधाम खोल पाय हन अऊ सिर्फ तीन ठन गौधाम संचालित करत हन। आठ ठन गौधाम के ठिकाना नई हे। मैं तो ये कहना चाहूँ कि पूर्व के सरकार के द्वारा जेन गौठान योजना लगभग सब गाँव में संचालित होत रिहीस हे। मैं राजनीति से परे सवाल करत हौं। सब गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने तैयार है, सरकार के पैसा लगे है। मैं कहत हौं कि कुछ नई करना हे। यदि हम चरवाहा मन ला निर्देश कर देन।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं हर कुरुद चल, मैं तोला इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हौं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तैं मोर संग चलना, मैं तोला देखा हौं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, ये हर नाचत-कुदत खरौद गांव गे रिहीस हे।

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहथंव कि अगर बनके तैयार हे त जैसे पहिले स्व-सहायता समूह के बहनी मन काम करथ रहिसे, पशुपालक मन काम करथ रहिसे, चरवाहा मन काम करथ रहिसे, वइसे व्यवस्था दे दिये जाये । कोनो प्रकार के गांव में जतका घूमथे वो नई घूम सकय अऊ साथ ही मैं आपले यह कहना चाहूँ कि आपके पास संचालित करे के ठोस अधिकार योजना नइ ए अऊ मोला त अइसे लगथे कि 2047 तक आपके विजन के हिसाब से गौठान...।

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ नेताम ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि आपको भी अवगत होगा कि जितने भी घुमंतु पशु हैं वह एक नगरीय क्षेत्र में है और एक ग्रामीण क्षेत्र में है । इन घुमन्तु

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पशुओं का भी रखरखाव हमारा विभाग नहीं देखता है । जैसे नगरीय क्षेत्र की बात है तो नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के तहत होता है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है । हमारा पशुपालन विभाग उसके स्वास्थ्य की चिंता, फीडिंग की चिंता और उसके संरक्षण से संबंधित है, यह काम हम करते हैं । यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी संवेदना कहां तक है । यदि हम पशु रखे हैं तो स्वाभाविक है कि जो पशु मालिक होता है, वह घर में बांधता है और वहां रखता ही है । इस तरह से कुछ घुमन्तु पशु हैं, बाकी जगह जो घर में भी पाले हुये हैं, करीब-करीब मिक्स अप करके सड़क किनारे आ जाते हैं और इसलिये भी यह दुर्घटनायें आये दिन हुआ करती है । यहां हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ...।

सभापति महोदय :- नीलकंठ टेकाम जी आप अगला प्रश्न करेंगे। अंतिम हो गया, बहुत हो गया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा पशु संगणना के बात होवत हे त गौ सेवक होवय...।

सभापति महोदय :- क्या है, मंत्री जी को बिठा दिया था । मंत्री जी कुछ बोलेंगे, फिर आप पूछेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, एक लॉस्ट प्रश्न हरय कि मंत्री महोदय जनगणना के बात करिस त मैं जेन हिसाब से जनगणना करेंव त मैं संतुष्ट नई हंव । मोर गुंडरदेही में जेन हिसाब से 2224 के जानकारी दे हे, मैं आंकड़ा बताथंव कि ए साल के आंकड़ा 2800 ले ज्यादा हे अऊ वोखर विभाग के कर्मचारी गलत आंकड़ा प्रस्तुत करे हे । मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नइ हंव । आप मन के आंकड़ा गुंडरदेही में आवारा पशु के 2224 हे अऊ मैं बताथंव कि मोर जानकारी के हिसाब से 2800 ले ज्यादा हे। आपके अधिकारी कहीं न कहीं आपला गलत जानकारी दे हे वोखर ऊपर कार्यवाही करहू का?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, गौठान के चक्कर में उधर पहुंच गये और अभी भी गौठान की बात कर रहे हो?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, अभी आप मन जो गऊ माता के नाम से वोट मांगे हव गाय ला राष्ट्रमाता घोषित करव ना?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संविधान के अनुच्छेद-275 (एक) के अंतर्गत कोंडागांव जिले के लिए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्राप्त आबंटन

[आदिम जाति विकास]

3. (*क्र. 928) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-(क) संविधान के अनुच्छेद-275 (एक) के अंतर्गत कोंडागांव जिले के लिए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? (ख) आबंटित राशि में केशकाल विधानसभा क्षेत्र को कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है? स्वीकृत कार्य में कितने कार्य प्रारंभ, अप्रारम्भ, पूर्ण है? अप्रारम्भ कार्यों की कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) पूंजीगत एवं राजस्व मद में केशकाल विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची मदवार पृथक से उपलब्ध करवाने का कष्ट करेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) संविधान के अनुच्छेद 275 (एक) के अंतर्गत कोंडागांव जिले हेतु वर्ष 2023-24 में राशि रू. 1109.77212 लाख एवं वर्ष 2024-25 हेतु राशि रू. 189.00 लाख आवंटन प्राप्त हुआ है। (ख) जानकारी संलग्न [1]प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

श्री नीलकंठ नेताम :- सभापति महोदय, मैंने आदिम जाति कल्याण विभाग से मैंने प्रश्न किया था और उसकी संपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हो गयी है, लेकिन यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। भारत के संविधान के 275 (1) और इसमें भारत सरकार के संचित निधि से आदिवासी क्षेत्रों के लिये राशि जारी होता है, आबंटन जारी होता है और जो जानकारी आज मांगने पर मिली है, अगर हमको स्वत: ही परियोजना प्रशासकों से और जिलो से यह जानकारी मिल जाती तो विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से समय देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं और मेरे साथ 29 विधायक और 4 सांसद आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। मेरे विधान सभा में खासकर कोंडागांव जिले में आज तक परियोजना सलाहकार मंडल की एक भी बैठक आयोजित नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि बाकी जगह पर हो रहा होगा और अगर नहीं हो रहा है तो माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह संवेदनशील मुद्दा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[1] संलग्न "परिशिष्ट-2"

आदिवासियों के मतदान करने पर हम उनके प्रतिनिधि बनकर आये हुये हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार उन क्षेत्रों में हो रहे कार्यक्रमों की, गतिविधियों की, योजनाओं की समीक्षा करें । सभापति महोदय, मैं बहुत सारे मामलों पर नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे विधान सभा के 3 एकलव्य विद्यालय वर्ष 2023 से पहले स्वीकृत है, अब वर्ष 2023 के पहले का चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आदिवासी विभाग के एकलव्य के काम हो, नहीं किए उनकी हालत तो हम देख रहे हैं, उधर चले गए हैं। लेकिन 2023 के बाद इन दो सालों में हमने क्या किया? आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिए न।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मेरा प्रश्न है, ये तीनों जो एकलव्य विद्यालय हैं, जिसमें 600 बच्चों को दूसरे भवनों में रहकर बड़े ही असुविधाजनक जगह पर पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं। इसमें एकाध आत्महत्या भी हुई है। फरसगाँव के मॉडल कैंपस में सारे बच्चे रह रहे हैं, हालत बहुत ही खराब है। ये तीनों भवन भारत सरकार से स्वीकृत है और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक चालू हो जाएगा?

सभापति महोदय :- मेरा कहना है, आप प्रश्न करके मंत्री जी से जवाब लीजिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- इस भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा? ये अप्रारंभ कामों की सूची में से है, मेरा प्रश्न है कि ये काम कब तक चालू हो जाएंगे?

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न किया गया है, वह प्रश्न.....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, रामविचार जी का लगातार तीसरा प्रश्न है। नियमतः तीसरा प्रश्न लगातार नहीं आना चाहिए, आप उनको संरक्षण दीजिये। तीन प्रश्न लगातार है।

सभापति महोदय :- सीनियर मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं, जवाबदार मंत्री हैं, अजय जी आप चिंता मत करिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी प्रिंटिंग में भी लगातार तीन प्रश्न नहीं आने चाहिए, दूसरी शलाका निकलनी चाहिए।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है और इस चिंता से मैं निश्चित ही विभाग को अवगत कराऊंगा और इसमें अभी तक बैठकें क्यों नहीं हुई इसको मैं दिखवाता हूँ। हम आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। इस सदन के बाकी सदस्य जो परियोजना सलाहकार में हमारे अध्यक्ष बने हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे परियोजना सलाहकार की बैठकें निश्चित तौर पर साल में दो बार कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुई है, उसको हम देखेंगे। बाकी सदन के भी बाकी सदस्यों की भी चिंता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न में अगर प्रश्न को देखा जाए तो आपने आवंटन के बारे में 2023-24 से 24-25 तक पूछा है। साथ ही साथ आपने प्रश्न किया कि कितने स्वीकृत कार्य थे, कितना प्रारंभ है, कितना अप्रारंभ है, कितना पूर्ण है, अपूर्ण है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने दी है। जहाँ तक अपूर्ण जानकारी है, उसमें भी हमने बताया है, इसमें तीन कार्य हैं, जो अप्रारंभ बताये हैं और 29 में से 23 कार्य पूर्ण हुए हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मैंने शुरू में धन्यवाद दे दिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, इसमें से तीन कार्य अप्रारंभ हैं, बहुत छोटे काम हैं। प्रारंभ अभी तीन काम और बचे थे, उसका भी प्रारंभ कर दिया गया है। जो अप्रारंभ है, उसमें स्थानीय स्तर पर कुछ पंचायतों का था तो उसके आधार पर वह भी शार्टलिस्ट कर लिया गया है, वह भी पूरा हो जाएगा। जहाँ तक आपने इससे हटकर एकलव्य मॉडल स्कूल के सम्बन्ध में एक और प्रश्न किया है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सर, प्रारंभ कार्यों की सूची में है। आपके जो जवाब आए हैं उसमें हैं।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, एक तो जो ट्राइबल एरियाज हैं, आपको भी मालूम है, माननीय भूपेश बघेल जी को भी मालूम है, आपके समय में भी जो हॉस्टल-आश्रम स्वीकृत किये जाते थे या अन्य संस्थान जो स्वीकृत होते हैं, तो जमीनों की बहुत बड़ी समस्या होती है और जमीनों के लिए आज हम ले दे कर कुल मिलाकर वन विभाग पर ही आश्रित रहते हैं। अगर हम गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वहां पर वन भूमि होती है और वन भूमि की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक बड़ी समस्या है कि उसकी स्वीकृति इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। उस प्रक्रिया में काफी विलंब हुआ है और तब जाकर यह हुआ है। भारत सरकार के इसमें एकलव्य विद्यालय के जो स्वीकृत भवन होते हैं, उनमें यह रहता है कि उन्हें शत-प्रतिशत क्लीयरेंस चाहिये और क्लीयरेंस मिलने के बाद ही हम कोई काम शुरू कर पाते हैं और इसलिए इसमें कुछ विलंब हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से यह भी अवगत करा देना चाहूंगा कि जहां-जहां हमारे जो-जो एकलव्य विद्यालय स्वीकृत हुए थे, उसकी लगातार मॉनिटरिंग हमारा विभाग कर रहा है और मैं स्वयं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हमने इसमें चर्चा की है और अलग-अलग विभाग के, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और वहां के संबंधित कलेक्टरों के साथ हमने वर्चुअल मीटिंग भी की है और यहां पर भी बुलाकर मीटिंग की है, तब जाकर इसमें काफी शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब भारत सरकार व बाकी जगहों से अनुमति मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया में काफी विलंब हुआ है तो टेंडर के लिए भी भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं, उनको हमने हायर किया है और टेण्डर दिया है कि जैसा भी हो, डी.पी.आर. आप बनाएंगे व बाकी चीजें भी आप बनाएंगे। क्योंकि ये बड़े काम हैं और कहीं ऐसा न हो कि इसमें शिकायत हो, इसलिए उन एजेंसियों की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी की है। पूरा टेंडर प्रोसेस करने के बाद अब वह फाइनल हो गया है और निश्चित ही अब वह गति पकड़ लेगा और बहुत जल्दी उसकी शुरूआत हो रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा केवल सुझाव है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि भारत सरकार ने खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में 5 एकड़ तक की भूमि के लिए कलेक्टर को अधिकार दिया हुआ था कि जो भी निर्माण कार्य हैं, जैसे-स्कूल, छात्रावास, हॉस्पिटल हैं, उसको बनाने के लिए कलेक्टर एक जिले में 5 एकड़ तक जमीन दे सकता है। वह समयावधि बीत गई। वर्ष 2021-2022 में मैंने उसके लिए पहल की थी, लेकिन उसको माना नहीं था। अभी आप फिर से पहल कर दीजिये। जो आप जमीन की समस्या बता रहे हैं, उसके लिए आप राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार से फिर से आग्रह कर लें, क्योंकि हमारे यहां वनाच्छादित है और इस प्रकार की जमीन मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध करके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फिर से उसकी अनुमति ले ली जाए कि कलेक्टर 5 हेक्टेयर तक निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की जमीन दे सकता है। इसके लिए आप पत्राचार कर लें।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां तीन बार उद्घाटन हो गए।

सभापति महोदय :- पहले उन्होंने हाथ उठाया था। आप बोलिये।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने प्रश्न क्रमांक 275 लगाया था। मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। नक्सली क्षेत्र होने के कारण मुझे अनेक ऐसी जगहों में जाने का अवसर नहीं मिलता है। इस मद का पैसा, परियोजना का पिछले दो सालों में एक भी बैठक नहीं हुई है और हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मुझे क्षेत्र के भ्रमण में पता चला कि राशि का ऐसी जगह बंदरबांट कर दिया गया। मैं मध्य क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरबा भी गया था। मैंने इस बात को वहां पर भी बताया कि 37 कामों में 3 कामों को प्रारंभ बताया गया है और आज तक ऐसी जगहों में काम किया गया है, जहां पर कोई भी जनप्रतिनिधि जा ही नहीं सकते हैं। वह संवेदनशील क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में बना दिया गया और जमीन में मात्र नींव भर बना दी गई है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उसकी जांच कराएंगे?

सभापति महोदय :- क्या है कि आपका प्रश्न अलग है और माननीय सदस्य का प्रश्न अलग है। आप सुझाव दे दीजिए, मंत्री जी उसको देख लेंगे।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से पूरे सदन के माननीय सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह की किसी भी संस्था से किसी भी विभाग का कोई भी कार्य यदि स्वीकृत होता है या कोई भी योजना स्वीकृत होती है तो हम सबका दायित्व बनता है कि हमें उसके लिए कैसे भी हो, जैसे भी हो, प्राथमिकता के आधार पर उसको जगह तय करके दिलाना चाहिए। क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो चीज बनने वाली है उसको तो आप तय करेंगे कि वह कहां बनेगी, किस हिसाब से कहां पर हमें जमीन देना ठीक रहेगा और अगर इसमें कहीं पर दिक्कत आ रही है, यदि विभाग नहीं कर पा रहा है तो इसमें आगे बढ़-चढ़कर हमें हिस्सा लेकर उसे पूरा करना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप लोग लिखकर दे दीजिए।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, एकलव्य स्कूल का ही मामला है।

सभापति महोदय :- यदि आप लोग एक-एक करके प्रश्न करेंगे तो प्रश्नकाल (व्यवधान)।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- सभापति महोदय, एकलव्य स्कूल का मामला है। मानपुर में उसका तीन बार उद्घाटन हो गया । माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया।

सभापति महोदय :- लेकिन मंत्री जी मानपुर का कैसे बताएंगे? मंत्री जी आपके प्रश्न में बताएंगे ।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- सभापति महोदय, यह तो एकलव्य स्कूल का मामला है।

सभापति महोदय :- मैं समझ गया, लेकिन जब आपका प्रश्न आयेगा, मंत्री जी उसमें जवाब देंगे ना? आप केवल सुझाव के रूप में दे सकते हैं। मेरा यह कहना है आप यहीं पर अपने सुझाव लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- सभापति महोदय, दूसरा उसी में है कि एकलव्य स्कूल में तीन बच्चे, बच्चियां फिनाइल पीकर...।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आदिवासी उपयोजना की राशि अन्य मद में परिवर्तित की जा सकती है? यदि हां, तो नियम शर्तें क्या हैं?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, यदि कुछ बताना है तो बता दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- इस तरह की कोई राशि जिस मद से स्वीकृत हुई हो, उसी मद से खर्च करने का प्रावधान होता है। यदि फिर भी मान लीजिए कि अतिरिक्त कमरे का स्वीकृत हुआ, अतिरिक्त कमरा वहां बन गया है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की यह जिम्मेदारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बनती है कि उस मद का परिवर्तन करा ले वह भी मुख्यालय की अनुमति से और अनुमति लेकर के कहीं दूसरी जगह भी उसका उपयोग किया जा सकता है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा छोटा-सा प्रश्न है। इसी में से मेरा प्रश्न भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परियोजना सलाहकार मंडल का गठन कब हुआ? अगर गठन हुआ है, तो उसमें कौन-कौन अध्यक्ष हैं?

सभापति महोदय :- अब आप प्रश्न करेंगे तो जवाब आएगा।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, परियोजना सलाहकार मंडल का जो गठन हुआ है, अब उसका प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपने किया है तो मैं अवगत करा दूंगा।

बजट में सम्मिलित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति

[वित्त]

4. (*क्र. 925) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में सम्मिलित किन-किन कार्यों के लिए दिनांक 03 फरवरी, 2026 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है एवं कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास किन-किन कारणों से तथा कब से लंबित हैं एवं इन कार्यों को कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में सम्मिलित कार्यो की स्वीकृत राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है। नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभागों को वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 01 मई 2012 द्वारा रू. 3 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्राप्त थे, जिसे स्थायी वित्त निर्देश 15/2025, दिनांक 14.05.2025 द्वारा बढ़ाकर रू. 5 करोड़ किया गया है ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति

[2] परिशिष्ट "तीन"

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दिनांक 03.02.2026 की स्थिति में वित्त विभाग में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति हेतु लंबित नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरा वित्त मंत्री जी से सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 तक बजट में सम्मिलित कितने कार्य वित्तीय स्वीकृति के लिए किन-किन कारणों से और कब से लंबित हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी कार्य वित्त विभाग में लंबित नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मंत्री महोदय का जवाब आया है और मैंने उसको पढ़ा है कि इसमें कोई भी कार्य लंबित नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इरीगेशन में, पी.डब्ल्यू.डी. में, पी.एम.जी.एस.वाई. में। अगर मैं इरीगेशन की बात करूं तो पिकरीपार माइनिंग 4 करोड़ 94 लाख रुपए, तांदुला परियोजना के तहत नमोरा माइनर 4 करोड़ 96 लाख रूपये। सभापति महोदय जी, मेरे पास ये पूरा बंच है। यह इरीगेशन का बजट में सम्मिलित पूरे कार्य हैं और मेरे पास पी.डब्ल्यू.डी. का यह पूरा बंच है। अगर देखा जाए तो पूरी फाइल तैयार हो जाएगी। मैं जब ई.ई. साहब लोग से बात करती हूं तो उनका यह कहना होता है कि यह सभी कार्य वित्त विभाग में गया है और बुकलेट भी जमा हो चुका है, लेकिन यह वहां पर लंबित है। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाह रही हूं कि क्या अधिकारी सही हैं या मंत्री जी सही हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, एक्चुअली आदरणीय सदस्या ने वित्त और पूरी सरकार के संबंध में जो प्रश्न उठाया है, मैं उसमें पूरी प्रक्रिया को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां सबको अवगत ही है, सब सीनियर मेंबर्स हैं। जैसे कोई भी कार्य बजट में प्रावधानित होता है तो फिर उसकी प्रक्रिया होते हुए वित्त विभाग में सहमति के लिए आता है। वह प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी नहीं आता है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वित्त विभाग देख चुके हैं, आदरणीय अमर अग्रवाल जी भी देख चुके हैं। वहां पर सहमति के लिए आता है। जो वित्तीय स्वीकृति और वित्तीय सहमति है और माननीय सदस्या जी के विधान सभा संजारी बालोद में जो प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है, उसमें 2023-24 में 155 कार्य 66 करोड़ रुपए के, 2024-25 में 580 कार्य 152 करोड़ रुपये के, 2025-26 में 595 कार्य 51 करोड़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रुपये के प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुके हैं। हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो, वित्तीय सहमति हो। इसके लिये हमने बहुत सारे वित्तीय रिफार्म भी अपनी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। वह भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। जैसे बजट में नवीन मद की जो परिभाषा थी, वर्ष 1995 में उसकी गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके बाद पहला संशोधन 2011 में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने 2024 में उसमें फिर से संशोधन किया है। इनमें नवीन मद की परिभाषा अंतर्गत जो राशि है, उसको बढ़ा दिया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- कृपया पूरी प्रक्रिया सुन लीजिए। 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह उत्तर में है, मैं पढ़ लिया है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- नहीं, ये उत्तर में नहीं है। आपके अलावा पूरे सदन को जानना जरूरी है। 01 करोड़ रुपये जो निर्माण का है, उसमें 2 करोड़ रुपये, मशीन उपकरण 50 लाख से बढ़ाकर, 01 करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह से जो प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती थी, उसकी सीमा को वर्ष 2024 में 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जो उसके पहले 2012 में था, उसको बढ़ाकर के 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरी सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो इसलिए वित्तीय रिफार्म वर्ष 2011 के बाद 2024 में किये गये हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो, ये है। मैं दूसरी चीज जो कहना चाहूंगा, माननीय सदस्या का जो बिन्दु है, उनकी जो पूरी सूची है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि बजट में जो प्रावधान होता है, वर्षों से चला आ रहा है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वह जो वित्तीय प्रावधान होता है, उससे बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं उदहारण के तौर पर बताना चाहूंगा कि वर्ष 2023-24 में 302 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि नवीन मद में कार्य 14257 करोड़ रुपये के शामिल थे। इसी तरह से 2024-25 में में 452 करोड़ रुपये के अगेन्स्ट में 16532 करोड़ रुपये के, वर्ष 2025-26 में 734 करोड़ रुपये के अगेन्स्ट में 19 हजार करोड़ रुपये के कार्य शामिल थे। ये बजट में जो प्रावधन रहता है, वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत ज्यादा रहता है। उसके अनुरूप सिंचाई विभाग हो या पी.डब्ल्यू.डी. विभाग हो, सभी में सरकार प्राथमिकता अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करती है। जो विभाग प्राथमिकता तय करता है, उसके अनुरूप वित्तीय सहमति के लिये आता है और उसमें प्रशासकीय स्वीकृति फिर विभाग द्वारा जारी की जाती है।

श्री भूपेश बघेल :- आपने पूरे प्रदेश की प्रक्रिया बता दी, वित्त विभाग की प्रकिया बता दी, लेकिन इनको तो जरूरत बालोद में है। आप बालोद की स्वीकृति तो बताईये। 300 करोड़ रुपये की जगह 14 हजार करोड़ रुपये कर दिये, लेकिन बालोद में तो जीरो है। आप यहां कितना दे रहे हैं यह बताईये?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, संजारी-बालोद में जो बजट में प्रावधान है, उसमें से अभी फिलहाल वित्तीय स्वीकृति के लिये या वित्तीय सहमति के लिये वित्त विभाग में एक भी फाइल लंबित नहीं है। मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा। और विभाग जो भी प्राथमिकता से भेजेगा, उसमें निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक पहल करेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आपने ये बात कह दी कि आपके पास कोई फाइल लंबित नहीं है। अब चूंकि माननीय सदस्य ने बात कही है और सदन में आ गया है तो क्या पी.डब्ल्यू.डी. और सिंचाई विभाग से वह प्रस्ताव मंगाकर स्वीकृति करेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे 3 करोड़ रुपये की सीमा को 5 करोड़ रुपये हमने बढ़ा दिये हैं। उसके कारण से 5 करोड़ रुपये से नीचे के जितने कार्य हैं, उसको वित्त विभाग भेजने की ही आवश्यकता नहीं है। यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। दूसरी चीज कौन से कार्य को करना है, यह विभाग की प्राथमिकता होती है। वह वित्त विभाग का क्षेत्राधिकार नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- वह कितने करोड़ का बता रहे हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 28 करोड़ 8 लाख 42 हजार।

श्री भूपेश बघेल :- 28 करोड़ रुपये का बात रही हैं। वह 28 करोड़ रुपये का है, 3 करोड़ रुपये का मामला नहीं है, वह तो आपके पास ही आयेगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- एक ही प्रोजेक्ट 28 करोड़ रुपये का है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ये वाला आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी देंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- हां, 5 करोड़ रुपये से नीचे के जितने कार्य हैं, उसके लिये वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तो मंत्री जी भी तो नहीं दिये हैं। हां, ठीक है आप बोल रहे हैं कि उसके लिए वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। आपको 18 करोड़ 18 लाख, यह तो आप दे सकते हैं?

श्री ओ.पी.चौधरी :- नहीं, वह विभाग की प्राथमिकता है, विभाग तय करेगा कि वह कार्य जरूरी है या नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें कहां जाऊं? (व्यवधान)

श्री ओ.पी.चौधरी :- अगर विभाग तय करेगा तो निश्चित रूप से सकारात्मक विचार सरकार करेगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे सब चीज को लेकर मैं वित्त मंत्री जी के पास जाऊं या मंत्री जी के पास जाऊं, यह आप ही बता दीजिये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आप सीनियर विधायक हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि सदन में आ गया है और वित्तमंत्री जी उदार हैं, थोड़ा उदारता बरतिये। अब यह 18 करोड़ रूपये का मामला है। आप मंगवाकर स्वीकृत कर देंगे, आपको इतना भर तो बोलना है क्योंकि सबका प्रश्न लगता नहीं है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी।

श्री भूपेश बघेल :- कोई-कोई प्रश्न लग जाता है तो कम से कम इस माध्यम से पूरे प्रदेश को यह संदेश जायेगा कि ओ.पी.चौधरी जी, वित्त मंत्री के रूप में बड़े उदार हैं। 18 करोड़ की बात है, आप स्वीकृत कर दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- करवा दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- इतनी ही तो बात है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं एक कार्य की ही मांग कर रही हूं, बाकी तो अन्य है।

श्री भूपेश बघेल :- अरे, भई स्वीकृत कर दीजिये। हम लोग भी मेज थपथपायेंगे। आपका स्वागत करेंगे। घोषणा करो भई। नहीं करोगे?

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, वैसे वित्तमंत्री जी उदार हैं। वह कहना का विषय नहीं है। (मेजों की थप्थपाहट) वित्तमंत्री जी उदार हैं और इसलिये बजट में हर तरफ देखे हैं कि बहुत स्वीकृति हुई है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आपके पास है, तो यह घोषणा करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- घोषणा कर दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं करेंगे?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, वह विभागीय प्रक्रियाओं की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि मैं यहां पर घोषणा करूं लेकिन मैं आपके माध्यम से...। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह विपक्ष के सदस्यों के कोई कार्य स्वीकृत नहीं करना चाहते और इस कारण से हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय : 11.46 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, बीजापुर-सुकमा में 100-100 करोड़ के एजुकेशन सिटी हम स्वीकृत कर रहे हैं, जगरगुंडा क्षेत्र सुकमा अंतर्गत आता है जहां पर विधायक नहीं हैं, वहां पर 100 करोड़ की एजुकेशन सिटी हम बजट में लेकर के आये हैं, यह कैसे बोल सकते हैं कि विपक्ष को हम स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उदार हैं, हमारी सरकार उदार है और यह सकारात्मक अगर रोल में रहते तो इस कार्य में भी हम सकारात्मकता के साथ उदार निर्णय लेते। (मेजों की थपथपाहट)

बिलासपुर जिले में कालोनाईजरों द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी/व्यावसायिक परिसर

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 783) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 04/02/2026 तक किन-किन कालोनाईजर/कंपनी द्वारा कितनी आवासीय कालोनी / व्यावसायिक परिसर का निर्माण कहाँ-कहाँ किया गया? कालोनाईजर के नाम पता सहित निर्मित कालोनी के नाम एवं निर्माण क्षेत्रफल सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश "क" की निर्मित कालोनियों/व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने अथवा निर्धारित मापदंड के अनुसार निर्माण नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आयी? यदि हां तो किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 अनुसार है।(ख)प्रश्नांश "क" की निर्मित कालोनियों/व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव से सम्बन्धी 21 शिकायत, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने सम्बन्धी 02 शिकायत, भू-सम्पदा की रकम वापसी से सम्बन्धी 15 शिकायत, भू-सम्पदा का अधिपत्य दिलाने सबंधी 11 शिकायत एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने सम्बन्धी 01 शिकायत कुल 50 शिकायत प्राप्त हुई है जिनमे से 28 शिकायतों में आदेश पारित किया गया है, शेष 22 शिकायत प्रक्रियाधीन है। आवेदक/अनावेदक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का नाम, प्रकरण क्रमांक, दिनाक, कार्यवाही सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-4, प्रपत्र-5, प्रपत्र-6,प्रपत्र -7 अनुसार है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बिलासपुर...।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, वित्त मंत्री जी।

सभापति महोदय :- वह प्रश्न अब समाप्त हो गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वित्तमंत्री जी, जब वह सरकार में यहां थे न तो मंडी बोर्ड का कागज देते थे तो उसको कचड़े में फेंक देते थे, आप टेंशन मत लीजिये। आप वैसा ही करिये, जैसा उन्होंने किया।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी, आप प्रश्न करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बिलासपुर जिले में कालोनाईजरों द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी/ व्यवसायिक परिसर के संबंध में था । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है जिसका पूरक प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं कि प्रपत्र क्रमांक-1 के सरल क्रमांक के 16, सरल क्रमांक-15, सरल क्रमांक-24, सरल क्रमांक-26, सरल क्रमांक-28, सरल क्रमांक-65, सरल क्रमांक-73 और सरल क्रमांक-77, 99, 100, 103 में एक ही बिल्डर द्वारा या अलग-अलग संस्थान बनाकर एक ही व्यक्ति द्वारा लगातार टाऊनशिप एक्ट, यह सारे लेआऊट एक ही बिल्डर द्वारा कुछ समय के अंतराल में, वर्ष 2022-23 यानी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश की एकीकृत उपयोजना जिसे हम टाऊनशिप एक्ट कहते हैं, जो 8 हैक्टेयर के ऊपर लागू होती है, उसका सीधा-सीधा उल्लंघन किया गया है । यह कॉलोनी एक ही बिल्डर द्वारा लगभग 100 एकड़ के आसपास निर्मित कर ली गयी है । जिसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पूर्ण नहीं किये गये और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत करते हुए तत्कालीन समय में, टुकड़ों में अलग-अलग तौर पर पास कराकर नियमों का सीधा उल्लंघन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लेआऊट के लिये जो ई.डब्ल्यू.एस. की पात्रता होती है, उसमें कोटवारी जमीन यानी सेवा भूमि को ई.डब्ल्यू.एस. की जमीन दिखाकर यह लेआऊट पास कराये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या ऐसे लेआऊट को स्थगित करते हुए परीक्षण कराकर इनकी बिक्री पर रोक लगायेंगे ताकि आमजन ठगे न जायें।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य का जो सवाल है वह काफी महत्वपूर्ण है और मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि इस विषय पर एक जांच समिति का ऑलरेडी गठन किया गया है, पहले उन्होंने विभागीय रूप से शिकायत की थी तो उस पर ऑलरेडी जांच समिति का गठन किया गया है और विभागीय अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं, टाऊन कंट्री प्लानिंग के अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं और नगर-निगम के अधिकारी भी सम्मिलित हैं तो जांच की कार्रवाई चल रही है और कोई भी गलत हुआ होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न व्यावसायिक परिसर पर है। सरकंडा में खसरा नंबर-546/1, 547/1, 577/1 जो पूर्व में 26.10.1998 में संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा आवासीय समूह, भवन हेतु लेआऊट पास किया गया, सभी भूखण्ड बेचने के बाद संबंधित व्यावसायिक संस्थान द्वारा उसको पुन: जिस विक्रेता को बेचा गया था, उससे फिर क्रय किया गया और दिनांक 07.03.2023 को उसमें से कुछ भाग को पुन: क्रय करते हुए, अनुमोदित ले आउट में दर्शित मार्ग/सड़क हेतु आरक्षित रकबे को पुन: खुली भूमि बताते हुए नवीन भवन अनुज्ञा आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई और बिना नगर और ग्राम निवेश के विकास अनुज्ञा लिये बगैर सीधे नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गयी। उक्त भूमि का व्यवसायीकरण आवासीय होने के बावजूद भी वाणिज्य कर भवन के रूप में अनुज्ञा अधिकारी की मिली भगत से जारी...।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। क्या भू संपदा विकास प्राधिकरण रेरा उक्त अनुज्ञा के रजिस्ट्रेशन को स्थगित कर, संबंधित ले आउट को स्थगित करते हुए, इसकी बिक्री पर रोक लगायेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने वर्ष 2023-2024 से 04 फरवरी, 2026 तक पूरे प्रकरणों की जानकारी मांगी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थी, यह जो प्रकरण बता रहे हैं, यह उससे पहले का है। इसलिए वह इस जानकारी में नहीं आया है। सम्माननीय सदस्य मुझे प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवा देंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम विभागीय रूप से उसमें एक जांच समिति गठित कर देंगे और जो कार्यवाही होगी, हम नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास शिकायत की कॉपी है।

सभापति महोदय :- वह बोल रहे हैं कि आप उनको इसके दस्तावेज दे दीजिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मेरे पास इसकी दस्तावेजी तौर पर कॉपी है। अगर आप कहें तो शिकायत, जो दिनांक बतायी गयी है, यह उसके पूर्व की है और वह बकायदा रजिस्टर्ड डाक से आधिकारिक तौर पर मिलकर दी गई है। अधिकारियों ने सदन में इस विषय को मंत्री जी से छिपाया है। मैं आपको दस्तावेज उपलब्ध करवा दूंगा तो क्या आप संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है और वर्ष 2023-2024 से वर्ष 2026 तक इस बीच में जो ले आउट पास हुए हैं । इस प्रश्न के उत्तर में इसकी जानकारी सूची बनी है। मगर मैं सम्मानीय सदस्य को पूर्णत: आश्वस्त करना चाहता हूँ इसके पहले का ले आउट पास हुआ, यह मामला है तो वह मुझे दस्तावेज उपलब्ध करवा दें तो मैं निश्चित रूप से इसमें विभागीय रूप से जांच समिति भी गठित कर दूंगा और हम उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- आप उनको इसके दस्तावेज उपलब्ध करवा दीजिए, उसके बाद मंत्री जी आपको कार्यवाही के लिए आश्वस्त कर रहे हैं तो आप उनको दस्तावेज उपलब्ध करवा दीजिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, जो व्यावसायिक तौर पर जो भवन अनुज्ञा दी गई। नगर निगम ने बनावटी तरीके से अभिमत मांगा और इसकी अभिमत तारीख 30.05.2023 है। मेरे पास इसकी अनुमति की कॉपी है और माननीय मंत्री जी यह उल्लेखित कर रहे हैं कि अधिकारियों ने उनको यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवायें हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय,सम्माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रायमरी ले आउट पास हुआ है वह वर्ष 2023-2024 के पहले का है इसलिए इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं हुआ है उस डेट की तकनीकी फेर में न मुझे जाना है और न उनको जाना चाहिए। आपके माध्यम से मेरा माननीय सदस्य से यह आग्रह है कि वह ले आउट कब पास हुआ था, मैं उस डेट की बात कर रहा था। अभी उन्होंने इस बीच में शिकायत की होगी इसमें कुछ कोई संशय नहीं है। सम्माननीय सदस्य इसके दस्तावेज उपलब्ध करवा दें निश्चित रूप से इसमें विभागीय रूप से जांच समिति भी गठित करेगें।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आप वही प्रश्न कर रहे हैं उसमें मंत्री का जवाब भी वही आएगा। एक प्रश्न को बार-बार रिपिट करने से कोई मतलब नहीं है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, क्या इसकी जांच करवाकर, आप ले आउट को स्थगित करेंगे?

सभापति महोदय :- आपको मैंने बता दिया कि आप उनको दस्तावेज उपलब्ध करवा दीजिए। उसमें मंत्री जी कार्यवाही करेंगे, वह आपको आश्वस्त कर रहे हैं। आप उनको दस्तावेज उपलब्ध करवा दीजिए। आपके प्रश्न का उतना ही जवाब आएगा।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है कि आप उस ले आउट को स्थगित करके, बिक्री को रोकेंगे क्या?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो सम्माननीय सदस्य ने कहा है कि आप उस ले आउट को कैंसिल करेंगे क्या तो निश्चित रूप से हम इसमें विभागीय जांच कमेटी गठित करेंगे और उसमें यथाशीघ्र जांच कराकर, उस ले आउट को भी कैंसिल करेंगे और जहां तक बिक्री रोकने की बात है उस पर प्राथमिक तौर पर जांच होने के बाद, नियमानुसार 100 प्रतिशत[3] कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[3] "परिशिष्ट - चार"]

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्।

<u>प्रदेश में फ्लाईएश एवं कोलडस्ट की अवैध डंपिंग के प्रकरणों में कार्यवाही</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (*क्र. 663) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने-कितने उद्योगों से फ्लाईएश डंप किया जाता है ? वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04/02/2026 तक अवैध फ्लाइऐश डम्प किए जाने के कितने मामले प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या बिना अनुमति के फ्लाइऐश डम्प करने का मामला प्राप्त हुआ है ? रायगढ़ जिला के फ्लाइएश एवं कोयला परिवहन के कारण दूषित पर्यावरण के सुधार हेतु क्या कार्ययोजना है? उस पर कितना अमल हुआ है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :रायगढ़ जिला के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04.02.2026 तक की अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव में किया गया/ किया जा रहा है। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों में से 06 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थाई रूप से राख का भण्डारण किया जाता है। वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04.02.2026 तक राख के अवैध/बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये है तथा उन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया गया है, जो कि दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील है तथा उद्योगों से जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु परिवहन की निगरानी बाबत औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आईडब्ल्यूएमएमएस) संचालित की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है। परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उद्योगों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। फ्लाई ऐश एवं कोयले के परिवहन दौरान पाई गई अनियमित्ताओं पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पूरा परिशिष्ट दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस प्रश्न के परिशिष्ट ''चार'' में 16 नंबर का प्वाईंट है इसमें जो शिकायत है वह आपको दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त हुई है और आपने उसका दिनांक 16.12.2025 को समाधान किया है मतलब 8 महीने तो यह 8 महीने की देरी क्यों हुई?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य उमेश पटेल जी ने जो प्रदेश में फ्लाईएश संबंधी प्रश्न किया है, इसमें कुल 49 केस हैं और उन्होंने 16 नम्बर के विषय पर प्रश्न किया है । उस पर मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 6,90,000 जमा करते हुए फ्लाई एश का समतलकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया गया । मतलब शिकायत पर कार्यवाही की गई है । उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद कार्यवाही की गई है, लेकिन मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि कार्रवाई हुई है और 6,90,000 रूपए की पेनाल्टी भी हुई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में जानकारी दी है कि इसकी शिकायत 22.4.2025 को हुई थी और इसका समाधान 16.12.2025 को हुआ है। सभापति जी, इसका समाधान इसलिए 16 तारीख को हुआ है क्योंकि पिछले सत्र में 17 दिसम्बर को मेरा यही प्रश्न लगा था । मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि प्रश्न के उत्तर का परिशिष्ट देखने के बाद मैंने सब जगह जाकर इसका जियो टैग से निकाला । मैं आपको चोलहा का बता दूं, यह देखिए। यह जियो टैकिंग के साथ है (पोस्टर/पेपर दिखाते हुए) आपके अधिकारी आपको धोखा दे रहे हैं, यह अभी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य उमेश जी पुराने सदस्य रहे हैं। प्रश्नकाल में पोस्टर वगैरह नहीं दिखाते हैं। आप बोल रहे हैं, वह पर्याप्त हैं। आप मंत्री रहे हैं, नये सदस्य नहीं हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- मैंने जियो टैग करके दिखाया। तीन-चार जगह का चाहे बोतलदा हो, चाहे चोलहा हो, चाहे बानीपातर हो, अभी भी फ्लाई ऐश वैसे के वैसे ही पड़े हैं। आपके अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं। क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले सरकार के समय में जो कार्रवाई होती थी, उससे 10 गुना ज्यादा कार्रवाई ट्रांसपोटिंग के मामले में हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता हूं, बताना भी चाहूंगा।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा बहुत स्पेशिफिक प्रश्न है। मैं चोलहा, बोतलदा और बानीपातर का प्रश्न पूछ रहा हूं। आप मुझे उसका जवाब दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में इनकी सरकार के समय में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जीरो कार्रवाई हुई है। 2022-23 में जीरो कार्रवाई हुई है, 2023-24 में 9 लाख रूपए पेनाल्टी हुई है, वर्ष 2024-25 में 21 लाख की पेनाल्टी हुई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, समय हो रहा है, मेरा प्रश्न बहुत ही स्पेशिफिक प्रश्न है। फ्लाई ऐश डंपिंग से चोलहा से संबंधित प्रश्न है, क्या मंत्री जी उसका उत्तर देंगे? समय बरबाद कर रहे हैं। मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है, मेरे प्वाइंटेड प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं परिस्थिति बता रहा था चाहे वह फ्लाई ऐश डंपिंग का मामला हो, चाहे ट्रांसपोटिंग का मामला हो, सम्माननीय सदस्य उमेश जी ने जो विषय मुझे बताया है, निश्चित रूप से मैं उनसे सारे विषय ले लूंगा, जानकारी ले लूंगा और कहीं पर भी कोई कमी होगी, उसमें विभाग द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। वहां सड़क पर ही लगातार फ्लाई ऐश डंप हो रहा है और इसकी शिकायत मेरे द्वारा खुद कई बार की जा चुकी है। उसके बाद भी विधान सभा में प्रश्न लगने के बाद उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और मंत्री जी, आपके अधिकारियों ने आज भी आपको गलत जवाब दिए हैं। मैं इसके आगे पूछना चाहूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं पहले इसका जवाब देना चाहूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- सभापति जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि 2021-22 जीरो, 2022-23 में जीरो कार्रवाई हुई है। लॉक डाऊन तो केन्द्र ने लगाकर रखा था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, 21-22 से 22-23 तक पूरा लॉकडाऊन नहीं था।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, उमेश जी पर्टिक्यूलर बोतलदा का प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताईए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छी तरह से अवगत थे कि लॉक डाऊन कब से कब तक लगा था। वह 23 मार्च, 2020 की तारीख थी और कुछ महीने लॉक डाऊन था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, गलत जानकारी देना इस सदन की परम्परा बन गई है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, 24 महीने तक ट्रांसपोर्टिंग में आपने जीरो कार्रवाई की।

श्री राजेश मूणत :- उस समय आप मंत्री थे और आपकी सरकार थी, आपने एक बार भी कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? उस समय सब तो मिलीभगत से चल रहा था।

श्री उमेश पटेल :- मूणत जी, प्लीज बैठिए, समय कम है। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरा प्रश्न यह है कि आज के दिन में कितने लाख मेट्रिक टन फ्लाई ऐश रायगढ़ जिले में उत्पादन हो रहा है और कितने प्रतिशत का निराकरण हो रहा है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद मॉडल एसओपी भी जारी किया गया है। इंटीग्रेडेट सिस्टम भी बताया गया है। सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उसमें बताना चाहूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। उनकी ओर से जवाब नहीं देने के कारण हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 11:59 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, 2024-25 में जो फ्लाई ऐश उत्पन्न हुआ है, मैं उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं । 2025-26 में हुआ है, उसकी भी जानकारी मैं उपलब्ध कराना चाहता हूं और जो उपयोग की गई मात्रा है, फ्लाई ऐश से ज्यादा उसका डिस्पोजल भी किया गया है और हमारी सरकार नया एसओपी भी लेकर आई है, इंटीग्रेडेट वेस्ट मैनेजमेंट भी लेकर आई है। वे लोग अनावश्यक अनर्गल राजनीति कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 12.00 बजे

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखता हूं।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उप धारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26

पशुधन विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- मैं, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>पृच्छा</u>

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी नया शिक्षा सत्र आने वाला है। शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय भांटागांव में एम.काम. उपाधि और बी.ए. में इतिहास विषय को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन उसको अभी चालू नहीं किया गया है। इसलिए क्या नये सत्र में उसको चालू कर दिया जायेगा? यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- आपने इसमें किसी प्रकार की सूचना दिए हैं क्या?

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चापा) :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर चांपा जिले के अटल बिहारी बाजपेयी ताप परियोजना के अन्तर्गत 160 भू-विस्थापित आज भी वहां पदस्थापना के लिए लगे हुए हैं। 31 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण करने की जिम्मेदारी कलेक्टर महोदय ने उठाया था, परन्तु निर्धारित अवधि से दो माह का अतिरिक्त समय भी निकलने जा रहा है। उन भू-विस्थापितों को अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाये, यह छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय सभापति महोदय, यह मोहला का मामला है। दिनांक 6.2.2026 को गोड़ समाज के द्वारा रैली और सभा के लिए आवेदन दिया गया था। अचानक उनको 17 तारीख को बुलाया गया, 18 तारीख को रैली थी, लेकिन 17 तारीख को बुलाकर एस.पी., एस.डी.एम., एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एस.पी. चारों अधिकारियों के द्वारा दो सीनियर सिटीजन श्री सुरेश दुग्गा और श्री पूर्णानंद नेताम जो रिटायर्ड प्रिंसिपल और रिटायर्ड रेंजर हैं एवं अन्य दो समाज के व्यक्ति को, चारों को एस.पी. वाई.पी. सिंह द्वारा भारी धमकाया गया है। इस पर शून्यकाल दिया हूं और ध्यानाकर्षण भी लगाया हूं। इसकी जांच की जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 12.03 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 149 “ब” बाईपास रोड निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि भुगतान नहीं किया जाना

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत), श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

राष्ट्रीय राजमार्ग 149 व सारागांव से कटघोरा मार्ग में ग्राम कोसमंदा तहसील चांपा जिला जांजगीर-चांपा के निवासी खीखराम कश्यप, खेमसाय कश्यप एवं श्रीमती मानकुंवर कश्यप के ग्राम कमरीद की कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 33/6, 7, 8, 63/1, 2 एवं 62/1, 2 को रोड निर्माण हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) चांपा के द्वारा लगभग 5 वर्ष पूर्व की गई है। उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि पर मिट्टी पाटकर फोरलेन सड़क सरंचना बना दिया गया, परन्तु उक्त प्रभावित भू-स्वामियों को आज दिनांक तक भू-अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा रोड निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके कारण प्रभावित कृषकगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रभावित कृषक सीमान्त किसान हैं तथा उनकी आजीविका एवं परिवार के भरण-पोषण का एक मात्र साधन कृषि कार्य है। राजस्व विभाग की लापरवाही से प्रभावित गरीब किसान परिवार अपने जमीन के मुआवजा प्राप्त करने हेतु एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों सहित समस्त जन प्रतिनिधियों एवं तहसीलदार से लेकर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र के माध्यम से गुहार लगा चुका है, परन्तु उसकी समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया है। प्रभावितों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में दिनांक 23.12.2024, 24.03.2025 एवं 02.06.2025 एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिनांक 05.03.2024 तथा माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को दिनांक 20.01.2025 को पत्र दिया गया। समस्त पत्रों का संबंधित विभागों द्वारा ऑनलाईन सूचना दिया गया है कि आपकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। परन्तु प्रभावित किसान आज भी भटक रहा है। प्रदेश के ग्रामीण कम शिक्षित लोगों की समस्याओं का निराकरण वास्तविक रूप से नहीं करने तथा उक्त सिस्टम से मात्र औपचारिकता किये जाने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कारण शासन प्रशासन के प्रति आम जनता में अविश्वास की भावना एवं आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 149 ब सारागांव से कटघोरा मार्ग में ग्राम-कोसमंदा, तहसील-चांपा, जिला जांजगीर चांपा के निवासी खीखराम कश्यप एवं खेमसाय कश्यप के पिता- हीरालाल आ. छेडूराम के नाम पर स्थित ग्राम- कमरीद की कृषि भूमि जिसके अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है, के प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2018 के अनुसार खसरा नं. 33/1 रकबा 0.305 हेक्टेयर, खसरा नं. 63 रकबा 0.085 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 62/1, 62/2 शामिल रकबा 0.100 हेक्टेयर की कुल मुआवजा राशि रूपये 24,42,060/- (चौबीस लाख बयालीस हजार साठ रूपये) का भूमि स्वामी हीरा लाल पिता छेडूराम के नाम पर निर्धारण कर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के समय वर्ष 2017-18 में आवेदकगण के पिता हीरालाल के नाम पर भूमि दर्ज था, जिसके कारण हीरालाल के नाम पर अवार्ड पारित किया गया है, जिसका मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। अवार्ड होने के पश्चात तथा हीरालाल की मृत्यु होने के उपरांत उनके वारिसों के द्वारा बचत भूमि का वर्ष 2022 में खाता विभाजन किया गया है, जिसके फलस्वरूप बचत भूमि 33/1, 33/5, 33/8, 62/1 एवं 62/2 मानकुंवर (पत्नी) के नाम पर, 33/2, 33/6, 63/1 खीखराम (पुत्र) के नाम पर एवं 33/4, 33/7 खेमसाय (पुत्र) के नाम पर दर्ज है, जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है। शेष बचत भूमि (आवेदित भूमि) की जांच हेतु आवेदकगण के द्वारा आवेदन पेश किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रभावित होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अर्जित भूमि का मुआवजा राशि प्रदाय कर दिया गया है। जिसके कारण शासन-प्रशासन के प्रति आम जनता में अविश्वास की भावना एवं आक्रोश उत्पन्न नहीं हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आपने देख लिया कि किस प्रकार से घालमेल हुआ है। मैं मंत्री जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर राजस्व विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी आज पटवारी है, उनके एक कलम चलाने से जमीन इधर का उधर हो जाता है, खसरा नं. बदल जाता है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वही मैं पूछना चाहता हूं कि जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खसरा नं. 33/1 में संपूर्ण जमीन से ज्यादा अधिग्रहण हुआ है तो बचत भूमि कहां से आयी, जिसका विभाजन हो गया। यह क्या जानकारी दे पायेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हीरालाल आ. छेड़ूराम के मौत के बाद इनकी फौती उठा और फौती में यह खसरा नंबर 33/1 और 33/2 अनेक टुकड़ों बंट गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनके बहुत टुकड़े हुए। 33/1 में भू-अर्जन 0.305 हेक्टेयर को सड़क के लिए अधिग्रहण किया गया है। इसमें 0.015 भूमि अभी भी बचा हुआ है। खसरा नंबर 33/2 का अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसी तरह से खसरा नं. 62/1, जिनकी रकबा 0.053 हेक्टयर है, इसमें 0.050 अधिग्रहित की गई है। इसमें भी इनका 0.003 हेक्टयर शेष है। खसरा नं. 62/2 में इनकी 0.0553 हेक्टेयर रकबा था, जिसमें से 0.050 भूमि अधिग्रहित की गयी है और 0.003 इनकी जमीन अभी बची हुई है। इसी तरह से खसरा नंबर 63 में 0.162 हेक्टेयर रकबा था, जिसमें से 0.085 को अधिग्रहित की गई और इनकी जमीन 0.077 बचा हुआ है। कुल मिलाकर इनके जो पाँच खसरे थे, जिसमें से कुल 0.908 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें से 0.490 हेक्टेयर भूमि यानी करीब एक एकड़ 21 डिसमिल सड़क निर्माण के लिए अधिगृहित की गयी और इनकी 0.418 हेक्टेयर यानी एक एकड़ 3 डिसमिल जमीन संयुक्त खाते का बची हुई है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री, आप देख रहे हैं कि कितने 0.08, 0.05, 0.06 हेक्टेयर खसरा नंबर की जमीन बता रहे हैं। अगर यह इतना सरल होता तो एक गरीब आदमी जो सारागाँव कंवरीद में रहता है, प्रधानमंत्री तक पत्र लिखने, आपके मुख्यमंत्री तक आने और कलेक्टर के पास बार-बार जाने की क्या ज़रूरत थी? एक गरीब आदमी जिसके पास कुल मिलाकर पूरे परिवार में एक एकड़, 1.01 एकड़ जमीन है, उसको आप 7 साल से कलेक्ट्रेट में या भू-अर्जन अधिकारी के पास घुमा रहे हैं। आप समझते हैं कि यह बहुत सरल है, फिर आप उसको निराकरण करा दीजिए या घोषणा कर दीजिए कि एक महीने में उनको भुआवजें का भुगतान हो जायेगा। अगर उसकी भूमि अधिगृहित हो चुकी है तो उस मामले को खत्म करें, नमस्ते कर लें। यदि उसका निराकरण नहीं हुआ तो गंभीरतापूर्वक उसकी जाँच करा लें। इतनी ही छोटा सा प्रॉब्लम है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं किसान की पीड़ा को समझता हूँ और अभी तक मुझको ऐसा लगा कि जो यह पेंडिंग रहा, उसके पीछे एक ही खसरे का कई बार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टुकड़ा होना है और टुकड़े के कारण वहाँ पर कन्फ़्यूज़न हो गया है। अभी हम इसमें एक संयुक्त टीम गठित करते हैं, जिसमें हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी रहेंगे और एन.एच.आई. के अधिकारी रहेंगे। दोनों विभाग के टीम को एक बार बैठाकर उनकी जमीन का सर्वे करायेंगे। वैसे यह 2018 का प्रकरण है। वर्ष 2018 में भी मुआवज़ा का वितरण हुआ, वर्ष 2022 में भी मुआवज़ा का वितरण हुआ। इनकी ज़मीन वर्ष 2018 से अधिगृहित की गयी है, लेकिन बीच में किश्त-किश्त में और अवॉर्ड पारित हुए हैं, उसमें भी वह शिकायत नहीं किए थे। वह वर्ष 2024 से लगातार शिकायत कर रहे हैं और वाकई में भटक रहे हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को आश्वस्त करता हूँ। मैं इस किसान की पीड़ा को मैं समझता हूँ कि छोटे से ज़मीन का टुकड़ा जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनको मुआवज़ा राशि मिलनी चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारी की टीम और हमारे एन.एच.आई. की टीम के दोनों विभागों के अधिकारी बैठाकर इनका सर्वे करा करायेंगे कि वास्तविक में इसकी कितनी ज़मीन सड़क में निकली है, ताकि उसका वास्तविक मुआवज़ा मिले। फिर से इसकी नई प्रक्रिया प्रकाशन अवॉर्ड की जल्दी करा करके हम चाहेंगे कि इनकी ज़मीन का मुआवज़ा मिले इसके लिए, मैं तत्काल काम करूँगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इसी विषय में मेरा एक प्रश्न है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाँ, आपके बाद है, भैया।

डॉ. चरणदास महंत :- यह तो मेरा प्रश्न है, जो मेरे गाँव के आसपास की ज़मीन का मामला है। माननीय मंत्री जी, ऐसे लगभग सभी गाँवों में पटवारियों ने अपना मायाजाल रचा है और उसका मुख्य कारण गरीबी का लाभ उठाना, उसके कमज़ोरपन का लाभ उठाना, उनके बिना पढ़े-लिखे होने का लाभ उठाना है। मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के जितने भी आवेदन आ रहे हैं, उसका निराकरण कर दीजिये। आपने गरीब आदमी के मर्म को समझा, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष जी का ध्यानाकर्षण है तो वृहत रूप से होगा । अब वह सक्ती में अशक्त हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वह निर्णय करें । ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है, मेरे यहां भी है । किसी जगह भी हो । जमीन का अधिग्रहण कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में अवार्ड

पारित होगा और कितने दिनों में उसके खाते में मुआवजा आ जायेगा । एजेंसियों के लिये एक जवाबदेही तय करेंगे और स्पष्ट नियम बनायेंगे क्या ? एक निश्चित अवधि में सभी विभाग अपना कार्य संपादित करके जिसका भी जमीन अधिग्रहण हो, वर्षों तक 10-10, 20-20 सालों से लंबित है। इसकी जांच कराके और एक स्पष्ट नियम की समयावधि तय करके नियम बनायेंगे क्या ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी काम के लिये चाहे वह सड़क की बात हो या जलाशय की बात हो या कोई भी काम हो । भूमि अधिग्रहण के सारे नियम बने हुये हैं, उसका समय निर्धारण है । प्रारंभिक प्रकाशन के बाद कब तक उनका दावा आपत्ति का समय है, कब तक उनका ऐवार्ड पारित होना है, कब तक उनको मुआवजा राशि मिलना है, इन सभी का समय पहले से निर्धारित है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मंत्री जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इसको बता दीजिए ? सभी के नियम हैं तो पालन क्यों नहीं हो रहा है ? अब जब नियम का पालन नहीं हो रहा है, आपने ध्यानाकर्षण में स्वीकार किया है तो फिर ऐसे प्रकरण की जांच करके संबंधित पर क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नियम बने हैं तो यह बता दीजिए ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, कई जगह ऐसे प्रकरण आते हैं, वैसे बहुत से प्रकरण निर्धारित समयसीमा में हो जाता है। कई जगहों पर मुआवजा राशि के निर्धारण से किसान संतुष्ट नहीं होता है, वह वाद दायर करता है, आपत्ति करता है, फिर वाद को न्यायालय में ले जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वह क्लियर कट है। न्यायालयीन को छोड़ दीजिए, वारिसान के कारण रूक गये हैं, जो क्लियर कट है और लेट हो गये हैं उन प्रकरणों की जांच करके, जवाबदेही तय करके, कार्यवाही करेंगे क्या? आप कारण बताने की कोशिश करें, पहले कहा कि गरीबों की जमीन, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जो क्लियर कट हैं, सारी औपचारिकतायें पूरी हो गयी हो, उनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, यदि इसमें सारी प्रक्रिया के बाद देरी होती है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसकी जांच करके कार्यवाही करेंगे क्या? यह बताईये। जब नियम क्लियर है और नहीं हो रहा है तो उसमें कार्यवाही कीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकरण में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, प्रकाशन हो गया है, ऐवार्ड पारित हो गया है, उनका पैसा आ गया, उसके बाद मुआवजा वितरण नहीं हुआ है या किसान को नहीं मिल पाया है, अभी ऐसा प्रकरण आया नहीं है। यदि ऐसा प्रकरण आयेगा, पैसा आ गया उसके बाद नहीं मिला है तो उसमें तो कार्यवाही...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं आपको ऐसा उदाहरण लिखकर दे दूँ तो आप कार्यवाही करेंगे? मैं आपको ऐसा प्रकरण दे देता हूँ वह कहीं का भी हो तो आप कार्यवाही करेंगे क्या?

श्रीमती शेषराज हरवंष :- देखिये, इसमें जिम्मेदारी तय करेंगे और जिन्होंने जानबूझकर मुआवजा प्रकरण को रोका है..।

सभापति महोदय :- शेषराज हरवंष जी, कुछ पूछना है तो?

श्रीमती शेषराज हरवंष :- सभापति महोदय, भू-स्वामियों को कितनी-कितनी राशि का मुआवजा निर्धारण हुआ है और यह मुआवजा का निर्धारण सिंचित दर पर हुआ है या असिंचित दर पर हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भूमि का मुआवजा सिंचित के लिये अलग दर है और असिंचित के लिये अलग दर है, दो फसली के लिये अलग दर है, इनका मुआवजा निर्धारण है । जिस सड़क की बात कर रहे हैं, इस प्रकरण में कहां पर किसको कितनी राशि का मुआवजा मिला है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूँगा।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इस मुआवजे के प्रकरण का अधिकारियों के द्वारा ठीक से निराकरण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार में तखतपुर बायपास की स्वीकृति मिली थी। NH का ही है, मैं उदाहरण सहित बता रहा हूँ, तब से लेकर 2 साल हो गए, मेरे लिए नया विधानसभा है, मैं वहाँ 2 साल से विधायक हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ कि आखिर ये मुआवजा कैसे मिलता है, कौन देता है, क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तरीका है, क्यों नहीं मिलता है? भैया सरकार का नियम है कि जिसकी जमीन जितना जाएगा, उतना रुपया उसको देना है। मंत्री जी इसमें क्या लफड़ा है? आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप नेता जी के प्रश्न पर तो कार्यवाही जरूर करिए, वहाँ पर भी गरीब लोगों का ही जमीन जाना है। वहाँ पर भी अभी मुआवजा ठीक से निर्धारित नहीं हुआ है। आप अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित करके उनको वितरण करने के लिए विशेष रूप से आज खबर कर देंगे क्या? भाई, उसको भी निपटवाइये । यही आपसे पूछना है, मैं माँग कर रहा हूँ कि आप हमारे तखतपुर बायपास के मुआवजे के प्रकरण को यथाशीघ्र करने के लिए कृपापूर्वक आप अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे क्या?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्माननीय धर्मजीत सिंह ने जो बात रखी है, जिनका मुआवजे का प्रकरण लंबित है, उसको हम तत्काल उनकी जाँच करते हैं कि क्यों अटका हुआ है, फिर हम उस उसको आगे बढ़ाएंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- करवा दीजिएगा।

श्री टंकराम वर्मा :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, आप कर किसान मन मिले रिहिस खैर आप तो बहुत आश्वासन दे रेहेव मैं कहेंव कि सदन में भी ओ बात ला देव करके।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार जी, अभी गाय, गरवा, गौठान के प्रश्न रिहिस तैं कहां चल दे रेहेस। तैं उहूंचे चरे ला तो नई चल दे रेहेस। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं तुंहर खोपड़ी के जांच करवाए बर गे रेहेव। (हंसी) एडीबी के तुंडरी से सक्ती रोड बनिस। ओखर मुआवजा बर किसान मन माननीय मंत्री जी से मिलिन, मंत्री जी ओला आश्वासन भी दे हे, मैं आपसे निवेदन करत हंव कि आप अपन अधिकारी ला बोल देहू। दूसरा सपोत से बघरेल रोड बनना हे। ओमे आपके राजस्व विभाग वाले मन काम में रुचि नहीं लगात हे। वैसे काम जहाँ रोड बनना है जनहित के काम हे, वहाँ भी राजस्व विभाग हर दूसरे चीज में भूले रथे। ये दो ठन विशेष मोर क्षेत्र में काम हे। आपसे निवेदन है, ओला अति शीघ्र पूरा कर देव, चूंकि 300 किसान मन आय रिहिन, माननीय मंत्री जी से 80 किसान मन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिलिन भी हे। मैं कहेंव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ला एक बर और निवेदन करत हंव। बस यही रिहिस।

सभापति महोदय :- ठीक है, ओला दिखवा लिही।

श्री ललित चंद्राकर :- सभापति जी एक मिनट।

सभापति महोदय :- इसमें बहुत चर्चा हो गई है।

श्री ललित चंद्राकर :- एक मिनट, एक मिनट। माननीय मंत्री जी हमारे दुर्ग जिला में, दुर्ग विकासखंड में, भारतमाला रोड गया है, उसमें सेम केस में स्क्वायर फीट में मुआवजा दिया गया और सेम केस में मुआवजा अभी तक दिया नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे मामला हमारे विधानसभा में है। क्या उसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे ?

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को लिखकर दीजिएगा।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भारतमाला प्रकरण अलग है और उसपर EOW की जाँच भी चल रही है और देख रहे हैं, लगातार कार्यवाही हो रही है। ये सरकार माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। जितने लोग उसमें लगे हैं, चाहे वह विभाग के अधिकारी हो, चाहे बिचौलिए हो, भू-माफिया हो, सबके ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है और अनेक तरह की उसमें अनियमितताएँ बरती हैं जिसकी जाँच EOW कर रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप सभी में कार्यवाही की बात बोल रहे हैं, लेकिन आपने सदन में घोषणा की है, उसमें आज तक कार्यवाही नहीं हुई है, 2 साल हो गए।

सभापति महोदय :- आप बैठिए, इसमें बहुत चर्चा हो गई।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय मंत्री जी, ये कार्रवाई आप कब तक कराएंगे बताईए?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, आपने सदन में घोषणा की है, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टंकराम वर्मा :- कार्रवाई कैसे नहीं हुई है, लगातार लोग अंदर जा रहे हैं। सस्पेंड हो रहे हैं, बर्खास्त हो रहे हैं, लगातार उनको हिरासत में ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेरे प्रश्न में आपने सदन में घोषणा की थी। विधान सभा अध्यक्ष महोदय के बोलने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधान सभा के प्रश्न प्रश्न में आपने घोषणा की है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर घोषणा की थी।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, जो निर्माणाधीन जगह है, वहां अभी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पुरदा के पास अभी लगातार कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी किसी कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय :- आगे बढ़ गये हैं। आप बैठिये।

(2) पी.एम.श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय रामचंद्रपुर को परीक्षा केन्द्र से वंचित किया जाना।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा), श्री अजय चन्द्राकर, श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छात्रहित में छत्तीसगढ़ राज्य, विद्यालयों एवं शिक्षकों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अधिकांश ब्लॉक मुख्यालयों में पी.एम. श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्र हित में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इसके विपरीत आदिवासी बाहुल्य जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) के ब्लॉक मुख्यालय रामचंद्रपुर में मौजूद पी.एम. श्री आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (परीक्षा केंद्र क्रमांक 711039) को माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के गंभीर लापरवाही के कारण परीक्षा केंद्र से वंचित किया गया है। विगत 25 वर्षों से संचालित हो रहे परीक्षा केंद्र रामचंद्रपुर के स्थान पर 04 कमरों से संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांजर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, इससे वर्तमान परीक्षा में सम्मिलित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो रहे छात्र-छात्राओं एवं सहयोगी अभिभावकों को इस आदिवासी बाहुल्य अत्यंत दुर्गम क्षेत्र, परिवहन सुविधा से वंचित हाथी प्रभावित क्षेत्र, जंगली जानवरों का भय, नदी-नालों से युक्त क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रामचंद्रपुर को परीक्षा केंद्र से वंचित करने के कारण छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में शासन और प्रशासन के प्रति रोष तथा आक्रोश व्याप्त है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सही है कि छात्रहित में छत्तीसगढ़ राज्य, विद्यालयों एवं शिक्षकों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अधिकांश ब्लॉक मुख्यालयों में पी.एम. श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिये छात्रहित में परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इसके विपरीत आदिवासी बाहुल्य जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) के ब्लॉक मुख्यालय रामचन्द्रपुर में मौजूद पी.एम. श्री आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामचन्द्रपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (परीक्षा केन्द्र क्रमांक 711039) को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की गंभीर लापरवाही के कारण परीक्षा केन्द्र से वंचित किया गया है।

वास्तविकता यह है कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 5 कि.मी. की दूरी पर एवं आदिवासी क्षेत्रों में 15 कि.मी. की दूरी पर संचालित संस्था को जिसमें छात्रों की बैठक क्षमता, प्रकाश, विद्युत, पेयजल की सुविधाओं एवं आवागमन को ध्यान में रखते हुए जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर मण्डल की परीक्षा समिति के अनुमोदन उपरांत परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है।

यह कहना सही नहीं है कि विगत 25 वर्षों से संचालित हो रहे परीक्षा केन्द्र रामचन्द्रपुर के स्थान पर 04 कमरों से संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांजर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, इससे वर्तमान परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र-छात्राओं एवं सहयोगी अभिभावकों को इस आदिवासी बाहुल्य अत्यंत दुर्गम क्षेत्र, परिवहन सुविधा से वंचित हाथी प्रभावित क्षेत्र, जंगली जानवरों का भय, नदी-नालों से युक्त क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वास्तविकता यह है कि परीक्षा वर्ष 2026 के लिये शास.उ.मा.वि. गांजर (711046) को परीक्षा केन्द्र बनाये के पीछे कारण यह है कि हाई स्कूल द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 मूल्यांकन केन्द्र-स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर में अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षा केन्द्र-स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामचन्द्रपुर जिला-बलरामपुर (711039) के विषय-गणित एवं सामाजिक विज्ञान के 04 छात्रों की मुख्य एवं पूरक उत्तर पुस्तिका में लिखावट में भिन्नता पायी गयी थी।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, इतना तो हमें भी मालूम है। उसमें उत्तर दिया गया है। जो मूल प्रश्न है, जिसमें ध्यानाकर्षण है, प्रबोध जी, आप उसको पूछिये। इतना डिटेल तो हमें भी मालूम है। वह आ गया है। आप समय की बर्बादी न करें।

सभापति महोदय :- आप बाद में प्रश्न पूछियेगा।

श्री गजेन्द्र यादव :- जिसके कारण मण्डल की परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र-स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामचन्द्रपुर को आगामी एक वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया एवं छात्रों का परीक्षाफल निरस्त एवं आगामी वर्ष 2025 की परीक्षा से वंचित किया गया, साथ ही केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों को मण्डल के समस्त पारिश्रमिक कार्य से एक वर्ष के लिये वंचित किया गया। परीक्षा केन्द्र-शास.उ.मा.वि. गांजर में छात्रों की पर्याप्त बैठक क्षमता व अन्य सुविधायें हैं, छात्र-छात्राओं एवं सहयोगी अभिभावकों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

यह सही है कि पिछले वर्ष 07 मार्च 2025 को आयोजित विधान सभा सत्र के ध्यानाकर्षण की सूचना में माननीय मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में कहा गया था कि पी.एम.श्री. आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय रामचन्द्रपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को केवल आगामी 01 वर्ष तक के लिये परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

वास्तविकता यह है कि पूर्व परीक्षा केन्द्र शा.उ.मा. वि. रामचंद्रपुर में मूल्यांकन के दौरान मुख्य एवं पूरक उत्तर पुस्तिका की लिखावट में भिन्नता पायी गयी थी, जो परीक्षा केन्द्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संचालन की दृष्टि से अंसतोषजनक होने के कारण परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया। यह कहना सही नहीं है कि रामचंद्रपुर को परीक्षा केन्द्र से वंचित करनें में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा लापरवाही बरती गई। यह भी कहना सही नहीं है कि रामचंद्रपुर को परीक्षा केन्द्र से वंचित करने के कारण छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के मन मे शासन और प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोष व्याप्त है। गत वर्ष परीक्षा केन्द्र शा. हाई स्कूल गाजर में रामचंद्रपुर के परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई थी, तत्समय या उसके पश्चात केन्द्र में अव्यवस्था के सबंध में छात्रों एवं पालकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अत: स्पष्ट है कि छात्र-छात्रों एवं उनके पालकों के मन में शासन और प्रशासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है, लेकिन वास्तव में इतने जो छात्र-छात्राएं हैं, विगत 25 वर्षों से रामचंद्रपुर में आत्मानंद स्कूल संचालित है और उसमें पिछले वर्ष की गड़बड़ी के कहने के कारण जो छात्र नकल कर रहे थे या ओव्हरराइटिंग थी, उसके चलते उस परीक्षा केंद्र को समाप्त कर दिया गया। पिछले सत्र में ही 7 मार्च, 2025 को इसी विषय में ध्यानाकर्षण आया था, जिसको माननीय रिकेश जी ने लगाया था। उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक वर्ष के पश्चात वर्ष 2026 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वतः ही परीक्षा केंद्र खोल दिया जाना है। एक वर्ष के पश्चात उसको खोला जाना था। सिर्फ एक वर्ष के लिए उसको बाधित किया गया था। एक वर्ष बीत गए और वर्ष 2026 का परीक्षा केंद्र पुनः वहां संचालित होना था, लेकिन उसे संचालित न करके इस वर्ष भी छात्रों को परीक्षा देने के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है। जिन्होंने नकल कराया या जो भी कराया हो, उस एक शिक्षक या किसी की गलती के कारण उस क्षेत्र के तमाम लगभग 500-600 छात्र-छात्राओं को आज इतनी दूर हाथी प्रभावित क्षेत्र में पैदल और समय के पहले जाना पड़ रहा है। एक प्रकार से उनको परीक्षा देने में हरासमेंट हो रही है। क्या जो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी थे, उन पर कार्रवाई हुई है? और जवाब आने के बावजूद भी इस वर्ष उस परीक्षा केंद्र को चालू नहीं किया गया तो उसके लिए दोषी कौन है और उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मंत्री जी के जवाब के बाद आप पूछ लीजियेगा।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, एक साथ पूछने दीजिये। एक साथ जवाब दे दूंगा।

सभापति महोदय :- आप पहले मिंज जी का जवाब दे दीजिये फिर वह पूछेंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण पूरी तरीके से स्पष्ट है। वहां चार बच्चे नकल करते हुए पकड़ाते हैं और उस परीक्षा केंद्र में अधिकारियों के द्वारा उन बच्चों पर जो सजा मिलनी थी वह सजा भी मिल गई। लेकिन वहां के अधिकारियों पर या वहां के शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कार्रवाई नहीं की, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह कैसे सही है कि परीक्षा केंद्र को वहां से बदल कर जंगल में 15 किलोमीटर अंदर दिया गया है। जहां पर शेर, भालू और हाथी आते हैं। परीक्षा केन्द्र को उस जंगल में भेज दिया गया और यह ध्यानाकर्षण मेरे द्वारा बार-बार सदन में लगाया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इतना गंभीर विषय, जिसके लिए इतनी बहस हुई और तत्कालीन शिक्षा विभाग जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था, उन्होंने सदन में यह कहा था कि एक साल के लिए इस परीक्षा केंद्र को निरस्त किया जाता है। हमने मान लिया और मानने के बाद आज यह दूसरा साल चालू हो गया है। ऐसा कौन-सा इतना बड़ा गंभीर विषय है, जिसके कारण उस परीक्षा केंद्र से बच्चों को वंचित किया जा रहा है? यह समझने वाला विषय है। इसे प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या उस परीक्षा केंद्र को कल से ही चालू ना किया जाए? मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को कहना है कि कोई नकल प्रकरण को छोटा-मोटा मान रहे हैं। मैं उसमें कहना चाहता हूं कि नकल प्रकरण नहीं था। बिलासपुर में जो पर्यवेक्षक सेंटर था, जहां पर परीक्षा पुस्तिकाओं की जांच हो रही थी, उत्तर पुस्तिकाएं और पूरक पुस्तिकाएं दोनों की राइटिंग अलग-अलग थी। यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। चार बच्चे हैं, उनकी मुख्य उत्तर पुस्तिका की राइटिंग अलग है और जो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका लिखने के लिये लेते हैं, उसकी राइटिंग अलग है। यह कोई चिटमार का विषय नहीं है। उसमें सिर्फ बच्चे ही इनवाल्व हैं, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं वह संस्था के कार्यरत जितने भी शिक्षक ड्यूटी में लगे हैं, वह सबकी उसमें कहीं न कहीं सहभागिता दिखती है। उसको ध्यान में रखकर पहले हमने उस सेंटर को निरस्त किया, चारों बच्चे के परिणाम को रोका गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके अलावा उस परीक्षा केन्द्र में जितने शिक्षक की ड्यूटी लगी थी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा यह निर्णय किया गया है कि 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रिमक कार्य उनसे न लिया जाये, जांच बैठी है, नोटिस दिया गया है। आज भी वह जांच प्रक्रियाधीन है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई पूरी हुई है। यह मामला एक बड़ा विषय है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग था, उन्होंने सदन में कहा कि मात्र 1 साल के लिये हम उस परीक्षा केन्द्र को निरस्त करते हैं उसके बाद यह यथावत चालू हो जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री के सदन में कथन के बाद अधिकारी उस परीक्षा केन्द्र को चालू नहीं कर रहे हैं। जब आपकी पूरी जांच पहले हो गई थी, उस जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि मात्र 1 साल के लिये निरस्त करेंगे। जब आपने बच्चे को सजा दे दिया, शिक्षक को सजा दे दिया, परीक्षा केन्द्र को सजा दे दिया, उसके बाद 01 साल के बाद उसको चालू करना था, लेकिन आज आप चालू नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग से अधिकारी प्रतिदिन पैदल उस जंगल में जायें जहां हाथियों, तालाबों का सामना करना पड़ता है, लोग पानी से चलकर जाते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच चल रही है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति जी, मेरा यह अनुरोध है कि इसे मुद्दा न बनाया जाये। उस परीक्षा केन्द्र को नियमानुसार जिस कथन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसके अनुसार इसे चालू किया जाये।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा कहना है कि हम सब बहुत भलीभांति जानते हैं, 10वीं 12वीं बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा मंडल की अपनी एक इकाई है, उसमें 20 सदस्य रहते हैं। 20 सदस्यों में 5 माननीय विधायक रहते हैं, बोर्ड के चेयरमेन, सचिव हैं और उसमें बाकी शेष शिक्षाविद सदस्य रहते हैं और बहुत गिने-चुने टाप के स्कूल के प्रिंसिपल उसमें सदस्य रहते हैं। कोई भी परीक्षा केन्द्र खोलना, नहीं खोलना यह निर्णय बोर्ड की समिति में तय होता है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सीधा सवाल है कि क्या यह परीक्षा केन्द्र खुलेगा या नहीं खुलेगा ? मुझे हां या ना में जवाब दे दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गजेन्द्र यादव :- मै उसका जवाब दे रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की की 25.11.2025, 22.12.2025 को जो बैठक हुई जिसमें संबंधित सारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित होते हैं। संबंधित जिला से जो मांग आती है कि हमारे यहां इतनी दूरी में ये स्कूल है, इसमें हमको नया परीक्षा केन्द्र खोलना चाहिए। ऐसी मांग आती है और उस मांग के आधार पर यहां के जो संबंधित कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनकी अनुमति, अनुशंसा से जिला शिक्षा अधिकारी रिकमंड करते हैं। मैं नियम की बात कर रहा हूं, नियम बता रहा हूं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में दिया है, उसके बाद ऐसा कौन सा अधिकारी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना कर रहा है ? किसकी इतनी ताकत हो जा रही है ? और बच्चे 15 किलोमीटर दूर जंगल में जाते हैं और यह राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। और सदस्य की बात कर रहे हैं, सुशांत शुक्ला जी सदस्य हैं, आप इसे बताईये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस समिति की बात कर रहे हैं, उस समिति का मैं सदस्य हूं। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल के किसी अधिकारी ने लिखित पत्राचार के आधार पर मीटिंग की सूचना दी? उस मीटिंग में कितने विधायक उपस्थित थे ? मैं आपको स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि 16-16 वर्षों से चलने वाले केंद्र एक अधिकारी की मनमानी के कारण बंद कर दिये जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की दुश्मनी है या उन बच्चों के साथ या उनके पालकों के साथ और यह परीक्षा केंद्र को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- रिकेश जी, उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, सत्तापक्ष के विधायक का यह हाल है तो हम लोगों का क्या होगा? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सदन में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि यथावत उसी परीक्षा केंद्र को चालू किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की, जहां ऐसा कोई आपत्तिजनक विषय आया है, कोई घटना हुई है, दुर्घटना हुई है या तो किसी प्रकार का कोई प्रकरण आया है तो आगामी एक वर्ष तक के लिये उस परीक्षा केंद्र को सस्पेंड किया जाता है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं यह घोषणा नहीं है कि उसको चालू किया जाये।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, यह कौन सी बात हुई? माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि एक साल के लिये निरस्त हुआ है।

श्री गजेन्द्र यादव :- निरस्त हो गया न।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, तो इसका मतलब अगले वर्ष चालू होगा और देखिये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन को आप मिनट्स में निकालकर देख लीजिये। उनके बयान को, उनके बोलने के बाद अगर अधिकारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से गलत है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा बता रहा हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बार-बार खड़े मत होइए। अजय जी को भी प्रश्न पूछने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक स्कूली शिक्षा का उसमें अभिमत है उसके बाद...।

सभापति महोदय :- अभी अजय जी का उसी में प्रश्न है।

श्री सुशांत शुक्ला :- एक अधिकारी की मनमानी के कारण व्यवस्था दी जा रही है यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, हमारा जवाब तो दिलवा दीजिये। घोषणा करवाईये कि परीक्षा केंद्र जो है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी खड़े हैं। आप लोग बैठिये।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी घोषणा करें कि परीक्षा केंद्र जो है वहीं पर यथावत चालू होगा।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, परीक्षा केंद्र खोलने की घोषणा तो उसी दिन हो गयी जिस दिन माननीय कलेक्टर की अनुशंसा से, जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा से डी.ओ. ने जब माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पत्र लिखा। लेकिन उसका...।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, तो इसका मतलब अगर आपने घोषणा कर दी थी तो बच्चे जो हैं, अभी भी दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देने के लिये 15 किलोमीटर दूर क्यों जा रहे हैं?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं। माननीय सदस्य पहले सुनें, वह जो पत्र आया जिसमें संयुक्त रूप से जिला के पुलिस अधीक्षक, जिला के कलेक्टर और जिला के शिक्षा अधिकारी का जो पत्र आया, वह माध्यमिक शिक्षा मंडल में दिनांक 09.02.2026 को पहुंचा। उस समय लगभग परीक्षा की, जो नये वित्तीय वर्ष की परीक्षा की लगभग तैयारी हो गयी थी। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, व्हाट्सएप का जमाना है, चिट्ठी पहुंचने में 3 महीने लग रहे हैं। यह कौन सा बयान है? व्हाट्सएप से हो जाता है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- वित्तमंत्री जी, (व्यवधान) फाईल में साईन कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा कहना है, अभी तो वह घोषणा है। खुल ही रहा है, इस साल नहीं खुल पाया है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, एक चिट्ठी पहुंचने में 3 महीने लगते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह सत्ता पक्ष का है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह घोषणा में है। चूंकि आवेदन लेट आया, लेट रहने के कारण इस साल नहीं हो पाया। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में एक ही रहता है। (व्यवधान) दोनों पड़ोसी...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए। श्री अजय जी। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप सभी में खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, क्या चिट्ठी पहुंचने में 3 महीने लगते हैं? 3-3 महीने से नहीं पहुंच पा रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट, भूपेश बघेल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, एक चिट्ठी को पहुंचने में 3 महीने लगते हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कह दिया कि जिला कलेक्टर और एस.पी. के माध्यम से जो अनुशंसा आ रही थी उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ इसके कारण से इस वर्ष जो परीक्षा केंद्र है वह नहीं खुला लेकिन वह प्रावधान में है और वह परीक्षा केंद्र खुलेगा । वह तय हो गया है और उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- ठीक।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, केवल वहां से जो अनुशंसा, स्थल का जो परीक्षण करके आता है, उसके आधार पर इस वर्ष खोलने का था। इस वर्ष नहीं हुआ है लेकिन अगले वर्ष उसमें खुल जाएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, यह सूची है, वर्ष 2025-2026 की जो केंद्र की सूची जारी हुई थी उस सूची में उस केंद्र का नाम है। उसके बाद डी.ओ. के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा...। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- केंद्र सरकार के आदेशों का भी उल्लंघन है। (व्यवधान) अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यहां पर उल्लंघन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, 21 तारीख को यह सूचना चिट्ठी के माध्यम से भी मंडल को आया हुआ है। (व्यवधान) समय पर सूचना आने के बावजूद उस केंद्र को जानबूझकर रोका गया है, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं । इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का यहां पर उल्लंघन हो रहा है। कार्रवाई की जाये। (व्यवधान)

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी घोषित करें कि यह केंद्र चालू होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल ही रहा हूं कि केंद्र चालू होगा। मैं यह बोल रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप हम लोग उस तैयारी में थे ही और सूची में ही चस्पा हुआ लेकिन जो वहां से चूंकि जब नया केंद्र खुलता है। एक-बार जब कोई केंद्र संदिग्ध हो गया, कोई घटना हो गयी तो उसमें अनिवार्य रहता है कि संबंधित जिला के कलेक्टर और संबंधित पुलिस अधीक्षक का अभिमत अनिवार्य है, जब उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी। मेरा ऐसा कहना है कि वह लेट आया। लेट आने के कारण वह इस साल चालू नहीं हुआ। वह अगले साल से प्रारंभ हो जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले मेरे प्वाईंट ऑफ ऑर्डर को सुन लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- हां ठीक है। आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने ध्यानाकर्षण स्वीकृत किया और ध्यानाकर्षण में शुरूआत के तीन नाम प्रिंट हैं। मैं दूसरे नंबर का प्रश्नकर्त्ता हूँ यहां आखिर क्या चल रहा है, यहां पर कौन प्रश्न पूछ रहा है, वह किस क्रम में प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा, उसकी कोई प्रकि्रया निर्धारित है या नहीं है? पहले आप इसमें व्यवस्था दे दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- इस सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले आप इसमें एक व्यवस्था दे दीजिए।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण में नाम के अनुसार होना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार प्रताड़ित हो रहे हैं। । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण ऐसे नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, विधायक भी पीड़ित हैं।

सभापति महोदय :- जिनका नाम है, उनको ही पहले प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इस ध्यानाकर्षण में नाम है और मैं प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आपका नाम है तो आप प्रश्न पूछिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में कहां से कैसे और किस क्रम में प्रश्न होगा और यह किस क्रम में चलना चाहिए, इसकी व्यवस्था दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चन्द्राकर जी का दोहन करना बंद करिये। इनको व्यवस्था दीजिए।

श्री रिकेश सेन :- इनकी आत्मा मेरे में आ गयी थी। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- यह बिल्कुल सही बात है।(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, एक मिनट।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम पुकार दिया गया है।

श्री उमेश पटेल :- क्या है आज रिकेश सेन का हाव-भाव देखकर, उनको यह लगा कि अजय जी बोल रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- छत्तीसगढ़ में पड़ोसियों के बीच प्रेम रहता है, लेकिन इनके पड़ोसी आपसे इतने क्यों नाराज हैं? यह छत्तीसगढ़ की परम्परा के विपरीत जा रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव:- अगर पड़ोसी नाराज रहता तो अपने विधान सभा क्षेत्र का ध्यानाकर्षण लगाता। पड़ोसी यहां से 700 किलोमीटर दूर रामानुजगंज का ध्यानाकर्षण नहीं लगाता ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय यादव जी, हम लोग तो आपसे दो किलोमीटर दूर रहते हैं। आपके पहले टेबल वाले आजू-बाजू रहते हैं वह फिर भी दूर हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो ध्यानाकर्षण की प्रकि्रया है उसके तहत ध्यानाकर्षण चलना चाहिए। चाहे कहीं से भी लगे और माननीय 90 सदस्य कहीं से भी ध्यानाकर्षण लगा सकते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि मुझे भी 5-6 महीने थोड़े समय के लिए स्कूल शिक्षा में काम करने का अवसर मिला था जो निरस्त करने कारण बताये गये हैं। मैं आपको एक घटना बता देता हूँ पोरा बाई का एक प्रकरण हुआ था, वह मेरिट लिस्ट में थी उसके बाद कुछ शंका हुई तो उसको मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया, उसमें जांच की गई। इसी तरह से एक त्रुटि पायी गयी कि इसमें जो लिखा गया है, वह अलग-अलग लिखावट पायी गयी है और अलग-अलग जानकारी दी गयी है। लेकिन उस समय हमने उस परीक्षा केन्द्र को निरस्त नहीं किया था। उस घटना की जांच करके, हमने मेरिट लिस्ट को निरस्त किया और उसमें जो लोग दोषी और संलिप्त पाये गये, पहले वह दोष मुक्त हो गयी थी। अभी एक महीने पहले उसमें निर्णय आया कि वह लड़की दोषी पायी गयी । मैं यह घटना इसलिए बता रहा हूँ दूसरी बात यह है कि एस.पी. या कलेक्टर डी.ओ. की अनुशंसा, इसमें जनप्रतिनिधि की कहीं पर कोई भूमिका नहीं है। एस.पी. जो हम अनुमोदित करके देंगे, वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। यह मेंडेटरी कहीं नहीं है कि एस.पी. अनुमोदित करेगा, उसके बाद परीक्षा केन्द्र स्वीकृत होगा, यह बहुत स्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो-जो कारण बताये गये हैं, वह इसमें पर्याप्त नहीं दिखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप मुझे बताईये कि इसके मापदण्ड क्या-क्या हैं? मैं प्रकि्रया की बात नहीं कर रह हूँ। एस.पी., कलेक्टर के बाद मापदण्ड का मतलब यह है कि उसकी दूरी कितनी है? दर्ज संख्या कितनी है? वहां सुविधा कितनी है? यह जो रामचन्द्रपुर किन कारणों से उल्लेखित है, उसको निरस्त किया गया, उसका कारण बता दिया गया और जब सारी प्रकि्रया हो गई तो इस सत्र में शुरू नहीं करने के कारण क्या हैं? मैं प्रक्रिया में नहीं उलझाना चाहता हूँ और इसके मापदण्ड क्या हैं, आप मुझको यह बता दें। अभी तक उसको सूची में शामिल नहीं करने के कारण क्या हैं, जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसको कर दिया जायेगा तो इस सत्र में होगा या नहीं होगा? आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मापदण्ड के बारे में पूछा तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री परीक्षा हेतु निर्धारित मापदण्ड जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव एवं संस्था से परीक्षा केन्द्र की दूरी सामान्य क्षेत्र हेतु 5 किलोमीटर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हेतु 15 किलोमीटर, बैठक की क्षमता, फर्नीचर व्यवस्था, प्रकश, पेयजल, प्रसाधन की व्यवस्था, भवन जर्जर न हो, ऐसी स्थिति शासकीय भवन को प्राथमिकता आदि के आधार पर परीक्षा केन्द्र का निर्धारण किया जाता है।

समय :- 12:50 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, क्या ब्यूरोक्रेसी तय करेंगे ? वही तय करेंगे, हम नहीं जानते कि हमारे क्षेत्र में कौन सी दूरी कितनी है, हमारे स्कूलों में क्या-क्या सुविधा है? पहले तो आपको सदन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का उल्लेख करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने सारी औपचारिकता पूरी कर ली है तो इस सत्र में खुलेगा या नहीं खुलेगा, एक लाईन में आप बताईए, प्रक्रिया को छोड़िए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, इस सत्र अभी नहीं खुल पाएगा क्योंकि अभी 10 वीं, 12वीं की परीक्षा चल रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसकी मांग आई है। इसके पीछे के कारण को या तो आप यह बताईए कि इस सत्र में खुलेगा या नहीं खुलेगा?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, अभी तो नहीं खुल पाएगा, अभी एग्जाम चल रहे हैं। अभी संभव नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, माननीय मंत्री जी, इस सत्र में परीक्षा चल रही है तो 2026-27 के सत्र में खुलेगा या नहीं?

श्री गजेन्द्र यादव :- वह खुलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्पष्ट बोलिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, सदन के सामने बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मुख्यमंत्री जी की बातों को इंटरप्रेट गलत किया गया। जो आप मुख्यमंत्री जी की बात का हवाला दे रहे थे। आप मुख्यमंत्री जी की बातों का रिकॉर्ड निकलवाकर देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। इसलिए यदि आपको खोलना है तो स्पष्ट बोलए कि इस सत्र से खुलेगा, यह स्पष्ट खुलेगा।

श्री रिकेश सेन :- मुझे बोलने दीजिए, मैं तीन साल से चुप हूं।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, आगामी नये शिक्षा सत्र में वहां परीक्षा केन्द्र खुलेगा।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को नजरअंदाज किया गया है तो हम कैसे मान लें, अभी कैसे मान लें? अधिकारी फिर आपको गुमराह करेंगे। सभापति जी, इसको आप बताईए। (व्यवधान) वहां तीन एग्जाम हुए, बाकी का क्या होगा?

सभापति महोदय :- आप सुनिए तो। रिकेश जी, पहले आप बैठिए।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, आप नीचे रहते हो तो बोलते हैं कि मैं बोलने का मौका दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बोलना है। ध्यानाकर्षण प्रस्तुत हुआ । मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको मौका मिला, आपने प्रश्न कर लिया । मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया। प्रबोध मिंज जी ने पूछा, मंत्री जी ने जवाब दिया। अजय चन्द्राकर जी पूछ रहे हैं तो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अब आप फिर उठकर खड़े होकर पूछेंगे तो ऐसा ध्यानाकर्षण कभी नहीं हुआ है, जैसा आप चाह रहे हैं ।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, अगर मंत्री जी की बातों से संतुष्ट नहीं होंगे।

सभापति महोदय :- संतुष्ट नहीं हैं तो आपको आगे जो करना है, वह करिए, लेकिन मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए बोल दूंगा। मंत्री जी, एक बार फाईनल बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने व्यवस्था का प्रश्न इसीलिए किया, आपने उसको स्पष्ट किया कि ध्यानाकर्षण क्रम से ही चलता है।

सभापति महोदय :- मैंने क्रम बताया, आपका नाम पहले था, लेकिन आपको आखिरी में पूछने का मौका मिला, लेकिन अब मैं मंत्री जी से एक बार निवेदन करूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उन्होंने अभी व्यवस्था मांगी, तब हुआ है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न ।

श्री कवासी लखमा :- चन्द्राकर जी का नाम दूसरे नम्बर पर था, उनको बाद में पूछने का मौका दिया तो यह ठीक नहीं है। यह अपमान नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है।

सभापति महोदय :- यह नहीं होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, अभी आपको बोलना मना है और आप बाहर में बोलना, मैं उसको लिखते जाऊंगा । हम उसका किताब छपवाएंगे।

श्री कवासी लखमा :- बाहर मत बोलना, मैं अंदर में बोलूंगा।

सभापति महोदय :- आप ध्यानाकर्षण में एक बार बता दीजिए कि परीक्षा केन्द्र की वस्तुस्थिति क्या है, इस साल खुलेगा या अगले साल खुलेगा? जो है, एक बार बताईए। ध्यानाकर्षण इतना लंबा नहीं चल सकता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा खड़े होने पर)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए न, काहे को मजा लूट रहे हैं। (हंसी)

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, आगामी सत्र 2026-27 के वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के केन्द्र के लिए उस स्कूल को खोला जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- अब हो गया।

श्री विक्रम मण्डावी :- अजय जी, अब आप संतुष्ट हैं न।

समय :12:54 बजे

<u>नियम 267 क के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

(1) श्री सुनील कुमार सोनी
(2) श्री अजय चन्द्राकर
(3) श्री ईश्वर साहू
(4) श्री अटल श्रीवास्तव
(5) श्री कुंवर सिंह निषाद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :12:54 बजे

<u>अनुपस्थिति की अनुज्ञा</u>

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03 , बैकुण्ठपुर के सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03, बैकुण्ठपुर के सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े, द्वारा फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है। उनका आवेदन इस प्रकार है :-

स्वयं के ईलाज हेतु ए.आई.जी हॉस्पिटल हैदराबाद जाने के कारण मैं फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03, बैकुण्ठपुर के सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े को फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2026 से दिनांक 27 फरवरी, 2026 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये?

मैं, समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

(अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।)

समय: 12.55 बजे

<u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>

याचिका समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन

सभापति महोदय, याचिका समिति (श्री अमर अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं याचिका समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 12.56 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री ललित चन्द्राकर
2. श्री धरम लाल कौशिक
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

समय: 12.57 बजे

वक्तव्य

दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या-08 (क्रमांक-54) के उत्तर के सम्बन्ध में

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा पूछे गए अतारांकित संख्या-08 (क्रमांक-54) के उत्तर से संबंधित प्रपत्र 'अ' के स्थान पर पृथकत: वितरित संशोधित प्रपत्र 'अ' पढ़ा जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, यह छोटा सा विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न में भी एक संशोधन दिया है। यह वक्तव्य का विषय नहीं था, यह संशोधन का विषय है। चूंकि इसमें वक्तव्य छपा है, इसलिए मैं बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया दूंगा। सभापति महोदय, विभाग का नाम सुशासन एवं अभिसरण विभाग है। यदि सुशासन एवं अभिसरण हो, विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करके शामिल करके उस पर बेहतर लक्ष्य पाते हैं तथा इसके लिए विभाग बनता है तो यह बहुत स्वागतेय है। आप देखेंगे कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पुराने प्रश्न में कैसे अभिसरण की शुरूआत हो रही है। पूरी विधान सभा में उसमें मेरा यह पहला प्रश्न था। उन्होंने पहले प्रश्न की पहली जानकारी दी है, उसमें 7 बिन्दुओं में जानकारी दी है और 9 बिन्दुओं में जानकारी दी है। उसमें उन्होंने एक बिन्दु को सुधारा है, 2 की जगह 3 कार्यरत है, लिखा है। तो इसकी शुरूआत ही थोड़ी गलत कर रहे हैं। वह विभाग, जिसके ऊपर पूरी मानीटरिंग, अटल पोर्टल, डेश बोर्ड एवं देखरेख की जिम्मेदारी है, वह पहली बार जानकारी दे रहा है तो पहले बार में ही गलती हो रही है, यह एक बात है। यह आगे ना हो। क्योंकि यह महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के माननीय मंत्रियों ने तय करके बनाया है।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि इसका जो उद्देश्य है, प्रदेश स्तर में तो बहुत सक्षम अधिकारी लोग बैठते हैं, आई.ए.एस. का कैडर, आई.एफ.एस. का कैडर, आई.पी.एस. का कैडर है। जिला स्तर में जहां से काम होते हैं, मानीटरिंग करने का, अभिसरण करने तथा बाकी चीजों के निर्णय करने का है, उसकी ट्रेनिंग और उसके ओरियेन्टेशन के जो कार्यक्रम हैं, कार्य की दक्षता है, जो उद्देश्य है, क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं, नीचे में जिले स्तर के लोग हैं, उन पर इनका प्रभाव झलकना चाहिए, इनकी व्यवस्था इस विभाग में होनी चाहिए। क्योंकि हम 2 साल कर चुके हैं। अभी 2 साल में जिला स्तर तक उन कर्मचारियों तक नहीं पहुंचे हैं, जो नीचे मानीटरिंग करते हैं। माननीय मंत्री जी वक्तव्य दिया है इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि इन बातों को ख्याल रखेंगे और माननीय मंत्री जी अभी बोलना चाहे या बाद में जैसा चाहे, जब मुख्यमंत्री जी इस विभाग में बोलेंगे तो इस विषय को शामिल करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>सदन को सूचना</u>

120 पुनर्वासित नक्सलियों द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्यवाही देखने आना

सभापति महोदय :- आज ऐतिहासिक दिन है। दशकों तक माओवादी संगठन से जुड़कर जंगलों में रहे, परन्तु केन्द्र सरकार, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की विशेष रणनीति से तथा छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल मार्गदर्शन में 120 पुनर्वासित नक्सली आज लोकतन्त्र से जुड़ने छत्तीसगढ़ विधान सभा देखने आए हैं। इन 120 लोगों में नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व से

गांव तक इन संगठनों में काम करने वाले 54 महिलाएं और 66 पुरूष हैं। भारत के संविधान को मानते हुए पुन: मुख्य धारा से जुड़ने वालों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट)

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, वस्तुतः इस ऐतिहासिक क्षण को मैं थोड़ा और स्पष्ट सदन के समक्ष आपकी अनुमति से करना चाहता हूं। बड़े ही प्रसन्नता का, हर्ष का विषय है और यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। भारत के संविधान को न मानते हुए दशकों तक माओवादी संगठनों से जुड़कर जंगलों में रहने के बाद केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी के कुशल रणनीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के माध्यम से आज जो ऐतिहासिक दिन आपने कहा..।

सभापति महोदय :- आपके भी कुशल मार्गदर्शन में।

श्री विजय शर्मा :- वह इतना महत्वपूर्ण है आज का दिन कि वह पूरा तंत्र एक साथ आज 120 लोग जो ऊपर भी हमारे साथ यहां बैठे हुए हैं और कुछ लोग अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसमें नक्सल कैडर के टॉप मोस्ट जो लोग थे, वहां से लेकर नीचे तक, ये सारे ही श्रेणियों के लोग हैं और वे सारे लोग यहां पर आज लोकतंत्र से जुड़ने के लिए, भारत के संविधान को स्वीकार करते हुए, भारत के संविधान से जुड़ने के लिए, हम सबसे जुड़ने के लिए यहां एक साथ उपस्थित हुए हैं। कल जब इनका आना हुआ था, माननीय सभापति महोदय, परसों ही आए थे तो कल इन्होंने आदिवासी संग्रहालय भी देखा, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित था। उसको भी देखा, सबको बहुत रोमांच हुआ, सबको बहुत संतुष्टि हुई। आज यहां लोकतंत्र के इस मंदिर में और सदन की इस कार्यवाही को देखते हुए लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ता है, उस गणतंत्र को छोड़कर जनतंत्र में आकर मिले हैं, यह बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा दिन है। माननीय सभापति महोदय, आपने अवसर दिया, आपने सबको शुभकामनाएँ दीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

समय : 1.04 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)</u>

सभापति महोदय :- आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का दूसरा दिन है। कल कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आय-व्ययक पर अपने विचार पर्याप्त रूप से रखे गए हैं। मेरे समक्ष आज की शेष चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुत लंबी सूची रखी गई है। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के उपरांत अशासकीय कार्य को भी लिया जाना है। आज अशासकीय कार्य का दिन है। अतः सभी माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में अपने विचार 10-10 मिनट में ही रखने का कष्ट करेंगे। कृपया समस्त सदस्य समय सीमा का जरूर ध्यान रखेंगे। सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए श्री उमेश पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वे आज की चर्चा की शुरुआत करें।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, जो सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2026-27 में 7,09,553 का अनुमान हमने रखा है, सर्वप्रथम मैं अपनी बात वर्ष 2024-25 को जो अनुमान प्रस्तुत किया गया था और वास्तविक जो बजट ऑडिटेड हुआ है, उसके बीच में जो अंतर मुझे दिख रहा है पहले उसी पर चर्चा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य जो हमने रखा था, वह 125 करोड़ 900 का था, जो अब 1,20,290 की हमें प्राप्ति हुई है। इसमें स्वयं का राजस्व 49,700 हमने अनुमानित किया था, जो 44,765 है, जो लगभग 10% इसमें प्राप्तियां कम हैं। गैर-कर राजस्व, जिसमें 18,700 का अनुमानित था जो अब 17,421 जो 7% की कमी है। केंद्रीय करों का हिस्सा 44,000 अनुमानित था, जो 43,800 लगभग थोड़ा सा ही कम है। केंद्र से सहायता अनुदान जो है...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>सदन को सूचना</u>

भोजन अवकाश का स्थगन

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सभा इस पर सहमत हैं।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

भोजन की व्यवस्था माननीय श्री रामविचार नेताम जी, कृषि मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)</u>

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, हमने केन्द्र से सहायता अनुदान 13,500 करोड़ का अनुमान लगाया था।

सभापति महोदय :- रामविचार जी, भोजन आपकी तरफ से है। आप निरीक्षण भी करके आ जाईये। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आदिवासी भोजन घलो हावय?

सभापति महोदय :- नई हे।

श्री बघेल लखेश्वर :- आदिवासी भोजन, मछलीपालन, बकरीपालन, सभी का पालन है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सूअरपालन भी है।

श्री रामविचार नेतामा :- जितने जीव-जन्तु हैं, वह सभी हैं। सभी का सेवन कराया जायेगा।

सभापति महोदय :- पालने से क्या फायदा, क्योंकि यहां तो कुछ आना नहीं है? चलिये, उमेश जी, अब आप बढ़िया बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने केंद्र से जो सहायता अनुदान 13,500 करोड़ अनुमानित किया था, जिसमें 6% वृद्धि होकर 14,261 करोड़ के आसपास हुआ है। गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति 150 करोड़ का अनुमान था, वह 28 करोड़ है, जोकि लगभग 81% की कमी है। हमारी जो ऋण (debt) हैं, जिसका हमने 29,110 करोड़ का अनुमान लगाया था,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह बढ़कर 33,463 करोड़ है, जिसमें लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर जो प्राप्तियाँ अनुमानित थी, उसमें 5% की कमी आई है। अगर मैं इसमें नीचे जाऊँ तो भू-राजस्व से हमें जो प्राप्तियाँ होनी थीं, वह अनुमानित 12,000 करोड़ का था, जो हमें लगभग 819 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई हैं। उसमें 32% की कमी आई है। सेल्स टैक्स (VAT) में हम लोग लगभग 9,960 करोड़ अनुमान किए थे, जिसमें हमें 6,880 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई हैं, जिसमें 31% की कमी आई है। राज्य उत्पाद शुल्क में हमने 11,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, वह 10,142 करोड़ है। उसमें 8% की कमी आई है। राज्य का GST पर हमने 17,446 करोड़ का अनुमान लगाया था, उसमें हमें 16,299 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई हैं। इसमें 7% की कमी आई है। बिजली में लगभग 1% की वृद्धि हुई है। उसमें हमने 5,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, जिसमें हमको 5,063 करोड़ मिला है। वाहन कर में भी लगभग 5% की वृद्धि हुई है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 6% की वृद्धि हुई है। इन अनुमानों में और वास्तविक आंकड़े में अंतर है। उसमें हमें लगभग 5% की कमी देखने को मिली है। अब अगर यह 5% की कमी को मैं व्यय के हिसाब से देखूँ, जो हमने व्यय में अनुमान लगाया था, यह तो प्राप्तियाँ हो गईं। अब व्यय में कहीं ना कहीं कमी हुई होगी, क्योंकि हमें प्राप्तियाँ कम हुईं तो व्यय भी कहीं कम होगा। इसलिए हमने राजस्व व्यय 1,24,840 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया था, वह बढ़कर 1,25,390 करोड़ रूपये राजस्व व्यय है। मतलब जो 5% की कमी है, वह यहाँ परिलक्षित नहीं हो रही है। अब जो ऋण और अग्रिम है, हमने उसका 322 करोड़ का अनुमान लगाया था, उसमें भी वृद्धि हुई है। ऋण का जो पुनर्भुगतान है, वह भी 9,360 करोड़ से बढ़कर 10,871 करोड़ हो चुका है। मतलब यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। कहाँ पर कमी आई है? पूँजीगत परिव्यय में कमी आई है। हमने उसका 22,300 करोड़ का अनुमान लगाया था और 20,055 करोड़ परिव्यय हुआ है। उसमें 10% की कमी आई है। अगर हम लोग वर्ष 2047 के विज़न पर जा रहे हैं। सभापति महोदय, इतना बताने का मेरा मेन लक्ष्य यह था कि सरकार ने कहाँ कमी की है? सरकार ने राजस्व व्यय में कहीं कमी नहीं की है। ऋण पुनर्भुगतान तो हम लोग कम कर ही नहीं सकते, वह तो करना ही है। सरकार और कहीं पर भी कमी नहीं की है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो व्यय है, उसमें हमने लगभग 10% की कमी की है। अगर हम वर्ष 2047 का अनुमान लगा रहे हैं कि वर्ष 2047 में हमारा देश विकसित राज्य बनेगा और जो हमारा टारगेट है कि हम हर साल 12% की वृद्धि देखेंगे और 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी तब जाकर हम इस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इकॉनामिक कंडीशन पर पहुंचेंगे, लेकिन बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्च किये क्या यह पॉसिबल है । सभापति महोदय, मेरे हिसाब से बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्च किये हुये ये पॉसिबल ही नहीं है । हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यय करने की आवश्यकता है । ठीक है, सरकार की बहुत सारी योजनायें चल रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसको भी कर रहे हैं, लेकिन जो 10 परशेंट की कमी का अनुमान है, हमारा 2047 विजन से कहीं पर भी नहीं हो रहा है । सभापति महोदय, मैं अलग-अलग विभागों के बारे में भी जानने की कोशिश किया कि कहां कितनी कमी हुई है, उर्जा क्षेत्र के व्यय में 37 परशेंट की बढ़ोतरी हुई है, कृषि में भी लगभग 15 परशेंट की बढ़ोतरी हुई है, परिवहन में भी लगभग 3 परशेंट की वृद्धि हुई है, पुलिस में 9 परशेंट की कमी हुई जो हमारा अनुमान था, सिंचाई में भी 10 परशेंट की कमी हुई है, आवास में भी 10 परशेंट की कमी हुई है, शिक्षा, खेल और कला संस्कृति में 14 परशेंट की कमी हुई है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 14 परशेंट की कमी हुई है, इस तरह से अन्य विभागों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी लगभग 50-55 प्रतिशत की कमी की गई है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और जो हमारी आय में कमी हुई है वह परिलक्षित हो रहा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, पिछली सरकार वाला डाटा पढ़ रहे हैं क्या?

श्री उमेश पटेल :- स्वास्थ्य मंत्री जी, अभी आपके विभाग में आया नहीं हूँ, आपके मंत्री जी ने जो कागज दिया हूँ ना, उसी से निकाला हूँ, कोई अलग से नहीं किया हूँ।

सभापति महोदय :- आप बोलिये, आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिये। आप बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- जी । सभापति महोदय, अभी के बजट पर बात करेंगे तो वह अनुमान है। यह वर्ष 2024-2025 का आडिटेड है, मैं इसी डेटा पर बात कर रहा था । इस साल का जो संशोधित अनुमान है, उसमें दिसम्बर तक का डाटा है, उसके आधार पर मार्च तक का डाटा संशोधित अनुमान में जो आया है, हमने पिछले मार्च में बजट किया था। वह अनुमान लगाया था कि जो हमारा कुल व्यय होगा, वह 1,76,327 और अभी जो संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया है, वह 1,64,337 है। इसमें बदलाव हो सकता है, आपने जो संशोधित अनुमान दिया है, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। ऋण का भुगतान शेम है, 11337 और कुल प्राप्तियां का जो

हमने अनुमान लगाया था, वह 1,75,437 है और अभी संशोधित अनुमान लगाया गया है, वह 1,66,000 है । सभापति महोदय, हमने उधारी का जो अनुमान लगाया था, आप इस पाईन्ट को देखियेगा, वर्ष 2024-वर्ष 2025 की उधारियॉ और इस समय की जो उधारियां जो हमारा अनुमानित है, वह 34,337 जो अब बढ़कर संशोधित अनुमान में 36,737 होगा । इसमें लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार की हमारी एक योजना थी जो एचसीए है, उस पर हम लोगों का अनुमान लगभग 4000 करोड़ का था और हमें 8000 करोड़ प्राप्त हुआ है या उधारी ले लिये हैं । इस तरह से हमारी शुद्ध प्राप्तियां रिवाईज बन रही है, वह 1,41,000 करोड़ थी, वह लगभग 1,29,00 यानी 8 परशेंट कमी आ गई । सभापति महोदय, हम लोगों ने पहले अनुमान लगाया था कि हमारा राजकोषीय घाटा 3.8 होगा वह अब 4.2 होने वाला है और वर्ष 2024-2025 की प्राप्तियां जो कम हुई थी, इस साल भी हमारी प्राप्तियां कम हो रही है। सभापति महोदय, मुझे सबसे ज्यादा जो हिट किया कि इस साल राजस्व व्यय जो हमने अनुमान लगाया था वह 1,38,000 और जो बढ़कर संशोधित अनुमान में 1,39,000 हुआ है। सभापति महोदय, पूँजीगत परिव्यय जो आऊटले है वह 36334 का हमारा अनुमान है...। सभापति महोदय, पूंजीगत परिव्यय जो है, वह हमारा 26,334 का अनुमान था, वह कम होकर 16,300 संशोधित अनुमान है, लगभग 38% की कमी है। पिछली बार लगभग 10% की कमी हुई और अभी जो संशोधित अनुमान है उसमें 38% की कमी बता रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए 2047 की तरफ जाने के बजाय पीछे हटते जा रहे हैं। ।

श्री रामकुमार यादव :- जायसवाल सर, सुनिए न, सुन डालेव ना कहां जावत हन तेला। जे उधारी ल हमन 5 साल में लेन तेला तुमन 2 साल में ले डालेव। ई होथे, डबल इंजन के सरकार, सुन लो ओदे।

श्री अमर अग्रवाल :- पांच साल में कितना उधारी लिए थे पहले वह बताईए।

श्री उमेश पटेल :- लगभग 50 हजार करोड़।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, उनको बताने दीजिए न। उन्होंने कहा है, कितना उधारी लिए थे पहले वह बताईए।

श्री रामकुमार यादव :- जतना कन तुमन ले हव उतना नई ले हन। दो साल में डबल इंजन ला ठग के ले डालेव।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमर अग्रवाल :- आप जो बात बोल रहे हो तो आप बताईए न।

श्री उमेश पटेल :- अमर भैया, अब छोड़िए न।

श्री रामकुमार यादव :- ठीक है, मैं जान डालेव अमर अग्रवाल जी ला। ओ पढ़े-लिखे हे, ओ पढ़े हे ता मैं गढ़े हंव। छत्तीसगढ़ के जनता हब तुंहर गणित ला जान डालिस। ओ पढ़े लिखे आंकड़ा से तुमन छत्तीसगढ़ ला ठग नई डालव।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी, वित्त विभाग की चर्चा है, पशुपालन वगैरह में ध्यान दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, पशुपालन में ही दुनिया के आर्थिक व्यवस्था टीके हे। एक बात याद रखिया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- रामकुमार जी, माननीय अमर भैया पूछ रहे थे कि उधारी कितना लिए तो इनको तो उधारी से कोई मतलब नहीं है, ये तो नगद-नगद वाले हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- उमेश जी आप बढ़िया बोल रहे हैं, चलिए।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- ये कर्जा की जानकारी तो आज लखमा जी देंगे। देख लीजिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी की जगह में बैठे हैं। ताली बजाईए। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, 26,341 के अनुमान के से अलग 16,300 जो 38% कम है, ये चिंताजनक स्थिति है, हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जा रहे हैं। राजस्व व्यय में फिर से 1% की वृद्धि और आउट-ले में सीधा 38% की कमी है। इस 16,000 में तो हमारा सौभाग्य है कि 8,000 करोड़ केंद्र से आ गया है, नहीं तो हमारा जो राज्य का राजस्व है उसमें से सिर्फ 8,000 करोड़ लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ 8,000 करोड़ लग रहा है । हम लोग कहां किस स्थिति में जा रहे हैं? अगर इस तरह का बजट हमारा आने वाले समय में भी होने जा रहा है तो मैं तो ये कहूंगा हम लोग 2015 से लेकर अब तक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले में कमी करते जा रहे हैं। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकार उसमें इंक्लूडेड हैं। 2015 से लेकर अब तक हर साल कुछ न कुछ परसेंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कम खर्चा करते जा रहे हैं । इसे हमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बढ़ाने की जरूरत है। अगर पूंजीगत व्यय नहीं बढ़ेगा तो इस छत्तीसगढ़ का भला नहीं होने वाला है। बाकी अनुमान इस साल का जो भी है वह ठीक है। सभापति महोदय, हमारे नेता जी ने किसानों से रिलेटेड स्थगन प्रस्ताव लाया था। इस छत्तीसगढ़ विधान सभा में आप इसका अगर रंग-रूप को देखेंगे, जिस दिन इसका उद्घाटन था, डॉ. रमन सिंह जी अपने भाषण में बता रहे थे कि हमारे ऊपर में जो धान के पत्तियों, बालियों का आकार बना है, आप जहां बैठे हैं वहां धान की बाली वाली चित्र बनी है। ऊपर में पत्ते लगे हुए हैं। ये दर्शाने के लिए है कि हम लोग इस सदन में बैठकर सरकार जो भी रहे, विपक्ष जो भी रहे, किसानों की चिंता करते हैं। लेकिन क्या हमने इस सत्र में किसानों की चिंता की है? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव लाया नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। आसंदी को बताए या पूछे बिना वह पहले ही अपना फैसला सुना दे रहे हैं। हमने नयी विधानसभा में ये सब चीजें इसीलिए लगायी हैं ताकि हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की चर्चा होगी, जब जरूरत पड़ेगी, तब होगी। लेकिन वह चर्चा है ही नहीं। सभापति महोदय, चर्चा तो छोड़िए। कबीरधाम, कवर्धा, महासमुंद, जांजगीर-चांपा वे जिले हैं, जिनमें यह कहा गया कि चूहे और कीड़े धान को खा गए। उसमें सक्ती जिला भी शामिल है।

श्री लखेश्वर बघेल :- इसीलिए तो वह चर्चा नहीं कराना चाहते हैं।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, क्या आप मुसवा को पाए? मुसवा कहां है? हम लोग तो खोज-खोज कर थक गए कि 26,000 क्विंटल धान खाने वाला चूहा कितना बड़ा होगा? बाप रे!

श्री अटल श्रीवास्तव :- उसको आप पाकिस्तान भेज दो। वह वहीं खाएगा।

श्री उमेश पटेल :- हां, वहीं खाएगा।

श्री लखेश्वर बघेल :- धान का फोकला नहीं मिला।

श्री उमेश पटेल :- महासमुंद में 18,433 क्विंटल धान है। वह करोड़ों का धान है। इसी तरह से कवर्धा के चारभाठा में लगभग 7 करोड़ रूपये का धान है। यही कारण है कि यह चर्चा नहीं कराना चाहते हैं कि वह मुसवा कौन है, शायद यह पता चल जाए। वह कहां से आया, कितना बड़ा है और कब तक रहेगा?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- खाद्य मंत्री ओला खोजत हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- खाद्य मंत्री जी तो मुझे सत्र में दिख ही नहीं रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- वह गुजरात गये हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- दंतेवाड़ा में 18 करोड़ रूपये का धान है।

श्री उमेश पटेल :- दंतेवाड़ा में 18 करोड़ रूपये का धान है। सभापति महोदय, ये सारी बातें निकलती हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मुसवा के डर मा ओ खुद लुका गे हे। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मुसवा की बात हो गई। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम लॉ एंड ऑर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर से महत्वपूर्ण विषय सरकार के पास नहीं होना चाहिए और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सुरक्षा की होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग यहां मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? गृह मंत्री जी के कवर्धा जिले में कितनी सारी घटनाएं हुई हैं। सीरीज ऑफ घटनाएं हुई हैं। जो संरक्षित आदिवासी परिवार हैं, उसके पूरे परिवार को जला दिया गया। एक यादव का गला रेत दिया गया। एस.पी. ऑफिस के सामने मां-बच्ची थी, लेकिन उन दोनों मां-बच्ची का एकसाथ मर्डर हो गया। कवर्धा में तो लिस्ट रखा हुआ है, फिर हमने इस प्रदेश में वे चीजें भी देखी हैं कि एक एडिशनल एस.पी. को, मेरे ख्याल से बलरामपुर है। मैं उसकी जगह भूल रहा हूं, लेकिन एडिशनल एस.पी. को महिलाएं पीट रही हैं। यह स्थिति है। मैंने एक एस.डी.एम. का वीडियो देखा, वह भाग रहा है और पब्लिक उसको पीछे-पीछे दौड़ा रही है। मंत्री जी, मेरे ख्याल से वह आपका ही बलरामपुर जिला है। यह परिस्थिति देखने को मिल रही है। तमनार में एस.पी., कलेक्टर व पुलिस के साथ जिस तरह से हिंसा या बर्बरता हुई, उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। उसकी निंदा होनी चाहिए। एस.पी. और कलेक्टर की उस दिन वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। हम यह परिस्थिति बना रहे हैं। बलौदाबाजार की घटना हुई। यह तो ठीक है, लेकिन एक घटना अभी देखने को मिली कि एस.डी.एम. के द्वारा हमारे एक बेचारे आदिवासी का मर्डर कर दिया गया। सतनामी समाज के लड़कों को तो जेल में डाल दिया गया, आदिवासी आदमी को जान से मार दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की यह स्थिति है। इस सरकार का यह मुख्य काम है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 1.26 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आलोचना तो हम लोग करते रहेंगे, हमारा काम है, बिल्कुल करेंगे और हम आपको सारी चीजों को आइने के रूप में बतायेंगे। क्योंकि विपक्ष की भूमिका हमको दी है और विपक्ष की भूमिका हम लोग निभायेंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में बस्तर ओलंपिक की बात आई। हम लोग इसी सत्र में थे, जब हम लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक कराये तो इनके लोग यह कह रहे थे कि यह आप लोग क्या करा हो, क्यों करा रहे हो, किसलिये करा रहे हो, उसका हम विरोध करते हैं। इसमें पैसे का खर्च हो रहा है, आप कोई बजट ऐलोकेट नहीं कर रहे हैं। अब वही चीज सरगुजा ओलंपिक भी आप लोग करने वाले हैं। आपको उसके लिये बधाई हो। लेकिन आप लोगों के व्यवहार में इधर-उधर में अंतर नहीं रहना चाहिए। अगर किसी चीज का विरोध करते हैं तो विरोध करते हैं, फिर डंके की चोट पर रखिये।

श्री रामकुमार यादव :- सबले ज्यादा धरमलाल कौशिक जी और मोहले ली करे रहिस हे अउ आगू में बैठे हे।

श्री लखेश्वर बघेल :- आपकी पार्टी करे तो वाह-वाह, विपक्ष करे तो?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अमर भैया मंत्री होते तो हम लोग भी बिलासपुर ओलंपिक कराते।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा सदन में की थी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी तात्कालिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि हम लोग 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, कितना समय हो गया? उस घोषणा को 2 साल होने वाला है। अभी आपने 5,000 शिक्षकों के भर्ती की घोषणा की है। 33,000 से 5,000 में आ गये, वह भी अभी शुरू नहीं हुआ है।

कृषि विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आप चिंता मत करिये। जितने कमिटमेंट हैं, एक-एक करके हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग अगर एक बार में पूरा कर लेंगे तो आप लोगों के पास बोलने के लिये क्या रहेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी कब करेंगे? घोड़ा के सींग जाम जाही तब करेंगे क्या?

श्री रामविचार नेताम :- आप लोग बोलते रहिये, लेकिन पूरा करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- कब करेंगे?

श्री रामविचार नेताम :- आप लोग 2047 तक इंतजार करते रहिये और उधर से ही आवाज उठाते रहिये। इधर का सपना देखना बंद करिये।

श्री रामकुमार यादव :- 2047 मतलब, 22 साल, जो करने घोषणा वाला हे, तुमन 100 साल जीया।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका 2047 वाला विषय मंत्री जी बोल दिये। उमेश जी, आप जारी करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :-आप मानसिक रूप से तैयार रहिये, तीन साल बाद आप पहली लाईन में रहेंगे।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए। उमेश जी बोल रहे हैं, वह पहले वक्ता हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, अभी 5,000 पर आ गये हैं, पता नहीं वह भी कब तक करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, अभी इन्होंने लैब टेक्नीशियन के लिये आउटसोर्सिंग की घोषणा की है। माननीय मंत्री जी, आपने किया है न? आपके जितने लैब टेक्नीशियन हैं, उसको आप लोग कोई कंपनी को देंगे, वह सीधा आकर काम करेगा। सारी टेस्टिंग वही करेगा।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- उसमें दिक्कत क्या है, वह तो बहुत बढ़िया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है, उसको बता रहा हूं। इनका कहना है कि हमको 230 करोड़ रुपये लगेगा। उसको आउटसोर्सिंग करेंगे और वह आकर टेस्टिंग करेगा, उसमें 230 करोड़ रुपये लगेगा। अभी उनको 300 करोड़ रुपये लग रहा है। आपका यही अनुमान है। नहीं है तो सही कर दीजिए या तो फिर मेरी बात

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

मान लीजिए। अभी के सेटअप में 300 करोड़ रुपये लगता है और जब आउटसोर्सिंग करेंगे तो 230 करोड़ रुपये लगेगा या 250 करोड़ रुपये लगता था, 20 करोड़ रुपये बचा लेंगे। सभापति महोदय, अब आप मेरे को यह बता दीजिए कि इनका टेस्टिंग का जितना टारगेट है, अभी के सेटअप में वह पूरा नहीं होता है और पूरा नहीं होने के बावजूद उसमें 250 करोड़ रुपये लगता है। आउटसोर्सिंग करेंगे और उसको 230 करोड़ रुपये में करायेंगे, फोर्स करेंगे तो वह आदमी तो फर्जी काम करेगा ही।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ओमन के चाल चा देखव, वो दोनों कांग्रेसिया मंत्री मन ला छोड़ के ओमन भाग गये हे। तुमन अपने आदमी ला कहत रहा, कह करके देख सकथव। ओमा कतके बड़े षडयंत्र है, तुमन ऐती आ जाव, ओती मत रहव।

सभापति महोदय :- बैठे हैं, 3 मंत्री जी बैठे हैं, सुन रहे हैं।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- अब ऐसा है रामकुमार, दुई-तीन झन भारी हें । ओ दे आ गिस हे, देख-देख।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वह तो भारी हे, भईया। बाकी दुनों के ला कर।

सभापति महोदय :- बैठिए। उमेश जी।

श्री उमेश पटेल :- जी । माननीय सभापति महोदय, आप अगर उस टेस्ट को 220 करोड़ में फोर्स करेंगे तो कैसा अनुमान लगाया है वह मेरी समझ से तो परे है लेकिन 230 करोड़ में आऊटसोर्सिंग करके उसी सारे टेस्टों को, टारगेट को पूरा करने का काम यह लोग करेंगे तो वह जो कंपनी है, आप इसको इंस्योर कैसे करेंगे कि वह फर्जी काम नहीं कर रहा है । वह तो गांव-गांव में टेस्टिंग की लिस्ट बनायेगा और टेस्ट पूरा कर दिया करके बोलेगा।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- चलिये, मेरी डिमांड मांग में जवाब दे दूंगा। समय खराब नहीं करूंगा।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल । माननीय सभापति महोदय, तो यह आने वाली समस्याएं हैं। सबसे पहले तो इन्होंने युवाओं को तो ठगा ही ठगा । (माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर जी के सदन से बाहर जाने पर) लेकिन यहां अजय चंद्राकर जी बैठे थे, वह चले गये क्या?

श्री रामकुमार यादव :- वह कहां जायेंगे, वह पूरा घोलकर खाकर जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने हमारे कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी । यह लोग विरोध करने वाले हैं, खासकर पुन्नुलाल मोहले जी । बोले कि 18 लाख लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपकी सरकार ने तो शुरू ही नहीं किया है, बेरोजगारी भत्ता देने का आपके घोषणा-पत्र में है। है ही नहीं, आप कब शुरू करेंगे ? मोहले जी, आपकी आवाज को तो हम लोग सुनते थे, महत्वपूर्ण तरीके से लेते थे, प्राथमिकता में लेते थे लेकिन आपकी सरकार आपकी बातों का ध्यान नहीं रख रही है और पता नहीं वह और कितनी दूरी करते जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कभी इधर, कभी उधर और अब वहां पर रख दिया गया है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आधा घंटे हो गये हैं । थोड़ा संक्षेप में करें ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, बस-बस जल्दी कर रहा हूं । आप बोलेंगे तो आखिरी कर देता हूं।

सभापति महोदय :- आखिरी करिये ।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है। बस, एक आखिरी पाईंट। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने 5 मिशन बनाया है और उसमें से एक मिशन है स्टार्टअप । अमर भैया, मेरे खरसिया के हैं। आपके यहां एक नया स्टार्टअप चालू हुआ है, हमारे यहां। वह है रेत का स्टार्टअप। (वाह-वाह की आवाज) रेत माफियाओं का स्टार्टअप शुरू हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- इन लोग रेत में तेल निकालने वाले हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, रेत की भयावह स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा । यह पत्र की कॉपी है । मैंने यह पत्र दिनांक 24.05.2025 को लिखा । इसमें हमारे यहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है । मेरे विधानसभा में एक धनांगर में और एक देवरी में, देवरी में तो एक आदमी घाट पर बैठा हुआ था । जनरली सुबह और शाम को लोग तफरी के लिये निकल जाते हैं, घाट पर बैठते हैं । मैं आपको बता दूं कि जे.सी.बी. उसके ऊपर में चढ़ गया, रेत में, रेत माफियाओं का । (शेम-शेम की आवाज) और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उस रेत माफियाओं के ऊपर कंट्रोल करने का, किसी अधिकारी का नहीं । आपके अधिकारी ऑफिशियली यह स्टेटमेंट देते हैं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमको ट्रेक्टर को पकड़ने की कोई अनुमति नहीं है और ऊपर से आदेश है कि हम लोग नहीं पकड़ेंगे । चाहे कितना भी निकले, एक-एक दिन में एक-एक घाट से ढ़ाई सौ-ढ़ाई सौ, उस सड़क में चलना मुश्किल हो गया है । मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कलेक्टर को पत्र लिखा । मैं उसी समय जहां यह रेत उत्खनन हो रहा है उसकी फोटो बनाकर कलेक्टर को भेजा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह अवैध।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव जी, आपकी बारी आयेगी न । आप बोलियेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बस, एक मिनट ।

सभापति महोदय :- बहुत सारे वक्ता हैं, इसमें 20 लोगों को बोलना है । अभी उमेश जी पहले वक्ता हैं, वह आधे घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, उमेश भैया जो बोल रहे हैं, वह इतना गंभीर मामला है । दिल्ली के सदन में भी यह उठ चुका है । सत्ताधारी दल के सदस्य के द्वारा ही ।

सभापति महोदय :- आप अपने समय में बोलिएगा, इसमें आपका नाम है । उमेश जी, समाप्त करिये ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह लोग ऐसा बता रहे हैं । इनके समय तो वह जो के.जी.एफ. फिल्म था न, कोलार गोल्ड फील्ड वाला, वह कैसे-कैसे दबता रहा । उस टाईप का पूरे प्रदेश में...। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- दिल्ली में आप ही के सांसद उठाये हैं । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप रायगढ़ जिले की स्थिति को नहीं जानते तो पहले समझ लीजिये कि वहां की क्या स्थिति है । दो लोगों की मौत हो चुकी है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, तब कहां चुप थे जब सेंद्री में कांग्रेस के एक नेता द्वारा अवैध रेत घाट चलाने पर एक परिवार की 3 बच्चियां असामयिक मौत की घाट उतरीं थीं ।

श्री उमेश पटेल :- अब हो गया न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशान्त शुक्ला :- उस समय क्यों चुप थे। इसी बात का तो प्रश्न उठता है। हम व्यवस्था की बात करें।

श्री उमेश पटेल :- प्रश्न जो भी उठता है आप उसे बाद में उठाना। जब आपके बोलने का समय रहेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपकी सांसद दिल्ली में बोल रही हैं हम तो यहां बोल रहे हैं आपके ही दल के सांसद दिल्ली में बोल रही हैं । (व्यवधान)

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमें तकलीफ इस बात की है कि अब मुगलिया वंशज के लोग अब प्रदेश में रेत काम काम नहीं कर रहे हैं, यह विष्णु देव जी का सुशासन है।

श्री उमेश पटेल :- कभी हाफ चड्डी वाले कर भी नहीं सकते हैं।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मुगलिया वंशज (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए। माननीय उमेश जी बोल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय,क्या रोज का मुगलिया वंशज ?

सभापति महोदय :- आप बैठिए। माननीय उमेश जी सब की बातों पर बोल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय,रोज मुगलिया वंशज की बात करते हैं । यह क्या है ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, रोज मुगलिया वंशज की बात करते हैं। यह कल भी यही बात बोल रहे थे।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, वह मुगलिया वंशज की बात की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ विचार करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, जिनके वंश का ठीकाना नहीं है, वह हमको मुगलिया बोलते हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप हमें ऐसा क्यों बोलते हैं?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, कल भी मुगल की बात कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री(श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- भईया, उन्होंने आपको नहीं बोला है। मुगलिया वंश के लोग रेत का करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है तो आप लोग रेत काम कर रहे हैं क्या?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम भी तो बोल रहे हैं कि हाफ चड्डा वाले पूरे प्रदेश के रेत को बेच रहे हैं।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, आप क्यों चिंतित हो गये। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ। ऐसा कोई करता था। यह कह तो रहे हैं कि इसका दस्तावेजी प्रमाण है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम भी तो बोल रहे हैं कि हाफ चड्डा वाले पूरे प्रदेश के रेत को बेच रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए। सुशान्त जी आप बैठिए। आपने बोल दिया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, प्रिंसिपल ने कलेक्टर के पास लिखित में शिकायत की कि वहां पर मेरा स्कूल है और वहां लगातार ढाई सौ गाड़ियां चल रही हैं। मेरे स्कूल के बच्चों को समस्या हो सकती है। मैं एक बात और बताऊं। यह शिकायत करने के 25 दिन के अंदर ही एक बच्चे के साथ दुर्घटना हो गयी। और उसको क्या बोलूं। माननीय नेता जी, यहां पर पूरा माफिया ही चल रहा है। यहां हर घाट में यह चल रहा है कि लोगों को रेत से निकलने का आदेश कर दिया गया है । चाहे डुमरपाली हो, चाहे देवरी हो, हमारा कोई घाट बचा नहीं है। हम लोग शिकायत करते हुए तंग आ गये। हमने मुख्यमंत्री जी को शिकायत दे दी और सभी से शिकायत की, लेकिन सभी को यह है भईया, रेत का काम करिये। इसमें सारे कार्यकर्त्ता लगे हुए हैं आप रायगढ़ घूमकर आ जाईये, आपको पता लग जायेगा।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, अब समाप्त करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। यह सरकार न तो पूंजीगत व्यय में खर्च कर रही है और न ही इनका लॉ एण्ड ऑर्डर में किसी तरह का यकीन है, न इनका अधिकारियों पर किसी तरह का यकीन है, यहां अधिकारी सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। यहां कोई घोषणा होती है उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। अभी रिकेश सेन जी शिक्षा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विभाग की बात उठा रहे थे। अभी शिक्षा विभाग में 33 हजार शिक्षकों के भर्ती की बात थी। हम किस हिसाब से इस बजट का समर्थन करें। इसलिए मैं उसका विरोध करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा):- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नये विधान सभा भवन का लोकार्पण हुआ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हम उस दौर के साक्षी हैं जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब यहां पहला बजट प्रस्तुत हुआ था। उस समय भी माननीय अमर अग्रवाल जी, अजय चन्द्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, भूपेश बघेल जी सदस्य हुआ करते थे और ऐसे कुछ सदस्य हैं। जब यहां पर प्रथम बार बजट प्रस्तुत हुआ तो हम लोगों ने उस बजट को देखा है। आज इस नये भवन में जब विधान सभा और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की रजत जयंती मना रहे हैं तो हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा जो 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा पहला बजट ज्ञान का था, दूसरा हमारा बजट गति का था और हमारा तीसरा बजट संकल्प का है । मैं इस संकल्प के विषय में कुछ लाईनें कहना चाहता हूँ:-

चलो संकल्प का दीप जलाएं, नवनिर्माण का पथ अपनाएं ।
हर जन मन में विश्वास जगाएं, समृद्धि का नव सूरज लाएं।।
जहां अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान है, युवा के सपनों को उड़ान है
नारी शक्ति का सम्मान है, हर घर में विकास का गान है ।

हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश का पहला बजट 5 हजार करोड़ से शुरू होकर पिछले वर्ष 1,65,000 करोड़ का बजट था और उसमें वृद्धि करते हुए 1,72,000 करोड़ का बजट इस साल का है । इस बजट की जो खासियत है कि

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास और अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने पर केन्द्रित है । यह बजट राज्य की नीति में प्रदर्शन, निवेश, परिणामों और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 2047 विकसित भारत, नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी और उस गारंटी को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखकर इस बजट को निर्धारित किया गया है । यह हमारा बजट भाषण केवल आय-व्ययक का लेखा नहीं है, प्रदेश की समग्र उन्नति, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुदृढ़ता का दूरदर्शी संकल्प है और समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे हमारे किसान हैं, युवा हैं, महिला है, श्रमिक है, विद्यार्थी है, सभी वर्गों के कल्याण की स्पष्ट झलक परिलक्षित होती दिखाई दे रही है।

सभापति महोदय, 2026-27 के बजट का जो हमारा संकल्प है-समावेशी विकास । बस्तर से शुरू होकर सरगुजा तक हमारी आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ऊर्जा के साथ में हमारे मानव संसाधन और जिस प्रकार से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे इस बात की खुशी है। हमने इस बात को देखा है कि जहां बस्तर में गोलियां की आवाज आती थी, अब स्कूलों में घंटियों की आवाज आ रही है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने में आया है।

श्री रामकुमार यादव :- 10 हजार स्कूल ला कोन बंद करिस।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, हमारा दंतेवाड़ा एजुकेशन हब बन गया है। उसके साथ में हमारे अबुझमाड़, जगरगुण्डा को एजुकेशन सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हमने बस्तर में मेडिकल कॉलेज खोला, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने अनेक जिलों का निर्माण किया और उसके बाद में आज हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री जी अमित शाह जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, 31 मार्च, 2026 तक इस प्रदेश को नक्सलवाद से सफाया किया जाएगा । इस मूवमेंट को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। यह कहने का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विषय नहीं है, यह आज हम सबको दिखाई भी दे रहा है कि नक्सली त्राहिमाम कर रहे हैं । हम लोग देखते थे कि नक्सली पर्चा फेंकते थे, हमारे वहां के जनप्रतिनिधियों के कहने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज नक्सली बात करने के पत्रों के माध्यम से बार-बार अवगत करा रहे हैं । यह उस मोड़ में लाकर खड़े हो गए हैं कि नक्सलियों का अंत सुनिश्चित हो गया है और इस दिशा में जो सफलता मिल रही है, वह हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति और हमार उद्देश्य है कि इस प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना है।

सभापति महोदय, यदि आज हम पर्यटन की बात करें तो हम बस्तर के पर्यटन की बात कर सकते हैं, हम चित्रकूट फॉल की बात कर सकते हैं, वहां कुटुम्बसर गुफा, हमारे बड़े गणेश जी, हमारा तीरथगढ़ का फॉल है। हम सरगुजा की बात करते हैं तो पर्यटन में सबसे बड़ी बात मैनपाट की बात करते हैं, वहां पर्यटन की दृष्टिकोण से इस प्रदेश को खेती के बाद हम कैसे विकास की दिशा में ले जा सकते हैं ? यदि हम छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर, इनको पर्यटन के क्षेत्र में ले जाकर, इनका विकास करके इस प्रदेश को नवनिर्माण की दिशा में जा सकते हैं। वहां पर ना केवल इतना ही, बल्कि स्टेहोम, वहां के लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ सके, उनको स्वरोजगार की प्राप्ति कैसे हो सके, इन तमाम बातों का जिक्र हुआ। इस बजट के माध्यम से उनके लिए प्रावधान रखा गया है। अभी बस्तर ओलंपिक का शानदार प्रस्तुतिकरण हुआ है। पिछले साल जितने लोगों का पंजीयन हुआ था, उससे बढ़कर 3 लाख 91 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ। उसकी सफलता को देखकर सरगुजा ओलंपिक की तैयारी शुरू हो गई है। हम नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं जिससे हमारे सरगुजा और बस्तर के ऐसे खिलाड़ी तैयार हों ताकि जब हमारा आने वाला ओलंपिक होगा, तो हम इसके लिए बुनियाद डाल रहे हैं। जब अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक के खेल होंगे तो हमारे बस्तर और सरगुजा के खिलाड़ी उस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें तथा इस भारत का नेतृत्व कर सकें, इस बात को लेकर हमारी सरकार चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, आधारभूत सरंचना, सुरक्षा को लेकर 15 सौ नये बस्तर फाइटर्स पदों की घोषणा भी हुई है। इसके लिए 221 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई को लेकर हमारी प्राथमिकता है। हम बस्तर और सरगुजा में सिंचाई को कैसे ज्यादा से ज्यादा विस्तारित कर सकें, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सिंचाई और कनेक्टिविटी, इन्द्रावती नदी पर देवरगांव और मटनार जैसे सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे 32 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। आप 32 लाख हैक्टेयर का मतलब समझ सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा भू-भाग बस्तर में सिंचाई के क्षेत्र में आयेंगे, जिससे हमारे किसानों में खुशहाली होगी। हमारे अन्नदाता खुशहाल होंगे। इसके साथ ही इस प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका को भी सुनिश्चित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इसके साथ ही कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन और डिजीटल सशक्तिकरण, होम स्टे पालिसी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 5 सौ मोबाइल टावर्स के निर्माण एवं इसके साथ ही डिजीटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यहां पर प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही साथ बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार ने जिस प्रकार से दिल खोलकर इस बजट में प्रावधान किया है और राशि दी है, निश्चित रूप से अब नवनिर्माण का समय आ गया है। इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक सम्पन्नता और लोगों के व्यक्तिगत सम्पन्नता आने वाले समय में दिखाई देगी।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, यदि आपके आदेश होही तो एक मिनट। सभापति जी, हमर सरकार रहिस हे तो हमर धरम लाल कौशिक जी, पुन्नू लाल मोहले अउ अजय चन्द्राकर जी, धर्मजीत सिंह नेता जी, ये मन ऐसन भाषण दीन, ऐसन भाषण दीन कि सही ला असत्य साबित करवा दीन अउ ये मन ला कुछु नइ मिलिस। तो मोला एक ठो बात याद आवत हे। मेहनत करे मुर्गी, अण्डा खाय फकीर। तु कुछु कर लेवा तुमन फकीर बरोबर हा, कुछु मिलने वाला नइ हे। तु ओती कतको तारीफ करा कुछ मिलने वाला नइ ए।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलो, हम लोगों को तो नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। जब तोर सरकार रहिस ए तो तोला केतका मिले रहिस ए भइया ? तै इतना बढिया आदमी अस, तोला कहां कुछ दे रहिन ए, यार।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बोलिये मत, उनको लिखित दे दीजियेगा। आप बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है और इसके साथ में आपने देखा है कि महिलाओं

को 1,000 रूपये प्रति महीना दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना में केवल इतना ही नहीं है, बल्कि अभी तक 15,000 करोड़ से ऊपर की राशि महतारियों के खाता में डालने का काम किया गया है। अभी उसमें बजट प्रावधान में 8,200 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही साथ रानी दुर्गावती योजना शुभारंभ की गई है और जब हमारी बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी तब उस बच्ची को डेढ़ लाख रुपये दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, यह 1,000 रूपये कहने की बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का आशय यह है कि महिलाओं को उनका हक मिले। महिला उस पैसे से छोटे-छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, कहीं सिलाई मशीन का, कहीं पर बुनाई मशीन का, कहीं पर अन्य जो महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा जो आपस में बैठकर जो काम कर रहे हैं, उस राशि का जो सदुपयोग कर रहे हैं और उस राशि के द्वारा अन्य जो आय अर्जित कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम हम कह सकते हैं जो महिलाओं को अपने पैरों में खड़े होने का, आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर ले जाने का काम हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। पहले जो 1 करोड़, 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, पूरे देश में 5 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित कर और हमारे छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जहां पर काम चल रहे हैं, महिलाओं को ले जाना, उनको दिखाना जो अच्छे कार्य हो रहे हैं और उसके साथ में उनको प्रमोट करना, उसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं कि जाकर देखें, उसको समझें, बाजार घूमें और उसके साथ में अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा तैयार कर गुणवत्ता के साथ में बनाकर उसको बेचें। इसके लिए भी जो प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप से इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में है और महिलाओं को इसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, 250 महतारी सदन के लिए 75 करोड़ रुपये रूपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष महतारी सदन के लिए विधान सभा में जो बजट में प्रावधान किए गए थे, यह आजकल लोगों की अब मांग आ गई है। लोगों के दिमाग में आ गया है कि गांव में जाएंगे तो यह कहते हैं कि महतारी सदन हमको मिलना चाहिए। महिलाओं की तरफ से ये मांग आती है। माननीय सभापति महोदय, एक इतना सुंदर महतारी सदन बनाकर देना, जिसमें अपने उत्पादों को वहां पर रखकर प्रदर्शित करना, उसको लोगों के बीच में एक व्यवसाय के रूप में वहां पर स्थापित करना और एक आकर्षण का केंद्र वहां पर बनाना, ये महतारी सदन के माध्यम से प्रारंभ हुए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगातार महतारी सदन की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और इस बार 250 महतारी सदन बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मैं हमारे पंचायत मंत्री जी को उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, थोड़ा संक्षेप करिएगा, काफी लोग हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी, जी। आंगनबाड़ी के लिए, साथ ही साथ में अन्य योजना के लिए। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत समय से बात आ रही थी कि कांग्रेस की सरकार के समय में आयुष्मान योजना लगभग बंद सी हो गई थी। उसका लाभ मिल नहीं रहा था और इसके कारण में जो डॉक्टर हैं, निजी अस्पताल के डॉक्टर इलाज करना लगभग बंद कर दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आयुष्मान कार्ड बनाना और उसके साथ में उस कार्ड का उपयोग करना। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि 1,500 करोड़ रुपये का आयुष्मान कार्ड के लिए जो बजट में प्रावधान किए हैं, नए सिरे से लोगों में फिर आयुष्मान कार्ड को लेकर के इलाज प्रारंभ हो जाएगा और माननीय सभापति महोदय, आज इसकी आवश्यकता है। चाहे हम बड़े अस्पतालों में जाये या प्राईवेट अस्पतालों में जायें, उनको 1500 करोड़ रूपये का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और उनको बेहतर ईलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे कई साथी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमको छोटी-छोटी बातों के लिए आयुष्मान कार्ड में पैसा नहीं आने के कारण दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकार के द्वारा उनको यह बड़ी राहत दी गई है। इसके साथ में आपने दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ यहां नये मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में प्रावधान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आज लोगों की डायलिसिस कराने की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग डायलिसिस के लिए जिला अस्पताल जाते हैं। हमारे ब्लॉक में ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां डायलिसिस की सुविधा की आवश्यकता है। ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि हम डायलिसिस की सुविधा देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम राशि में यह डायलिसिस की सुविधा उनको प्राप्त होगी। इसके लिए बजट में 25 विकासखण्डों का चयन किया गया है, जिसमें डायलिसिस की सुविधा होगी और 50 विकासखण्डों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज हम लगातार देख रहे हैं कि बी.पी. और शुगर जैसे गंभीर बीमारी के कारण डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी राशि दी गई है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि जो अपूर्ण सिंचाई योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाये। मुख्यमंत्री जी अभी नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पथरिया बैराज है, उसका लगभग 50% कार्य हो गए हैं और जो 50% कार्य बचे हैं। यदि आप उस कार्य को पूरा कराएँगे तो उससे बड़े क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसलिए अपूर्ण सिंचाई योजनाओं के लिए उसमें राशि का प्रावधान करेंगे तो किसानों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, भूपेश जी जब मुख्यमंत्री बने, तब सड़कों को भूल गए थे। सड़कों का काम भी शुरू हुआ तो सिर्फ दो-तीन जिलों में शुरू हुआ था। उसमें एक दुर्ग जिले का हुआ काम शुरू हुआ था, उसके साथ में एक-दो जिले का और काम शुरू हुआ था, क्योंकि PWD मंत्री भी वहीं से रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, भूपेश बघेल जी की सरकार में जितनी सड़कें बनी थीं, वह आज तक नहीं बनी थी। आपकी सरकार में हम रोड को मांगते रह गए थे, लेकिन आपकी सरकार ने एक रोड की स्वीकृति नहीं दी थी। आज आप लोग फिर से वही स्थिति कर दिए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, संगीता जी सड़क की बात कर रही हैं। संगीता जी, नए सड़क बनाने की छोड़ दीजिये। हमने डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में जो सड़कें बनवाई थीं, उसका पिछले 5 साल में आप लोगों ने पैच रिपेयर तक नहीं करवा पाया। इसलिए आप नए सड़कों की बात बनाना बंद कर दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं बजट में बोलना चाहूँगी। आज की स्थिति यह है कि मेरे संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के गुरुर ब्लॉक में एक रोड पास नहीं किए हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, जब विभागों की अनुदान मांग में चर्चा होगी, उस समय आप अपनी बात रखिएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, दर्द तब होता है, जब हम लोग इतनी सारी सड़कों की माँग दी है। लेकिन संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के गुरुर ब्लॉक में एक रोड सेंक्शन नहीं हुआ। आप उस रोड को बजट में नहीं दिए हैं। इसलिए दर्द होता है।

सभापति महोदय :- बैठिए ना। विभाग का अनुदान मांग आएगी, उस समय आप अपना विषय रखिएगा। धरमलाल जी, आप बोलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य बात ही ऐसे करती हैं। वे बोल रही थी कि आप लोगों ने कितने लोगों को नौकरी को दी है? मेरा प्रश्न लगा हुआ था, उस समय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। उस समय संगीता जी भी विधायक रही हैं। संगीता जी, आपको याद है कि भूपेश बघेल ने क्या जवाब दिया था? आप लोगों ने 5 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है? यह आपको याद है? वह मुख्यमंत्री थे, उस समय वह क्या जवाब दिये थे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आँकड़ा आपको दे दूँगी कि माननीय भूपेश बघेल ने कितने लोगों को नौकरी दी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोगा बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए थे कि 4 लाख 80 हजार लोगों को नौकरी दी गयी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार ने 33,000 पदों पर भर्ती के लिए घोषणा करके के बाद भी अभी भर्ती नहीं किया है। आदरणीय सभापति महोदय जी, शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय बृजमोहन जी, जिनको सांसद के रूप में केन्द्र सरकार में भेज दिए हैं, उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। इसलिए आज आप बजट में करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग नौकरी दिए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन में सब नेताओं के बेटे डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए। ऐसा नौकरी दिए थे? हम वैसा नौकरी नहीं देंगे। हम नियम बना रहे हैं कि कड़ाई से परीक्षा होगी और जो योग्य है, उसको नौकरी देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब डी.एड., बी.एड. वाले बच्चों को नौकरी मिलेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- इंजिनियर का अभी भर्ती हो रहा था...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- डी.एड, बी.एड. वालों के लिये आपने कुछ नहीं किया है। बेचारे हड़ताल में बैठे हैं । सभापति महोदय, डी.एड. बी.एड. के बच्चे लोग आज भी हड़ताल पर बैठे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि उनके लिये बजट में व्यवस्था कर दो । आप बजट इस पर बनाईये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इस विधान सभा में बी.एड. के बच्चों को जब निकाल दिया गया था, मैं ही यहां खड़े होकर उनके बारे में बोला था। 90 विधायक में मैंने अकेले बोला था और 2600 बच्चों को प्रयोगशाला सहायक के रूप में लिया गया और भी बच्चे जिनकी उपेक्षा हो रही है, अन्याय हो रहा है या उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनके बारे में भी बोलेंगे और सरकार को बोलने के बाद सरकार उनका संज्ञान भी लेगी और उसमें कार्यवाही भी किया जायेगा। हम भी आपके साथ है। वह हमारे छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं। हमारे आपके बोलने से अगर छत्तीसगढ़ के बचचों का अगर हित होगा तो किसी को तकलीफ है क्या? यह सरकार ही बनी है कि बच्चों का कल्याण करो, गरीबों का कल्याण करो, हम आपकी भावना का पूरा सम्मान करते हैं। आपके बोलने से तत्काल कोड्र आर्डर नहीं हो सकता है। उसके बारे में आवाज उठायेंगे, आप भी उठाईये, हम भी उठायेंगे।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार ने 34,500 शिक्षकों का विज्ञापन जारी किया और पांच साल में 34,500 शिक्षकों की भर्ती नहीं करा पाई । बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाये थे कि 4,80,000, 3,50,000...। (व्यवधान) सच बतायेंगे कि... । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए कि पुराने बजट में चर्चा करा ली जाये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पांच साल में ढ़ाई साल बुलक गे। नया भर्ती नइ कर पायेव। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- कितना भर्ती हुआ है उसके बारे में ...।(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती शेषराज हरिवंष :- माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा विभाग में अक्टूबर 2023 में प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन जारी किया गया था । व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित किया गया । दो वर्ष पश्चात् दिसम्बर 2025 में दो चरणों में अभयर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया गया । परन्तु आजपर्यन्त ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये। बजट पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कुकुर दिलवाने का काम आप लोग किये हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- गुरूजी मन ला कुकुर बिलई..(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- दारू भट्ठी खोलने का उल्लेख है और स्कूल उन्नयन का उल्लेख नहीं है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 100 करोड़ के धान ला मुसवा खादिस ।(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शिक्षा के क्षेत्र में जीरो ।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि बजट पर चर्चा करें, बजट पर बात करें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलिये, मैं इनकी नौकरी की बात ...(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :-सभापति जी, चन्द्राकर जी को बोलने दिया जाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिये । आप लोग बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय विधायक संगीता सिन्हा जी के सीट की जांच माननीय संसदीय समिति से जांच करवाई जानी चाहिये । माननीय सभापति महोदय, संसदीय समिति से उसकी सीट की गंभीर जांच होनी चाहिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :-चलो, मैं इनकी नौकरी की बात को छोड़ देता हूँ । मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ । भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार यदि किसी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की सरकार है तो वह किसानों की सरकार है । मैं इस बजट के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- धान ला बेचे नइ सकिन । किसान मन फांसी लगावत हे । धान के समर्पण करावत हावय । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी बोल रहे थे, वास्तव में जांच करानी पड़ेगी। (हंसी) मैं सदस्यों से आग्रह करूँगा कि कृपया टोकाटाकी न करें । अपनी बारे में सभी लोग बोलेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं गलत क्या बोला हूँ..।(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वह टोकाटाकी के बगैर बोल भी नहीं पायेंगे। उनको पूछ लो। आप उनको संरक्षण दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- विष्णुदेव साय की सरकार है, वह किसानों की सरकार है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, हमने तीन साल में 4 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और किसानों के खाते में 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये गया है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने तीन साल धान खरीदी की, मैंने इस बार भी सोसायटियों गया और जाकर बोरे के बारे में पूछा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- फटा था।

श्री धरमलाल कौशिक :- इनकी सरकार थी, बोरा की बात करते थे, केंद्र सरकार बोरा देंगे, हमारे पास बोरा नहीं है, ये उपलब्ध करायेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न प्लीज। नहीं-नहीं आप बैठिए न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, इनकी सरकार की बात आई है तो बोलना पड़ेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इनकी सरकार में धानी खरीदी एक सप्ताह लेट से शुरू हुआ था। धान खरीदी की शुरुआत नहीं हुई थी और समर्पण का एक नया शब्द आया जो आज तक संसदीय कार्य...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- सोसाइटी में जइहा त बोरा के बात नई होत हे, मुसवा के बात होत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपने समर्पण लाया है किसानों के लिए। किसानों को चोर समझे हैं, किसानों के घर जाकर चेकिंग करने का काम किए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया । ये बोरा नहीं है करके दिल्ली तक हल्ला मचाए। मैंने स्वयं प्रश्न लगाया था, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत जी अभी नहीं हैं, उन्होंने जवाब दिया कि बोरा खरीदने का काम राज्य सरकार का है। ये बोरा उपलब्ध नहीं करा पाए और हम लोगों ने किसानों से 4 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप सबको बता दूँ, आपने धान खरीदी में जो-जो किया है मेरा हाईकोर्ट में पीआईएल है । बोलो तो उसके पूरे दस्तावेज़ दे देता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसको कैसे-कैसे किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, चंद्राकर जी बोल रहे हैं कैसे किया है। ये चूहा कहाँ से आया? 'मुसवा' कहाँ से आया? आप मुसवा को क्यों बदनाम करके बचा रहे हो।

श्री रामकुमार यादव :- पहली बार किसान के घर में पुलिस भेजे रहे, पहली बार किसान के घर में पटवारी भेजे रहे, अउ आप मन किसान के बात करथव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मुसवा लोग सात करोड़ का धान खा लेंगे। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने मुसवा को भी नहीं छोड़ा।

श्री अनुज शर्मा :- मुसवा के जवाब तो मैं कल दे हों न। सुन लेहा।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप कल अपनी बात बोल चुकी हैं, रामकुमार जी भी बोल चुके हैं। चूंकि समय का अभाव है और इतने सारे सदस्यों को बोलना है। धरमलाल जी आप अपनी बात को संक्षेप में करके समाप्त करिए। टोका-टाकी लगातार जो कर रहे हैं, फिर मैं इस बात को इसको रिकॉर्ड से बाहर करूँगा। आप कल लोग बोल चुके हैं कल। धरमलाल जी आप बोलिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है। (हंसी)

सभापति महोदय :- नहीं आप समाप्त करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंने धान के बारे में कहा। इन लोग जो चार किस्त की राशि देते थे, हम लोगों ने समर्थन मूल्य में दिया और उसके बाद एक किस्त में सारे पैसा का पेमेंट किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और बजट में वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है, हम होली के पहले 10,000 करोड़ रुपये अंतर की राशि किसानों के खाता में डालने का काम करेंगे और हम होली का उपहार किसानों को देने वाले हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, एहसान थोड़ी करत हे। ये तो उनकी उपज का पैसा है। कुछ अतिरिक्त दे रहे हैं तो बता दीजिए। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, दो-दो साल के एमएसपी का पैसा नहीं दिए हैं। ये उसके एमएसपी के पैसे की बात नहीं कर पाएंगे।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मोला धान बेचे एक महीना हो गे, अभी तक मोर पैसा नई डले हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, किसानों को 0% ब्याज में ऋण उपलब्ध कराना। जब डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, इनके समय में तो 14%, 15% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी अल्पकालीन ऋण लाया। हम लोगों ने उस समय योजना बनाई कि शून्य प्रतिशत ब्याज में उनको ऋण उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। हम किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज में ऋण उपलब्ध कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार में हम सिंचाई पंपों के लिए लड़ते थे। इनके द्वारा टारगेट फिक्स किया जाता था कि इतने किसानों को पंप का कनेक्शन मिलेगा। जैसे ही हमारी सरकार बनी, आज हम लोगोंन ने कनेक्शन देना शुरू किया है। सिंचाई पंपों हेतु निःशुल्क बिजली के लिए 5,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है और किसानों को इसका पंप के कनेक्शन उसके बिजली के बिल में कम्पंसेट होगा। इसके साथ नए गोदाम बनाए जाएंगे, अलग-अलग काम किए जाएंगे। एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी खेती के साथ उद्योग जनरेट किये जाएंगे। हम लोगों के लिए रोजगार कैसे जनरेट कर सके, इसके लिए उद्योग विभाग के बजट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को बढ़ाकर 1,750 करोड़ रूपये किया गया है। 23 नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आज भी यदि हम खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कहीं दे सकते हैं, युवा को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर उद्योग है। जिसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने में और इस प्रदेश को विकास की दिशा में लाने में सफल होंगे। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के द्वारा हमारी रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे डॉ. रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तीर्थ योजना शुरू की थी। इन सारी योजनाओं को इन लोगों ने बंद कर दिया था। उस योजना को शुरू करने के बाद बजट में प्रावधान किया गया। हर बुजुर्ग का सपना होता है कि यहां के जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारे यहां के जो तीर्थ स्थल हैं, वहां जाकर मैं एक बार उसके दर्शन करके आऊं। शायद जो काम उसके परिवार के लोग न कर सके, वह काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) उन्हें उनका आशीर्वाद मिल रहा है और यह जो सरकार बनी है वह उनके आशीर्वाद से बनी है। दंतेवाड़ा से लेकर कुदरगढ़ तक हमारे जो शक्तिपीठ हैं, उसको जोड़ने के लिए, सर्किट बनाने के लिए, उसकी सड़क की व्यवस्था और बाकी चीजों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ इस बार हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत सारे काम हुए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इसका परिणाम देखेंगे। न केवल सड़क कनेक्टिविटी बल्कि रेल कनेक्टिविटी, इसके साथ में एयर कनेक्टिविटी और इस एयर कनेक्टिविटी के लिए भी 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर व कोरबा के हमारे स्ट्रिप को नया बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है ताकि यहां के लोगों को भी उसकी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज जिस प्रकार से हमारे नगरीय निकाय में अधोसंरचना और उसके साथ में नगरोत्थान, इस योजना के अंतर्गत जो कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और स्वीकृत होकर उसमें नगर का जो एक बेहतर व आदर्श स्वरूप मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में बनाने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े सेक्टर में काम हो रहा है और इससे सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, जिससे सुंदरता भी बढ़ रही है और लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं। माननीय सभापति महोदय, चाहे SC वर्ग के छात्रों के हॉस्टल हो, चाहे ST वर्ग के छात्रों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हॉस्टल हो, उसके साथ में हमारे जो OBC वर्ग के छात्र हैं, हमारे प्रयास रायपुर, उसके साथ में हमारे बिलासपुर के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं कि उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। आज हमारे छात्रों को बढ़ाने, उनकी शिक्षा के अच्छे प्रबंध करने और उसके साथ में उनके लिए समग्र रूप से काम करने की आवश्यकता है। खेती के साथ में हमारा पशुधन, पशुधन के साथ में हमारी डेयरी, हमारे चिलिंग प्लांट और उसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन करने के लिए जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन करने के लिए 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे आसपास के हमारे जो दूध उत्पादक किसान हैं, उन किसानों को रोजगार भी मिलेगा, उनको डेयरी के लिए लोन भी मिलेगा और उसके साथ में खेती के साथ हम उनको अतिरिक्त आय कैसे दे सके, इसके लाभ उनको मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण। हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट हैं, उनको एक आधुनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा और जिसके माध्यम से उनके जो उत्पाद हैं, उस उत्पाद को ले जाकर लोगों के बीच में रखने और विक्रय करने का अवसर मिलेगा। उसके लिए 93 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से कुनकुरी में भी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रावधान किये गये हैं। मैं दो विषय में बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिये 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके पहले हमारे केन्द्र के मंत्री आये और लगातार हमारे प्रधानमंत्री आवास को बढ़ाया। हमने चुनाव के पहले 18 लाख आवासों का आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना लगातार शुरू हो गये। इसके साथ में जब हमारे मुख्यमंत्री जी आये तो उनको उन आवासों की चाबी देने का काम शुरू किया गया। इस बार बजट में 4 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिये दिया गया है। इसी प्रकार से प्लस टू शहरी आवास के लिये बजट में 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आज जो उनको बेसिक रूप से आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप उनको मकान मिल सके। हमने जो मोदी जी की गांरटी और विष्णु देव साय जी के सुशासन में जो व्यवस्था की गई है, पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास को कांग्रेसियों ने जान-बूझकर रोकने का काम किया। यदि चाहते तो भूपेश बघेल जी भी प्रधानमंत्री आवास दे सकते थे, लेकिन भूपेश बघेल जी का आवास नहीं बनना था, उसमें उनके मंत्रियों का आवास नहीं बनना था। यिद किसी के अधिकार को लूटने का काम किया गया तो हमारे गरीब लोगों के आवास को लूटने का काम उनके द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया गया। भाजपा की विष्णु देव सरकार आने के बाद में हम लगातार उस दिशा में काम रहे हैं और उस दिशा में जा रहे हैं।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जितने भी कमार, भुंजिया के लोग हैं, उनकी तीसरी किश्त अभी तक 4 महीने हो गये है, नहीं मिल पा रही है। पैसा ही नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, दूसरी वाली किश्त अभी तक नहीं आई है। उसको भी दिलवा देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय है विकसित भारत, रोजगार फार गांरटी एण्ड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी, जिसके लिये हल्ला मचाये हुए हैं। सभापति महोदय, यह जो नया विधेयक लाया गया है और जो खामियां थीं, उसको दूर करके कि हम गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मे कैसे जोड़ सकें, उसके लिये 4 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हम लोग गांव में जाते थे तो देखते थे कि एक तालाब की लगातार 3 बार खुदाई हो रही है, उसमें लगातार काम रहे हैं, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इसमें हमारा जो बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, आपको पंचायत भवन, स्कूल भवन के निर्माण की आवश्यकता है, उसमें सी.सी. रोड बनाना है, आपके आजीविका मिशन के लिये ट्रेनिंग के लिये भवन बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जी राम जी में यह जोड़ करके जो संपूर्ण रूप से लाया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो जी-राम-जी है, अभी तक एक राशि इस सरकार से नहीं दी गई है। आप अभी तक पूर्ववर्ती सरकार की राशि उपयोग कर रहे हैं, अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जिस प्रकार से नगरों का उत्थान हुआ है, आने वाले समय में मैं यह कह सकता हूं कि ये पंचायत के हमारे जो रास्ते होंगे और 2047 में जो विकसित भारत बनेगा, हमारे पंचायत के रास्तों से विकसित भारत बनेगा और हमारी पंचायत आत्मनिर्भर, सुंदर पंचायत बनेगी। जिस प्रकार से नगरों की सुंदरता है, उस प्रकार से सर्वसुविधायुक्त हमारी पंचायतों का निर्माण होना है और पंचायत की हमारी आधारभूत संरचना के माध्यम से जी-राम-जी के माध्यम से हमारी पंचायतों का कायाकल्प होना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह हम निश्चित रूप से बात करें तो जो मैं आदर्श शहर की बात कर रहा था, उसके लिये जो प्रावधान किये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिये मैंने बताया कि 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ में पी.एम.सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है। यह जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल कैसे कम किया जा सके, यह कम करने का नहीं, बल्कि पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हम अपने घरों की छत पर सोलर का पैनल लगाकर के मुफ्त बिजली कैसे प्राप्त कर सकें, उसके लिए बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रावधान रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां पी.एम. सूर्य घर योजना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है । हम जब अन्य प्रदेशों की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको और प्रोत्साहित करने की आवयश्यकता है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी):- माननीय सभापति महोदय, यहां ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपअप सब्सिडी दिया जा रहा है और मैं इतना बोलूंगा, कल भी कई सारे किसान हमारे साईड के आये थे तो उनमें से कई लोग पी.एम. सूर्य घर लगाये हैं तो बहुत अच्छा उसका प्रतिसाद मिल रहा है मतलब जो भी लगा रहा है। वह बता रहे थे कि मतलब एक रूपये बिजली बिल भी नहीं आ रहा है और 2 बार, 3 बार सरकार से उनको जो बिजली गयी है, उसकी एवज में पैसा भी मिल गया है करके तो मुझे लगता है कि यदि हम उसको अच्छे से प्रोत्साहित करेंगे तो वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ के लिये...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसलिये बोल रहा हूं कि...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वित्त्मंत्री जी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ग्रामीण में लोगों का बिजली बिल...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप कल बोल चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसमें विधायकों की कमेटी से जांच करवाओ, सीट की। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उनको उसकी कोई राशि नहीं मिल रही है । वह योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, आप अपनी बात को बोलकर समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 2 लाईन में समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय :- 45 मिनट हो गये हैं, बहुत लंबा समय है। आप समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं चौधरी जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि एक तो पी.एम. सूर्य घर योजना में प्रोत्साहित करने की आवयश्यकता है। दूसरा, उसको देना पड़ेगा, अपने को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, उसमें जनजागरण करना पड़ेगा और उसमें मैं यह बोल रहा था कि उद्योग के उसमें, जिसमें 1 मेगावाट और 2 मेगावाट का लगा रहे हैं उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सब्सिडी के लिये विचार करना चाहिए । यदि विचार करेंगे तो प्रदेश में हमारा अच्छा स्कोप है । हमारा पथरिया अधूरा सिंचाई योजना है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि उसको पूरा कराना है तो उसके लिये कुछ पैसा देंगे तो वह उस राशि से पूरा हो जायेगा । माननीय सभापति महोदय, लगातार बजट देखने के बाद यानी पहले ज्ञान का फिर गति का और फिर हमारे संकल्प का, मैं इस बजट के माध्यम से केवल यह कह सकता हूं कि हम इसमें केवल आय और व्यय की चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि हमने जो पहले उधारी ली है, सबसे पहले वित्त्मंत्री जी उसमें राज्य सरकार से उस पैसे की उधारी को कैसे पटाया जाये उसकी भी व्यवस्था हमारे वित्तमंत्री जी कर रहे हैं कि जिससे हमारा कर्ज का भार कम हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, ब्याज लेकर कर्जा पटा रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हमारे कर्ज का भार कम हो, यह व्यवस्था लगातार की जा रही है और यह व्यवस्था कम करने का परिणाम यह हो रहा है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को इंसेंटिव भी अब मिलना प्रारंभ हो गया है, मैं इसके लिये वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं आय-व्यय बजट 2026-27 का मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्तमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस प्रदेश को विकास की दिशा में आगे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ले जाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वर्ष 2047 में हमको विकसित छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आगामी जितने वक्ता हैं, समय का भी अभाव है और इसलिये संक्षेप में, कम शब्दों में 5-5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे, रखेंगे। अनुदान मांगों पर सभी विभागों का जब विषय आयेगा उसमें भी आप लोग बात रखियेगा। अटल श्रीवास्तव जी ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, आपने समय को जरूर कर दिया है लेकिन मैं मुद्दों पर ही बात करूंगा कि 1 लाख 72 हजार करोड़ का यह छत्तीसगढ़ का बजट और हमारे छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री जो कि बहुत विद्वान हैं और हम लोग इनकी विद्वता की प्रशंसा भी करते हैं लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि इनका पहला बजट आया ज्ञान का, दूसरा बजट आया गति का और तीसरा बजट संकल्प का आया । तीनों के बीच में जब ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान कहीं है नहीं । गति की बात होती है, जिस गति की यह कल्पना कर रहे थे कि हम वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी पर ले जायेंगे वहां पर वह गति दिखती नहीं और अभी जो संकल्प लिया गया है उस संकल्प का कहीं न कहीं विकास से कोई तारतम्य दिखता नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 तक डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी तब इस राज्य में जो कर्ज था, वह लगभग 45 हजार करोड़ रूपये का था। यहां 5 साल कांग्रेस की सरकार के बाद वर्ष 2023 में यह कर्ज बढ़कर 95 हजार करोड़ रूपये हो गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी वर्ष 2026-2027 का जो कर्ज बताया है हमारे ऊपर 1 लाख 52 हजार कर्ज चढ़ चुका है। केवल दो सालों में ही इतना है। हमारे ऊपर 5 सालों में जितना कर्ज चढ़ा था, उससे ज्यादा कर्ज लिया गया है हमारे ऊपर 1 लाख 52 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। आने वाले 2 सालों में जब यह बजट प्रस्तुत करेंगे तब हमारा लगभग कर्ज 2 लाख हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस 3 करोड़ की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति 66 हजार 666 रूपये का कर्ज हर आदमी के ऊपर आएगा। यह ऐसा कौन सा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो यह चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, हमारा कर्ज कम हो, लेकिन लगातार हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता जा रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मानननीय सभापति महोदय, मैं कृषि क्षेत्र की बात करूंगा। हमेशा कृषि क्षेत्र में बजट बढ़ रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में माईनस 15 प्रतिशत का रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की जो धान खरीदी हुई जो 1 लाख 49 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी थी, वह इस बार 1 लाख 41 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, इनका उद्देश्य था। मैं यह जान सकता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी का यह उद्देश्य रहा होगा जो इस प्रदेश में बाहरी राज्यों से धान आ रहा है, उसको रोका जाये और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राउण्ड पर जो अधिकारी बैठे हुए थे उन लोगों ने किसानों को खून के आंसू रूला दिया। जब आपके एग्रीटेक के नाम पर जाते थे तो यह लिख दिया जाता था कि इसमें अन्य फसल लगी हुई है, कई जमीनों के टुकड़े छोड़ दिये गये, अगर किसी का जमीन विवाद में हैं तो वहां पर उसका वह कर दिया गया। उसके बाद कहा कि हम उसका भौतिक सत्यापन करने जाएंगे । हमारे किसानों को चोर समझ लिया गया। क्योंकि सरकार का उद्देश्य दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकना था, पर यहां के कर्मचारियों ने इस तरीके से हमारे किसानों को खून के आंसू रूलाया है कि कई किसानों ने आत्म हत्या कर ली और कई तो मरने की धमकी देने लगे। हमारे पास ऐसे कई लोग आये थे। मैं, आपको एक व्यक्ति का प्रकरण बताता हूँ कि एक व्यक्ति को टोकन मिल गया था उसने कहा कि मुझे टोकन मिल गया है और मेरा नंबर आने वाला है, केवल दो दिन बचे हुए हैं। एक पटवारी उसके भौतिक सत्यापन के लिए गया, पटवारी के भौतिक सत्यापन के बाद वह खुश हो गया कि अब मेरा धान बिक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं। अभी नायब तहसीलदार और आएगा। मैं भी भौतिक सत्यापन करूंगा आखिर में डेढ़ सौ क्विंटल धान की खरीदी के लिए उसने पैसा देकर कहा कि आप जो भी भौतिक सत्यापन करना है, आप कर लीजिए। आप मुझसे पैसा ले लीजिए क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है । आप मेरे धान को बिकने दीजिए। आपने किसानों की यह हालत पैदा कर दी। हमारा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था वहां के किसानों की यह हालत थी अगर यही गवर्नेंस है तो फिर यह कैसे चलेगा । जब हमारी सरकार थी तो उस समय आवास नहीं बन रहे थे आपने कहा कि हम 18 लाख आवास बनायेंगे। इस बार आपके बजट में आवास के लिए जो पैसा एलॉटेड है वह माईनस 48 प्रतिशत है। इसका मतलब यहां पर भी आपका इंटेंशन यह है कि आपको धीरे-धीरे आवास में पैसा कम करना है। जैसे किसानों की धान खरीदी कम करना है चाहे किसी भी तरीके से की जाये वैसे ही आने वाले समय में आवासों की स्थिति भी कम करनी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, राज्य की जी.एस.टी. पर कहना चाहूंगा। इस बार की जी.एस.टी. में माईनस 17 प्रतिशत का कलेक्शन हुआ है और अभी आप कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में 21 प्रतिशत ज्यादा लेंगे तो किस तरीके से हमारे राज्य की जी.एस.टी. बढ़ेगी। इसको भी बताने की जरूरत है। क्या इसे व्यापारियों से वसूला जाएगा, क्या हमारे राज्य में लोग जी.एस.टी. नहीं पटा रहे हैं क्योंकि पिछले बार तो यह कहा जा रहा था कि एक साल में ओ.पी. चौधरी साहब का आतंक चल रहा है यहां व्यापारी दर-दर भटक रहा है यह अच्छी बात है कि आप जी.एस.टी. वसूल कर रहे हैं, पर इतना बड़ा टारगेट कहां से पूरा होगा।

माननीय सभापति महोदय, वसूली के कार्यक्रम में इतना बुरा हाल है कि आपने जमीन का रेट आसमान में पहुंचा दिया। हमारी सरकार में जो गाईड लाईन का रेट था चूंकि उस समय कोरोना आया था तो उस समय 30 प्रतिशत कम रेट पर जमीन की खरीदी हो रही थी। आप भी समझते हैं कि यहां किसान जमीन खरीदता है या तो शहर में रहने वाले छोटे-मोटे मकान बनाने वाले लोग खरीदते हैं, पर आपने जमीन के रेट पर, पता नहीं मुझे आप बहुत ज्यादा ट्रम्प से प्रभावित लगते हैं। आपने जमीन का रेट सीधे 100 प्रतिशत बढ़ा दिया, आपने पहले 30 प्रतिशत कम किया, फिर जमीन का रेट सीधे 100 प्रतिशत बढ़ा दिया, आपकी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री अब वर्तमान सांसद ने, सबने इतना विरोध किया कि यहां पर जमीन का इतना रेट नहीं होना चाहिए। फिर आप ट्रम्प से प्रभावित हुए ।

श्री अनुज शर्मा :- आपका दर्द वाजिब है, आप जमीन से जुड़े आदमी हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हम तो जमीन से ही जुड़े हैं और जिस तरीके से आपने 100 प्रतिशत से सीधे 30 प्रतिशत पर ले आये। साहब, आपको बताऊं कि आपने लगभग 300 से 500 गुना जमीन के रेट बढ़ा दिये। आप यह सोचकर देखिए कि कोई गरीब आदमी की क्या स्थिति होगी। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जमीनों के रेट किस तरीके से बढ़ाए गए हैं। मैं सेन्द्री, रतनपुर की बात कर लेता हूं । मुख्य मार्ग में वर्ष 2024 में जमीन की कीमत 1 करोड़, 36 लाख थी । 2025 में जब नीति आई तो वह जमीन 3 करोड़, 60 लाख हो गई, 165 प्रतिशत की वृद्धि । संशोधन के पश्चात् जो भी रेट आ रहे हैं, वह 3 करोड़ रूपए आ रहे हैं। इस तरीके से आप ट्रम्प से प्रभावित होकर पहले रेट बढ़ाते हैं, उसके बाद उसको कम कर देते हैं। आखिर जमीन खरीदी-बिक्री में इतना कौन सा आपको रेवेन्यू मिलने वाला है कि आप जमीनों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आपने अच्छी घोषणा की कि अगर महिलाएं जमीन खरीदेंगी तो उसको रजिस्ट्री रेट में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी । पहले 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता था, उसको आपने बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया । आखिर रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर एक आम आदमी को इस तरीके से क्यों भुगताने का काम हो रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए। आपने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप बस्तर में एजुकेशन सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे हैल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बन रहा है, पर उसको चलाने के लिए हमें मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है, वह एकदम नील है। अगर मैं कहूं, जहां तक मेरा अनुभव है । माननीय अमर अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, वे स्वास्थ्य मंत्री थे। अजय चन्द्राकर जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, पर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने पिछड़े हैं, जितना ज्यादा परेशानियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत विकास हुआ। 14 मेडिकल कॉलेज खुल गए, हमारे पास सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल आ गया। सिम्स को खुले हुए 25 साल हो रहे हैं, पर आजतक हम उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाये हैं, उसके मानव संसाधन को प्रोवाईड नहीं कर पाये। आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करके मानव संसाधन पर कब ध्यान देंगे, वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति कब होगी, कब सिम्स में सफाई होगी? मेरी समझ में नहीं आता कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह आने वाला 5 साल जो हमारे पास आलरेडी है, उसको हम किस अच्छे तरीके से आम जनता की सुविधा के अनुरूप चला सकें, उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है । अभी आपने तीन मेडिकल कॉलेज और खोले हैं । 100-200 करोड़ रूपए और लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा । न आपके पास नर्सिंग स्टाफ हैं, न आपके पास डॉक्टर हैं, न आपके पास पोस्ट ग्रेजुएड के डॉक्टर हैं तो आखिर हॉस्पिटल कैसे चलेगा। अभी जो सिम्स चल रहा है, उसको 25 साल हो गए। वित्त मंत्री जी, आप तो कलेक्टर रहे हैं। मैं सिम्स की एक घटना के बारे में आपको याद दिला देता हूं कि जब सिम्स की घोषणा स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने की कि बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा तो उस समय के कलेक्टर ने जब रिपोर्ट सब्मिट की तो उसने बताया कि उसमें दो एकड़ जमीन कम है। अजीत जोगी जी के काम करने का तरीका किस तरह था, वह मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कलेक्टर को बुलाया और कहा कि अगर दो एकड़ जमीन कम हैं, मैं पटवारी से बोलूंगा तो किस तरीके से जमीन बढ़ती है, वह बढ़ जाएगी और फिर सिम्स के लिए दो एकड़ जमीन नदी के तरफ बढ़ाई गई क्योंकि मेडिकल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन जरूरी होती थी और उस समय जितने अधिकारी थे, उन सभी को एक जगह स्पॉट पर मीटिंग में बुलाया और कहा कि सभी अधिकारी कांटीन्यू फाईल पर साईन कीजिए, आज ही सिम्स मेडिकल कॉलेज सेंशन होगा। इस तरीके से काम होता है । यहां तो स्थिति यह है कि अभी पीडब्ल्यूडी का 60 प्रतिशत पैसा लेप्स हो गया, वह कैरी फारवर्ड हो रहा है। क्यों? आखिर फाईलें घूम रही हैं, फाईलें चल रही हैं । पहले बताया कि इस्टीमेट बनेगा, फिर रि-इस्टीमेट के लिए आता है, उसमें तीन महीने निकल जाते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल के लिए जाता है, वहां पर फाईल तीन महीने चलती है । वहां पर फाईल निकलती है तो उसके बाद वित्त विभाग में जाता है । वित्त विभाग में पता नहीं फाईल किस कोने में पड़ी रहती है, उसमें 6-8 महीने निकल जाते हैं । उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है । जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर दो महीने निकल जाते हैं और जब टेंडर किसी को एलाट होता है तो एग्रीमेंट करता है या नहीं करता है, उसके बाद बरसात आ जाती है । उसके बाद चार महीने बाद ठेकेदार को काम एलाट होता है । आपके दो, ढाई साल तो केवल इसी में निकल गए। इस सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ काम होना चाहिए कि आखिर यह सिस्टम कैसे सुधरेगी और लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जल्दी होंगे । हमारे बिलासपुर जिले का बेहतराई स्टेडियम आज छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा स्टेडियम बन गया है, पर उसको भी सुधारने में कितना समय लग गया । आज जाकर थोड़ी सी स्थितियां सुधरी हैं कि वहां खेलों की गतिविधियां तेज हुई हैं । हम लोग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमारे पास क्या योजना है, वह कैसे रन करे, कैसे जनता को फायदा पहुंचे । हमारे हर जगह पर मानव संसाधन की कमी है, सिस्टम की कमी है । कहीं बिजली बिल नहीं पट रहे हैं तो बिजली कट जा रही है । इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक प्रशासनिक सुधार आयोग बना दीजिए। अभी हमारे गृहमंत्री जी सदन में नहीं हैं । हमारे यहां पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि अवैध शराबबंदी करेंगे । केंदा में एक आदिवासी परिवार है, उसका पति शराब बनता था । उसने शराब बनाकर छोड़ी है, वह किसी दूसरे गांव में चला गया । उसकी पत्नी वहीं रहती थी । एक पुलिस का सिपाही पहुंचता है और दो डण्डे मारकर कहता है कि तुम शराब बनाओ और हमको पैसा पहुंचाओ। इस तरह से सिस्टम में खामियां है, इस सिस्टम की खामियों को कौन बतायेगा, कौन सुधारेगा? इस प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत है तो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाने की जरूरत है।

यह सिस्टम जो नीचे रन करता है, वह किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बना तो हमको यहां कुछ रिजेक्टेड लोग मिल गए, जिनके हाथों से हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा था। आप प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से किस तरीके से विकास के एक नये रास्ते पर आये, इसका प्रयास करें। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। आपके ऊपर सबकी नजर है कि आप तो छत्तीसगढ़ को एक बहुत अच्छा विकसित करने का काम करेंगे। मैं आज आपको अंतिम बात कहना चाहता हूं कि आपने बस्तर में बहुत अचछा काम किया, यहां पर माननीय गृह मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, मैं उनको बधाई दूंगा। मैं उन्हें इस बात की बधाई दूंगा कि अगर नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश किसी ने झेला है तो कांग्रेस परिवार ने झेला है। उसमें हमारे 31 शीर्ष नेता मारे गये थे। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि आप जिस तरीके से बस्तर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, सरगुजा ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ ओलंपिक की बात करिये। अभी से क्षेत्रीयता की बात क्यों करते चले जा रहे हैं ? लगातार क्षेत्रीयता की बात हो रही है। आप छत्तीसगढ़ ओलंपिक को बस्तर में आयोजित करिये, बस्तर पंडुपम को बस्तर में आयोजित करिये। ऐसा क्या कारण है कि केवल बस्तर पर फोकस हो रहा है। आप बस्तर पर फोकस करिये। वहां की नक्सलाइट समस्या को हल कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर में बैठे हैं। यह सन् 2005 के बाद विकसित होना शुरू हुआ। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि वह आज 20 साल बाद,अपने निवास पर पहुंचे। यहां पर बहुत सारे मंत्रियों ने अपना निवास ले लिया है। यहां मंत्रालय खुल गया है, यहां विधान सभा आ गया। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बने हुए 20 साल हो गए हैं और 20 साल बाद यहां बसना शुरू हुआ है। यहां पर बसाहट लगभग कम है और लोग धीरे-धीरे आना शुरू कर रहे हैं। आने वाले 20 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी एक नया स्वरूप लेगा। आप जिस तरीके से बस्तर पर काम कर रहे हैं, आपने बस्तर में बहुत सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम किया, सड़कों का काम किया, वहां पर एजुकेशन का काम किया, वहां पर लाइवलीवुड का काम किया। मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप बस्तर का विकास चाहते हैं तो आने वाले 20 सालों तक कोई उद्योगपति वहां पर उद्योग नहीं लगाये, वहां कोई खनिज सम्पदा नहीं खोदी जायेगी, जब तक बस्तर का आदमी इसके लायक हो जाये। आप यह घोषणा करिये कि वहां पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एन.एम.डी.सी. खुदाई करें, लेकिन कोई बाहर का व्यापारी जो अपनी जीभ निकालकर लार टपकाती हुए देख रहा है कि बस्तर की खनिज सम्पदा को कैसे लूटा जायेगा, उसको रोकिये। माननीय वित्त मंत्री महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप खरसिया के एक गांव से यहां पहुंचे हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी गांव से यहां पहुंचे हैं। अगर आपको बस्तर को बचाना है, जो लोग अपने आपको बहुत होशियार समझ रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा को लूटेंगे, आपको उनको दिखाना है कि आने वाले 20 सालों में जब बस्तर में आज पैदा हुआ आदमी जब 20 साल बाद तैयार हो जाये, उसकी शिक्षा हो जाये, वह समझने लायक तैयार हो जाये कि खनिज सम्पदा में उसका क्या हक है, तब आप वहां के विकास को चालू रखिये, लेकिन बाहर के उद्योगपतियों के लिए रास्ता बंद कर दीजिये। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कि मैं बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं पिछली बार होली का आयोजन था, इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. रमन सिंह जी आपरेशन के लिए गए हुए हैं। भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें। परन्तु इस बार होली का कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है।

श्री ओ.पी. चौधरी:- होली के बाद कार्यक्रम होगा।

सभापति महोदय :- अटल जी, चिंता मत करिये, रंग लगेगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- रंग भगवा लगेगा।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री चौधरी जी ने इस रजत जयंती वर्ष में 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस बजट भाषण से पूरे देश में अच्छा नाम कमाया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय अटल बिहारी जी ने सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। यदि अटल जी राज्य नहीं बनाते तो 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये का बजट नहीं दे पाते। मैं माननीय अटल जी को नमन भी करता हूं और उनकी आत्मा के लिए मैं आशीर्वाद भी चाहता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को आशीर्वाद देकर आज नये परिवेश में हम इस बजट के भाषण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में आज भाग ले रहे हैं। मैं जगदलपुर से शुरू करता हूं । जगदलपुर में आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की तथा बस्तर, सरगुजा में भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए आपने 50 करोड़ का प्रावधान किया। बस्तर, सरगुजा में नेटवर्क के लिए 5 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया। बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव में 60 किलोमीटर नहर के लिए 2,024 करोड़ का प्रावधान किए। सरगुजा जशपुर विकास प्राधिकरण हेतु 50 करोड़ से बढ़ाकर आपने 75 करोड़ किया। बस्तर विकास प्राधिकरण को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 70 लाख महिलाओं को आपने 24 किस्तों में 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के भुगतान के लिए आपने प्रावधान किया और 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा है। इसी वर्ष आपने प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है तथा किशोरियों के नौनिहाल के लिए महिलाओं एवं बच्चों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंगनबाड़ी के संचालन हेतु 800 करोड़ रूपये, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़ रूपये, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। शहरी क्षेत्र में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 120 करोड़ रूपये तथा मिशन वात्सल्य योजना हेतु 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने के लिए हमारी बेटियों के लिए 18 वर्ष पूरा होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये देने के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शासकीय चिकित्सालय अथवा निजी चिकित्सालय हेतु मुफ्त में 5 लाख रुपये के इलाज हेतु आपने 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिससे गरीब लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए सक्षम हो सकें। ऐसे पहले जब कोई योजना नहीं बनी थी, कोई खेत बेचते थे, जमीन गिरवी रखते थे या स्वतः कहीं नौकरी लगते थे और धन के अभाव में कई लोगों की जान भी जाती थी, इसके लिए हमारी सरकार ने अच्छे काम किए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। चरण पादुका योजना के अंतर्गत जंगल में रहने वाले भाइयों के लिए जो तेंदूपत्ता तोड़ते हैं, उसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के लिए आपने 11 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का प्रावधान किया है। सहकारी समितियों के लिए 50 नये गोदाम के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लोक निर्माण विभाग के अन्य कार्यों के लिए 9450 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और मेरी विधान सभा क्षेत्र में फास्टरपुर-झलियापुर रोड का इसमें प्रावधान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जल संसाधन विभाग में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास अंतर्गत आपने 33/11 के.वी. के 90 नए उपकेंद्र हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सार्वजनिक स्थानों तथा चौक-चौराहों में सोलर हाईमास्ट के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है तथा बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने हेतु 354 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। नियद नेल्लानार योजना में विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आपने 400 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 800 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इससे गांव के गरीब लोगों के पास पहले टूटा हुआ घर था, छानी का घर था, उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए आपने उन 18 लाख लोगों को पक्का मकान दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आवास से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को आपने पक्का मकान देकर उनका स्वाभिमान बढ़ाने का काम है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शिक्षित युवाओं के लिए 33 नालंदा लाइब्रेरी की स्वीकृति के लिए आपने 22 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपने बजट में 8,000 करोड़ प्रावधान किया है तथा 15,000 रोजगार सृजित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी को तीन गुना बढ़ाया है, उसके लिए आपने 750 करोड़ रुपया दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पांच महाविद्यालयों को एक्सीलेंसी के रूप में उन्नयन करने हेतु आपने बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया है तथा 25 महाविद्यालयों के लिए आपने 25 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है और मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में आपने जरहा गांव में महाविद्यालय के भवन के लिए राशि की स्वीकृति की है, उसके मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। प्रदेश में आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अधोसंरचना उन्नयन के सुदृढ़ीकरण हेतु आपने बजट में 50 करोड़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का प्रावधान किया है। युवा कौशल विकास के स्किल डेवलपमेंट हेतु आपने बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया है। युवाओं के करियर काउंसलिंग हेतु आपने 10 करोड़ का प्रावधान किया है। युवाओं की परीक्षा के तैयारी के लिए आपने बजट में CG-ACE योजना को शामिल किया है, जिसमें उड़ान का मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी, शिखर का मतलब लोक सेवा आयोग की तैयारी तथा मंज़िल का मतलब बैंकिंग, रेलवे की परीक्षा की तैयारी होता है, उसके लिए आपने 33 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में आपने बजट में 5200 करोड़ का प्रावधान किया है। चना, शक्कर, फोर्टिफाइड राइस, गुड़ तथा आयोडाइज्ड नमक हेतु आपने बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान है, जिससे आदिवासी क्षेत्र में गरीब लोगों को मुफ्त में चावल, मुफ्त में नमक और 2 किलो चना भी मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत दिव्यांगों तथा असहाय लोगों के लिए पेंशन हेतु बजट में 1442 करोड़ का प्रावधान है, जिससे जो दिव्यांग एवं जो महिला बहनें हैं, उनको पेंशन समय पर मिलना है, उनके पेंशन के लिए आपने व्यवस्था की है। उसके लिए बजट में 1442 करोड़ का प्रावधान है, इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं। सभी जिलों में सियान लोगों के लिए 'सियान गुड़ी' स्थापना के लिए आपने बजट में 5 करोड़ की प्रावधान किया है, जिससे सियान लोगों के लिए सियान गुड़ी की स्थापना होगी। वहां स्यान लोग बैठेंगे और वे अपने जीवन संबंधित समय में अच्छे काम के लिए विचार करेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दृष्टिहीन तथा श्रवण बाधित विद्यालय हेतु आपने 850 करोड़ का प्रावधान किया है। जो आंख से देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे लोग विद्यालय में पढ़ेंगे और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमारी सरकार को भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। जनमन योजना के अंतर्गत सड़कों के लिए आपने 500 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बाल विकास सुरक्षा योजना में बजट में 72 करोड़ का प्रावधान है। हमारे बाल हृदय रोग वाले जो छोटे बच्चे हैं, जिनके पालक अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए आपने नि:शुल्क ईलाज कराने की व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, बालक-बालिका छात्रावास भवन के लिए आपने 75 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसानों को नि:शुल्क विद्युतीकरण के लिए आपने 5500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो जी राम जी योजना है, उसमें काम करने वाले मजदूर को 100 दिन की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तुलना में 125 दिनों की मजदूरी मिलेगी तथा उन्हें 15 दिन के बजाय 7 दिन में ही मजदूरी की राशि मिल जाएगी। उनको मजदूरी की राशि नहीं मिलने पर केंद्र के सरकार के मुताबिक जी राम जी योजना में उनको जुर्माना या अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान है। इसको आप लागू करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। जिसमें सी.सी. गली, रोड, पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी भवन या जो पंचायती राज्य के प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा तथा आपने पंचायतों को 20 लाख के बजाय 50 लाख रूपये की राशि से कार्य करने का निर्णय लिया है, मैं उसके लिये भी धन्यवाद देता हूँ । सभापति महोदय, मैं विभिन्न स्थानों पर सामाजिक भवन तथा मुंगेली में 25 लाख के भवन की स्वीकृति के लिये धन्यवाद देता हूँ । अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के लिये 80 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूँ तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिये 50 करोड़ से 75 करोड़ करने के लिये धन्यवाद देता हूँ । मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिये 50 से 75 करोड़ तक जो किया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। भूमि मजदूर है, जो परिवार है, जिसके पास भूमि नहीं है, आपने उसके लिये 6000 करोड़ रूपया दिया है, इसमें 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये दिया जायेगा, मैं इसके लिये भी आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ । सभापति महोदय, आपने 21 क्विंटल धान 3100 रूपये में सुनिश्चित किया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूँ । खरीफ वर्ष में आपने 140.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है और 437 टन धान की खरीदी कर इस कार्यकाल में ऐतिहासिक खरीदी की है तथा किसानों के लिये 1 लाख 40 हजार करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया है । मैं इसके लिये बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ । मार्कफेड के धान उपार्जन हेतु 6000 करोड़ का प्रावधान किया है, धान की खरीदी में मार्कफेड की अहम भूमिका होती है । गन्ना कृषकों के लिये प्रोत्साहन हेतु 60 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूँ । नेशनल मिनरल ऑयल एण्ड नेटवर्किंग फार्मिंग के लिये 40 करोड़ का प्रावधान है । मिनिरल ऑयल के लिये 90 करोड़ का प्रावधान है तथा दलहन की आत्मनिर्भरता के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ ।

समय:2.53 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह)पीठासीन हुये)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषकों के लिये नि:शुल्क विद्युत पंप कनेक्शन के लिये 5005 करोड़ का प्रावधान है। कृषकों के पाम ऑयल खरीदी हेतु किये जाने वाले अनुदान के अलावा टॉप अप हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया है । फसल बीमा के तहत योजना में आपने 820 करोड़ का प्रावधान किया है। किसानों के खेत में आग लग जाये, पानी गिर जाये, ओला पड़ जाये, वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की हानि हो जाये, चाहे खरही में भी हानि हो, आपने उनके लिये फसल बीमा योजना लागू की है। किसानों के नुकसान को भरपाई करने के लिये फसल बीमा हेतु 820 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । एकीकृत वॉटर शेड प्रबंधन के लिये 170 करोड़ रूपये तथा कृषि विकास योजना में 150 करोड़ रूपया और प्रधानमंत्री कृषि योजना में 130 करोड़ तथा राष्ट्रीयकृत कृषि विकास योजना में 30 करोड़ का प्रावधान है । मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । इससे किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लाभ मिलेगा । चरवाहा भाई और पशुपालकों के डेयरी फार्म के लिये 90 करोड़ का प्रावधान किया है । मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । समग्र योजना में पशुवर्धन के लिये 8 करोड़ का प्रावधान किया है । आप उसके लिये भी धन्यवाद के पात्र हैं । प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिये 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिससे मछली पालन करने वाले भाईयों को भी लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, प्रधानमंत्री की पहल पर युनिटी मॉल हेतु हस्तशिल्पियों के लिये 93 करोड़ का प्रावधान किया है । सरकार इसके लिये भी धन्यवाद के पात्र हैं । छत्तीसगढ़ पेंशन एवं ग्रोथ एबिलिटी फण्ड के लिये क्रमश: 5 करोड़ रूपये तक का है इसमें 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । भाटापारा, भिलाई, केशकाल सहित अन्य 15 स्थानों में मॉडन उप पंजीयन भवन के लिये प्रावधान किया है । जी.एस.टी. में तकनीकी सुधार हेतु बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट जी.एस.टी.कॉल सेंटर हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है । छत्तीसगढ़ के अंजोर विजन में 247 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । पी.एम.श्री योजना के माध्यम से 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिये आपने प्रावधान रखा है तथा प्रथम चरण में 150 चयनित स्कूलों के लिए आपने 100 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 500 प्राइमरी स्कूल, 100 मिडिल स्कूल, 50 हाई स्कूल तथा 50 हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन हेतु 123 करोड़ का प्रावधान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। रामलला के दर्शन हेतु आपने 36 करोड़ का प्रावधान किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय स्तर के ईको टूरिज्म के पहचान हेतु पर्यटन में 500 से अधिक लोगों का निवेश किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। शासकीय महाविद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकसित करने हेतु नवीन योजनाओं के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने आवास योजना में भी गाँव के लिए 5 लाख खर्च से लेकर 4000 तक के प्रावधान भी किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र सहित आपने एक कॉलेज भी दिया है, स्कूल भी दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपसे एक अनुरोध करूँगा कि मैंने पिछले समय विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया था जिसमें मुंगेली जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, इस अशासकीय संकल्प को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया था, जिसके लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को भी इसके लिए पत्र भेजा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूँगा कि मुंगेली में मेडिकल कॉलेज का प्रावधान करेंगे, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ। मुझे बोलने का अवसर देने के पहले मैंने फिर आपसे कहा कि गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल के लिए 25 लाख की जगह 50 लाख राशि का प्रावधान किया है। मुंगेली जिले में लालपुर में गुरू घासीदास जयंती के लिए 10 लाख को 15 लाख का किया है। आपने श्वेतगंगा में 50 लाख का सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की है, 10 लाख तक बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के लिए राशि दी है। इसी तरह आपने अमर टापू में भी दी है और तीर्थ स्थल भंडारपुरी और गिरौदपुरी के लिए भी 5-5 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय:- श्री विक्रम मंडावी। श्री द्वारिकाधीश यादव। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे 2026-27 के बजट के आय-व्यय में भाषण देने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया है जिसमें राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,43,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ अनुमानित बताया और सीधा कह दिया कि 2000 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। आपने राजस्व घाटा का पहले अनुमान लगा लिया बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने कविता और संस्कृति का उल्लेख तो बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों की वास्तविक जो कला संस्कृति है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभ्यता है उसे दरकिनार कर दिया। उन्होंने 3 करोड़ जनता को आभार करते हुए अपनी बात रखी लेकिन करमा, ददरिया या दोहा या छत्तीसगढ़ के बहुत से कवियों को साइड कर दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज के कार्यसूची में लिखा है, अशासकीय दिवस होगा। 3 बज रहे हैं अशासकीय दिवस शुरू नहीं हुआ है। आज होगा, नहीं होगा, बाद में होगा, चर्चा समाप्त होने के बाद होगा, कब होगा? क्योंकि 3 बज रहे हैं, इसमें आपका कुछ निर्देश आ जाए।

सभापति महोदय :- जी-जी, जरूर निर्देश दूंगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अभी मैंने शुरुआत की है बोलने दीजिए। आप जिनका दर्द कम नहीं कर पाए उन भाई-बहनों को आपने आभार किया अच्छी बात है। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने कहा कि आज आम जनता यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि बजट में हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली और आप वर्ष 2047 कहते हैं। आपने बार-बार यह कहा कि उसके लिए दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हर्षिता जी, एक मिनट। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, आप नयी सदस्य हैं, बोलिये। मैंने आसंदी से कहा कि 3.00 बज रहे हैं, आज अशासकीय कार्य होगा या नहीं होगा? इसमें आपकी व्यवस्था आ जाए। आज अशासकीय दिवस है, जो कार्यसूची में शामिल है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, पहले आप व्यवस्था दे दीजिये।

सभापति महोदय :- अशासकीय संकल्प के लिए आखिरी का एक घंटा रहता है और मैंने पहले ही कहा था कि अशासकीय संकल्प लिये जाएंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन अशासकीय दिवस में तो अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य होते हैं।

सभापति महोदय :- अशासकीय संकल्प के लिए 1 घण्टा तय हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैंने अशासकीय संकल्प के बारे में नहीं पूछा था। अशासकीय समय अंतिम ढाई घंटे का होता है। 3 बज रहे हैं। इस सभापति महोदय :- यह चर्चा समाप्त होने के बाद उसको करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं कह रही थी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बार-बार कहा था कि वर्ष 2047 तक हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन वह दीर्घकालिक लक्ष्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं और करीब आकर देखो तो फटा हुआ ढोल मिलता है। जिसका आवाज तो आता है थपथपाहट, लेकिन बेसुरा आवाज आता है। आपने पिछले बजट में ज्ञान की बात कही थी, लेकिन यह ज्ञान बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाया। बच्चों से ज्ञान छीनने के लिए आपने शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था को ही दरकिनार कर दिया, बल्कि युक्तियुक्तकरण करके आपने ज्ञान की पूरी धज्जी उड़ा दी। ज्ञान के कल्याण की बात आ रही है और ज्ञान के कल्याण के लिए आपने बजट थीम संकल्प रखा है। मैं अपने शब्दों में इसको बयां करती हूं कि वर्ष 2025 में आपने कहा था कि हम रजत वर्ष मना रहे हैं और राज्य युवावस्था में है। जब राज्य युवावस्था में है तो इसको एक अच्छी दिशा मिलनी चाहिए थी। अच्छी दिशा न देकर आपने युवा राज्य को नशे में डुबा दिया और अधिक शराब बिक्री होने लगी। (मेजों की थपथपाहट) आज छत्तीसगढ़ इस तरह से है। वित्त मंत्री जी, मैं इस लाइन को बहुत अच्छे से बोल रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा अभी ध्वस्त हो गया है, किसान त्रस्त हो गया है।

छत्तीसगढ़ में युवा शिक्षा ध्वस्त हो गया है, किसान अभी त्रस्त हो गया है।

युवा राज्य अपने ज्ञान से भटककर, सरकार यहां भ्रष्ट हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप संकल्प की बात करते हैं, चहुंमुखी विकास की बात करते हैं। आज बजट में सिर्फ बस्तर को टारगेट किया गया और रायपुर की कुछ व्यवस्था को देखा गया। बाकी जिले राजनांदगांव, मोहला-मानपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा, धमधा व अन्य विधानसभा क्षेत्रों को दरकिनार कर दिया गया। बस्तर में आपने बस्तर हब की बात कही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। यह बस्तर हब किसके लिए बनाया जा रहा है? क्या मोदी जी के दो भाइयों अम्बानी और अडानी के लिए बनाया जा रहा है? ताकि वह आते-जाते रहें और हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि को खोदकर वहां की खाद्य संपदा को लूटते रहें। बस यही छत्तीसगढ़ का विस्तार है। छत्तीसगढ़ की खाद्य संपदा को बचाए या वनों को काटने से बचाए, इस पर आपका ध्यान नहीं है, इस पर कोई बजट नहीं है और आप कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम। यह कैसे संभव है, यह कैसी व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था को लाचार करके शिक्षक भर्ती या स्कूल व्यवस्था, स्कूल बिल्डिंग के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। समर्थन मूल्य के अलावा जिसकी फसल बारिश में अतिवृष्टि में खराब हुई, उनको फसल बीमा या मुआवजा मिल सके। और तो और जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए कर्ज माफी के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की पूर्ति होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए। उनके लिए भी आपके बजट में प्रावधान नहीं है। कुशल मानव संसाधन, उच्च शिक्षा महाविद्यालय के लिए बजट में तो रखा परंतु बहुत कम बजट रखा जबकि आई.टी.आई., तकनीकी शिक्षा और व्यवस्था के लिए 209 पद खाली है, उनके लिए कोई पद खाली नहीं है। सभी जगहों में डी.एड., बी.एड. कॉलेज होने चाहिए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप प्रतिभावान युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को बढ़ाने की बात करते हैं। आपने पहले ही उन्हें बढ़ने नहीं दिया है। कौशल विकास की सुविधा के लिए 75 करोड़ रूपये बहुत कम हैं, जो कि सिर्फ ढिंढोरा पीटने में चला जाएगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उस पर बेरोजगार पढ़े-लिखे पंजीकृत युवाओं को अनदेखा किया जा रहा है। इनके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय, अब आई महिलाओं की बारी। महिलाओं के लिए सिर्फ एक महतारी वंदन योजना है, जिसमें आपने साल का 12,000 क्या दे दिया, आप सभी जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप कहते हैं कि हम हर विवाहित महिला को 1,000 रूपये दे रहे हैं। लेकिन आप यहां विधवा और वृद्धा महिलाओं को सिर्फ 500 रुपये पकड़ा रहे हैं और तो और जो नवविवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए 2 साल से पोर्टल ही नहीं खुल पा रहा है। सभापति जी, आप पोर्टल खुलवाईए ताकि वह लोग भी अपना नाम जुड़वा सकें और उनको भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ जो हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं, सहायिकाएं और रसोइया हैं, उनके मानदेय में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। वे 3,000-4,000 रुपये के मानदेय में आठ-आठ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

घंटे की ड्यूटी करती हैं। उनका भी मानदेय बढ़ाना चाहिए। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आप रसोई गैस 500 रूपये में देंगे लेकिन आपने तीसरे बजट में भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

सभापति महोदय, नक्सलमुक्त कहने वाले, नक्सलमुक्त करने की घोषणा करने वाली सरकार ने हमारे राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त कहा, लेकिन अभी हाल ही में डोंगरगढ़ में एक नक्सली मुठभेड़ होती है। उस नक्सली मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के एस.आई. आशीष का देहांत हो जाता है। यह कैसे नक्सल मुक्त हुआ? अभी तक की कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ अभी भी नक्सली मुठभेड़ हो रहे हैं, उसको आपने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है।

सभापति महोदय, अब मैं विकलांगों के लिए कहना चाहूंगी कि विकलांग समूह वाले लोग बार-बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बार-बार मंत्री-विधायकों के पास पहुंच रहे हैं। वे मेरे पास भी अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। उनकी मांग पूरी नहीं की गयी, उनको अनदेखा किया गया, उनके विश्वास को छला गया। इस बजट में उनके लिए पेंशन या अन्य कोई लाभ का प्रावधान नहीं किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी, आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- बिल्कुल, सुन रहा हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह सरकार हर समय अपने भाषणों में जनता को गौ माता की सेवा करने के लिए कहती है। आप सुन रहे हैं ना? गौ माता की रक्षा करो, आप बस यही कहते हैं लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए या उनके रख-रखाव के लिए लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय, आज आम जनता के ऊपर बिजली बिल का इतना मार पड़ा है कि उसके बारे में मैं क्या बताऊं। स्मार्ट मीटर लगने से सरकार फुल बिजली बिल दे रही है और फुल बिजली गुल भी होते जा रही है। आज आम ग्रामीण जनता इतनी त्रस्त है कि बार-बार रात के 12 बजे तक हम लोगों के पास फोन आता है कि मैडम लाइट गुल हो गई है, ट्रांसफार्मर फेल हो गया है। लेकिन उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। आपके घोषणा पत्र में बिजली बिल का हाफ योजना शामिल थी। इस तीसरे बजट में भी आपने बिजली बिल हाफ नहीं की। ऊपर से आप लोगों ने यह माहौल बनाया कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें, सब्सिडी मिलेगी और उसके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

साथ में बिल भी पटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा लगा दिए तो आपका बिल नहीं आएगा, उसमें बिल भी पटाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अभी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में आपने सीमित बजट रखा है। जिसमें धार्मिक जगहों के लिए, भ्रमण के लिए या मेला के लिए व्यवस्था। बाकी शिक्षा के लिए? आपने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में शिक्षा के लिए क्या किया? वहां पर जो पी.जी. हॉस्टल है, वह पूरे जिलों में होना चाहिए, पी.जी. हॉस्टल कहीं नहीं है। छात्रावास तो हर जगह है, हर जगह पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रावास है, लेकिन पी.जी. हॉस्टल कहीं भी नहीं है। उन बच्चों को किराए से रहना पड़ता है। फिर हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? मेला की बात है, तो मेला की व्यवस्था के लिए आपने 25 से 50 लाख रूपये कर दिया लेकिन सही मायने में गिरौदपुरी धाम, चटवा पूरी धाम, भंडारपुरी धाम ऐसी जगह हैं, जहाँ पर यदि दूर-दराज से कोई आ रहा है तो उनके रहने के लिए, रुकने के लिए भवन नहीं है और उनके लिए शौचालय भी नहीं है। वे सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर सकें, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है।

आपने ऐसा क्या बजट तैयार किया है कि आज अनुसूचित जाति कल्याण को बहुत कम बजट देकर आपने दरकिनार कर दिया। उसको खाली छोड़ दिया गया है। नशा को बढ़ाने के बाद आपने नशामुक्ति के लिए बजट में 20 करोड़ रूपये रखे हैं। आप पहले बढ़ा देते हैं, उसके बाद नशामुक्ति के लिए 20 करोड़ का बजट में प्रावधान रखे हैं। बहुत अच्छा, लोगों को दिखाने के लिए। पुलिस जो कि रक्षा व्यवस्था पर अपना पूरा समय देती है, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की।

सभापति महोदय: हर्षिता जी, समाप्त करिये। आपको 13 मिनट हो चुके हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैं एकदम जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। सुरक्षा के लिए जो हमारा पुलिस विभाग है, उनके लिए आपने बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखा है। क्राइम ब्रांच जैसे विभाग को भी बजट में महत्व मिलना चाहिए।

राजस्व व्यवस्था, आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये जो आपने राजस्व व्यवस्था जिसमें स्वतः ही नामांतरण, ऑटो डिवीजनल, जियो-रिफ्रेंसिंग शामिल है, जो आपने बनाया है, इसे पूरे जिले में कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपने 25 करोड़ रूपये का बजट रखा है, यह बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कम है, इसको भी बढ़ा दीजिये। इसमें स्वतः ही नामांतरण हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये लिमिट होगा या पूरे जिले में होगा?

श्री ओ.पी. चौधरी :- यह पूरे प्रदेश में हो रहा है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, नहीं हो रहा है, अभी भी हमारे क्षेत्र में अधूरा है। मेरे ही पी.एस.ओ. ने अभी शिकायत की थी कि मैडम मेरा नाम में अभी भी नामांतरण नहीं हो पाया है।

सभापति महोदय :- चलिए अब आप समाप्त करें। बहुत से लोग हैं, 34 लोग हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, 2 मिनट। मैं आपका ध्यानाकर्षित कर रही हूँ कि आप इस पर विशेष ध्यान दीजिये और नामांतरण जल्द से जल्द हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं आपको पुराने बजट में शामिल की हुई राशि के बारे में बताऊँगी । पिछले बजट में आपने रिंग रोड के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया था। मेरे विधान सभा डोंगरगढ़ में भी आपने बाईपास के लिए कहा था ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- हर्षिता जी, एक मिनट। राजेश जी कुछ समर्थन मांगने गए हैं, तो कम से कम भूपेश बघेल जी वाले समर्थन कर दीजियेगा, वे टी.एस. जी को हरा कर आये हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- वे इधर ही शामिल हो जाएंगे।

सभापति महोदय :- आप सुनिए न, आप भाषण दीजिये। आप उनसे बात मत करिए, आप भाषण दीजिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी। सभापति महोदय, आपने पुराने बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था, परन्तु आज तक हमारे डोंगरगढ़ बाईपास के लिए सर्वे की भी शुरुआत नहीं हुई और रजिस्ट्री में बैन लगा हुआ है । इसके लिए रजिस्ट्री में बैन लगा दिया गया है। जबकि वहां अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ है, उसमें कोई प्रावधान, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें भी आप विशेष ध्यान दीजिये।

कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल मार्ग, जो कि पिछले बजट में भी शामिल था, इस बजट में भी था। लेकिन आपने स्पष्ट राशि जारी नहीं की। क्या उसका सर्वे होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से यह सिर्फ कागज़ में ही रह जायेगा और हमको पेपरों में ही देखने को मिलेगा। इसमें काम होगा कि नहीं होगा? इसमें भी कोई सही उल्लेख नहीं है।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सड़क योजना, जिसके बारे में हम लोग बार-बार बोल रहे हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत बेहाल है। लेकिन इस साल इस बजट में भी सड़कों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऊपर से डोंगरगढ़ की बहुत सी सड़कें जो पिछले बजट में शामिल थी, उनको भी हटा दिया गया है। ये आपने बहुत अच्छा किया। डोंगरगढ़ की जनता उम्मीद में ही बैठी है कि अभी जो सरकार है कम से कम कुछ तो करेगी, कुछ तो सुशासन की बात करेगी लेकिन डबल इंजन तो फेल है, क्या कर सकते हैं। अब डबल इंजन फेल है तो सही ढंग से न पानी की व्यवस्था हो पा रही है, न बिजली की व्यवस्था हो पा रही है, न सड़क की स्थिति सुधर पा रही है और न ही सुरक्षा की व्यवस्था हो पा रही है। माननीय सभापति जी, हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं गति दो।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कर दीजिये, 17 मिनट हो गये हैं। इतना ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, सिर्फ दो लाइन। आप गति की बात करते हैं। डबल इंजन छत्तीसगढ़ को गति से भगा रहा है । डबल इंजन की सरकार में गति इतनी धीमी है कि छत्तीसगढ़ का बजट आय-बाय साय-साय है और छत्तीसगढ़ का जो विकास है, वह वहीं पे चित्त हो गया है। मैं अपने बजट भाषण यहीं पर समाप्त करती हूं और इसका खंडन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, माननीय सदस्य ने भी बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। इस बजट के विषय में बस यही कहूंगा कि 5 हजार करोड़ रुपये से जो सफर शुरू हुआ है, 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये तक का यह सफर सिर्फ आंकड़ों की बढोत्तरी नहीं है बल्कि GYAN के प्रकाश में GATI के साथ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का SANKALP है। GYAN से सीखा GATI से रास्ता बना, अब SANKALP से बदलेगा छत्तीसगढ़ अपना। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि जब

प्रति व्यक्ति आय नई ऊंचाई छू रही है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि नये भारत की दिशा भी तय कर रहा है। इसके विषय में मैं कहूंगा कि एक महत्वपूर्ण काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है जो आकांक्षी जिले थे, जहां निवासरत हमारे भाई-बहन जो विकास की मूलधारा से पीछे छूट रहे थे, उनको बराबरी पर लाने का इस बजट में जो उन्होंने प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। चाहे बस की कनेक्टिविटी, डिजिटिलाइलेशन की बात हो, टावर बनाने की बात हो, ऐसे दूरस्थ स्थानों पर अगर पर्यटन स्थल है तो होम स्टे को बढ़ावा देने की बात हो, इससे उन क्षेत्रों को विकास की नई धारा के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि कि हमारे बजट में देश के बाकी राज्यों के बजट का जो एवरेज है, उससे ज्यादा उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में 16 प्रतिशत बजट को रखा है। हमारे छत्तीसगढ़ का 16 प्रतिशत बजट रहता है यानि बाकी स्टेट की तुलना में छत्तीसगढ़ में एजुकेशन में शिक्षा व्यवस्था में विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने इस बजट में अतिरिक्त व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही स्वास्थ्य में देश के एवरेज से ज्यादा पैसा हमारे प्रदेश के बजट में प्रोविजन होता है, ऐसा ही एग्रीकल्चर में है और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यानी हमारे किसान भाईयों के लिये सबसे ज्यादा चिंता हमारे प्रदेश में की जाती है जिससे सबसे बड़ा अंतर है जो राष्ट्रीय औसत है, उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत में बजट में प्रोविजन है। राष्ट्रीय औसत 5.7 प्रतिशत का है जबकि छत्तीसगढ़ में 18 प्रतिशत एलोकेशन बजट का किसान भाईयों के लिये है। मैं इस विषय में माननीय मंत्री होते तो उनको आभार सामने देता, अभी उनके पीठ पीछे आभार देना पड़ेगा। उन्होंने बंगोली में आई.टी.आई. के लिये भवन और छात्रावास के लिये 5 करोड़ 36 लाख रुपये स्वीकृत किया है, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। दो स्कूल भवन के लिये 1 करोड़ 96 लाख रुपये स्वीकृत किया है, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। हमारे क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की नई सड़क जो मोवा से सेरीखेड़ी तक आयेगी, रायपुर के यातायात की सुगमता के लिये बहुत लाभकारी होगी, उसके लिये भी उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारे यहां बहुत सारे पुल, पुलिया और सड़कों का बजट में प्रावधान किया है, उसके लिये भी आभार व्यक्त करता हूं। पिरदा चौक मे फ्लाईओवर जो बहुत जरूरी थ, उसके लिय भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू हुआ है।

सभापति महोदय :- मैं सोचा कि आप समाप्त कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अनुज शर्मा :- अब उनको आभार पहले दे देता हूं। हम नये विधायकों के भाग में एक तो कम समय आता है उसमें भी तीन तकादा के साथ आता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें मुझे थोड़ा सा समय कृपापूर्वक दें।

सभापति महोदय :- मैं तो आपको टोक नहीं रहा हूं। आपका जो टापिक आया न तो मैं सोचा कि ये समापन बेला वाला रहता है।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, वह चले गये तो मैंने बोला कि उनका आभार पहले व्यक्त कर दूं। यह महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह इकानामी का बजट है, जहां विकास का पहिया तभी घूमेगा, जब आधी आबादी आगे बढ़ेगी। ये ममता का विश्वास है, हर मां-बहन की मुस्कान में प्रदेश का विकास है । मातृत्व से लेकर बेटियों के भविष्य तक हर कदम पर सुरक्षा, सम्मान और संबल का वायदा इस बजट में साफ झलकता है । रानी दुर्गावती जी के नाम पर योजनाएं हों या लखपती दीदी का सपना, यह सिर्फ योजनाएं नहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मजबूत नींव का निर्माण करने वाली बात है । महतारी वंदन योजना के लिये 8200 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिये 2320 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिये 120 करोड़, मिशन वात्सल्य के लिये 80 करोड़, रानी दुर्गावती योजना के लिये 15 करोड़ रूपये, अब जब परिवार में बच्ची का जन्म होता था तो हमें उनकी शिक्षा के लिये, उनके आने वाले भविष्य के लिये चिंता करनी पड़ती थी अब डेढ़ लाख रूपये, अगर छत्तीसगढ़ में हमारी कोई बिटिया पैदा होगी तो उसे 18 वर्ष की आयु पर डेढ़ लाख रूपये मिलेंगे जिससे वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है, जिससे वह अपने जीवन को संवार सकती है ।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिये बात हो या ढ़ाई सौ महतारी सदन, हमारी बहनें जो गांव में, स्वसहायता समूह की बहनें होती थीं उनको एक निर्धारित स्थान मिलेगा जहां वह अपने आपस में सामंजस्य के साथ अपने गांव को, अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिये विचार-विमर्श कर पायेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे । बड़ा सुंदर महतारी सदन बनता है उसके लिये मैं अभिनंदन करता हूं, युवाओं के लिये इस बजट में ढ़ेर सारे प्रावधान किये गये हैं, चाहे वह आदिवासी क्षेत्रों के लिये हो । मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि इन विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है । स्पेशली पी.वी.टी.जी. के लिये आवासीय विद्यालयों का प्रावधान किया गया है, बैगा एवं पूजारियों के प्रोत्साहन के लिये क्योंकि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर, यहां की सनातन परम्परा पर आक्रमण करने के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं ऐसे में हमारे आदिवासी क्षेत्र के बैगा एवं पुजारियों को प्रोत्साहित करना यह बहुत नेक कदम है, इसके लिये मैं माननीय वित्तमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं ।

तु धैर्य रख, मेरा हौसला देख,

विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का काफिला देख ।

माननीय सभापति महोदय, यह तो बस शुरूआत है अभी तो पूरा आसमान बाकी है । कहते हैं कि वर्ष 2047 की बात करते हैं, वर्ष 2047 की बात करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे मुखिया विजनरी हैं । चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों और एक बात और जब कहते हैं तो निर्धारित समय में काम करना भी जानते हैं । चाहे धारा-370 हटाने की बात हो, चाहे नक्सलवाद के समाप्ति की बात हो या भारत को विकसित भारत, शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बनाने का लक्ष्य हो उसके आधार पर यह बजट आया है जो छत्तीसगढ़ को मजबूती के साथ खड़ा करेगा । जब भी काम की बात कहते हैं तो हमारे विरोधी साथी कहते हैं कि हर बार कहना कुछ नहीं हुआ, हर बार कहना कुछ नहीं हुआ जैसे रोना ही इनका धंधा हुआ । मैं एक बात कहूंगा कि इस बजट में एक विशेष प्रावधान किया गया है, किसी देश की सांस्कृतिक समृद्धि कैसी है, वहां खेल-कूद का वातावरण कैसा है इसके लिये सबसे बढ़िया उदाहरण होता है वहां का स्वास्थ्य और उसके लिये छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये इस बजट में जो प्रावधान किया गया है कि कोई खिलाड़ी अगर ओलम्पिक में भाग लेता है तो उसके लिये 21 लाख रूपये, अगर वह गोल्ड मेडल लाता है तो 3 करोड़ रूपये, 2 करोड़ रूपये सिल्वर मेडल जीतने के लिये और ब्रांज मेडल जीतने पर 1 करोड़ रूपये की घोषणा इस बजट में की गयी है, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसी प्रेरणादायी योजना एनाउंस की, जिसमें ऐसी खेल प्रतिभाएं जो अपने जीवन में खेल को करियर बनाना चाहते हैं उनके प्रोतसाहन के लिये इन्होंने बहुत बढ़िया घोषणा की है और यह बहुत अच्छी योजना आयी है । इस वर्ष हमारे यहां नेशनल ट्राईबल गेम्स का आयोजन हुआ, बस्तर ओलंपिक हुआ, बस्तर पंडुम हुआ, फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है । सालों से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की मांग थी, मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष इस प्रोफेशन को दिये हैं । हमने लंबे समय से यह मांग रखी थी कि फिल्म

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विकास निगम की स्थापना हो । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने फिल्म विकास निगम की स्थापना की थी। उसके बाद अभी वापस से फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इससे पहले की सरकार में 5 सालों तक फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पायी थी, राज भाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पायी थी। क्योंकि इनकी प्राथमिकता में संस्कृति नहीं थी। इनकी प्राथमिकता में यहां की भाषा थी ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में यहां के कलाकार थे ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ:-

''कुछ लोग सिर्फ सवालों में उलझे रह गये
हम जवाब बनकर, इतिहास लिखते चले गये
वह कमियां गिनाते रहे, हर कदम पर
हम उपलब्धियों से नया विश्वास जगाते चले गये।''

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने साथी भाई के लिए कुछ लाईनें कहना चाहता हूँ, उनकी जो कविता है उसको उनके ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ :-

''यह जो तुम्हारी शक करने की आदत है, इसे छोड़ना पड़ेगा।
मुझ पर एतबार का तार जोड़ना पड़ेगा
रिश्ता विश्वास पर चलता है मेरे दोस्त।
भ्रम का पर्दा खोलना पड़ेगा।''

श्री अनुज शर्मा :- ''क्या खोया, क्या पाया, इसका हिसाब तू रख।
मैं तो चला छत्तीसगढ़ गढ़ने बस तू सब्र रख।''

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुज भाई का जवाब दे देता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय विधायक जी आपके क्षेत्र में आवास घर बने हे। ओला भी पूरा तोड़ दे गे हे। ओमा सब महतारी मन गारी देथे । खोजत हे कि हीरो कहां हे।

एक माननीय सदस्य :- बहन जी, बढ़िया कवि सम्मेलन चलत हे तो चलन देना।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- उहां चलत हे, सब उहां देख बर जाहू।

सभापति महोदय :- आप लोग भी बैठिए। एकाध कविता हो गयी । यहां कोई कवि सम्मेलन थोड़ी हो रहा है। यहां भाषण होने दीजिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रही हैं मुझे उनके ज्ञान पर बड़ा अफसोस है। उनकी जानकारी बहुत ही कमजोर है और कमजोर क्या, वह आधारहीन बात कर रही हैं। जहां कि बात कर रही हैं वहां से अभी तक एक तिनका तक नहीं हटा है, उनको पता ही नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन वहां पर तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया है, यह सत्य है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की जानकारी से मुझे समृद्ध करने का प्रयास न करें। मुझे मेरे क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है।

सभापति महोदय :- अगर आप बोल रहे हैं तो उनको चुप होना होगा और अगर वह बोल रहे हैं तो आपको चुप रहना होगा, ऐसे में कोई क्या समझेगा। आप अपना भाषण दीजिए। आप क्यों बीच में बोल रही हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरे क्षेत्र की पूरी जानकारी रहती है:-

अब रोने वालों को रोने दो काम चलता जाएगा,

तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों को बस यही कहूंगा।

सभापति महोदय :- माननीय अनुज जी, एक मिनट। आप बोल लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अनुज जी, आप जिस खेल-कूद के विभाग की भारी भूमिका बांध रहे हैं और यहां तारीफ कर रहे हैं। पिछले बजट में उसी विभाग में 14 प्रतिशत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कम खर्च हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके विधायक दल में यह तय हुआ होगा कि इस बजट सत्र को कविता में उलझा कर रखना है ताकि वास्तविकता तक विपक्ष या जनता न पहुंच पाये, आपके सारे विधायक.ऐसा कर रहे हैं। केवल इन्हीं की बात नहीं है।

सभापति महोदय :- वह फिल्म स्टार है। उनका गाना, फिल्म में शूटिंग करना आम बात है। आप मेरी बात सुनिये।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, इनको विधायक दल के बारे में कैसे मालूम हुआ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं संभावना बता रहा हूँ। विधायक दल में जो तय होता है, वहां दिखता है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, यहां भावना जी नहीं है। आप भावना मत बोलिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, वहां विधायक दल में जो तय होता है वहां सदन में दिखता है।

सभापति महोदय :- वह मूलत: अपने व्यवसाय में फिल्म स्टार हैं, म्यूजिक देना, गाना, उनका अपना बैंड है तो उन्होंने बोल दिया। बाकी यहां पर कोई कविता कोई नहीं पढ़ता है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमें भी उस बात की खुशी है कि हमारे एक साथी फिल्मी दुनिया के हैं।

सभापति महोदय :- आप लोग भी कविता पढ़ सकते हैं यह भी पढ़ सकते हैं। उसमे मनाही नहीं है, लेकिन अगर लगातार होगा तो फिर विधान सभा सरीखे कहां लगेगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उनकी पीड़ा समझ पा रहा हूँ। कल उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी एक फाग गा रहे थे। उसके बाद जब छोटे भाई की ओर से जवाबी कार्यवाही आई तो ये वह दर्द कह रहा है, वह निरूत्तर होने का दर्द है। उस पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओंकार साहू :- अनुज भैया, कम से कम फाग गीत ला गा के सुना देव, हमु मन सुनबो।

सभापति महोदय :- यहां कोई गाना गाने की जगह नहीं है।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैं उनके दर्द को समझ पा रहा हूं। इस बजट की जो सबसे खुबसूरत बात है, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हमारे भाई हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई हों, सभी के लिए इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी के विकास के लिए चिंता की गई है। इतना संतुलित बजट, जिसमें सभी की चिन्ता की गई हो। अगर आप देखें तो राजिम दाई की कांस्य प्रतिमा की मूर्ति के लिए के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गिरौधपुरी, भंडारपुरी धाम के लिए मेले का बजट बढ़ाया गया है और वहां पर विकास कार्यों के लिए घोषणा की गई है। ऐसे ही हमारे जनजाति भाइयों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं।

सभापति महोदय, यह एक ऐसा बजट है, जो छत्तीसगढ़ को विकास की रफ्तार पर लेकर जाने वाला बजट है। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में अक्सर कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य है, यह हम कहते हैं और इस बजट में खास बात यही है कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, उनको शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम (पाली तानाखार) :- धन्यवाद सभापति जी। सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में वर्ष 2026-27 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ का बजट हमारे राज्य के लिए और राज्य की करोड़ों जनता के लिए आशाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ था, परन्तु यह बजट छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहा है । जिस तरीके से हम किसान की बात करें तो किसानों के लिए अनेक वायदे किए गए। जब चुनाव आते हैं तो बार-बार उन वायदों की पुनरावृत्ति होती है, परन्तु किसानों के लिए सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। समर्थन मूल्य की बात होती है, पर वह समय-सीमा पर नहीं मिलती है। जब किसानों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के खाते में पैसे आते हैं तो किसान बैंकों में लाईन में लगे हुए दिखते हैं और मेरे तानाखार क्षेत्र ऐसे-ऐसे जंगल और बीहड़ क्षेत्र हैं, उसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। जब तानाखार क्षेत्र के पसान से पैसा निकालने के लिए कटघोरा जाते हैं तो वह 100 किलोमीटर पड़ता है, उसके बाद भी उसको एक-दो दिन में पैसा नहीं मिल पाता है। इस तरीके से अव्यवस्थाएं आज भी हैं। किसानों की बात करें तो किसानों की खेती के लिए सिंचाई परियोजना की बात होती है, परन्तु आज भी बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं हमारे तानाखार क्षेत्र में अधूरे पड़े हुए हैं, नहरों की हालत जर्जर है। तानाखार क्षेत्र में सिंगल एक फसल हो रही है । निश्चित ही सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, परन्तु जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा, किसानों को बीज, खाद, दवा सस्ते दामों में उपलब्ध नहीं होगी तो किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। कृषि के यंत्र लगातार महंगे होते जा रहे हैं। इस बजट में किसानों के लिए सस्ती दवा, सस्ते खाद-बीज की घोषणा नहीं हुई है। सोसायटियों में जिस तरीके से खाद पहुंचता है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मोरगा के बारे में कलेक्टर से खाद के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। ट्रक खाद लेकर सोसायटी के अंदर जाती है और फिर से खाद भरकर वापस चली जाती है। किसानों के खाते में खाद मिलना चढ़ जाता है, लेकिन किसानों ने लिखित में शिकायत दिया है कि हमें कोई खाद नहीं मिला है। इस शिकायत पर कलेक्टर ने जांच बैठाई और बाद में वहां के प्रबंधक को निलंबित किया गया। निश्चित ही लगातार कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं। राज्य के युवा आज रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार कौशल विकास की बात करती है, परन्तुरिक्त पदों की भर्ती की समय-सीमा निर्धारित नहीं है। हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय अजय चन्द्राकर जी ने भी युवाओं के लिए एक प्रश्न लाया था। बाहर से कम्पनियां आ रही हैं, उसमें स्थानीय निवासियों को नौकरियां दी जाए। हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य भी चिंतित हैं कि यहां के युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आज प्रदेश के सरकारी विद्यालय एकल शिक्षकीय हो गए हैं। प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं होती हैं, वह एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। एक शिक्षक को पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य सरकारी काम करने पड़ते हैं। हमारा एक स्कूल शिक्षक बच्चों को पढ़ाये या सरकारी काम करे ? निश्चित ही यदि शिक्षा विद्या का मन्दिर है, हमारी नींव है, बच्चें हमारे देश के भविष्य हैं तो उनके बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना होगा। मेरा 25 तारीख को तारांकित प्रश्न लगा था, जिसमें मैंने सी.एस.आर. मद की जानकारी मांगी थी। पाली तानाखार में पाली, पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड के अन्तर्गत संकलित 88 प्राथमिक शालाएं एवं 101 पूर्व माध्यमिक शालाएं स्मार्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्लास पूर्ण किया जाना बताया जा रहा है। परन्तु कहीं भी स्मार्ट क्लास नहीं बना है, जीरो है। मैने पूरा सर्वे कराया है। कहीं कोई स्मार्ट क्लास नहीं है। खाली पेपर में स्मार्ट क्लास बताया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से माननीय मंत्री जी को गलत जानकारी देंगे तो वहां शिक्षा का स्तर क्या होगा ? निश्चित ही आज प्रदेश में जिस तरीके की बात हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, वास्तव में प्रदेश बना तब यहां का बजट 5 हजार करोड़ रूपये का था लेकिन आज 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपये का बजट है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के ऊपर प्रति व्यक्ति 66 हजार रूपये कर्ज है। वह यह दर्शाता है कि हम प्रदेशवासियों को कितने कर्ज तले दबा दिया गया है। निश्चित ही मैं कहूं तो ज्ञान की बात कहकर यह सरकार की गति धीमी हो गई है। संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ को कर्जदार बना दिया है। आज छत्तीसगढ़ राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकार विकास के नाम से उधार ले रही है और हम पर लगातार बोझ बढ़ते चला जा रहा है। यदि हम आदिवासियों के हितों की बात करें तो आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं। वर्षों से काबिज भूमि पर, एक पीढ़ी दो पीढ़ी से काबिज वन भूमि पर, उनके पुरखों के द्वारा कमायी हुई जमीन पर उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। वन विभाग के कर्मचारी उनको हटा रहे हैं, उनकी जमीन पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारा आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज छत्तीसगढ़ के विकास में, देश के विकास में अग्रणी रहा है। चाहे कोयला खदान हो, चाहे बॉक्साइट खदान हो, चाहे लोहे के खदान हो, हर जगह उन्होंने अपनी जमीन दी और उनके हिस्से में क्या आया? सरकार सर्वे करे। यदि हम बांगो डैम की बात करें तो हमारे तानाखार क्षेत्र में 56 गांव विस्थापित हुए। उन 56 गांव के विस्थापित परिवार आज किस स्थिति में हैं, सरकार ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। मछली मारने का ठेका स्थानीय समिति को न देकर के ठेकेदारों को देना। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि विस्थापित परिवार जिस जमीन से विस्थापित हुए हैं, उन परिवारों की समिति बनी हुई है, उन समितियों को मछली मारने का ठेका दिया जाए, उनका जीविकोपार्जन चलना चाहिए। निश्चित ही कोरबा जिला ऊर्जाधानी जिला है। माननीय सभापति महोदय, पर खेद है कि आज भी कोरबा जिला के बहुत सारे गांव अंधियारे में जीवन बसर कर रहे हैं। हमारा कोरबा जिला बिजली के लिए पूरे देश में जाना जाता है, अव्वल जाना जाता है। कोरबा से ही हम दूसरे जिले को रोशन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश को रोशन कर रहे हैं, परंतु बहुत से गांव आज भी अंधेरे में हैं और कोरबा जिला में हमारे तानाखार क्षेत्र में ऐसा कोई विद्युत उपकेंद्र नहीं है। कोरबा जिला से विद्युत के लिए अंबिकापुर जाती है, अंबिकापुर से वापस फिर से कोरबा जिला आती है तो मैं इस सदन में निवेदन करूंगा कि तानाखार क्षेत्र चोटिया में एक 132 के.वी. विद्युत उपकेंद्र खोला जाए, जिससे हमारे कोरबा जिलेवासियों को, तानाखार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्षेत्रवासियों को अपने जिले में ही बिजली मिले। सड़क, पेयजल, बिजली आज भी जस की तस है। कई लघु सिंचाई परियोजना आज भी वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। सूखा प्रभावित क्षेत्र, इतना बड़ा बांध होने के बाद भी आज तानाखार क्षेत्र एक फसलीय है। पूरा का पूरा पानी जांजगीर-चांपा जिला, रायगढ़ जिला, तमाम जिलों में जा रही है। आज लगातार तानाखार क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है और उस हाथी प्रभावित क्षेत्र से किसान परेशान हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने तानाखार क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, के लिए कुछ मांग करूंगा। बांगो जलाशय पर जिस तरीके से हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्वा पार्क की घोषणा की है, मैं तो मांग करूंगा कि वहां पर मत्स्य महाविद्यालय चालू किया जाए ताकि वहां पर स्थानीय लोगों को उसकी शिक्षा दें, वहां पर उनको रोजी-रोजगार मिले। साथ ही साथ उस चोटिया क्षेत्र में जो बीहड़ जंगल क्षेत्र है, वहां पर एक महाविद्यालय की भी स्थापना हो। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब बजट की बात होती है, दोनों तरफ करीब 5 से 7 साल इधर सरकार में बैठने वाले हैं, 15 से 17 साल बैठने वाले इधर वाले हैं। अब दोनों आरोप-प्रत्यारोप में रहते हैं। मैं तो इधर वाला हूं। मैं किधर बोलूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। उधर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जगह में सुरक्षित हूं। माननीय सभापति महोदय, बस इतना ही कह कर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- देखिए, सभी लोगों से निवेदन है कि इस चर्चा को जल्दी समाप्त करना है। आप सब के लिए निवेदन है कि आप सब सहयोग प्रदान करें। मैं आपको बुलवाऊंगा और आपको यह आग्रह करते हुए बुलवाऊंगा कि आप ज्यादा भूमिका वगैरह में मत रहिए, सीधे अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए। 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कम शब्दों में अपनी बात को रखूं।

सभापति महोदय, मैं वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के विषय पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का यह जो बजट, उसमें हम लोगों की गहन समीक्षा के बाद हमारे सामने एक बात स्पष्ट है कि बजट राज्य की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप नहीं दिखता है। उसमें घोषणाएं अधिक हैं, लेकिन वित्तीय स्पष्टता और दीर्घकालिक विकास की ठोस दिशा का अभाव है। माननीय सभापति महोदय जी ने अपने-अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए कहा है। माननीय मंत्री जी, मैं जरूर अपने क्षेत्र की बात रखूँगी। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास की भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बात आई है और उसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। 18 लाख आवास के बाद अब उसको बढ़ाकर 26 लाख किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे एक निवेदन करती हूँ कि हमने बजट में आवास की संख्या तो बढ़ाया है, लेकिन क्या आवास में मिलने वाली राशि को बढ़ावा दिया है? वर्ष 2017 से 1,20,000 रूपये ही मिल रहे हैं और आज वर्ष 2026 आ गया, लेकिन वह राशि 1,20,000 रूपये ही है। जबकि निर्माण सामग्रियों का जो रेट बढ़ गया है। माननीय मंत्री जी, इसलिए मैं आवास की राशि को बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले हम वित्तीय स्थिति पर ध्यान दें तो पिछले वर्ष सरकार राजस्व अधिशेष की बात कर रही थी और इस वर्ष 2000 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा सामने है। राजकोषीय घाटा 20,400 करोड़ रूपये तक पहुँच चुका है। पूँजीगत व्यय घटकर 15.4% रह गया है। जब कैपेक्स घटता है, तब अधोसंरचना, उद्योग और रोजगार प्रभावित होते हैं। माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रूपये की 'कृषक उन्नति योजना' घोषित की गई है, परंतु इसमें कर्ज राहत, MSP की कानूनी गारंटी और लंबित फसल बीमा दावों के त्वरित भुगतान पर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हम पिछले बजट की बात करें। मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूंगी। पिछले बजट में हमारे क्षेत्र के जो कार्य शामिल हुए हैं, उनकी प्रशासकीय स्वीकृति आज तक नहीं मिल पाई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो जांजगीर से रायपुर तक को जोड़ता है। माननीय मंत्री जी उस सड़क से बखूबी अवगत हैं। यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी भी और यहाँ के ज्यादातर सदस्य उस डोंगा-कोहरौद सड़क से अवगत हैं। माननीय मंत्री जी, डोंगा-कोहरौद सड़क के लिए आज से 4-5 साल पहले 4 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान था। 5 करोड़ में ही, जहाँ पर प्रशासकीय स्वीकृति की जरूरत न पड़े, उसी राशि से में उसको पूरा कर दीजिए, लेकिन उसको पूरा कर दीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और एक और शिवरीनारायण खरताल सड़क है, जो 18 किलोमीटर का है, जिसमें 15 गाँव आते हैं। अभी आप शिवरीनारायण गए थे, जहाँ खरौद के कॉलेज में आप मुख्य अतिथि थे। आपने वहाँ पर लोगों को शायद बोला है कि इसको बजट में दोबारा जुड़वाया जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति दी थी, लेकिन यह सरकार आते ही उसको मितव्ययिता सूची में डाल दिया था। चूंकि फिर से वह बजट में जुड़ा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्रशासकीय स्वीकृति के लैप्स होने के प्रक्रिया के पहले उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दे दीजिएगा। माननीय सभापति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, महिलाओं के नाम पर 8,200 करोड़ रूपये का प्रावधान है, किंतु सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक स्वावलम्बन पर ठोस संरचनात्मक पहल कम दिखती है। युवाओं के लिए CG-ACE जैसी योजना में 33 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान बेरोजगारी की व्यापक समस्या के सामने अपर्याप्त है। लाखों युवा अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु समयबद्ध भर्ती और उद्योग आधारित रोजगार सृजन की स्पष्ट रणनीति नहीं दिखती है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है, परंतु उनकी समय सीमा और क्रियान्वयन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। केवल स्वीकृति पर्याप्त नहीं है, परिणाम भी आवश्यक हैं। माननीय मंत्री जी ने बजट में पाँच नए मिशनों को शामिल किया है। AI, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन इनके लिए आवंटन और क्रियान्वयन की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न है। माननीय सभापति महोदय, कोई भी मिशन तभी सफल होते हैं, जब उनके साथ संस्थागत क्षमता और स्पष्ट लक्ष्य जुड़े हों। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के रूप में हमारा उद्देश्य केवल आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि बेहतर दिशा सुझाना है। राज्य को मजबूत पूँजीगत निवेश, कृषि सुधार, युवाओं के लिये रोजगार सृजन, आदिवासी अंचलों के लिये विशेष पैकेज की आवश्यकता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये ठोस और संरचनात्मक कदम उठाये जाने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में शिवरीनारायण को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है, जबकि धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में शिवरीनारायण महोत्सव इतना फल-फूल रहा है, लेकिन बजट में कहीं प्रावधान नहीं है । मैं इस चर्चा के दौरान एक बात कहना चाहूँगी कि इस बार माननीय हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों को, मंत्रियों को, शिवरीनारायण के हमारे मेला समिति के लोग निमंत्रण देने आये थे, लेकिन किसी के पास भी एक दिन जाकर उपस्थिति देने का समय नहीं मिला और यह पहला वर्ष है कि शिवरीनारायण में मेला तो हुआ लेकिन महोत्सव नहीं हो पाया । मैं माननीय मंत्री जी से शिवरीनारायण को विशेष ध्यान देने की बात कहूँगी। माननीय मंत्री जी ने पामगढ़ विधान सभा में पी.डब्लू.डी. विभाग के 8 सड़क और इरिगेशन के 8 नहर को जोड़ा है, मैं इसके लिये धन्यवाद देती हूँ। मेरा विशेष आग्रह है कि प्रशासकीय स्वीकृति दे दिया जाये। यह विपक्ष के किसी विधायक का काम नहीं है, जनता से जुड़ी हुई सुविधाओं को देखते हुये हम जनता की मांग को लाकर रखते हैं, जनता को यदि सुविधा मिल जाती है, कोई भी विधायक उसको लेकर अपने घर पर नहीं जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान स्वरूप में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह बजट राज्य की संभावनाओं के अनुरूप नहीं है इसलिये हम इस बजट का विरोध करते हैं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, चूँकि कम शब्दों में बोलने के लिये कहा गया था तो मैं सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा किसान हितैषी योजनाओं पर पिछले दो वर्षों से बजट में जो प्रावधान है वह हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके खर्च की रफ्तार बहुत ही धीमी है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने बजट के कार्यों के लिये प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रश्न लगाया है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि पिछले बजट का प्रशासकीय स्वीकृति अब तक नहीं मिला है और फिर हमारा बजट आ गया है । मैं इस बजट का विरोध करती हूँ, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा का बजट वर्तमान सरकार द्वारा 1,72,000 करोड़ का बजट जो प्रस्तुत किया गया है, यह निश्चित ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं । इस बजट में गति और ज्ञान के बाद संकल्प के माध्यम से केवल छत्तीसगढ़ की दुर्गति है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मुंगेरी लाल कोने गा बता?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उही डार हे, जेन सपना देखाय हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सपना तो आप मन देखाय हव।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ना-ना, सपना वो डाहर ले देखाय हे 1,72,000 करोड़ के। वोखरे ऊपर बात करथंव माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। मत दव चलही ।

सभापति महोदय :- आप भाषण दीजिए ना, आपस में बात क्यों कर रहे हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं नइ करथंव । वही डाहर बोलिन हे।

सभापति महोदय :- बोलियेना, पांच मिनट का तो टाईम मिला है । समय खराब कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और उसके पहले मैं किसानों के संबंध में बात करना चाहूँगा । माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी, समर्थन मूल्य और सिंचाई सुविधाओं को लेकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो परिस्थितयां आज पूरे प्रदेश में निर्मित है, उसमें किसानों को तीन तरह से परेशान किया गया है। सबसे पहले समय पर खाद नहीं देना । खाद्य की आपूर्ति को लगभग ठप्प कर दिया गया है ताकि खाद मत मिले, उनका उपज भरपूर मत हो और वह परेशान रहे। माननीय सभापति महोदय, एग्री स्टेक के नाम से किसानों को ठगने का काम किया गया है और लगातार किसान परेशान होते रहे हैं । पंजीयन के नाम से घुमाते रहे हैं और उसके बाद जब खरीदी की बात आई तो समर्पण और टोकन का समय पर नहीं कटना।

समय : 3.55 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

किसानों के घर में उच्चाधिकारियों का निर्देश, तहसीलदार जा रहे हैं, नायब तहसीलदार जा रहे हैं, आर.आई .जा रहे हैं, पटवारी जा रहे हैं, यहाँ तक सिंचाई विभाग के कर्मचारी को लगा दिया गया, शिक्षकों को लगा दिया गया। सभापति महोदय, ये क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में किसान चोर? उन्हें अपने उपज के मूल्य के लिए, बेचने के लिए संघर्ष करना पड़े। क्या किसान इसी उम्मीद से अपने खेत में धान लगाया था? विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब किसान मज़बूत और समृद्ध होंगे, आपका किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम कितना प्रभावी हुआ, अभी धान खरीदी के समय हमने परिलक्षित कर लिया। माननीय सभापति महोदय, तय समय में धान की खरीदी नहीं हुआ। आपने पंचायतों में भुगतान की घोषणा की थी, वह भी वैसी की वैसी रह गई, अभी तक लागू नहीं हुई। क्या ये 2047 तक का विजन आपका पूरा होगा? क्या इसीलिए आपने निर्धारित लक्ष्य को रखा है? एक बड़ी विसंगति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आई है, जिस पर मैं समझता हूँ शायद किसी ने अपनी बात नहीं रखी है। ये किसानों और दोनों सरकारों की जेब में डाका डालने वाली योजना है, क्योंकि आपने देखा है, 2024 में कुल 14,95,800 किसानों के फसल का बीमा करवाया गया था और वर्तमान में 16,17,572 है। अभी वर्तमान में जो बीमा की राशि है, अगर रकबा के हिसाब से देखें तो 20,05,251 हेक्टेयर है और उसमें कुल प्रीमियम राशि जो किसानों द्वारा, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा 1402 करोड़ 29 लाख रुपये दी गई और मात्र 2 करोड़ 70 लाख रुपये ही क्षतिपूर्ति दावा राशि बतौर 4,711 किसानों को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों ने प्राप्त राशि की अपेक्षा 1,399 करोड़ 59 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम के रूप में यह राशि निजी बीमा कंपनियों को दी है। ये पूरा पैसा बीमा कंपनियों के, निजी जो हैं, उनके खाते में चला गया। अब ये पैसा कहाँ जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि सरकार उपक्रम करते, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के पास होती तो यह पैसा सरकारी कोष में जमा होता लेकिन ये एक खेल है कि हम निजी बीमा कंपनी को देकर किसानों के हक में डाका डालने का काम कर रहे हैं। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में वनाधिकार का पत्र जारी हुआ है। वनाधिकार पत्र जारी करने में छत्तीसगढ़ सरकार अव्वल स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर वनाधिकार पट्टाधारी किसान का धान समय पर नहीं खरीदना, उसे परेशान करना, डेढ़ माह तक धान बेचने के लिए वे इधर-उधर घूमे हैं। लगभग डेढ़ माह तक घूमे हैं, उसके बाद धान की खरीदी हुई। तब तक आदिवासी क्षेत्रों में मेला लगता है, मड़ई लगती है, उसके लिए उन किसानों को ज़रूरत के लिए कुछ लेना पड़ता है। फिर वे व्यापारियों से कर्ज लेते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- चिंता मत कर, कल 10,000 करोड़ रुपये पूरा किसान मन ला देवत हन। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं वही तो कह रहा हूँ कि कर्जा ले डरे हन, कर्जा ला चुकाही का? मेला-मड़ई के चक्कर में कर्जा ले हे बेचारा मन। ये निश्चित ही आपकी खरीदी पर होने वाले अव्यवस्था के कारण हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा, आपने बजट भाषण में शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 500 आंगनबाड़ी भवन हेतु निर्माण अभिसरण के माध्यम से प्रावधान किया है। अभी तक अभिसरण मनरेगा योजना से दिया जाता था जिसे आपने बंद कर दिया। अब अभिसरण किस मद से होगा इसे भी बताना पड़ेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी राम जी से होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी राम जी के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- 2800 करोड़ की जगह में 4000 करोड़ का प्रावधान किया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह तो सबके लिए है। मैं स्पेशली उसी के लिए बता रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री आशाराम नेताम :- निषाद जी, 100 दिन के 125 दिन कर दिए हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी कइसे होही तेला देखबो न ग। अभी 40 प्रतिशत राशि जमा करहू न पता चल जाही। 50 प्रतिशत मैचिंग ग्रांट ला जब राज्य सरकार जमा कर लेही तब केन्द्र सरकार तोला पैसा दिही, अइसे मत समझ।

श्री आशाराम नेताम :- हमारी गारंटी है, 15 दिन में नहीं मिलेगा तो हम उसका ब्याज देंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- 100 दिन के पैसे को दे नहीं पा रहे हो, 125 दिन का कहाँ से दोगे? एक-एक साल की सामग्री के पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है।

समय : 4.00 बजे

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग की बात करे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट। मंत्री जी, महत्वपूर्ण विषय है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में रोजगार सहायक के नीचे जो भी आपके आवास मित्र हैं, वह गरीबों को ऑनलाइन में लूट रहे हैं। 10,000-20,000 रूपये ले रहे हैं, तब वह ऑनलाइन कर रहे हैं। कृपया इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें रोक लगनी चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में आपने जितनी आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी, उनकी राशि अभी तक जिला कार्यालय तक नहीं पहुंची है। वह अभी तक अटका हुआ है और अधूरे निर्माण हुए हैं। जो निर्माण हो गए हैं, उसके पैसे अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। निश्चित ही मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य विभाग की फ्री इलाज की सुविधा की घोषणा तो करते हैं, परन्तु हर बार योजना का नाम क्यों बदल देते हैं? पहले वह संजीवनी योजना थी, फिर आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, फिर आपने मोदी जी का प्रचार करने के लिए उसको प्रधानमंत्री आरोग्य योजना कर दिया और इस साल फिर नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- उस समय आपके स्वास्थ्य मंत्री जी थे तो वह एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाये थे। उसकी एकाध कुछ है? आपके उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लायेंगे। उसमें यू टर्न मार गये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं आपकी 4-4 योजनाओं का बता रहा हूं। क्या आप लोग इसीलिए योजना का नाम बदल रहे हैं? 4-4 नाम बदल गये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसके नाम से कोई नया खेल तो नहीं होगा? फिर हितग्राहियों को नए कार्ड तो नहीं बनवाने पड़ेंगे? स्कीम चेंज होगा तो शहीद वीर नारायण सिंह लिखाएगा, फिर नाम चेंज होता तो कैसे नहीं बनेगा? इस पर भी आपका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह जी, समाप्त करें। आप समय देखिये, बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अभी तो मैं चालू करे हो।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो बहुत पुराना हो गया है। विधायक जी, लगता है कि आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, मे जाथो।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यह बहुत पुराना है। तोला कइसे पता नहीं चलत हे? हमन शुरू में आए हन ता करे हन। सबके कार्ड बन गेहे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं चौथा के बात करे हो। माननीय सभापति महोदय, मेकाहारा में एडवांस कार्डियक यूनिट की सुविधा के विस्तार हेतु AI के उपयोग हेतु 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। अब यदि एडवांस कार्डियक यूनिट के बिस्तर में जाकर देखहूं ता अतका ढेकना होगे, जेखर सीमा नहीं हे। एकाध दिन सूत के देख लो ता वहां के सुविधा के बारे में पता चल जाही कि कइसे हे। साथ ही मैं यही बात कहहूं कि मोर परिवार के 2-3 मन भर्ती रीहिन ता मैं ओमन ला देखे बर गे रहे हव।

श्री केदार कश्यप :- ओ तोला देख के कीहिस होही कि ए कहां ले चूसीस हे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, मैं देखेल गे रहे हव। मैं रात-रात को गे रहे हव, तेखर सेती मैं बतात हो। रही बात प्रदेश की सड़कों की हालत तो फिर माशाअल्लाह है। मैं अपना विधान सभा क्षेत्र के बतता हो, बाकी अउ बताहुं। साल भर में दो बार चक्काजाम होगे। चक्काजाम के बाद आश्वासन मिलीस कि जनवरी में बन जही। नहीं बनीस ता अभी फरवरी में फेर चक्काजाम होइस, फिर आश्वासन दे हे कि एक-डेढ़ महीना के अंदर बन जाही।

श्री रिकेश सेन :- ते पिछले 5 साल में काबर नहीं बनवाएस?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं ओखर उखड़े के बाद के बात करत हो।

श्री रिकेश सेन :- अच्छा, ओ उखड़ गे ता फेर जांच कमेटी बनाना पड़ही।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तोर सरकार मा बने रीहिस हे।

सभापति महोदय :- समाप्त करें। चैतराम अटामी जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आज अमूमन यह स्थिति हे। आज जेन सड़क मन ला प्रशासकीय स्वीकृति दे के बात होत हे ता माननीय वित्त मंत्री जी हा बइठे हे। मैं आपसे आग्रह भी करहूं अउ निवेदन भी करहूं। बड़ा अकन हे, मैं ओला लिख के दे देहूं।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें। आपको 15 मिनट हो गये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं तो अभी कुछ बात नहीं करे हव। अभी मोला 5 मिनट नहीं हो हे। मोला थोड़किन बोलन तो दे। बीच-बीच में मोर दू-तीन ठन बात हा रही गे। मोला बहुत विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण बात करना रीहिस हे, ओला मैं नहीं कर पाए हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहहूं कि नई उद्योग नीति में जेन पर्यटन के बढ़ावा ऊपर बात करे गेहे, नई उद्योग नीति में पर्यटन उद्योग को दर्जा देने के कारण होम स्टे के माध्यम से विदेशी लोग बस्तर के गांवों में रूकेंगे।

सभापति महोदय :- आपके यहां कुछ नहीं है। सब दलेश्वर जी के यहां हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं, आप सुनिये। मैं संस्कृति से जुड़े हो, तेखर सेती बोलत हो कि ओ परंपरा ला मैं करीब से देखे हो, तेखर सेती बोलत हो। होम स्टे के माध्यम से जब लोग बस्तर के गांवों में रूकेंगे और वहां के लोगों के साथ रहेंगे तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विदेशी संस्कृति का प्रभाव बस्तर के जनजीवन पर पड़ेगा। मैं सीधा-सीधा बता रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं कि पश्चिम फाइल जैसा खतरनाक खेल भी बस्तर में प्रारंभ हो सकता है। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- क्योंकि वह भोले-भाले आदिवासी हैं। घोटुल उनकी एक संस्कृति है, जिसको आज हम लोग लीव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। वह सदियों से चला आ रहा है, उस सभ्यता और संस्कृति का क्या होगा? संस्कृति के माध्यम से उनकी संस्कृति विपरीत हो जाती है। क्योंकि उस संस्कृति को मैंने करीब से देखा है। उनके साथ मुझे रहने का भी अवसर मिला है।

श्री आशाराम नेताम :- निषाद जी, इसीलिए तो बस्तर में बस्तर पंडुम शुरू किये हैं।

सभापति महोदय :- अभी अशासकीय कार्य भी है। इसलिए आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मुझे एक बात और बोलना है।

सभापति महोदय :- आपने एक बोला था और आप अपनी एक बात बोल लिये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, इसी सदन में वर्ष 2014 में मैं बात करे रेहेव।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, यह गलत व्याख्या है। (व्यवधान) हमारा घोटुल नहीं है।

सभापति महोदय :- देखिये, अशासकीय संकल्प का समय पूर्ण हो गया है।

श्री आशाराम नेताम :- घोटुल हमारा संस्कृति केंद्र, हमारा धार्मिक केंद्र और हमारी आस्था का केंद्र है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी घोषणा करें रिहीन कि 33 हजार शिक्षक के भर्ती होही और जेमा छत्तीसगढ़िया पढ़े हन, तेन मन डिग्री और डिप्लोमा लिए हैं, तेकरो मन के भर्ती हुई। लेकिन आज तक आश्वासन मिले के बाद एक ठन शिक्षक के घलो भर्ती नहीं होए हे। ए में भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जल्दी हो सके तो शिक्षा कर्मी मन के भर्ती करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निषाद जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- चैतराम अटामी जी।

श्री आशाराम नेताम :- तै विदेशी मन के बात करे हस तो तोला विदेशी मन से एलर्जी हे का बता तो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मोला ओकर मन से कोई एलर्जी नहीं है, ओकर जो कार्ययोजना चलत हे, तेकर बर एलर्जी हे। में तो अतका कहू कि गोधन योजना, मनरेगा, ये बात जेन बोलत हे। में हर बस यही कहना चाहूं ।

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बजट के विषय पर बोलने का मौका दिया है। हमारे विषणुदेव..।

सभापति महोदय :- अब आप बैठ जाईये। मनरेगा में हो गया है, आप बैठ जाईये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, में हर एक और बात करना चाहत हव।

सभापति महोदय :- हो गया। आप एक बात में तीन बात कर लिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, में हर अतका कहना चाहूं कि हमन छत्तीसगढ़िया हन अउ मनरेगा जेन छत्तीसगढ के आत्मा रिहीस ओला बदल के जेन करना चाहत हव, कर देओ अलग बात नहीं। लेकिन वी.बी. ग्राम जी ला राम जी के नाम से मत कहो, काबर कि राम जी के नाम से बहुत अकन बात हो गे हे। आज हमन राम के महत्व के बारे में अतका जानथन कि सबो छत्तीसगढ़िया मन ला राम के प्रति आस्था और विश्वास है। तन में राम, मन में राम और राम-राम के दोनों मन के नाता राम। राम बसे सबके हृदय, सबके भाग्य विधाता राम, राम रसे रटना निस बारन कोटी पंडित भांचा राम।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में हमारे वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी जी ने 1 लाख 72 हजार रूपये का बजट पेश किया है। जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अरे सबके बर तो राम भगवान हमर मन बर छत्तीसगढ़िया मन बर भांचा राम। सबके भक्त हो, राम बोले तो हमर मन बर छत्तीसगढ़िया मन बर भांचा राम। माननीय सभापति महोदय, मैं हर बस अतका कहना चाहूं। सभापित महोदय, मोर बात ला दबाये के कोशिश कर देत हव तो का बात ला कर सकत हन। जेन स्पष्ट बात आना चाहिए, ओ बात नहीं आये अउ हम बात नहीं रख सकन तो कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपके बात के विरोध करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, मैं दंतेवाड़ा जिला से आता हूं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक विषय है। माननीय सदस्य जिस तरीके से आसंदी पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहे हैं कि उनकी बातों को दबाया जा रहा है। आपकी बात को कौन दबा रहा है ? आप तो बोल रहे थे ना। आसंदी ने जब चैतराम जी को बोलने की व्यवस्था दी है तो उसके बाद वही बोलेंगे।

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं दंतेवाड़ा जिला से आता हूं इसलिए मुझे दंतेवाड़ा क्षेत्र के बारे में मालूम है। इतने वर्षों से दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवाद के कारण पूरे क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं होता था। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर और हमारे गृहमंत्री विजय शर्मा जी ने संघर्ष करते हुए आज देश के हमारे यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी के संकल्प में हमारे प्रदेश के गृहमंत्री नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ते हुए आज नक्सली खत्म करने की ओर है। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला के नीचे एक ऐसा गांव हैं, जहां आजादी के बाद से आज तक कोई भी वहां पर नहीं गया है और अभी 13 फरवरी को मैं 17 किलोमीटर पैदल जाकर पहाड़ी चढ़ के उतर कर वहां गया और वहां की स्थिति देख कर आया। वास्तव में आज तक सरकार की कोई भी योजना वहां नहीं है। वहां के बच्चे स्कूल नहीं देखे हैं, आंगनबाड़ी नहीं देखे हैं और सरकार की कोई भी योजनाओं को नहीं देखे हैं। हम वहां पर सारी व्यवस्था पहुंचाकर आ गए, वह ऐसा क्षेत्र है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- विधायक जी, आप जो बता रहे हैं वहां 17 साल में कैसे कुछ नहीं हुआ ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री चैतराम अटामी :- वहां 17 सालों में कैसे कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं। सुनिये। वहां पर नक्सली थे। मैं जहां गया था, वहां चारों तरफ नक्सली थे तो नक्सलियों के बीच में कौन जाएगा? किसी के जाने की बात नहीं है। वहां तो अपने रिश्तेदार के घर में भी कोई नहीं जा सकता था। ये स्थिति थी। हमारी बेटी अगर अबूझमाड़ में गई है तो वहां पर हम नहीं जा सकते थे। उसका बाप भी नहीं जा सकता था। वहां ऐसे स्थिति था। इसलिए वहां कोई नहीं गया। मैं पहली बार नक्सली खत्म होने के कारण वहां जाकर आ गया हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- मामा, दादी से पूछिये कि कैसे कोई नहीं पहुंचा।

श्री आशाराम नेताम :- उधर जमानत करवाते थे।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूं। मैं ओ.पी. चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि वे समय तत्कालीन कलेक्टर रहे (मेजों की थपथपाहट) और उन्होंने वहां छू लो आसमान की स्थापना की। उस छू लो आसमान, पोटा केबिन और एजुकेशन हब सिटी, शायद हमारे दंतेवाड़ा जिला में प्रदेश का पहला सेंटर है। जब 'छू लो आसमान' शुरू हुआ, तो मैं बता दूँ उस 'छू लो आसमान' के कारण वहां पढ़ने वाली बेटी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम आई है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे दंतेवाड़ा जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में एक छात्र छठवाँ नंबर रैंक में आया है। यह हमारे यहाँ शिक्षा का क्षेत्र है। वहां पर ओ.पी. चौधरी जी ने इतनी अच्छी शुरुआत की है। मैं सदन को यह भी अवगत करा दूँ कि उसके बाद हमारे यहाँ से आई.ए.एस. निकले। आज एक बेटी कलेक्टर बनी बैठी है। (मेजों की थपथपाहट) एक बेटी आई.एफ.एस. बनी है और उसके बाद एक बेटी पायलट बनी है। हमारे यहाँ एजुकेशन होने के बाद लगातार हमार क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहा है।

सभापति महोदय, यदि मैं विकास की बात करूँ तो जैसे ही नक्सली खत्म हुए तो हमारे गृहमंत्री के मार्गदर्शन पर 'नियद नेल्लानार' बनाया गया है और 'नियद नेल्लानार' के नाम से हम उन क्षेत्रों में काम शुरू किए हैं, जहाँ पहले प्रशासन कोई काम नहीं करता था। उन क्षेत्रों में 'नियद नेल्लानार' के नाम से पुल बनाना, रोड बनाना और पहले रास्ता बनाने का काम किए हैं। आज हमारा दंतेवाड़ा बहुत तेजी से विकास की ओर जा रहा है।

मैं 'बस्तर ओलंपिक' के बारे में बताना चाहता हूं। हम एक-दूसरे गाँव के लोगों से नहीं मिलते थे। इसी उद्देश्य से 'बस्तर ओलंपिक' की शुरुआत की गयी है और उस ओलंपिक में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नक्सलगढ़, अबूझमाड़ क्षेत्र के अंदरूनी गाँव के युवा और युवती भाग लिए हैं। सबसे पहले वहां वर्ष 2024 में 1,65,000 पंजीयन किये गये। उसके बाद जब अभी दोबारा हुआ तो वहां 3,90,000 पंजीयन करके हमारे बस्तर ओलंपिक को आगे बढ़ाए है। जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 'मन की बात' में भी इस ओलंपिक की चर्चा की है।

मैं बस्तर पंडुम के बारे में बता दूं। यहाँ लखमा दादी कल बोल रहे थे अभी आम पंडुम आने वाला है। मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है। बस्तर में पूरे साल भर पंडुम होता है। मई महीना से बीज पंडुम शुरू होता है और लगातार होता है। उसके बाद आम पंडुम होता है, महुआ का पंडुम होता है, हम सेमी खाते हैं, उसका पंडुम होता है। यह सारे पंडुम होते हैं इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारी पंडुम की परंपरा खत्म न हो।

श्री लखेश्वर बघेल :- विधायक जी, उस दिन जो पंडुम मनाये तो वह कौन सा पंडुम मनाए थे ?

श्री चैतराम अटामी :- मैं बता रहा हूं। आप सुनिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- वह विकास पंडुम है और वह आगे भी चलता रहेगा।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय विष्णु देव साय जी ने, हमारे पंडुम धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, आज का पढ़ा-लिखा जनरेशन वहां पंडुम में नहीं जाता है और इतना अच्छा पंडुम मनाते हैं, हर प्रकृति को मानते हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग प्रकृति पूजक होते हैं । इसलिए इसका दुनिया में प्रचार-प्रसार हो इसलिए 'पंडुम उत्सव' मनाया गया है।

श्री लखेश्वर बघेल :- लेकिन विधायक जी, हमारे बस्तर में तो तिहार मनाते हैं। हम लोग पंडुम जानते ही नहीं हैं। हम लोग बस्तर में तिहार मनाते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यह पहली बार हे कि आप मन आदिवासी दिवस नहीं मनाये हन। आप मन क्या बात करते हो ?

श्री चैतराम अटामी :- तिहार, मैं वह भी बता देता हूं। मैं दंतेवाड़ा की बात करता हूँ। मैं दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की बात करता हूँ। हम उधर भी आमुस तिहार मनाते हैं और नवा तिहार मनाते हैं। आप उसको सुनिए कि तिहार अलग होता है और पंडुम अलग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होता है। ऐसे लोग मिले और हमारे पंडुम का पूरे दुनिया में प्रचार हो, इस उद्देश्य से उसको उत्सव का नाम दिया गया है। ऐसे पंडुम मनाते हैं। क्या आप शहर के लोग वहां जाएंगे ? हम जब आमा पंडुम मनाते हैं, आम का पंडुम मनाएंगे तो वहां कौन जाएगा? इसलिए शहर में उनको बुलाकर दिखाया जाता है कि यहाँ के आदिवासी इस प्रकार पंडुम मनाते हैं। इसका प्रचार करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। (मेजों की थपथपाहट) यह पंडुम है और कई लोग पंडुम को नहीं जानते, उन्हें जानना चाहिए। लोगों को वहां देखने जाना चाहिए। आप लोग तो पंडुम में नहीं आए हैं तो आप कहाँ से जानेंगे? आप कम से कम पंडुम में आए होते तो आपको मालूम होता कि कैसे पंडुम मनाते हैं।

श्री आशाराम नेताम :- लखेश्वर भईया, जो बस्तर का नहीं है वह पंडुम को नहीं जानता, जो बस्तर का होगा, वह जानता।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम बापू जी, आदिवासी दिवस नहीं मनाये हैं। आप लोग क्या बात करते हैं?

श्री चैतराम अटामी :- कौन बोलता है? रामकुमार जी, हम आदिवासी दिवस मनाये हैं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- आप लोग यह बताईये कि बिरसा मुंडा जी की जयंती में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हो या नहीं मनाते हो?

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब जी, क्या आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी दिये थे ? आप लोग तो होली के दिन दारू बेचने वाले हो, दारू वाले बाबा, क्या कहोगे ?

श्री आशाराम नेताम :- आपको पीना है तो आप जाओ न। आपको पीना ही नहीं है तो दारू दुकान का मतलब क्या है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, अभी रामकुमार यादव जी बोल रहे थे कि आदिवासी दिवस नहीं मनाये। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के नाम से दिवस घोषित किया है, छुट्टी मिली है। हम सब मिलकार ये दिवस मनाते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग आदिवासी नहीं, वनवासी बोलते हैं। आप लोग आदिवासी का अपमान करते हैं, आप लोग क्या बात करते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जनक ध्रुव :- वन में तो शेर, भालू और चीता भी रहता है। सब वनवासी शेर, भालू, चीता हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य :- वनवासी कौन भैया ?

श्री चैतराम अटामी :- मैं उसका अर्थ भी बता दूंगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, संविधान के दस्तावेजों में जनजातीय समाज लिखा हुआ है।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, वनवासी उसको बोलते हैं जो जंगलों में रहते है, वनों में रहते हैं, उनको वनवासी बोलते हैं। शहर में रहते हैं उनका आदिवासी बोलते हैं। अगर सीखना है तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे से सीखो किसको आदिवासी, किसको वनवासी बोलते हैं। .. (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आपस मे हम दोनों का डिबेट हो जाये।

श्री आशाराम नेताम:- रामकुमार जी, तय चादर में रहकर का जानबे, बस्तर में आकर देख लेव, आदिवासी और वनवासी के अंतर समझ आ जाही।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, ये प्रदेश में आदिवासी समाज के आंदोलन सबसे पहले मैं करे रहेंव। आप मन देख सकथव, सबसे पहली मैं लड़न वाला हवं।

श्री आशाराम नेताम:- तैं यादव हा, कब आदिवासी ला संघर्ष करबे।

श्री अनुज शर्मा :- तैंहा कभू कहथस लड़ने वाला हवं, कभू कहथस छेरी चलाने वाला हवं।

श्री रामकुमार यादव :- और समय पड़थस तो हिरण मन घलव चराने वाला हयेन हमन।

श्री जनक ध्रुव :- आदिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी कहलायें हैं और जंगल में रहने वाले लोग वनवासी कहलायें हैं। माननीय सदस्य को इस बात को ध्यान रखना चाहिए।

श्री चैतराम अटामी :- वही बात तो बोला, आप सुने नहीं हो। वनों में रहने वाले वनवासी हैं, आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं। आदिकाल से कौन-कौन रहता है ? रामकुमार यादव जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी आता है, वह भी आदिवासी में आयेंगे। वह भी आदिकाल से रहते हैं। वहां पर ठाकुर हो, यादव हो, हर कोई आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं।

श्री अनुज शर्मा :- अटामी जी, मेरा एक निवेदन है अब आदिवासी समाज में ही देख लीजिए न। आज आप रामकुमार यादव जी को बोले हैं।

श्री चैतराम अटामी :- वह भी आदिवासी में आयेगा।

श्री रामकुमार यादव :- तोर मुख्यमंत्री पद खतरा में आ जाही मै जब आदिवासी बन जाहव ता।

श्री सुशांत शुक्ला :- तैं इतना रहीस हे कि दू पत्ता आगे, दू पत्ता पीछे, झींगा ला ला हू करत घूमत रहितस।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मेडिकल कालेज को शुरूआत करने के लिये 50 करोड़ रुपये बजट में जोड़ा गया है जिसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में नया थाना खोलने के लिये जोड़ा गया है, उसके लिए भी वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। सभापति महोदय, मुझे बहुत कम समय मिला है, मैं नया हूं, पहली बार बोला हूं।

सभापति महोदय :- लेकिन आप पहली बार बोले हैं, अच्छा बोले हैं।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप थोड़ा समय की सीमा है तो मैं आपका संरक्षण भी चाहूंगा।

सभापति महोदय :- अशासकीय संकल्प भी है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मुख्य बात आ जाये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए अपने आपको आंकड़े और पालिसी तक ही सीमित रखूंगा और आपके माध्यम से मैं आदरणीय वित्त

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंत्री जी से चाहूंगा कि वह बात को सुनें। उन्होंने अपनी बात की शुरूआत एक बहुत ही सुंदर कविता से की थी तो मैं भी दो पंक्ति पढ़ देता हूं।

ना तालियों की गूंज से, न शब्दों के श्रृंगार से

मैं सच की सादी धरती पर जनता के आशीर्वाद से आया हूं

जो अंकों में सपने बुनते हैं, मैं हालात दिखाने आया हूं

जो बजट में नहीं दिखता, वह दर्द सुनाने आया हूं।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का सफर 5 हजार करोड़ रुपये से आज 1 लाख 72 हजार करोड़ पर हम आ गये हैं। यहां पर लगातार योगदान की बात होती है, हमने बनाया, किसी ने बनाया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये पीढ़ियों से हमारा छत्तीसगढ़ रहा है, किसी एक व्यक्ति को इसका शिल्पकार नहीं माना जा सकता। हमें आज उन पीढ़ियों को भी धन्यवाद देना होगा जिन्होंने यहां की जल, जंगल, जमीन और जितनी हमारी समृद्ध खनन सपंदायें हैं, उसको बचाकर रखा हुआ है, हमारी नदियों को बचाकर रखा हुआ है, हमारी छत्तीसगढ़ अस्मिता को बचाये हुए हैं।

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष

सभापति महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत अच्छी बातें भी कही । एक वरिष्ठ सदस्य उसके बाद अपने भाषण में कह रहे थे कि बजट दशा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और दिशा तय करता है, मैं उनकी बात से सहमत हूं । हमारा बजट हमारा प्रतिबिम्ब भी है, बहुत सारी बातें आयीं, मैं तो डिटेल में जा रहा था लेकिन संक्षेप में कह देता हूं । बस्तर की बात आ रही थी, जहां पर विकास की, नक्सलवाद की और शायद 31 मार्च को फोर्सेस वापस हो जायेंगी ऐसा बोला नहीं गया लेकिन भाषण से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सब कुछ जब खत्म हो जायेगा तो फोर्सेस वहां से वापस चली जायेंगी । माईनिंग की बात भाषण में नहीं आ पायी लेकिन जब हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो एक लंबा-चौड़ा आंकड़ा माईनिंग का वहां से आता है । सरगुजा में जंगल काटने को छोड़कर ढ़ेर सारी बातें और वायदे किये गये । इको टूरिज्म, होम स्टे, महतारी वंदन, रानी दुर्गावती योजना इसका मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोलना चाहता था लेकिन अभी इसलिये नहीं बोलूंगा क्योंकि अनुदान मांगों पर हमें बोलना ही है लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि यह जो बात हुई कि Available, Affordable, Accessible लेकिन अगर हम वास्तविक देखें तो आज की तारीख में हालत है Unavailable, Unaffordable and not Accessible जनता भाग रही है, जगह-जगह हम हास्पिटल में जा रहे हैं, जहां पर ईलाज बंद पड़े हुए हैं । बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में आयुष्मान से डॉयलिसिस बंद कर दिया गया है, स्थिति यह है । सी.एच.सी. कॉमन सर्विस सेंटर और बड़े-बड़े दावे, बहुत सारे सदस्य भी बोल रहे थे, धान के लिये हमने इतना पैसा दिया, हमने धान खरीदा लेकिन अगर वस्तुस्थिति देखें, जिनका धान बिक गया वह बिक गया लेकिन बहुत ही ऐसी स्थिति आयी कि ऐसा लगा कि हम लोग चोर हो गये हैं, किसान चोर हो गया है। अवैध धान, अवैध धान क्या होता है, आसमान में उड़ता है या पेड़ में उगता है? अवैध धान पकड़े गये । पी.डी.एस. के अगर बोरे में है, उस पर धान पकड़े गये । आज हमें जरूरत है कि हम ऐसे नियम बनायें कि असली किसान परेशान मत हो।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि अवैध धान, जो हेराफेरी करेगा और जो व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना है?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, मैं आपको अपने क्षेत्र का एक उदाहरण।

श्री केदार कश्यप :- आप चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में व्यवस्था चलती रही उसी तरीके से चले।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- नहीं, आदरणीय। मैं इस बात को माननीय सभापति महोदय के माध्यम से उसको क्लियर कर देता हूं यदि धान अवैध है, यदि कौचिया है, अगर गलत तरीके से धान बेच रहा है तो आप उसको पकड़िये लेकिन कई किसान...।

श्री केदार कश्यप :- वही तो किये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- नहीं किये हैं।

श्री केदार कश्यप :- वही किये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, कई जगह किसानों के धान।

श्री केदार कश्यप :- 9 लाख 47 हजार मीट्रिक टन हम लोगों ने धान किया है और यह पूरा रिसाईकिल करने के लिये किया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इसीलिये स्थगन लेकर आये थे कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका धान नहीं बिका है । मेरे क्षेत्र में जहर पीया है और उसके बाद...।

श्री केदार कश्यप :- आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं गलत बयानबाजी नहीं कर रहा हूं । मैं सीधी बात कर रहा हूं। आदरणीय महोदय, आप परीक्षण करा लें। मैं तो आपको साफ कह रहा हूं। हम आपको नाम दे दें, आप परीक्षण करवा लें।

श्री केदार कश्यप :- आप नाम दीजिये न।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- बिल्कुल, मैं आपको नाम देने को तैयार हूं। आप परीक्षण करा लेंगे, आप उसमें चर्चा करा लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- आप चर्चा करा लीजिये। नहीं, अभी तो पहले से हाथ को हिला दिये थे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह वायदा ठीक उसी तरीके का था जैसा पहले बजट में बोला गया था कि कैश काउंटर हर सोसायटी में लगाया जायेगा ताकि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बैंकों में लाईन न लगना पड़े और सारा पैसा अगर किसान को चाहिए तो वह सोसायटी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। उच्च शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, आई.आई.टी., जनजातीय, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी संग्रहालय कई जगह सड़कों के लिये, बस्तर और सरगुजा 500 करोड़, 200 करोड़, जी.एस.टी. रिफॉर्म्स की बहुत सारी बातें हुईं। मैं उस पर डिटेल में अभी नहीं जाउंगा । बी.वी.जी. राम जी पर लगभग 4 करोड़ का हमने प्रावधान किया है । मंत्री जी, चूंकि यह आय-व्यय की चर्चा है तो मैं उसकी डिटेल में न जाकर सीधे इस पर आ जाता हूं । जब मैंने बजट भाषण पहले सुना और पढ़ा तो लगा कि प्रगति का छत्तीसगढ़ है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हम प्रभावी नीति से बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे लेकिन जब हम लोगों ने आंकड़ा देखा तो यह आंकड़ा उसी तरीके का था जैसा कहा गया था कि हम कैलेण्डर बनाकर एक लाख नौकरी देंगे । अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं । अगर हम डेड रि-पेमेंट को ले लेते हैं। अगर हम लोग next expenditure की बात करते हैं तो वर्ष 2025-2026 में 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट हुआ था जिसमें रिवाईज बजट माइनस 5 प्रतिशत पर हम लोग एक्युअल्स पर आये थे। हम लोग इस बार 10 प्रतिशत की वृद्धि पर हमने अपना बजट पेश किया है। बहरहाल अगर वर्ष 2025-2026 में नेट रिसिव्स की बात करूं तो एक लाख 41 हजार हमारा बजट था, लेकिन उससे लगभग 8 प्रतिशत कम 1 लाख 29 हजार पर हम लोग आकर टिके थे। पिछली बार जब कर की बात हुई थी तो हम लोगों ने बहुत बार कहा था कि यह unrealistic फिगर हैं। कई ऐसे होंगे जहां पर हम जी.एस.टी. की बात करें तो वहां प्रशासनिक और टैक्स terrorism की बात आएगी । मैं जब आंकड़ों को देख रहा था तो बाकी को न बोलते हुए, मैं कैपिटल आउट ले के आंकड़ों पर आता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी, वर्ष 2024-2025 में हमने जब एक्युअल्स किये थे तो 20 हजार 55 के आसपास आंकड़ा आया था। हमने वर्ष 2025-2026 में बजट में 26 हजार करोड़ के आसपास का आंकड़ा लेकर आये थे लेकिन जब वर्ष 2025-2026 के खर्च की बात हुई तो 38 प्रतिशत कम गये। जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने देखा कि यहां डिस्ट्रीक्ट रोड, हाऊसिंग और रूलर वॉटर सप्लाई पर आपका ध्यान था। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र छूट गये जहां पर हमने कैपिटल आउट ले के लिए पैसा रखा हुआ था। वहां पर लोगों को विश्वास था कि हमारे यहां पैसा आएगा। लेकिन इस diversion से वह ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, हमें नीतियों को देखना होगा। आज अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं तो आज भी हम नेशनल एवरेज से पीछे चल रहे हैं। अगर हम बजट देखते हैं तो हमें अपने ऊपर वित्तीय भार भी देखना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। वर्ष 2024-2024 में लगभग 33 हजार करोड़ के आसपास लिया गया, उसके बाद वर्ष 2025-2026 में 36 हजार करोड़ के आसपास लिया गया और अभी लगभग डेढ़ लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा जा चुका है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जब हम ब्याज की बात कर रहे हैं तो वर्ष 2024-2025 में लगभग हमने 8 हजार 900 करोड़ के ऊपर का ब्याज दिया है, वर्ष 2024-2025 में 10 हजार करोड़ के ऊपर और वर्ष 2025-2026 में जो प्रोजेक्टेड है वह 10 हजार करोड़ के ऊपर देने वाले हैं। सेन्ट्रल की एक स्कीम है। स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट, इसे हम लोग शार्ट फार्म में सैसकी कहते हैं। वह राज्यों के लिए इसलिए बनायी गयी थी कि वह राज्यों में जाएं, वह जो पैसा दिया जाये तो वह उसका समर्थन करे। वित्त मंत्री जी, हमें उस पर निर्भर नहीं होना था। लेकिन लगभग अगर हम आज 30 प्रतिशत की बात करें तो कैपिटल आउट ले, अगर मेरे आंकड़े गलत है तो आप मुझे जरूर करेक्ट करिएगा अगर हम बात करें तो लगभग कुछ ऊपर नीचे 30 प्रतिशत, हम लोग कैपिटल आउट ले सैसकी से ले रहे है। हमें निर्भर नहीं होना है। एफआर बीएम एक्ट में आपकी बात से सहमत हूँ कि हम 2.8 पर हैं। ठीक है उस पर सैसकी इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन हमें पूरे बजट को एक साथ देखना होगा तो हमें उस लोन को अपने लिए कैल्कुलेट करना चाहिए। हमें अपनी स्थिति जानने के लिए करना चाहिए। उसके बाद fiscal deficit हमारा 4.1 पर जाता है। यह चिंता का विषय है कि हम कितना लोन ले रहे हैं, हम कितना ब्याज पटा रहे हैं। हमें धीरे-धीरे इसको सही करना होगा। अगर हम कैपिटल expenditure की बात करें जो हमारे committed expense हैं तो आपकी सैलरी, पेंशन और ब्याज में हमारा लगभग 35 से 40 प्रतिशत पैसा चला जाता है।

समय: 4.29 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.)**

माननीय सभापति महोदय, अगर कृषक उन्नति, महतारी वंदन, पी.एम.आवास और पॉवर सब्सीडी को साथ में मिला लेते हैं तो हमारे लगभग बजट का 61 प्रतिशत पैसा इन योजनाओं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में और इन committed expenditure पर जा रहा है। हमारे शायद थोड़ी सी पालिसीज को रि-थिंक करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा स्टेट 44 प्रतिशत वन भूमि का स्टेट है तो हम sustainable विकास की तरफ जा रहे हैं। आज भी यह चिंताजनक विषय है। हमें अपने विकास और नीतियों पर ध्यान देना होगा। हमें इस बात से भी बाहर आना होगा।

समय: 4.30 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सांसद, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत

सभापति महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में कोरबा संसदीय क्षेत्र से सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी उपस्थित है। सदन की ओर से उनका स्वागत है।

(मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की तैयारी अच्छी है या नहीं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी आशंकित था। सदन में कभी हमारे नेता जी देखकर, तैयारी नहीं करते हैं। वह अचानक गंभीर होकर पढ़ रहे थे मैंने सोचा कि क्या बात है। अभी देखा तो मैंने हमारे सांसद भाभी जी को देखा तो मैं मामला समझ गया।

सभापति महोदय :- वैसे भी नेता जी, का संसदीय अनुभव इतना लंबा है कि उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, अनुभव कितना भी हो, लेकिन फिर भी तैयारी करनी पड़ती है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति महोदय, ऐसा है कि वित्त मंत्री जी ने पूरा भाषण पढ़कर सुनाया है । आज मैं भी पढ़कर भाषण देने के मूड में हूं।

सभापति महोदय :- वे दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. चरण दास महंत :- मैं समझ रहा हूं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ठीक तरफ ईशारा किया है । जब ओ.पी. चौधरी जी बजट भाषण पढ़ रहे थे, उस समय भी भाभी जी अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित थीं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- तभी डर के कारण हमारे भैया विलम्ब से आ रहे थे। सभापति जी, मैं टैक्सेस की बात कर रहा था । अगर हम अपने टैक्स कलेक्शन पर जाते हैं तो हमारा जो माईनिंग सेक्टर है, हम लोग एक्साईज और माईनिंग सेक्टर की जीएसटी की बात करते हैं । अगर हम लोग माईनिंग सेक्टर की बात करते हैं तो पिछले साल हमारे राज्य के जो अपने टैक्सेस थे, वह हमें मिलने चाहिए थे, जो हमने बजट किया और जो हमें मिला, उसमें लगभग 16 प्रतिशत की कमी है। अगर 16 प्रतिशत की कमी है तो हमें फिर से ऐसे टैक्सेस बजटेड नहीं करने चाहिए, जहां पर हमें इनसे दिक्कत हो । अगर हम बस्तर और सरगुजा की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, हम लोग लगातार चीजों को खोलते जा रहे हैं, लेकिन हम जितना खोल रहे हैं, उतना हमें Sustainable development की भी बात करनी पड़ेगी ।

सभापति महोदय, मैं जीएसटी में कहूंगा । हम लोग अकलतरा से आते थे तो रास्ते में बड़े-बड़े बोर्ड लगे होते थे कि ट्रेक्टर में इतने की छूट मिली । मैंने हंसकर कहा और आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि आपने जनता को तो बताया कि आप इतने साल से ज्यादा टैक्स ले रहे थे । अगर हम Unrealistic figure रखेंगे तो कहीं न कहीं यहां पर छोटे व्यापारियों को हमें संरक्षण देना होगा, ताकि वे परेशान न हों। अगर हम एक्साईज़ ड्यूटी की बात करें तो हमें आज कहना पड़ेगा । इस बीच नशे पर बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण लगा था । अवैध शराब बिक रही हैं, उसके अलावा शराब की दुकानें बढ़ रही हैं । हमें टैक्स सिर्फ इसलिए कलेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को पैसा चाहिए और हमें यूज़ करना है । हमें अपने राज्य के युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए । सभापति जी, मैं अपने यहां का एक उदाहरण देता हूं । वहां गर्ल्स स्कूल हैं, जहां बच्चियां आना-जाना करती हैं और वहां पर बीच में शराब भट्ठी हैं । हम लोग उसको हटाने के लिए दो साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसको हटाने में हम लोग असमर्थ रहे हैं और वहां पर बहुत सारे हादसे हो गए हैं ।

अशोधित/टंकण के लिए नहीं

सभापति महोदय, Rare Minerals, कटघोरा का क्षेत्र, सरगुजा का क्षेत्र । माईनिंग से ही हम लोग करीब-करीब 19 हजार करोड़ की आमदनी इस बार Anticipate किये हुए हैं । अगर मैं एक बजट इस्टीमेट जैसा कि आज वे कह रहे थे कि बजट पर हम लोग बहुत ज्यादा चीजें लेकर आते हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में प्राथमिकताओं के दौर पर हम लोग करते हैं । इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी विसंगति हमें 24-25 के बजट में मिली । अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण में लगभग 56 प्रतिशत कम खर्च हुए । Water Supply and Sanitation में जितना बजट था, उसमें से हमने 31 प्रतिशत बजट कम खर्च किया । Rural Development में हमने 28 प्रतिशत बजट कम खर्च किया । Health and Family Welfare में हमने 20 प्रतिशत कम खर्च किया । यह लिस्ट लंबी है । हमें वित्तीय प्रबंधन ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इतना भारी भरकर अनुपूरक बजट न लाना पड़े कि पिछली बार हमने 33 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लेकर आये । हमें वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना ही होगा । मैं हमेशा ग्रीन जीडीपी की बात करता हूं । वित्त मंत्री जी इस बार का थीम लेकर आये हैं-संकल्प । तो मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे देता हूं कि कुछ संकल्प में वे इसको भी शामिल करें । S से Sustainable development, A से Agriculture, N से Natural Convocation , K से Knowledge for Crime attention, A से A forestation, L से Low carbon चूंकि आप पैरिस एग्रीमेंट के हिसाब से इस बार ग्रीन बजट भी लेकर आये हैं और P से Pollutions prevention । आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि हम उन अग्रणी राज्यों में हैं, जो ग्रीन बजट लेकर आये हैं कि हमारा पैसा कहां-कहां जा रहा है और उसमें एन्वायरमेंट में कितना आएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं । लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है कि हमें ग्रीन जीडीपी की ओर जाना होगा । मंत्री जी, आप हमेशा कहते हैं कि हम लोग अगली बार इसको जरूर लेकर आएंगे । मेरा निवेदन है कि ग्रीन जीडीपी पारम्परिक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यावरण का नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और गिरावट की लागत को घटाकर हम निकालते हैं तो हमें एक समायोजित सस्टनेबल डेव्हलपमेंट का आंकड़ा मिलेगा । यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग 44 प्रतिशत वन भूमि पर हैं । हम खनिज का दोहन कर रहे हैं, हम खनिज निकाल रहे हैं, हम वनों को काट रहे हैं तो हमें ये तो पता चले कि उससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है । हमें सस्टेनेबल डेव्हपलमेंट, ईको टूरिजम, फारेस्ट राइट्स, आखिर इनकी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी बात करनी होगी। हमें एग्रीकल्चर की भी बात करनी होगी। आदरणीय मंत्री जी, एक अच्छी बात कर रहे थे कि हमने इतना खरीदा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अच्छा यह बताओ कि आपने पूरे बजट में कौन सी बात बुरी है, कहा है। सारी बातें अच्छी है, आखिरी में क्यों बोल रहे हो ? शुरू से बोलो कि बजट अच्छा है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जो अच्छा है, मैं उसको बोल रहा हूं, जो नहीं है, उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सभी अच्छे हैं। आपने एक भी चीज गलत है, कहां कहा है ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, आप मेरा भाषण तो सुन लीजिये।

श्री राम कुमार यादव :- ये विधान सभा के समस्या फेर इहां आ गय।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दूसरे विषय की बातें यहां ना करें।

श्री राम कुमार यादव :- 5 साल ले तुंहर दिमाग मा गोबर भरे रहिस ए अउ आज ले ओसनहे भरेच ए।

सभापति महोदय :- बहुत बढिया भाषण दे रहे हैं। सुनिये। आप बोलिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं वही बात कह रहा था कि हम लोगों को प्लाण्टेशन और फारेस्टेशन के बीच में जो अंतर है, उसको समझना पड़ेगा। चूंकि समय कम है, इसलिए कुछ बातें और कह देता हूं। आप कह रहे थे कि आपने कई बातों को नहीं कहा। मैं अभी तक यही बोल रहा था कि क्या-क्या इस बजट में नहीं आया है। हमें अपने राज्य के लिए सही तरीके से पालिसी बनाकर किस ओर जाना होगा, यह दशा और दिशा हमें इस विधान सभा में तय करनी होगी। आज लगातार पिछले 5 सालों की बात हो रही थी। बिजली बिल हॉफ योजना से लेकर कई बातें आई कि आपने बंद कर दी। लेकिन यहां पर यू टर्न की बात आ जाती है। बिजली बिल का सब्सिडी खत्म कर दिया जाता है और फिर बाद में आधा जोड़ दिया जाता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। लगातार बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम गाईड लाईन के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कम करने की बात होती है। अभी कोई कह रहा था कि हम लोग होली के दिन भी शराब दुकान खोलने की बात कर रहे थे। जमीन की गाईड लाईन पर एक सोशल इम्पेक्ट यह आया है, मैं आदरणीय मंत्री जी को भी कह रहा था। जितने भी डी.पी.आर. बनकर आये थे, जिस पर लैण्ड एक्यूजिशन होना था, वे सारी फाईलें अब दोबारा जानी है। क्योंकि वहां पर रेट बदल गए हैं, रेश्यो बदल गया है। जैसे सड़कों के लिए जमीन के आवार्ड पारित नहीं हुए हैं, उसमें दोबारा जाना होगा। दोबारा लैण्ड एक्वीजिशन के रेट आयेंगे, उसके बाद वे सड़कें बन पायेंगी। तो इस तरह के यू टर्न निर्णय होते हैं, वह चाहे जी.एस.टी. में हो, चाहे गाईड लाईन में हो, चाहे सब्सिडी पर हो, यह हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आज मेरा प्रश्न भी लगा हुआ था, लेकिन वह नहीं आ पाया। कृषि अभियांत्रिकी विभाग में केन्द्र से पत्र भी आया है, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है। उसकी एक समिति बना दी गई है, जिसकी जरूरत नहीं थी। अभी वह बजट लेप्स हो जायेगा और वह हमारे प्रदेश में नहीं बन पायेंगे। अगर आप संकल्प ले रहे हैं, जो आपका संकल्प-पत्र था, उसमें मोदी की गारंटी में तो एक लाख नौकरी की भी बात करनी होगी, 5 सौ रूपये में गैस सिलेण्डर देने की भी बात करनी होगी, 5 सौ जन औषिधि केन्द्र खोलने की भी बात होगी, कालेज छात्रों को मासिक ट्रेवल एलाउंस की बात करनी होगी, रेडी टू इट संचालन वापस देने की बात करनी होगी, हर ब्लाक में डायलिसिस सेन्टर, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, हर पंचायत भवन में कैश की व्यवस्था, आदिवासी बच्चों के विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय, 57 हजार शिक्षकों की भर्ती, यह आपकी गारंटी थी, आपका संकल्प था, उनके बारे में कोई बात इस बजट में नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सन् 2014 की भी बात कर देता हूं। सन् 2022 तक आप दोगुनी करने वाले थे। प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, सौ स्मार्ट सिटी देने वाले थे, मेक इन इण्डिया, स्टार्टअप, नोटबंदी से आतंकवाद बंद, आपने काफी सारे ऐसे वादे किए हैं। सबसे पहले तो आप अपनी मोदी की गारन्टी पढ़ लीजिये और उसके बाद बताईये कि आपने कितने बजट में पूरे किए हैं और कितने पूरे नहीं हुए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसान-सियान केयर, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान, मोबाइल टावर, आपकी कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसके बारे में बात की थी, लेकिन आज तक वह धरातल पर नहीं उतर पाई है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय में 10 हजार स्कूलों का समयोजन कर दिया गया। अब हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा नीति साफ कहती है कि पिछड़े क्षेत्रों में हमारा 25 का रेश्यो होना चाहिए, लेकिन हमारे पूरे राज्य में 30 का रेश्यो कर दिया। जब शिक्षा विभाग की मांग पर चर्चा होगी तो मैं अपनी बात प्रमुखता से रखूंगा।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जी, बस आखिर में बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए, जो कैशलेस स्कीम आई है, मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक अच्छी स्कीम है। बहुत समय से इसकी मांग आ रही थी। जो अच्छा काम है, मुझे उस पर बधाई देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहां काम नहीं है, उसमें भी हम लोगों को यह बात रखनी होगी। आज रसोइये और कई ऐसे लोग हैं, आज सड़क पर हैं। हमें उनके बारे में सोचना होगा। हमने सचिवों से वादे किए थे, हम उनके बारे में प्रावधान देना होगा। अगर मैं बजट की बात करूं तो युवा, महिला और बुजुर्ग, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक आखिरी बात करना चाहता हूं। हम लोग नये विधायक हैं, हम लोग यहां सीखने के लिए आते हैं, हम देखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, एक बात आदरणीय बघेल जी ने कही, उसके बाद एक मंत्री जी ने कही कि हम यहां से आदेश नहीं दे सकते, आज आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने कही कि क्या ब्यूरोक्रेट चलाएगा। तो सरकार में बड़ी कंफ्यूजन सी स्थिति है । आपने एक बात कही कि विभागीय आएगा कि हम बताएंगे जनप्रतिनिधि कि कौन सी हमारी प्राथमिकता है। हम लोग विधान सभा तो यही समझकर आये थे कि प्राथमिकता जनप्रतिनिधियों की होगी। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से सरकार चलाएंगे और वह प्राथमिकता तय करेंगे...।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये बात तो सही है, मैं उस में कायम हूं कि हमारी चलेगी क्योंकि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास मैंडेट है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस चीज़ को हमको सिखा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट नहीं जनप्रतिनिधि सरकार चलाएगा और ये सब चीज़ें हम आपसे सीखते हैं। इसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इस बजट का, जिसमें युवा और महिलाओं के लिए नहीं है, बुज़ुर्ग के लिए नहीं है, हमारी स्टेट पॉलिसीज़ गलत हैं, मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू। आप भी पांच-सात मिनट में निपटा दीजिये।

श्री दलेश्वर साहू :- एक मिनट में।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, पाँच-सात मिनट में नहीं। एक मिनट में कभी कोई भाषण होता है?

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं । सभापति महोदय, ये मुगलाते शब्द एक उर्दू शब्द है मुगलाते। भ्रम में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो, मुगालता है मुगालता। कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं। देखो हमारे..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनो तो, आप उर्दू बोल रहे हैं ना, उर्दू?

श्री दलेश्वर साहू :- भाई, मुझे बोलने तो दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो आपको रमज़ान की बहुत-बहुत बधाई। ठीक है?

श्री दलेश्वर साहू :- ठीक है।

सभापति महोदय :- हां, बोलिए ना आप बोलिए।

श्री दलेश्वर साहू :- कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आपने जब शुरुआत की तो मैं भी शुरुआत करने का मन बना लिया था।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, अच्छा लग रहा है, बोलिए।

श्री दलेश्वर साहू :- कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का अवसर रखता है। जम रहा है ना?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- जम गया, बिल्कुल जम गया।

श्री दलेश्वर साहू :- लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। ये आसमां छिन गया तो क्या? मतलब आसमां की जगह सरकार चली गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति ने कौन सी कविता पढ़ी थी? आपने सुना था?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं सुना था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या बोले थे?

श्री दलेश्वर साहू :- अब मैं इतना याद थोड़ी रखूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस लाइन में आप भी पढ़ो। उसी लाइन में आप भी पढ़ो।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं वही तो कह रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- ये आसमां छिन गया तो क्या, फिर से हासिल कर लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे।

श्री विजय शर्मा :- उड़ना।

श्री दलेश्वर साहू :- हम वो परिंदा नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे, उड़ना छोड़ देंगे।

श्री विजय शर्मा :- उड़ना छोड़ देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- ये आसमां छिन गया तो क्या, फिर से हासिल कर लेंगे, हम वो परिंदा नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है साहब?

सभापति महोदय :- हां, मैं समझ रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- मत पूछो हौसले हमारे, आज कितना नि:शब्द है। मत पूछो हौसले हमारे, आज कितना नि:शब्द है, एक नई शुरुआत नया आरम्भ तय है। ये पतवार छूट गया तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे, हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। हमारा प्रयास जारी है और वही जारी रहेगा, भ्रम मत पालो, गलतफहमी में मत रहो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, ये कविता भूपेश बघेल जी को समर्पित है कि चरणदास महंत जी को समर्पित है या टी.एस. बाबा को समर्पित है?

श्री दलेश्वर साहू :- आप लोगों को समर्पित है।

श्री रामकुमार यादव :- नेताजी, अगर कहें आप आदेश तो एक ठन मैं और कह दूं। ये कविता समंदर की वो लहरें हैं, चंद्राकर जी, ये कविता समंदर की वो लहरें हैं, जो वापस फिर से आता है। सभापति महोदय, बस यही है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह किसको समर्पित है?

श्री दलेश्वर साहू :- हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य समाज के जाति के लोग, रीति-रिवाज़, अलग-अलग धर्म की मान्यताएं के लोग निवास करते हैं और एक-दूसरे की संस्कृति को हम लोग सम्मान करते हैं। अगर भक्त माता कर्मा की अगर रैली जा रही है तो वहां के लोधी समाज के लोग भी वहां सम्मान करते हैं, आदिवासी भाई के लोग सम्मान करते हैं। धर्म के प्रति आस्था पैदा करने वाले हमारे पूर्वज हैं और धर्म के प्रति आस्था पैदा करने वाले ही उनके संस्कार से आज हम लोग एक-दूसरे का सम्मान करते हुए बैठे हुए हैं। मैं उसी पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपकी ही योजना पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, विस्तृत तो हम अपने बजटीय भाषण में बोलेंगे जब होगा। आपके पी-अजय योजना पर समीक्षा करने की ज़रूरत है मंत्री जी। धरती आबा जनाजति उत्कर्ष योजना के बारे में, पी.एम. जनमन आदिवासी महाभियान योजना के बारे में, डॉ. दीनदयाल राष्ट्रीय शहर योजना के बारे में आपको थोड़ा-सा समीक्षा करने की जरूरत है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के संबंध में मुख्यमंत्री धरोहर योजना और मुख्यमंत्री झरोखा योजना व अन्य ऐसी कई योजनाएं आपने लागू की हैं। मैं विस्तार से बताऊंगा तो फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि आप लोग कई योजनाओं में महापुरुषों के नाम रखते हैं, परंतु यह सरकार उन महापुरुषों के नाम को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। मैं डॉ. रमन सिंह जी के इलाके का पड़ोसी विधायक हूँ, साहब जी। आप समीक्षा करियेगा, चिंतन करियेगा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे प्रदेश में हर गाँव को चिन्हांकित किया। उन्होंने हर जिले में कि उन चुनिंदा 15 गाँवों में वह योजना लागू किया कि हम गाँवों को शहर के तर्ज पर बसाएंगे। साहब, यह आपके विभाग का विषय है। आपको एक-एक ऐसे गाँव मिलेंगे, जैसे शहरों में सुविधा रहती है। मैं तो कहता हूँ कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिन-जिन जिलों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना लागू होगा, उसका कम से कम अवलोकन करें, चिंतन करें। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन में आता है। हमें उन महापुरुषों का नाम रखने के पहले थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि उनके नाम को डुबाएंगे या उन महापुरुषों की इज्जत को रखेंगे। ये सारी चीजें चिंतन के विषय हैं। अब मेरा पहला प्रश्न भारत सरकार की PM-AJAY योजना पर है। आपने वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2025 में 965 करोड़ रूपये को खर्च नहीं कर पाया है। सिर्फ एक PACC गठित प्रोजेक्ट 'अप्रैल जल' कन्वर्जन कमेटी ने पास कर दिया, पर पोर्टल में अपलोड नहीं होने के कारण आपने पैसा खर्च नहीं किया है। 965 करोड़ यहीं पर है? ये छोटी-मोटी रकम है? जिसे आपने वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में खर्च नहीं कर पाया है। फिर आप इतना बजट क्यों बनाते हैं? इसलिए आप सिर्फ समीक्षा करिये और एक पोर्टल में अपलोड नहीं होने की वजह से तीन-तीन साल का पैसा खर्च नहीं हो पाया है। ये ऑथैंटिक सत्य है। सिर्फ इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान, इसमें आपके पास कितना पैसा है? Centre of Accommodation के प्रस्ताव सिकल सेल के लिए रोकथाम हेतु अनिवार्य रूप से करना था। आप जंगल की बात करते हैं, आदिवासी के हित में बात करते हैं। आप जो भी बात करते हैं। छात्रावास के उन्नयन अंतर्गत अधोसंरचना के पैसे के लिए आपने सारे विभागों से प्रस्ताव मंगवाया। आपने आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग से प्रस्ताव माँगाया। जनजाति बहुउद्देशीय के.सी. टी.एम.सी.सी. सिकल सेल एनीमिया, सी.ओ.सी. का वन अधिकार के रूप में अधिनियम एफ.आर.ए., सी.आर.सी. के हर छात्रावास को अधोसंरचना। ऐसे ही आपने स्वास्थ्य सेवा में भी कुछ नहीं कर पाया। छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण में आपने कुछ खर्च नहीं कर पाया। स्कूल शिक्षा विभाग में आपने एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाया है, सिर्फ आपने ऊर्जा विभाग में पैसा खर्च किया है। जो नक्सल बेल्ट है, उस पैसे का आपने उपयोग किया है और उसके बावजूद भी आप समय में लक्ष्य की पूर्ति कर पाए। वन विभाग PVTG वन धन विकास केंद्र स्केलिंग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, लेकिन आपने एक भी पैसा आपने खर्च नहीं कर पाया है, वह सिर्फ नाम रह गया है कि अनुसूचित जनजाति धरती आबा जनजाति योजना। इसलिए आपको किसलिए पैसा मिलेगा, किसलिए हम इसका अनुमोदन करेंगे और इसमें किसलिए हमारी सहमति होगी? आपने विद्युत विभाग में खर्च किया। वैसे ही मैं पी.एम. जनमन योजना की बात करता हूँ, जो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आता है। पी.एम. जनमन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना में आप वर्ष 2022-23 में 135 करोड़ 78 लाख 43 हजार, वर्ष 2023-24 में 156 करोड़ 76 लाख 77 हजार, 2024-25 में 145 करोड़ 6 लाख 6 हजार को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में किसी भी जिले में आपने दो वर्ष तक आवंटन जारी नहीं कर पाया। यह क्या स्थिति है? बड़ी-बड़ी योजना बनाने से, हरित क्रांति लाने से कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और मैं फिगर के साथ कह रहा हूँ। अगर यह गलत साबित होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। मैं ऑथेंटिक आंकड़ें बता रहा हूँ कि वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में पी.एम. जनमन योजना में आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप नियद नेल्लार योजना की समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्रों में अपने हितों की बात करना चाह रहे हो, यहां भी आपको समीक्षा की जरूरत है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की जानकारी दूँगा कि आदिवासियों को 7,13,405 रूपया आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हो । अनुसूचित जाति के तहत आप 26 करोड़ 54 लाख 31 हजार 552 रूपया की छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हो । ओबीसी के तहत 105 करोड़ 38 लाख 48 हजार 576 रूपया, कुल मिलाकर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के 185 विद्यार्थी को पैसा नहीं दिये हो । उसी प्रकार वर्ष 2023-2024 का अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के 31 विद्यार्थियों को आपने पैसा नहीं दिया है । कुल मिलाकर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के 973 विद्यार्थी का आपने पैसा नहीं दिया है । सभापति महोदय, यह सरकार बच्चों के उत्थान की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है, जन-जंगल-जमीन के उत्थान की बात करती है, हम तो फिगर की बात करते हैं । आप समीक्षा नहीं कर पा रहे हो तो धरातल पर क्या काम होगा । सभापति महोदय, मैं उर्जा में जाना चाहूँगा । बहुत दुखद घटना रहती है, मैं हमेंशा आर.डी.एस. रेपिडेस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की बात करता हूँ । यह इतनी शानदार योजना है कि गांव के मोटर पंप के लिये अलग से ट्रांसफार्मर होगा, गांव में बसने वाले जो जीवन यापन करते हैं उसका अलग ट्रांसफारमर होगा, किसी भी प्रकार से वोल्टेज प्राब्लम नहीं होगा । मैं हर विधायक को कहना चाहता हूँ कि इस आर.डी.एस. योजना पर गहन अध्ययन होना चाहिये । पैसा रहकर भी खाली ठेकेदार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको पेनॉल्टी लगाकर आप सालों बरबाद कर रहे हैं । यह कितना गंभीरता हुआ है, मैं छोटा-मोटा रकम की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनांदगांव जिले में 125 करोड़ किसको बोलते हैं, वैसे ही आपने मुंगेली पूरे जिले में पूरे जिले में कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है कि जिससे पेनॉल्टी लगाकर अपना पल्ला झाड़ा होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन,चना, सरसों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिये हैं । आपने वर्ष 2024-2025 और वर्ष 2025-2026 में और वर्ष 2023 में आपने एक दिन न तो अरहर खरीद पाये, न मूंग खरीद पाये, न उड़द दाल खरीद पाये, न मुंगफल्ली खरीद पाये, खाली सोयाबीन 5-10 परशेंट ही खरीद पाये हो । सभापति महोदय, कितनी विडम्बना है, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना को भी आपने डिब्बा में डाल दिया । जितना भी गिना रहा हूँ, सब डब्बा में जा रहा है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार ने इस बार मक्का भी नहीं खरीद पाये हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024...।

श्री जनक ध्रुव :- किसान जो खर्चा किये थे वह ठीक से वसूली नहीं हो पा रहा है । किसान औने-पौने दाम में बिचौलिया के पास जा रहे हैं। यह स्थिति है।

सभापति महोदय :- वही तो बता रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- वही बता रहा हूँ । सभापति महोदय, धान खरीदी के मामले में...।

श्री दलेश्वर साहू :- बस, ये आखरी बोल देता हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, खरीदी वर्ष 2025 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति 25-26 में वर्णित प्रावधानों के धान उपार्जन कार्य में नियोजित सहकारी समिति, नंबर वन, जिला सहकारी केंद्र बैंक और विपणन संघ के बीच उस नियम में त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य था। आपने न कोंडागाँव में किया, न बस्तर में किया, न बालोद में किया, न बेमेतरा में किया, न दुर्ग में किया, न कवर्धा में किया, न राजनांदगाँव में किया, न खैरागढ़-छुईखदान में किया, न मानपुर-मोहला में अंबागढ़ चौकी में किया, न बलरामपुर में किया। इसको आपने कर लिया होता तो जो दूसरे प्रदेश से आपने धान लाकर कवर किया है तो शायद ये संभावना नहीं बनती। आपने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया ? ये तो एग्रीमेंट होना था, पोस्टर लगना था, बैनर लगना था, कितने रूप में किसको कैसे देना है, हमाल को कितना देना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें थी, आपने 33 जिला में से 12 जिला में नीति का पालन नहीं किया, आपने इस नियम के तहत 12 जिले को ऐसे ही छोड़ दिया। सभापति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, धान खरीदी के मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग के द्वारा निर्देश जारी हुआ था। कंडिका 3, 4 एवं 5 में दर्शित निर्देश के अनुसार NAICC द्वारा डेवलपमेंट PBF के संयुक्त माध्यम से कैरी फॉरवर्ड अपूर्ण की समस्या का निराकरण, खसरा में दर्ज रकबा, खसरा में DCL डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी भौतिक सत्यापन, एग्रीटेक, UR लंबित टोकन सुधार हेतु पूर्ण प्रकरण ये सारे नियम कानून में कलेक्टर के माध्यम से निदान करने का प्रावधान था।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, इसी को अंतिम करते हुए समाप्त करूंगा। जितने भी प्रकरण आए, किसान से संबंधित आवेदन किए, वहाँ के जो नोडल अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति सीधा तीनों सचिव को लिखते हैं। ये रकबा संशोधन का मामला है, कौन सा राजस्व सचिव के पास जाएगा या सहकारिता सचिव के पास जाएगा या कृषि सचिव के पास जाएगा ? ये तीनों को पत्र लिख देते थे। मैंने कलेक्टर साहब से पूछा था, आपको समाधान पता नहीं है? जैसे कोई बीमारी आती है तो दसों प्रकार की दवा उस दवा को ठूँस देते हैं तो उनको इतनी समझ में नहीं है कि रकबा संशोधन राजस्व प्रकरण करेगा या सहकारिता मंत्री जी करेंगे या कृषि मंत्री करेंगे। वह प्रकरण वहीं पर घूम-घूम के रह गया, हम लोग जा जाकर मेहनत करते थे तब थोड़ी-थोड़ी सफलता मिल जाती थी। ये कैरी फॉरवर्ड के नाम में, पोर्टल हेड के नाम में, बहुत सारे किसानों को आज वंचित होना पड़ा है और रकबा संशोधन आज देखने का अवसर मिला है। खैर अभी तो जो दिन बाकी हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर फिगर आते रहेंगे, फिर चर्चा करते रहेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री किरण देव सिंह जी।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहले मैं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को और आदरणीय हमारे युवा वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बजट है। आपने 1,72,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह बहुत ही सर्वव्यापी, बहुआयामी, सर्वस्पर्शी बजट है, मैं ऐसा मानता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र को विकास की दृष्टि से समाहित करते हुए कई प्रावधान किए गए हैं। आदरणीय सभापति जी, ये तीसरा बजट है। पहला बजट GYAN को समर्पित था, दूसरा GATI को समर्पित था और तीसरा संकल्प से सिद्धि तक का है। मैं यहां पर हमारे बहुत वरिष्ठ वक्ताओं व वरिष्ठ सदस्यों को सुन रहा था। पूर्व में हमारे वक्ता ने जिस तरीके से कहा। मैं भी पहली बार का सदस्य हूं तो बड़ों को, वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ वक्ताओं को सुन कर सीखते जाता हूं। इस दृष्टि से मुझे यह लगता है कि बजट एक ऐसा विषय है, जिसको राज्य के पूरे समावेशी विकास की दृष्टि से बनाना और लागू किया जाना और इसकी प्रतीक्षा पूरा राज्य और पूरी जनता करती है कि इस बजट में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से कुल मिलाकर हमारे लिए क्या है? मैं बहुत ज्यादा आंकडों पर नहीं जाऊंगा। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैथमेटिक्स में कमजोर भी हूं। लेकिन मैं जब वरिष्ठों की बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि जिस तरीके से बस्तर विकास की दृष्टि से वर्षों तक अछूता रहा है। हम सब जानते हैं कि 4 दशक से भी ज्यादा समय तक पूरा बस्तर जिस तरीके से नक्सल आतंक के साये में रहा, विशेषकर बस्तर का दूरस्थ वन भाग। हमारे बॉर्डर स्टेट और उससे लगे हुए गांव, जहां तक कभी विकास पहुंच ही नहीं पाया था। अब जब मैं यह बात कहता हूं तो इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं किसी की ओर इंगित भी नहीं कर रहा हूं। मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं आक्षेप भी नहीं लगा रहा हूं। लेकिन वह एक बड़ा कारण था। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आदरणीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी यहां बैठे हुए हैं, उनका बहुत अभिनंदन करूंगा। (मेजों की थपथपाहट) एक दृढ़ संकल्प, एक इच्छाशक्ति, ऐसी बहुत सारी टिप्पणियां मैं बस्तर के विचार के विषय में सुन रहा था। यह आसान काम नहीं था और उसके बाद चैलेंज के साथ डेडलाइन देना कि मार्च 2026 तक बस्तर से समूचा नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) यह अटल विश्वास है। मैं भी बस्तर से ही आता हूं। यहां पर हमारे अन्य वरिष्ठ साथी लखेश्वर बघेल जी, चैतराम अटामी जी, टेकाम जी और अन्य सभी बैठे हुए हैं। बस्तर के विषय में हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, हमारा जो-जो दायित्व है उस तरीके से हम अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं और उस संबंध में अपने विचार को रखते हैं। लेकिन बस्तर को देखा जाए तो इस विषय को इसलिए मैं रेखांकित कर रहा हूं कि बस्तर में सारा विकास इसी से अवरूद्ध होकर रूका था और आने वाले समय में इसी से तेज गति से आगे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बढ़ने का क्रम बनेगा। इस बात को सभी जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था, जब बस्तर का सुकमा जिला हो, बीजापुर जिला हो, दंतेवाड़ा जिला हो, नारायणपुर जिला हो। मैं हमारे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं शहर की बात कर रहा हूं। मैं सुकमा शहर की बात कर रहा हूं। I belongs to sukma. हमारे लखमा राम जी भी वहीं से हैं। एक समय ऐसा था कि वहां देश से नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के ही दूसरे जिलों से विवाह के लिए वहां कोई बेटी नहीं देना चाहता था। वहां पर यह स्थिति थी। विकास तो बहुत दूर की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व अभिनंदन है। नियद नेल्लानार एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। अभी मैं मुंबई में था तो मुझसे पूछे कि यह योजना वास्तव में क्या है? यह गोंडी शब्द है, जिसका अर्थ है–मेरा अच्छा गांव, हमारा अच्छा गांव और इस दृष्टि से उस योजना के तहत सरकार की 25 और उससे भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं उन क्षेत्रों में संचालित हैं, जो कि लाल आतंक के साये में 40 वर्षों तक रहे तथा जहां पर विकास का कोई नामोनिशान नहीं था। अभी मैं सुन रहा था तो मोबाइल टावर की बात हो रही थी। मेरे पास पूरी जानकारी है कि कितना करोड़ का प्रावधान है, 500 करोड़ और सारा कुछ। मैं तो मर्म पर जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में उन क्षेत्रों में बहुत तेजी से टावर लगने प्रारंभ हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेव्हलपमेंट प्रारंभ हुआ है, जो नक्सल मुक्त ग्रामीण क्षेत्र हैं। चाहे PSC, mini PSC हो। नियद नेल्लानार योजना के तहत वहां पर प्राइमरी स्कूल के अलावा विद्युत की व्यवस्था। ये सारी वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और ये दिख भी रहा है। मैं महतारी वंदन के विषय को भी सुन रहा था। माननीय सभापति जी, मुझे समझ में नहीं आता कि यह इतनी अच्छी योजना है और उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की जाती है। आप लोग अपनी तरफ मत ले लीजिएगा। कोई भी, किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी करता है कि इसमें ये कमी है, इसमें खामी है। सरकार ने पहली बार तो सुध लिया है कि 70 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में 1000 रूपये डालेंगे। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर हम इसको आराम से, सहज रूप से बैठकर सोचें तो यह चिंता बड़ी चिंता है। अब इसमें एक-दो नाम इधर-उधर हो जाएं, कहीं कुछ आगे-पीछे हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जरा बस्तर, सरगुजा और ऐसे Below the category के जो परिवार हैं, जहां पर कभी-कभी पारिवारिक स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, जहां पर बहन-बेटियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह योजना विवाहित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बेटियों के लिए है। वे हमारे बस्तर में छोटे-छोटे मेला-मड़ई में जाती हैं। जब वे मेला-मड़ई जाती हैं या कहीं बाजार जाती हैं, वहां बाजार का ट्रेडिशन बड़ा पक्का है, तो वहां जाकर कभी कोई चूड़ी ले ले, कोई बिंदी ले ले। क्योंकि वहां के दोनों प्रधान बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कभी-कभी पुरुषों के साथ। ऐसा जो दूरस्थ वनांचल। मेरा परिवार तो वहां पर 780 साल पुराना है, मैं भी जानता हूं। क्या ये डेव्हलपमेंट नहीं है? क्या यह डेवलपमेंट का एक अंग नहीं है?

सभापति महोदय, अभी प्रधानमंत्री आवास के ऊपर टिप्पणियां हो रही थी। मैं सुनता हूं लेकिन सहज भाव से लेता हूं। प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना है, जिसमें शहरी भी है और ग्रामीण भी है। यह काम रुका हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ इच्छाशक्ति से यह निर्णय लिया और उसके लिए बजट में प्रावधान किया। अब मैं 400 करोड़ और 200 करोड़ शहरी और ग्रामीण में पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ मर्म पर जा रहा हूं। क्या सिर्फ हमें ही पक्के मकान में रहने का हक है? गरीब परिवार की दृष्टि से बड़ी खुशी होती है । मैं बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में और अंदर भी जाता हूं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी कई जगह पर गया हूं तो उनके चेहरे देखते बनते हैं। जब बारिश के समय अतिवृष्टि हो जाए तो उन परिवारों की क्या स्थिति होती है जो घास-फूस के घर में रहते थे ? यह पहले तो 18 लाख परिवारों का था और अब यह बढ़कर 25 लाख परिवार से भी ज्यादा का है और यह तेज गति से बन रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन है । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, बस्तर को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं बस्तर में ही अपनी बात सीमित कर रहा हूं। मैं पूरे प्रदेश में भी आ सकता हूं। अभी एक विषय आया। बस्तर में पिछले वर्ष से दो चीजें प्रारंभ हुई हैं, मैं उसके लिए भी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारा जो वनांचल है, जो बस्तर का ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से जैसे-जैसे भय और आतंक का वातावरण कम होता गया, वैसे ही धीरे-धीरे बस्तर के उन क्षेत्रों में शांति फैलती गई। बस्तर के युवाओं को लेकर या बस्तर का ट्रेडिशन। अभी बस्तर पंडुम की बात हो रही थी और चैतराम जी बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम के बारे में बता रहे थे। इसमें कुछ बातें आई थीं कि पंडुम ऐसा है, तिहार ऐसा है। मैं इस बात को मानता हूं कि दोनों अलग-अलग चीजें हैं इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसके भी मर्म को समझना पड़ेगा। पहली बार बस्तर में बस्तर ओलंपिक हुआ। बस्तर में ट्रेडिशनल से जुड़े हुए खेल खेले गये, चाहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह फुटबॉल हो, खो-खो हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो। जब पहली बार बस्तर ओलंपिक हुआ था तब इसमें करीब 1 लाख 60 हजार के आस-पास प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस बार उसकी संख्या 3 लाख 90 हजार के आसपास पहुंची है। यह अपने आप में सारी कहानी कह देती है कि विकास कहां तक पहुंच रहा है। (मेजों की थपथपाहट) उनको भी अधिकार है। इस तरीके से सरगुजा ओलंपिक चालू हुआ।

सदन का सूचना

सभापति महोदय :- एक मिनट, आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री किरण देव :- माननीय सभापति जी, ऐसे ही बस्तर पंडुम का विषय है। यह तो खुशी की बात है। इसमें तो पूरे छत्तीसगढ़वासियों को, बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि ये दोनों बस्तर ओलंपिक और पंडुम की ख्याति देश से भी बाहर जा रही है। बस्तर अदभूत है, बस्तर कई विशेषताओं को समेटे हुए है। बस्तर का अपना सांस्कृतिक महत्व है। बस्तर के नृत्य, बस्तर के लोग, बस्तर की भाषा, बस्तर की बोली, पहनावा, खान-पान, वहां के वाद्य यंत्र एक मंच पर आकर, पहले ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर ऐसी योजना सरकार ने बनाई और उन कलाकारों को, बस्तर की संस्कृति को, उन खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिये, लगातार दो बार हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन भी हुआ। इस बार तो सबसे अच्छा विषय ये था देश की माननीय राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मु जी ने आकर पूरे कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया। इस पर टिप्पणी की किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व अगर छत्तीसगढ़ को, बस्तर को जान रहा है तो यह प्रसन्नता का विषय है। सरकार के इस कार्ययोजना की प्रशंसा होनी चाहिए। रोजगार के विषय में मैं बीच में सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने इसको उठाया था। फिर मैं बस्तर को ही फोकस करके कह रहा हूं। जब हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं तो ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में यह देखने को आता है कि उनकी जो इकानामिक ग्रोथ है, उनका जो आर्थिक व्यवस्थापन है, उनका इकानामिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट का जो आधार है वह सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के बूते है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय: 5.16 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

बस्तर जैसे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं और पहले से चल रहा है। मैं इस बात को यहां पर बोलूंगा फिर due all of your respect मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, इसको अपनी तरफ मत लीजियेगा। डॉ. रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय का हमारा चित्रकूट, तीरथगढ़, बारसूर, कोटमसर, ढोलकाल का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, उसके बाद पहली बार इको टूरिज्म पर पर्यटन से लेकर वहां पर एक कारीडोर बनाने की जो योजना तैयार हुई है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी अभिनंदन करता हूं। यह बहुत अच्छा है। लाखों टूरिस्ट पूरे पश्चिम बंगाल से और पूरे देश से बस्तर को देखने, समझने और घूमने के लिये आते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर चित्रकोट, तीरथगढ़, धुड़मारास, टाटामारी, दोड़काल आदि को टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और एक धुडमारास का मैं यहां पर जरूर बात रखना चाहूंगा। हम सबको मालूम है कि धुड़माराम जगलदपुर विधान सभा में हैं, यह मेरे भी थोड़ा सा कह सकने वाली बात है कि पूरे विश्व में 60 देशों में यूनेस्कों के माध्यम से 20 गावों का चयन हुआ। उसमें हमारे देश में धुड़मारास, धुड़मा जनजाति का वह गांव है, कोटमसर के पास वह गांव है, धुड़मा जनजाति के लोग वहां रहते हैं और उसको यहां से चयन हुआ है। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिये भी गर्व और गौरव का विषय है। उसके विकास की दृष्टि से भी सरकार अपनी उत्तम योजना बना रही है। उसी में छत्तीसगढ़ होम-स्टे पॉलिसी है। मेरा खुद का ऐसे दो होम स्टे चित्रकूट, तीरथगढ़ ऐसी जगहों पर लोकार्पण के अवसर पर जाना हुआ और ये काम भी मेला स्व-सहायता समूह के हाथ में दिया गया है। उनको रोजागर के अवसर सुनिश्चित हो रहे हैं। अभी एक नया काम वहां पर चालू हुआ है जिसमें तेजी से वहां के युवा आगे आ रहे हैं। आपको तीरथगढ़, चित्रकूट, चित्रधारा और अन्य ऐसी जगहों पर बैंबो राफ्टिंग का देखने को मिला है। यही बैंबो राफ्टिंग करने के लिये हम लोग नार्थ ईस्ट में और अन्य जगहों में जाते थे, आज हमारे बस्तर में यह चालू हुआ है। उसके लिये भी जो पालिसी बनाई गई है, उस योजना के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि कम लगती होगी। लेकिन इसकी शुरूआत है। उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पर्यटन को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उद्योग का दर्जा देने का निर्णय वास्तव में प्रशंसनीय है। उस क्षेत्र में औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय है, उसका भी अभिनंदन है। इस दृष्टि से हमारे बस्तर और सरगुजा में आबादी का घनत्व जरूर कम है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल है। इस कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बस योजना प्रावधानित किया है उसके अंतर्गत 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इसके लिये भी मैं बधाई देता हूं और इसके अंतर्गत 70 बसों का संचालन बस्तर और सरगुजा में किया जा रहा है। हमारे बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ जैसे दूरस्थ अंचल जहां लोग जाने से घबराते थे, उस समय अनेक प्रकार की नक्सली घटनाएं हुई थीं। वहां पर जो रहने वाले हैं वह इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। क्या यह विकास नहीं है? यह डवलपमेंट नहीं है? मैं इसके लिये भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय । मैं उस विषय में जरूर बोलना चाहूंगा और उसके लिये धन्यवाद भी देना चाहूंगा । राज्य के जो शासकीय कर्मचारियों को लेकर केशलेश उनके ईलाज के लिये जो 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है यह बहुत महत्वपूर्ण है । (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये भी बहुत-बहुत बधाई । हमारे रोजगार का विषय है तो मैं बार-बार इस विषय पर इस बात को कहता हूं, मुझे यहां भी सुनने को मिला कि इतने हजार रोजगार, उतना हजार रोजगार का वायदा-वचन, कोई भी सरकार हो । माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरियां नहीं होतीं । सरकारी नौकिरयां तो यह है कि किसी विभाग, आप किसी स्कूल में प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल ले लीजिये या किसी विभाग में कितनी संख्या में क्लर्क होने, कितने टीचर होने, कितने अनुपात में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मिडिल स्कूल में टीचर होने हैं, कितने लेक्चरर होने हैं यह तो तय है । आप उससे ज्यादा ले भी नहीं सकते लेकिन रोजगार के कई अवसर सुनिश्चित कराने की दृष्टि से और शिक्षित युवाओं को इसका अवसर प्राप्त हो सके । उद्योग को निवेश की दृष्टि से ऐसे 23 नये औद्योगिक पार्क बनाने के लिये जो 250 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है उसके लिये भी वित्त मंत्री जी आपका अभिनंदन, सभी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैंने महतारी वंदन में बताया कि 200 करोड़ रूपये का प्रावधान । अभी तक 24 किस्तों में भुगतान हो चुका है, इसकी विशेषता यह है कि इसका 1 भी महीना खाली नहीं गया । (मेजों की थपथपाहट) 1 तारीख से 3 तारीख के अंदर हमारी बहनों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खातों में 1 हजार रूपये जाना । यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को सिद्ध करता है । हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिये नि:शुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन हेतु 33 करोड़ रूपये का प्रावधान इसमें हुआ है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, बार-बार एयर कनेक्टिविटी का विषय आता था । मैं स्वयं उसका साक्षी हूं क्योंकि अभी मेरी भी बात हुई है । उसकी तैयारी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर पत्र भी और सारा कुछ करने के बाद यह स्थिति बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर ऐसे एयरपोर्ट को विकसित करने हेतु 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसके लिये भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद । बिलासपुर से नियमित फ्लाईट की संख्या बढ़ाना, अंबिकापुर से नियमित फ्लाईट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच में जो फ्लाईट बंद हुई है, बहुत शीघ्र मुझे जानकारी है, मैं यहां बोलूंगा नहीं लेकिन उसकी शुरूआत करने का प्रयास सरकार कर रही है । उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं । प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अपने आप में एक महतवपूर्ण योजना है और इसके अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के साथ-साथ 400 करोड़ रूपये का राज्य सरकार ने जो प्रावधान किया है वह भी बहुत ही उल्लेखनीय है इसके लिये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं । हमारे किसान का विषय बहुत बार विभिन्न-विभिन्न स्त्रोतों से उठता रहा है, आज भी यहां पर उठा है । किसानों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का मैं भरपूर समर्थन करता हूं और बजट में जो प्रावधान किया गया है । जैसे कि प्रदेश के किसानों हेतु कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़, कृषि पम्पों की सब्सिडी के लिये 6700 करोड़ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 820 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसकी भी बधाई और मुख्यमंत्री जी को तो मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि हम जो कहते हैं वह करते हैं, उसको चरितार्थ करते हुए कल ही हमारे 25 लाख इस छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में जो अंतर राशि है उसकी राशि एकमुश्त भेजने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) अधोसंरचना विकास, जी राम जी की बात होती है, कभी यह बात आयी कि वह पहले इस नाम पर था तो कितना, क्या हुआ, उसमें कितनी गड़बड़ी हुई ? पूरे देश में उसकी क्या स्थिति थी ? माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल से यहां तक हमारे पास उसके आंकड़े हैं और जब 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मामला आया तो प्रभु राम के नाम से जी राम जी में जो विकसित भारत है उसके तहत उस योजना में ऐसे 4000

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 825 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1725 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ एवं जल जीवन मिशन में 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से, यहां अधोसंरचना का अच्छे से निर्माण हो सके, इस दृष्टि से जो प्रावधान किया गया है उसके लिए भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। उसी प्रकार से नगर पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए, समग्र विकास के लिए जो सरकार की नगरोत्थान योजना है उसके तहत मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे अनुज जी ने उस एक विषय को रखा है। यह बहुत दिनों से था। मेरे सामने यह भी विषय दो दिन पहले ही आया और यह चर्चा का विषय है कि यहां बहुत दिनों से छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी के निर्माण की बात हो रही है तो उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूँ। आपने अभी बताया कि पर्यटन विभाग द्वार चित्रोत्पला फिल्म सिटी महानदी के नाम से होगा एवं ट्रायबल एवं कल्चरल कंवेंशन सेन्टर विकसित करने के लिए 350 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पिछले बजट का है तो इस तरीके से यह स्कूल शिक्षा विभाग की चर्चा में यह आएगा। मैं सारे विभागों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उपरोक्त जितने भी सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ कि वर्तमान समय में जिस तरीके से देश और विश्व हमारा आधुनिकीकरण को अपना रहा है। पहले ए.आई. के विषय में चर्चा आयी थी उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उस मिशन के अंतर्गत ऐसे 5 मिशन ए. आई. टैलेंट का विकास, ए.आई. से संबंधित स्टार्टअप को प्रोत्साहन तथा ए.आई. से संबंधित शोध, अनुसंधान को गति प्रदान करने की दृष्टि से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, मैं उसकी भी बधाई देता हूँ। यह पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया में और केन्द्र के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है। यहां पर पायलेट प्रोजेक्ट नवाचार इत्यादि के लिए जो इको सिस्टम तैयार किया जायेगा। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के तहत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, खेल उत्कर्ष मिशन के तहत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अधोसंरचना मिशन के तहत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इस तरीके से 500 करोड़ के ऐसे 5 मिशन प्रभावशाली मिशन को लेकर कार्य किया गया है, मैं उसकी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, हमारा मैं पुन: एक विषय जरूर रखना चाहूंगा। हमारे जगदलपुर में बहने वाली बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी पर जो बैराज निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। क्योंकि वह जगदलपुर विधान सभा में है तो मैं उसके लिए जरूर धन्यवाद् देना चाहूंगा कि उसके लिए इसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही आवश्यक था और इसके पहले भी आ चुका है। कि हमारे देउरगांव में 2024 करोड़, मटनार में अन्य बैराज और नहर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, जिससे बस्तर में 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होगी। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। खुसफुसाहट के बीच मैं समझ गया।

श्री रामकुमार यादव :- हूज़ूर, नहीं। मैं वह नहीं कह रहा हूँ। आप भी तो मेन हैं।

श्री किरण देव :- आप भी मेन हैं।

श्री रामकुमार यादव :-हूज़ूर, यह जितना पैसा है, यह आप ही के हाथ से जाएगा।

श्री किरण देव :- आप भी मेन हैं। आपको धन्यवाद्। मैं इस बात को समझ रहा था। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसमें बोलना है। इसमें विस्तार से विषय आएंगे। आदरणीय वित्त मंत्री जी भी इस पर अपना वक्तव्य देंगे। मैं इस अच्छे बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। आप विश्वास मानिये कि इसमें बोलने के लिए बहुत से विषय हैं यह बहुत अच्छा बजट है। मेरे पास और विभागों की बातें थीं मैं कई चीजों पर नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे यह भी डर लग रहा था। मैं उसे विनियोग में बोलूंगा। लेकिन मैं इसलिए आपकी तरफ बार-बार देखकर बोल रहा था क्योंकि आपने समय फिक्स कर दिया था तो मुझे यह भी डर लग रहा था कि मैं समय से ज्यादा न बोलूं।

श्री रामकुमार यादव :- आपसे सब डर रहे हैं।

श्री किरण देव :- नहीं-नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। मैं इस अच्छे बजट के लिए बहुत बधाई देता हूँ मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मैं पहली बार का विधायक हूँ, इस चीज को देखता हूँ। मैं वित्त मंत्री जी के समीप ही बैठता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि वास्तव में बजट बनाना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है, बहुत लंबा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय भी लगता है और वास्तव में विकास के दृष्टि को लेकर मीलों तक की सोच होनी चाहिए । वित्तीय संसाधनों को जुटाने की दृष्टि से, उसका समायोजन करने की दृष्टि से बहुत कठिन काम है । वित्तमंत्री जी ने इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। यह बजट विकास का माईल स्टोन होगा । आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रचना है, उस पर भी टिप्पणी होती है। जब 2047 तक की बात होती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन रखा है जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन रखा है। इसमें एक लाईन जोड़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । कोई भी काम बिना लक्ष्य के संधान किया ही नहीं जा सकता, आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा । 2047 का लक्ष्य है, उस पर टिप्पणी बहुत होती है कि कब तक रहोगे, कैसे होगा, रहोगे या नहीं रहोगे ? यह तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र की अपनी बाध्यताएं हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो विजन है, उसके बाद विजन तक पहुंचने का, उसको टारगेट करके उसको साधने का लक्ष्य बहुत आवश्यक होता है, जिसने लक्ष्य को साध लिया, वह लक्ष्य की पूर्ति तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति महोदय, इस नई विधान सभा के भव्य गुम्बद के नीचे खड़े होकर जब मैं इस 1,72,000 करोड़ रूपए के बजट को देखता हूं या पढ़ रहा हूं । वित्त मंत्री जी गए क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- पानी पीने गए हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- क्या बात है, मेरे उठते ही पानी पीने के लिए चले गए। (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- आपने इतना पानी पिला दिया कि बाजू वाले भी चले गए हैं, वे आ ही नहीं रहे हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- उनके बगैर मजा नहीं आएगा न।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- तब तक केदार जी हैं, उनसे बात कर लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- नेता जी, तब तक कुछ सामान्य बात कर लीजिए न।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो सोच रहा था कि आसंदी में आप बैठे होंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो अभी आप ही को सुनने आये हैं, फिर वहां जाकर बैठ जाएंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- वित्त मंत्री जी आ जाएं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी उनके विपक्ष में भाषण नहीं दूंगा । लगभग आजू-बाजू में जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय किरण देव साय जी ने, साय नहीं हैं, पर मैंने लगा दिया । किरण देव प्लस साय । उन्होंने मर्म की बात कही है, उसी मर्म की बात मैं भी कहना चाहता था और वे मर्म को नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उनको जल्दी बुलवाते हैं, आपके मन को छोटा नहीं करेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- मेरे मन को शांति मिल जाये ।

श्री अनुज शर्मा :- यहां पर के लिए एक पुरानी लाईन है-मोर होगे आती अउ तोर होगे जाती । आगू के ला नहीं बोलवं ।

डॉ. चरण दास महंत :- बोल ना, तब तक वित्त मंत्री जी ह आ जही। बोल-बोल।

श्री अनुज शर्मा :- मोर होगे आती अउ तोर होगे जाती अउ रेंगते रेंगत...।

डॉ. चरण दास महंत :- आंखी मार दिए। (हंसी) तै मारेस कि ओला मार के चल देस?

श्री सुशांत शुक्ला :- नेता जी, हमर बीच के एक सदस्य हे, ओकर आंख ह चीनी-बूटी हो गे हे। (श्री रिकेश सेन की ओर इशारा करते हुए)

डॉ. चरण दास महंत :- का हो गे हे ?

श्री सुशांत शुक्ला :- चीनी-बूटी, छोटे-छोटे ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन आंखी मारे के बात मत करौ, हमन दाई ह बइठे हे।

सभापति महोदय :- वित्त मंत्री जी आ गए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. चरण दास महंत :- वित्त मंत्री जी, मैं शुरूआत कर रहा था । सभापति महोदय को बोल ही रहा था कि आप शायद निकल गए । इस नई विधान सभा के भव्य गुम्बद के नीचे खड़े होकर जब मैं इस 1,72,000 करोड़ रूपए के बजट को देखता हूं, जिसे आपने तीन दिन पहले 24 फरवरी को इस सदन में वित्त मंत्री जी के रूप में 62 पन्नों का बहुत शानदार कलात्मक और काव्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय नेता जी, आपकी तरफ से 2 लाईन मंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- एक मिनट, सटक जाही मोर, जीभ मा अटक जाही। (हंसी) वह मजा किरकिरा हो जायेगा। उन्होंने अपने भाषण के शुरूआत में माथे पर तिलक लगाने और सौभाग्य जगाने वाले छन्दों के साथ शुरूआत की थी। उन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा था कि न चंदन से न वंदन से, मैं तिलक लगाकर आया हूं छत्तीसगढ़ की माटी का।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने माथे पर तिलक तो लगा लिया, लेकिन शायद उस पसीने की गंध को भूल गये, जो इस प्रदेश के किसान और मजदूर के माथे पर बदहाली की इमारत लिखी जा रही है। अब तै बोल ले। तै बोल ले न गा।

श्री अनुज शर्मा :- बस इतना सा कह रहा था, एक शेर याद आ गया था।

क्यों न रोके तुम्हें, उठकर जाते हो तुम,

जान जाती जब उठकर जाते हो तुम।

आज जाने की जिद न करो।

आप माननीय मंत्री जी को मिस कर रहे थे, जब तक वह आये नहीं थे। तो मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करा रहा था।

डॉ. चरण दास महंत :- वह तो जिद करने वाली बात ही थी, यहां से तो भाग ही गये थे।

श्री अनुज शर्मा :- नहीं-नहीं, वह आपको सुने बगैरे कैसे जायेंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी बोल देता हूं:-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,

कमाल यह है कि तुम्हे यकीन नहीं।

डॉ. चरण दास महंत :- Thank you. तो मैं कह रहा था कि आपने किसान और मजदूर माथे पर बदहाली की इमारत लिखी जा रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप शेरो-शायरी में बिलकुल विचलित मत होइये। आप बहुत बढिया भाषण देते हैं। आपकी अदा, हम लोगों को आपकी स्टाइल बहुत पंसद है। इसलिए मैं दो लकीर बोल देता हूं फिर आप आगे बोलियेगा (हंसी) -

इश्क भी आप हैं, मोहब्बत भी आप हैं

और इस सदन में हम देख रहे हैं तो चरण दास जी आप ही आप हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी,

न तू जमी के लिए है न आसमां के लिये,

तेरा वजूद है, इस जहां के लिये।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, पूरा होली का माहौल आ गया।

सभापति महोदय:- नेता जी, आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं आप विचलित मत हाईये।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मैं विचलित नहीं हो रहा हूं जनाब। इन्हीं के मन में जो भाव आ रहे हैं, यहां के हमारे विधायक जी ने जिस मर्म को देखा, प्रस्तुत किया और कुछ छपा-छपा के किया, आज मैं उसी अंदाज में बोलना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, मुझे यह बजट एक ऐसी हाई डेफीनेशन (एच.डी.) जिसको एच.डी. फिल्म बोलते हैं, हाई डेफीनेशन फिल्म की तरह लगा। मंत्री जी, जिसको आप बहुत ही टूटी हुई जर्जर स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं। फिल्म के जो दृश्य बहुत रंगीन हैं। संगीत मधुर है, विजुवल इफेक्ट भी कमाल के हैं। लेकिन आप जिस स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को यह फिल्म दिखाना चाहते हैं, वह स्क्रीन गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, अधूरी क्रांति के कारण टूटी फूटी हुई है। बजट के आंकड़ों का श्रृंगार तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आत्मा और आम आदमी की जरूरत इस बजट में कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं एक बात कहूं, आपके साथियों को बुरा लग सकता है। आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आपने पिछली बार भी उन्हें पूरा बजट का संपूर्ण आशीर्वाद, प्यार और सब सौंपा। जब पिछली बार बजट भाषण दे रहे थे तो मैंने गिनकर बताया था कि शायद उस दिन बुरा लगा होगा, आपने 15-20 बार प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का गुणगान किया था। मगर जरा आप देखियेगा कि इस साल वह अचानक सिमट कर मात्र 5 में रह गया है। इसका अर्थ क्या होता है? क्या डबल इंजन की सरकार का एक डिब्बा टूटकर छूट गया है या पटरी से उतर गया है या दिल्ली से आने वाली मदद आपको आधी होने लगी है। क्या बात है, यह मैं नहीं जानता, मगर आपके भाषण से मुझे यह दर्द छलक रहा है। मगर आपके भाषण से मुझे ये दर्द छलक रहा है और ये भी देख रहा हूं कि आप मदद की बात तो करते हैं मगर मदद शायद आपके ख़ज़ाने तक नहीं पहुंच रही है और वह विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई है।

समय : 5.35 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

इसलिए मुझे इस बात का दुःख है कि जब केंद्र से पैसा नहीं आता और वादे अधूरे रह जाते हैं, शायद नाम लेने में भी संकोच लगता है। मंत्री जी, यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, यह केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती हुई इस दूरी और अविश्वास का पहला दस्तावेज़ी प्रमाण है, जिसे आप विज्ञापनों से ढक नहीं पाएंगे। आप सोच रहे हैं या गंभीर हो रहे हैं, मैं नहीं जानता। जब मैं बजट के उस हिस्से पर आता हूं जिसे वित्त मंत्री जी ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए बड़े उत्साह से सी.जी. वायु योजना की घोषणा और उस पर 110 करोड़ का प्रावधान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बताया था, तब आपने कहा था कि ये जो पहले उड़ान योजना थी, यह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई एक सौगात है। आज ऐसा क्या हो गया कि आपको सी.जी. वायु योजना छत्तीसगढ़ के लिए अलग से लाना पड़ा? क्या यह उड़ान योजना की विफलता है? पिछले साल इसी सदन में आपने उड़ान योजना के बारे में बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, आपने कहा था कि बस्तर और सरगुजा हवाई जहाज सांय-सांय दौड़ेगा। अगर केंद्र की यह योजना सफल थी तो आज छत्तीसगढ़ के करदाताओं का 110 करोड़ रुपया आप इस पर खर्च क्यों कर रहे हैं? मैं जानना भी चाहता हूं। आपने बताया तो है कि 80 करोड़ का हम रनवे बनाएंगे और नाइट लैंडिंग की बुनियादी ढांचे तक खर्च करेंगे और 30 करोड़ रुपये उड़ान चलाने के लिए जो वी.जी.एफ., वी.जी.एफ. को कितने लोग समझते हैं, मैं नहीं जानता, वी.जी.एफ. के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। माननीय सभापति जी, डबल इंजन की सरकार है। उड़ान दिल्ली की है। फोटो दिल्ली की है। वाह-वाही दिल्ली की है और उसका सारा खर्च छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के नाम पर खज़ाने में लुटाया गया, लुटाया जा रहा है, क्या होगा मैं नहीं कह सकता। मगर बस्तर और सरगुजा हवाई अड्डों को तो आपने केवल चुनावी पर्यटन का केंद्र बना दिया है। आपने अभी जो राज्य के लिए नई योजना शुरू की है, वह सिर्फ़ आपके पुराने उड़ान योजना के मलबे को ठीक करने के लिए की है, ऐसा मैं मानता हूं। सभापति महोदय, G RAM G की आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर मैं उसका पूरा नाम या पूरा स्पेलिंग तो नहीं बोल रहा हूं, मगर आपने राजनीति और आस्था का बहुत ही खतरनाक घालमेल कर दिया है। आपने नाम बदला। यह एक जीवनदायिनी ग़रीबों की योजना थी और आपने इसका भार 40% हम पर लाद दिया। हम जानते हैं कि नाम बदलने पर ज़्यादा आपका, चूंकि अब रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, उस नाम से छत्तीसगढ़ वाले तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। मगर मज़दूरों के साथ किए जा रहे जो आर्थिक छल आपने उसमें वी.बी.जी.राम जी. का नाम जोड़ा है, वह हम लोगों को पसंद नहीं आया है। हालांकि आपने नाम नहीं जोड़ा है, अब आप कहते हैं विकसित भारत तो मैं कह देता हूं विकसित भारत का आपका वि.बी. हो गया। गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। किसी तरीके से राम जी का नाम इसमें लगाकर आपने इसे वी.बी.जी.राम जी. कह दिया। मगर इस तरह से अंग्रेज़ी-हिंदी, अंग्रेज़ी-हिंदी का जो उपयोग आपने और ऊपर वालों ने किया है, वह अच्छा नहीं लग रहा है। अब आपको कितना अच्छा लग रहा है आप करिए, हमें कुछ नहीं कहना है। पिछले साल मज़दूरी का पूरा पैसा आप कहते थे, हम जानते हैं लगभग पूरा का पूरा 100% केंद्र सरकार से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आता था और छत्तीसगढ़ का दस पैसे भी नहीं लगता था। अब आपने अपना 400 करोड़ पैसा लगाकर यह कह रहे हैं कि हम मजदूरों को 125 दिन का रोजगार देंगे। आपने पिछली बार 10,000 करोड़ का काम कराया और औसतन काम सिर्फ 52 दिन का हुआ है। अभी आप 4000 करोड़ या 40% के हिसाब से काम देंगे, 60% पैसा केंद्र सरकार का आएगा तो कितने दिन का काम होगा? अब मैं सफ़ेद झूठ कहूँगा तो शायद गलत हो जाएगा। आपका पिछले वर्षों के काम का रिकॉर्ड दिखा रहा है, उसके लिए यह 4000 करोड़ बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हो सकता है, आप कहें कि हम आने वाले दिनों में इसको बढ़ाएंगे, आगे करते रहेंगे, मगर यह गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ। राम का नाम बदनाम ना करो वाली गाने जो भाई जी सुना रहे थे, उसी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस छलावे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को इस तरह से छोटी-मोटी जगह न घसीटें, यह हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। सर, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो इस सरकार का अपना आधार है, जिसे उन्होंने बताया, हमने माना। चाहे किसी भी सरकार की बात हो। यहाँ का किसान परेशान हैं। आपने इसमें कृषि उन्नति की बड़ी-बड़ी बातें शामिल की हैं, मगर इस बार धान खरीदी में किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के सरकार से जो वादाखिलाफी हुई है या की गई है, वह बहुत दुखद है। जिसके बारे में हमारे सभी सदस्यों ने बोला है। लगभग 22 सदस्यों ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी-अपनी बातें रखी हैं। वे सब बातों को कह गये हैं। इसलिए मैं स्वयं ही अभी खाते-खाते वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आखिरी भाषण देने वालों के लिए कुछ भी नहीं बच पाता, सभी बातें कह जाते हैं। उसी उलझन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर यह प्रधानमंत्री जी की गारंटी में थी। आपने यह कहा था कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। आपने कहा था कि हम 3100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे। आपने दिया, मगर धीरे-धीरे आपको या सरकार को क्या हो रहा है, यह मैं समझ नहीं पाया कि इस बार धान खरीदने के लिए आपने इतने सारे आपत्ति लगा दी थी कि हमारा किसान खून के आँसू रो रहा है। कल भी मैंने इस बात को कहा था। बुजुर्गों को तो यह कहना पड़ रहा है कि साहब, जितना अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह के कष्ट नहीं दिए थे, उतना इस बार इस तरह से गरीबों एवं किसानों को कष्ट हुआ है। चाहे वह पंजीयन के बहाने हो। उदाहरण के लिए वर्ष 2024 में 97.13 लाख एकड़ में धान बोया गया था, लेकिन अगर उसके पंजीयन को देखें तो उसके हिसाब से सिर्फ 83.73 लाख एकड़ आता है। अब मैं यह कहूँ कि वह 13,40,000 एकड़ का रकबा कहाँ गायब हो गया? तो आपका जो कृषि विभाग का आंकड़ा है, वह दूसरी बात करता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, आपने इकोनॉमिक सर्वे का किताब छपवाया है, वह दूसरी भाषाओं में बात करता है और यह जो 13,40,000 एकड़ गायब हुए हैं, उसके धान का हिसाब-किताब नहीं मिल रहा है। जो किसान पंजीयन कराने के बाद खरीदी से वंचित हुए हैं, उनकी संख्या 2,29,000 हैं। इस प्रकार से 8.24 प्रतिशत पंजीकृत किसान, अपने टोकन के बावजूद भी धान नहीं बेच पाए, यह एक बहुत दुखद बात रही। भले ही आप कहें, पीठ थपथपाएं कि हमने 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, लेकिन आप यह आंकड़ा भी देख लीजिएगा। यह षड्यंत्र से छुपा हुआ लगता है, क्योंकि किसान मंडी के बाहर धान लेकर घूमता रहा है, उसका रकबा कम हो गया। उसकी रिकॉर्ड खरीदी कैसे हो गई? यह आपके और मेरे समझ के बाहर है। आपने किसान को निर्मल जल का वादा किया, वह आप नहीं दे पाये। वित्त मंत्री जी, मैं आपकी ही बात याद दिलाना चाहूंगा। चुनावी जोश में आपने एक बार कलेण्डर लेकर भाषण दिया था कि मैं एक साल नहीं बल्कि दो साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां भरकर दिखाऊंगा । आपकी सरकार को दो साल से ज्यादा हो गये, लगभग 27 महीना हो गये हैं, कैलेण्डर की तारीखें बदल गई, लेकिन 1 लाख युवाओं की किस्मत नहीं बदली हैं । आपने विज्ञापन छपवाया, विज्ञापन की तारीखें खत्म हो गई, मगर नियुक्ति की तारीख अभी तक नहीं आई । आपने कहा कि बस्तर फाईटर्स बना रहा हूँ, आपने 1500 की घोषणा की है, 1 लाख के बजाय 1500 को नौकरी देकर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं । यह हमें पसंद नहीं आ रहा है । आप छत्तीसगढ़ के आई.ए.एस. समुदाय से आये हुये मंत्री हैं, आपको इस तरह से राजनीतिक उलझनों में फंसकर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ आप ऐसा मत करिये । आप चाहते हैं कि हमारे युवा छत्तीसगढ़ के हैं, आपने पिछले साल 12 नर्सिंग कॉलेजों का वादा किया था, आप बतायेंगे कि 12 खुल गया है और 4 इस साल का कोटा है । आप बतायेंगे कि 12 किसी कारण नहीं खुल पाये हैं और 4 इस साल खुलेंगे । सभापति महोदय, मैं पूरा देख रहा था, पिछले साल आपने कहा था कि नवा रायपुर में निफ्ट टेक्नॉलाजी संस्थान खुलेगा । 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी का भव्य सपना आपने दिखाया था। आपके इस बजट की किताब में कोई भी निफ्ट शब्द मुझे नहीं मिला । शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा कि केवीएस हम शुरू करने जा रहे हैं, इससे आने वाला भविष्य सुधर जायेगा । सरकारी स्कूलों का छत हर जगह टपक रहा है, आप सुपरस्पैशियलिटी अस्पताल की बात करते हैं, बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों में अभी एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है । रायपुर का आपका मेकाहारा का अस्पताल टेक्निशियन के अभाव में अभी तक चल नहीं पा रहा है । बीमार बच्चे, युवतियां, हमारे महतारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जैसे भी हैं, वहां से रोकर वापस जा रहे हैं । आप सुधार कहां पर कर रहे हैं, स्पष्ट कर दीजिए तो बेहतर होगा । आपने रानी दुर्गावती के लिये मात्र 15 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है । हमारी आबादी 3 करोड़ की है । आप 15 करोड़ में कितने बच्चों को पढ़ा पायेंगे, कितने बच्चों को शिक्षा दे पायेंगे, कितने बच्चे स्कूल जाकर पढ़के, लिखके, अधिकारी-कर्मचारी बनेंगे, कितने की शादी होगी, यह आप बतायेंगे । आपने पिछले बजट में जोर-शोर से यह बात कही थी कि पेट्रोल में हम एक रूपया कम कर रहे हैं । ऐसा लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर आपकी कलम पूरी तरह से सूख चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है, परिवहन महंगा हो रहा है, लेकिन आम आदमी के राहत के लिए आपने इस बजट में एक शब्द नहीं कहा है। आपकी इस बजट की किताब में कुछ भी नहीं है। आपने मोदी जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी जी की गारंटी के नाम से टाइमलाइन पर आधारित किया था। आपने 18 लाख पीएम आवास को 26 लाख कर दिया, मगर उस 26 लाख में से कितने आवास बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में और बस्तर में खास करके गाँव के एरिया में, आप ज़रा सुनिए या देखिए या जाइए, बस्तर में आप दंतेवाड़ा में रहे हैं। प्रथम किस्त जारी हो गया, दूसरा किस्त मिल नहीं रहा है और रो-रो के अभी तक उनके घर के छत भी नहीं ढल पाए हैं। आपने हर घर में नल का वादा किया था कि दो साल के भीतर छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल होगा। मैं टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी गरीबों की प्यास बाकी है, घरों तक आपका पानी नहीं पहुँचा है। आप अभी कुछ बोनस देने जा रहे हैं तो मैं इस बात को नहीं कहूँगा, धान का बोनस दे रहे हैं, पिछले चुनावी वर्ष का बोनस दे रहे हैं कि अभी आप जो बोनस देने वाले हैं वह दे रहे हैं, वह तो कल देने के बाद समझेंगे। मगर यह बजट गरीब और किसानों के लिए कोई सम्मान नहीं दे पा रहा है। आप उसको देखिएगा। सिर्फ अनंत इंतज़ार दे रहा है। वह अनंत इंतज़ार जैसा कि हमारे लोग कह रहे थे, वह 2047 का है कि इन तीन वर्षों का है, आप तय करिएगा। आपने दूरगामी सड़क संपर्क योजना बताया है। सैकड़ों नहीं करोड़ों रुपये आपने उस बजट में आवंटित किया है और उस आवंटन को आप बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करा पाएँगे तो हमें खुशी होगी, नहीं तो हम आपका विरोध करते रहेंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि केवल कांक्रीट सड़क से ही छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो जाएगा। उस सड़क पर चलने वाले मज़दूर जब तक भूखे रहेंगे, काम नहीं मिलेगा, उस सड़क के आसपास बने हुए अस्पतालों में जब तक डॉक्टर नहीं आएँगे, टेक्नीशियन नहीं आएँगे, तब तक आपका विकास अधूरा माना जाएगा। आपने राजस्व प्रशासन के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपहार प्लेटफ़ॉर्म और साइबर तहसील की बात कही है। डिजीटल प्रशासन अच्छा है, जिस किसान को अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड के लिए आज भी पटवारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आज भी हमें ध्यानाकर्षण लगाना पड़ता है, किस बात की आपकी साइबर तहसील होगी ? उसमें कितना काम करा पाएँगे, आप उसमें विचार करिए। आपने एक बहुत अच्छी बात ग्रीन बजटिंग बताई है। ग्रीन बजटिंग से मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, छत्तीसगढ़ में जितने पेड़-पौधे लगे हैं, उनको भी आपकी ओर से सरकार की ओर से संरक्षण मिलेगा। मगर आप कई महीनों से सुन रहे हैं, जब से आप आए हैं तब से सुन रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री जी शपथ नहीं ले रहे हैं तब से सुन रहे हैं कि उनके आने से पहले ही हसदेव की कटाई हो चुकी थी और कटाई होना था। तमनार में लकड़ी की कटाई चल रही थी, पेड़ों की कटाई चल रही थी, पुलिस के डंडे खा रहे थे, हमारी बहन गिरफ़्तार हो गई थी जो यहाँ विधायिका के रूप में बैठी है और आज भी उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। अब अध्यक्ष जी के बस्तर में, हमारे उपनेता के बस्तर में फिर से पेड़ काटने वाले पहुँच चुके हैं । इस ग्रीन बजटिंग में क्या पेड़ काटना नहीं आता? क्या इसके लिए आपको एनजीटी का कोई निर्देश नहीं है? क्या यह सरकार पालन करेगी? क्या यह आपके बजट का हिस्सा है? आप यह देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब माथा में आप यहाँ का टीका लगा के अपना सौभाग्य मानते हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आँखें बंद करके आप सिर्फ मंत्री पद पर खुश मत होइए, छत्तीसगढ़ की सेवा कीजिए, यह मैं कहना चाहूँगा। आपने एक बात बड़े ज़ोर-शोर से कही भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाता है, मानव इतिहास बनाता है तो इतिहास रचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यह मेरी आपको समझाइश है और अगर नीयत नहीं है तो आप किसी का भाग्य नहीं बना सकते, इसके लिए नीयत होनी चाहिए। इस बजट में नीयत की कमी है। मजदूरों के लिए श्रम का एक नया और खतरनाक जाल है। युवाओं के लिए एक्सपायर हो चुका एक ऐसा पुराना कैलेंडर है, जिसमें वह नौकरी के विज्ञापन और नौकरी की तारीख देख रहे हैं। किसानों के लिए केवल शब्द और नारों की खोखली खेती है जो इस बार उन्होंने भुगत लिया है। प्रदेश की जनता के लिए 110 करोड़ रूपये जैसे गैर जरूरी हवाई खर्चे शामिल हैं। इन सबको मैं विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप नहीं मानता, बल्कि पिछले साल की विफलताओं को छिपाने के लिए एक सफेद असत्य का पुलिंदा मानता हूं और इसे सांय-सांय धोखा मानता हूं। सभापति महोदय, मैं इस दिशाहीन और युवा विरोधी, मजदूर विरोधी और आंकड़ों की बाजीगरी वाले बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। ऐसे बजट का मैं सम्मान नहीं कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सकता। यह भविष्य को उज्ज्वल बनाने का नहीं, बल्कि हमारे भविष्य, हमारे छत्तीसगढ़ को धुंधला बनाने का बजट है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर देने का यह अवसर प्रदान किया है। इस बजट की सामान्य चर्चा में कल और आज मिलाकर जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया, आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आदरणीय संगीता सिन्हा जी, मोतीलाल साहू जी, रामकुमार यादव जी, उद्देश्वरी पैकरा जी, ब्यास कश्यप जी, उमेश पटेल जी, धरमलाल कौशिक जी, हर्षिता स्वामी बघेल जी, अनुज शर्मा जी, तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम जी, शेषराज हरवंश जी, कुंवर सिंह निषाद जी, चैतराम अटामी जी, राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, दलेश्वर साहू जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे जितने भी प्रतिभागी जो इस चर्चा में शामिल हुए, उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पक्ष-विपक्ष दोनों पक्ष के साथियों को इस स्वस्थ परिचर्चा में भाग लेने के लिए मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के बिंदुओं पर कुछ प्रकाश डालूंगा। उससे पहले जो आर्थिक गति चल रही है और जो हमने सम्माननीय सदन में इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट भी किया है, उसके बिंदुओं को मैं रखना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, वह बहुत सुखद तरीके से आगे बढ़ रही है और वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्रचलित दरों पर हमारी जी.डी.पी. ग्रोथ का जो अनुमान है, वह साढ़े ग्यारह प्रतिशत (11.57 प्रतिशत) है, जो राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत से अच्छी तरह से ज्यादा है। तो एक अच्छे ग्रोथ रेट के साथ हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यह सुखद बिंदु मैं सम्माननीय सदन में आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर हम क्षेत्रवार इसकी तुलना करे तो कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 0.8 प्रतिशत का जो ग्रोथ रेट है, उसकी तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र 12.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से साढ़े छह प्रतिशत (6.6 प्रतिशत) की वृद्धि है और हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 10 प्रतिशत से ऊपर है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत है और सेवा क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर सवा तेरह प्रतिशत है। हमारे छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

है। यह बिंदु मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधि जो इतनी तेजी से आगे बढ़ी है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, जनता जनार्दन ने अपने-अपने क्षेत्रों में, अपनी-अपनी जगह में जो भूमिका निभाई है, चाहे वह किसान भाई हों, चाहे वह मजदूर भाई हों, चाहे छत्तीसगढ़ की माताएं-बहनें हों, हमारे छत्तीसगढ़ के उद्यमी हों, व्यापारी हों, सबने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए सबके उद्यम से, सबके पराक्रम से, सबके परिश्रम से, मेहनत से यह वृद्धि दर संभव हो पा रही है और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता जनार्दन का अभिवादन करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो पहला बजट प्रस्तुत किया था, उसमें हमने GYAN के रूप में समर्पित किया था। जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी थी। इन वर्गों के कल्याण के लिए हमने समर्पित किया था और जो हमारा संकल्प पत्र था, हमारा जो मेनिफेस्टो था, उसमें हमने इन वर्गों के लिए जो बड़े वायदे किए थे, उस पर पूरी तरह से हमारे प्रथम बजट को डेडिकेट किया था और उसी का परिणाम रहा कि हमारी सरकार बनने के मात्र 12 दिनों के भीतर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन 3,716 करोड़ रुपए की राशि किसान भाइयों के खाते में अंतरित की गयी। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, 3,100 रुपए के भाव से 21 क्विंटल धान की खरीदी करना, यह भी उस बजट में शुरू से ही प्रारंभिक बिंदु रहा। महतारी वंदन योजना को लागू करना, आवास योजना को लागू करना, ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु रहे। जिन बिंदुओं पर कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता जनार्दन को छला गया था, उन बिंदुओं को हमने एड्रेस किया और लोगों के कल्याण के लिए काम किया। हमने उसके लिए हमारे प्रथम बजट को डेडिकेट किया। हमारा बजट GYAN के लिए समर्पित बजट रहा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो दूसरा बजट प्रस्तुत किया, उसमें हमने चिंता की कि GYAN का वेलफेयर तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकता जब तक उसके लिए स्पष्ट रणनीति न हो। इसलिए हमने GATI की रणनीति प्रस्तुत की। G के लिए गुड गवर्नेंस, A के लिए एक्सेलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T के लिए टेक्नोलॉजी और I के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इंडस्ट्रियल ग्रोथ। GATI की रणनीति के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास दर को प्राप्त करके GYAN के वेलफेयर के लिए जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं, हमारी योजनाएं चल रही हैं, वह हमेशा चलती रहें। वह तभी संभव है जब तीव्र आर्थिक विकास होता रहे। हमने इस रणनीति के साथ, GATI की रणनीति के साथ दूसरे बजट को प्रस्तुत किया।

इस बार भी हमने जो SANKALP का बजट प्रस्तुत किया है, उसके पीछे जो हमारी सोच है, वह GYAN का उत्थान ही है। हम चाहे आर्थिक स्तर पर कोई भी रणनीति अपनाएंगे, किसी भी तरीके से तीव्र आर्थिक विकास दर को प्राप्त करेंगे परंतु उसका अंतिम ध्येय समाज होगा, समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति होगा, समाज के भीतर जो गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है, वह होगा। GYAN के उत्थान के लिए संकल्प की रणनीति के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने हमारा तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, S के लिए समावेशी विकास, A के लिए अधोसंरचना, N क लिए निवेश, K के लिए कुशल मानव संसाधन, A के लिए अंत्योदय, L के लिए लाइवलीहुड और P के लिए पॉलिसी से परिणाम तक। यह शब्द अपने आप में एक होलिस्टिक रणनीति को, एक समग्र नीति को प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे अनेक साथियों ने, विशेषकर हमारे सम्मानीय सदस्य श्री रामकुमार जी बार-बार 2047 की बात बोलते रहते हैं। हमारे विपक्ष के अनेक साथी बोलते रहते हैं, अकेले रामकुमार भाई बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। 2047 की बात, 2047 की बात। सभापति महोदय, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में देश विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इस विकास यात्रा में पूरे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्पष्ट रोडमैप बनाकर, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच से, लाखों लोगों से सलाह लेक, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, रोडमैप बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई भी दीर्घकालिक लक्ष्य किसी भी समाज, राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति, परिवार के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे सभी सम्माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, मैं हमारे सभी साथियों से पूछना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहूंगा कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी की योजना नहीं बनाते? क्या हमारी next generation कैसे सेटल होगी, हमारा बच्चा, बेटा कैसे सेटल होगा, इसकी चिंता नहीं करते? चाहे उसके आर्थिक तो छोड़िये, राजनीतिक चिंता भी बखूबी की जाती है कि कैसे राज्यसभा तक पहुंचाया जाये। विधान सभा में भी हमारे सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिये मीडिया में चर्चा हो रही है कि वह जल्दी राज्यसभा जाने वाले हैं और आदरणीय सूरज जी सक्ती से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा मैंने सुनी है। आपके माध्यम से सभी सम्माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हम सब लोग next generation की चिंता करते हैं। जब हम अपने परिवार के next generation की चिंता करते हैं तो क्या किसी राष्ट्र या राज्य के next generation की चिंता नहीं करनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) और देश का यह दुर्भाग्य रहा कि आजादी के कई दशकों तक केवल साल भर की या 5 साल की चुनावी राजनीति के लिये ही देश में नीति, नियम बने और केवल परिवार के लिए ही नीति, नियम बने। केवल चुनावी वोट बैंक की राजनीति के लिये नीति नियम बने। किसी ने दूर की बात नहीं की। हम सब लोग relevant topics पर निबंध लिखते थे। जब हम लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी थे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी हों, आदरणीय हमारे विपक्ष के, पक्ष के साथी हों, जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग कभी निबंध लिखते थे तो कभी भी ''विकसित भारत'' शब्द हम लिखे ही नहीं और पढ़ाई में सुने ही नहीं। सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी का विजन है, एक दूरदर्शी सोच है कि भारत अपनी आजादी के जब 100 साल पूरा करेगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरा करेगा।(मेजों की थपथपाहट) यह कोई दिवास्वप्न नहीं हैं, कोई शेख चिल्ली का सपना नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक कंक्रीट रोड मैप पर आधारित सपना है।(मेजों की थपथपाहट) जिसमें 2035 के, 2030 के मिडटर्म टारगेट डिसाइड हैं। जिसमें मध्यकालिक लक्ष्य तय हैं। अभी जो बोला जाता है कि अभी क्या है, अभी क्या है। आज जो बजट है वह आपके सामने है। 2047 के लक्ष्य का एक दीर्घकालिक, मध्यकालिक लक्ष्य है और जो आज का बजट है वह हमारा एक वर्षीय लक्ष्य है। इसलिए हम पूरी तरह से अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक लक्ष्य की रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, बजट के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं उस पर और ज्यादा विस्तार से आज चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो फ्लैगशिप योजनायें हैं, वह निरंतर अच्छे तरीके से चलती रहें, यह हम वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर रहे हैं। चाहे कृषक उन्नति योजना के लिये 10

हजार करोड़ रुपये, महतारी वंदन योजना के लिये 8200 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिये 6500 करोड़ रुपये, बिजली की एनर्जी सब्सिडी के लिये 6700 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के लये 4 हजार करोड़ रुपये, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के लिये 1500 करोड़ रुपये, जैसे रूटिन स्कीम्स के लिये हम पूरी तरह से प्रावधान किये हैं। पिछले दो सालों से कोई भी रूटिन स्कीम हो, तमाम चुनौतियों के बाद कहीं पर डिस्टरबेंस हमने नहीं आने दिया है।(मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, उस समय की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में योजना के नाम में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है, यह बोल करके उस योजना को ही रोक देने का दुष्कृत्य किया गया था। (शेम-शेम की आवाज) हमारी योजनायें अच्छे तरीके से चल रही हैं। इन सारी योजनाओ को चलाते हुए भी हम नई योजना भी लेकर आ पाने में सफल हुए हैं। तमाम तरह की चुनौतियों के बीच में, वित्तीय चुनौतियों के बीच में हम ये सब लाने में सफल हुए हैं। अभी विकसित भारत जी राम जी की चर्चा रही थी। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी भी उसके नाम में आपत्ति कर रहे थे। वह कह रहे थे कि ये कैसे चलेगी। हमारे कई विपक्ष के साथियों ने कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा की तुलना में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना हम लोग लेकर के आये हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैंने बजट भाषण में भी जिक्र किया था कि मनरेगा योजना उसी साल लागू हुई थी जिस साल मैं आई.ए.एस. में चयनित हुआ था। मैं अपने जीवन की इतनी लंबी यात्रा करते हुए, 20 साल से अधिक की लंबी यात्रा करते हुए आज यहां पर खड़ा हूं और मनरेगा वहीं के वहीं खड़ी थी। हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं और 20 साल तक किसी योजना में अगर हम कोई प्रासंगिक परिवर्तन नहीं करेंगे तो कैसे कोई योजना समाज और अर्थव्यवस्था के लिये प्रासंगिक रह सकती है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, बजट बढ़ाकर मजदूरी भुगतान के दिन को जिस लिमिट में भुगतान होगा उसको कम करके, मानव दिवस बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी योजना माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लागू की है और आप सब लोगों को पता है, पूरे सदन के माननीय सदस्यों को पता है कि कैसे मनरेगा से जो टेंजिबल एसेट्स (Tangible assets) जिसको हम बोलते हैं दिखने वाली परिसंपत्तियां, अच्छी परिसंपत्तियां, श्रम के साथ-साथ, रोजगार के साथ-साथ वह क्रियेट नहीं हो पा रहा था और यह सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

। आज राज्य 40 परसेंट लगायेगा, बिल्कुल लगायेगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं । वित्तीय रूप से हमारी पूरी तैयारी है और उससे Tangible assets भी क्रियेट हो पायेंगे । अभी क्लियर गाईडलाईन नहीं आ पायी है लेकिन मैं पूर्णत: आश्वस्त हूं कि हमारे ग्रामीण विकास के लिये जितने सारे बजट की जरूरत पड़ती है, जो महत्वपूर्ण कार्यों को करना पड़ता है वह सब हम कर पायेंगे और पहले जो मनरेगा स्कीम चलती थी, उसमें जो अच्छे तरीके के काम जो हम करना चाहते हैं, हमारे सभी विधायक साथी करना चाहते हैं जिसको हम नहीं करा पाते थे । आज उस तरह के काम जो हम समग्र में या अन्य योजनाओं में जो हम लेते हैं प्राधिकरण की योजना में उस तरह की भी अनेक योजनाओं को हम कर पायेंगे और हमारा 40 परसेंट लगकर अगर 100 परसेंट का काम राज्य में होगा तो यह हमारे राज्य के लिये बेहतर है और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पायेंगे उसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि केंद्र का 60 प्रतिशत हमको सपोर्ट मिलेगा, मैं उसे उस रूप में देखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शहरी विकास के लिये जो हमारी अधोसंरचना की स्कीम चलती है । वह ऑलरेडी चल ही रही है, उसमें भी हमने बजट आवंटन बढ़ाया है । पिछले बजट में हमने नगर निगमों के हमारे प्रदेश में जो 14 नगर-निगम हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि बहुत बड़ी हमारे छत्तीसगढ़ी भाई-बहनों की संख्या वहां पर निवासरत रहती है तो अच्छे प्रोजेक्टस जो करने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिये साढ़े 400 करोड़ रूपये की नगरोत्थान योजना भी हम कंटीन्यू चला रहे हैं । पिछले वर्ष हमने नगरोत्थान योजना प्रारंभ की थी और इस बार भी हमने उसमें साढ़े 400 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया है। उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अधोसंचना की योजना जो पहले चलती थी, वह चलती रहेगी। पिछले साल हमने नगरोत्थान योजना चालू की वह भी कंटीन्यू रहेगा और उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए नगर पालिका, नगर पंचायतों में विकास कामों को और आगे बढ़ाने के लिये मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ रूपये की हमने लागू की है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे अधोसंरचना विकास हो, नेशनल हाईवे हो, उसके लिये युगांतकारी काम हो रहा है और उसके अलावा भी जो हमारी राज्य की सड़कें हैं । हमारे राज्य की जो सड़कें हैं उनकी दृष्टि से छत्तीसगढ़ की 36 सड़कों को मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना से जोड़ने का हमने निर्णय लिया है । जिसमें मिनिमम टू लेन की सड़क हर जगह पर होगी । (मेजों की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थपथपाहट) स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना हो, वह भी हमने एक नयी योजना लागू की है । (मेजों की थपथपाहट) अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने एप्रिशियेट भी किया कि केशलेश चिकित्सा, हमारे आदरणीय किरण देव जी ने उसमें विशेष रूप से जिक्र किया । केशलेश चिकित्सा सुविधा, आप सब लोगों को पता है कि सालों से नहीं, दशकों से इस चीज को हम देख रहे हैं, कर्मचारी साथियों को जब बीमार होते हैं तो उनका बिल तो प्रतिपूर्ति किया जाता है, वह हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको तो फायदा मिल जाता है लेकिन उसके पहले हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले पैसा भी उनको देना पड़ता है फिर बिल क्लियर कराने के लिये कितने ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने तरह के करप्शन का और गलत-गलत प्रेक्टिस का उनको सामना करना पड़ता है, यह चीज दशकों से चली आ रही थी । हमने सोचा, हमने चिंता की कि जब पैसा खर्चा हम करते ही हैं लेकिन कोई जबरदस्ती ऑफिस में घुमाता है, अगर कोई इस विषय पर भ्रष्टाचार करता है तो क्यों न हम उसको केशलेश कर दें और इस सोच के साथ हमने केशलेश चिकित्सा सुविधा हमारे कर्मचारी साथियों के लिये प्रारंभ की है । हमारे छत्तीसगढ़ के युवा केंद्रीय स्तर की प्रतियोगी परिक्षाओं में भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें इसके लिए सी.जी.एस. छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एक्जाम यह योजना प्रारंभ किँया है और हमने इसके तीन कम्पोनेंट तैयार कियें हैं जिसमें उड़ान, शिखर और मंजिल है। उड़ान में नीट, जेई और क्लैट की प्रतियोगी परीक्षा तैयार करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी शिखर के माध्यम से यू.पी.एस.सी., सी.जी.पी.एस.सी. की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और मंजिल के माध्यम से रेलवे, बैंकिग और एस.एस.सी. की तैयारी करने वाले जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको मदद मिलेगी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, अभी सी.जी. वायु का काफी लम्बा जिक्र हुआ । हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे। उन्होंने उड़ान योजना और सी.जी. वायु योजना दोनों को लेकर कई सारे सवाल उठाये। आजादी के बाद वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2014 तक 67 सालों में जितने एयरपोर्ट बने थे, उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ही बनवा दिया। उन्होंने उड़ान योजना लाते हुए देश में एक विजन रखा कि एक दिन हवाई चप्पल पहनकर चलने वाले व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ेगा। यह हमारी सोच है और इसी उड़ान योजना का परिणाम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में आज एयरपोर्ट बन पाया। अंबिकापुर में एयरपोर्ट बन पाया, बिलासपुर में एयरपोर्ट बन पाया। आजादी के इतने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दशकों तक इसकी चिंता नहीं की गयी थी इसे आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने करके दिखाया है। अब आगे की जो विकास यात्रा है जो आगे का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए हम सी.जी.वायु के माध्यम से मदद कर रहे हैं। यहां एयरपोर्ट तैयार करना, हमारा एक विजन है और जैसे-जैसे वायबिलिटी आती जाएगी, जो जहाज हैं उनके लिए वायबल पेसेंजर्स मिलते जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत तेजी से जहाजों की संख्या में वृद्धि होगी और कनेक्टिविटी में और वृद्धि होगी, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर चलने में हमारे जहाज ज्यादा से ज्यादा चल सकें, उसमें सपोर्ट करने के लिए, प्राईवेट एजेंसी को प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता इसलिए वह जहाज नहीं चलाते हैं। इसलिए हमने उसे वायबिलिटी गैप फंडिंग करने के लिए सी.जी.वायु योजना लायी है और उसमें हम राज्य सरकार की ओर से मदद करके प्रयास कर रहे हैं कि चाहे बिलासपुर हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, वहां से जहाज उड़ान भरें। इसमें राज्य की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी और मैं पूर्णत: आश्वस्त हूँ कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, अर्थ व्यवस्था बढ़ती जाएगी लोगों की एयर कनेक्टिविटी चाहे जगदलपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बिलासपुर हो उससे और तेजी से बढ़ेगी। उसकी बुनियाद नरेन्द्र मोदी जी ने रखी है और आगे भी हम उस पर समर्पित होकर प्रयास करते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, रानी दुर्गावती योजना का जिक्र हुआ, इसमें मात्र 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। मैं रानी दुर्गावती योजना में यह कहना चाहता हूँ कि जो नई जन्म लेने वाली बेटियां हैं एक अप्रैल 2026 के बाद जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, वह उनके लिए लागू होगी और जब वह 18 साल की उम्र पूरा करेंगी, जब उनकी आयु 18 साल पूरी होगी तब उनको डेढ़ लाख रूपये मिलेगा ताकि वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। हमारे संकल्प पत्र के अनुसार यह बड़ी सोच, रानी दुर्गावती योजना अंतर्गत है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे संभाग मुख्यालयों में बहुत सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। कई महत्वपूर्ण संस्थानों में उनका चयन हो जाता है, लेकिन उनका चयन होने के बाद उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं रहती है। संभागीय मुख्यालयों में प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक सहायता देने की दृष्टि से हमने मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना इस बजट में प्रावधानित किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, लखपति दीदी भ्रमण योजना, उनको बेहतर से बेहतर एक्सपोजर हो सके, वह अपनी आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्तिकृत हो सकें, इस सोच के साथ लखपति दीदी भ्रमण योजना, इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शक्तिपीठ हमारी आस्था के केन्द्र हैं। कुदरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा यहां तक पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए यहां पर हमारे पर्यटकों, आस्थावान लोगों को ले जाने के लिए हमने मुख्यमंत्री आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना प्रारंभ की है। जैसे हम प्रथम बजट में रामलला दर्शन योजना लेकर आये थे, जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलती थी, जिसे 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार ने बंद करके रखा था, उसे हमने पुन: प्रारंभ किया है। जब बाहर के तीर्थ स्थलों तक हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को लेकर जा रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों का भी भ्रमण कराएं, इस सोच के साथ इस बजट के माध्यम से यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

सभापति जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, वे हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का दर्शन करें। कई बार होता है कि हमारे रायपुर का आदमी धमतरी से नीचे नहीं देखता है। कई बार होता है कि हमारे बस्तर का बच्चा सरगुजा कभी नहीं देख पाता है। रायपुर पहली बार आता है। कई बार ऐसा होता है कि वह दिल्ली-मुम्बई देख लेता है, लेकिन अंबिकापुर नहीं देख पाता है। ऐसी स्थिति के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवाओं को छत्तीसगढ़ का दर्शन कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, अभी बहुत सारी चर्चाएं हुईं, डबल इंजन पर बहुत सारे उपहास उड़ाए जाते हैं । बहुत सारी बातें अनर्गल रूप से की जाती हैं, विपक्ष के द्वारा आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। डबल इंजन की सरकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण है-नक्सलवाद की समाप्ति। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब जी, कौन मठाधीश हे, ओकरो दर्शन मोला करा देतेव, जेला तुमन ईलाहाबाद में पेलन नहीं देव, तेकरे दर्शन करे के मोला बहुत शौक हे महाराज।

सभापति महोदय :- भिजवा देंगे, आप बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति जी, आज हम सबने देखा कि माओवाद से जुड़े हुए जो संघम सदस्य जनमिलिशिया से लेकर सी.सी. मेम्बर तक के लोग हमारे विधान सभा में आकर इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे, इससे बड़े सुकून का क्षण मेरे लिए नहीं हो सकता। (मेजों की थपथपाहट) उस पीड़ा को मैंने देखा है, जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, 2011 से 2013 तक मैं वहां पर प्रशासनिक रूप से काम करता था तो कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता था, जब हमें कोई शहीद की लाश न उठानी पड़ती हो। ऐसा समय और ऐसा परिवेश भी हमने देखा है, भुगता है। ऐसी परिस्थिति में जब हमको उस समय लगता ही नहीं था कि माओवाद कभी समाप्त हो सकता है, लेकिन नेतृत्व की संकल्प शक्ति है। आदरणीय अमित शाह जी की संकल्प शक्ति है, हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति है, हमारे गृहमंत्री विजय शर्मा जी का भी परिश्रम है, जिसके कारण आज माओवाद समाप्त हो रहा है और आज हम लोग देख रहे हैं कि सी.सी. मेम्बर से लेकर जनमिलिशिया तक या संघम सदस्य तक यहां पर आकर लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ रहे हैं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और हमारे पूरे सरकार के लिए भी सबसे बड़ा सुकून का विषय है। (मेजों की थपथपाहट) निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं को खोया, चाहे हम भीमा मण्डावी जी के शहादत की बात करें, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं आदरणीय महेन्द्र कर्मा जी, नंदकुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल, ऐसे बड़े-बड़े नेताओं की शहादत हुई है और जब माओवाद पर इस तरह से काम हुआ है तो मैं कांग्रेस के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि सबको मिलकर अमित शाह जी, नरेन्द्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के गृहमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस समय जो एक मॉडल खड़ा हुआ था और दंतेवाड़ा के जवांगा में एजुकेशन सिटी बनाई गई थी, उसी तरह के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बस्तर में हम दो नए एजुकेशन सिटी और प्रारंभ करने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) अबूझमाड़ और जगरगुण्डा में दो एजुकेशन सिटी बनाने की बात कही गई है । 250 करोड़ रूपए की लागत से 23 नये औद्योगिक पार्क, औद्योगिक विकास के लिए लैण्ड बैंक 200 करोड़ रूपए का प्रावधान है। बस्तर एवं सरगुजा में शिक्षा के अलावा सीधे रोजगार के लिए भी बहुत सारे सोच के साथ इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। जो वहां की इंडस्ट्री है, उस पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। बस्तर में इतने वनोत्पाद हैं, ईमली है, महुआ है, चार है, चिरौंजी है, तिखुर है, इस तरह के जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वनोत्पाद हैं, जो वहां के एग्रीकल्चर हैं, एग्री प्रोडक्ट हैं, कृषि उत्पाद हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस तरह से उनके जीवन से सीधे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, कृषि, खाद्य, वनोपज, इनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सौ करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट) इसके अलावा बजट में व्यक्ति मूलक योजनाएं हैं। चाहे मधुमख्खी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, इसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। ताकि उनके लाइवलीवुड, उनके जीवन से जुड़े हुए रोजगार प्राप्त कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रानिक मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हो, सिरपुर विकास योजना हो, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन योजना हो, जनजातीय सुरगुड़ी हो, श्रमिक मजदूरों और कृषकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना हो, साइबर तहसील हो, सेन्ट्रल ट्रेजरी हो, जिसे लागू किया जा सके। हस्त-शिल्प उत्पादों के लिए देश के प्रमुख एयरपोर्टस पर शो-रूम की स्थापना हो या वन्देमातरम्, जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसका जगह-जगह पर गायन करने के लिए बजटीय प्रावधान है। इस तरह से अनेकों बजटीय प्रावधान इसमें किए गए हैं।

सभापति महोदय, इसके आलवा 5 महत्वपूर्ण मिशन की भी चर्चा विशेषकर हमारे पक्ष के साथियों ने बहुत विस्तार से की है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ए.आई. मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसरंचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप NIPUN मिशन। माननीय सभापति महोदय, NIPUN के फुलफाम को आपके माध्यम से जरूर सदन में पुन: रिपीट करना चाहूंगा। new age industrial preparation for up skilling of new generation youth, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। (मेजों की थपथपाहट) जो एक समाज को, एक राज्य को उभरती तकनीकी चुनौतियों के बदलते तकनीक के मद्देनजर इसको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई बिन्दु आए हैं, उन बिन्दुओं पर संक्षेप में जवाब देने की कोशिश करूंगा। सारे विषयों पर विस्तार से जवाब विनियोग के समय दूंगा। मगर मैं यहां पर कुछ बिन्दुओं को लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, धान खरीदी पर बहुत सारी चर्चा हुई। विपक्ष के लगभग सभी साथियों ने धान खरीदी का जिक्र किया है। तो केवल हल्ला करने वाली बात अलग होती है। वह उनका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धर्म है, जनता जनार्दन ने जो नौकरी उनको दी है वो नौकरी वह कर रहे हैं, हमको जो नौकरी दी है, वह नौकरी हम लोग कर रहे हैं। तो उनकी नौकरी ही हल्ला करने वाला है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले चीज रखना चाहूंगा कि धान की बिक्री करने वाले किसानों की संख्या कितनी थी ? मैं बिलकुल तथ्यात्मक रूप से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सन् 2018-19 में इनकी सरकार आई। उस साल धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15 लाख 70 हजार थे, लगभग 15 लाख थे। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी शुभागमन हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, सन् 2018-19 में इनकी सरकार आई उस समय धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15 लाख 70 हजार थे। 2019-20 में 18 लाख 40 हजार, 2020-21 में 20 लाख 50 हजार, 2021-22 में 20 लाख 50 हजार, 2022-23 में 21 लाख 80 हजार किसान थे। हमारी सरकार आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 3 धान खरीदी हुई है। मैंने इनके समय का बताया कि धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15 लाख 70 से 21 लाख तक थी। हमारे कार्यकाल के 2023-24 में 23 लाख 40 हजार किसानों ने धान बेचा। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2024-25 में 24 लाख 70 हजार किसानों ने धान बेचा। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2025-26 में 25 लाख 20 हजार किसानों ने धान बेचा है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, यह तथ्य है, जो सम्माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक धान खरीदी के टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो इनके पूरे कार्यकाल 2018-19 से 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23, इनके पूरे 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल धान खरीदी हुई, वह 4 करोड़ 62 लाख मीट्रिक टन थी और हम लोगों ने केवल 3 साल में लगभग उतना, 4 करोड़ 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। (मेजों की थपथपाहट) किसानों को जो बोनस भुगतान है, सभापति महोदय, इनके पूरे 5 साल मिलाकर इन्होंने किसानों को जो बोनस भुगतान किया था, वह 31,726 करोड़ रुपया किया था। हमने अपने 3 साल में ही इनके 5 साल से ज्यादा 35,565 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- हम लोग 10,000 करोड़ रूपये का कर्जा माफ किये थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, कुल धान खरीदी में कुल भुगतान की बात है, 5 साल पूरा मिलाकर इन्होंने 1,19,000 करोड़ रूपये धान पर टोटल भुगतान इन्होंने किया। पूरे 5 साल मिलाकर 1,19,000 करोड़ रूपये धान का भुगतान किया। हमने अपने 3 साल में ही 1,35,000 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। (मेजों की थपथपाहट) तो ये तथ्य हैं, जिसमें किसी को कोई विषय नहीं है, जिसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय मंत्री जी बार-बार 5 साल, 5 साल का जिक्र कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- बोलने दीजिये ना।

श्री बघेल लखेश्वर :- 1 मिनट, ये 5 साल का ज्यादा जिक्र हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। 5 साल में हम लोग 2 ही साल काम किए हैं, 3 साल तो कोरोना में चला गया। उसको भी जोड़ लीजिये ना, उस परिस्थिति में क्या आर्थिक स्थिति थी?

सभापति महोदय :- बघेल जी, वे दो दिन से सुन रहे हैं, अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना। जवाब तो सुन लीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- ये 5 ही साल का ज्यादा बोलते हैं, 15 साल की बात नहीं करते हैं। 15 साल में क्या-क्या हुआ, उसको भी तो बता दीजिये। 5 साल की बात करते हैं।

सभापति महोदय :- हो गया। आप बैठिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- आप भी बैठिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- लखेश्वर जी, आप लोग तो उस समय भी मास्क लगाकर खाते थे कोरोना में। (हंसी)

सभापति महोदय :- बैठिए, मंत्री जी, आप बैठिए। बैठिए बैठिए वित्त मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, केपेक्स पर बहुत सारी बात हो रही थी और विशेष कर हमारे राघवेंद्र भाई ने भी इस विषय को काफी रखा था। पता नहीं उमेश पटेल

जी भी कुछ-कुछ डेटा बोल रहे थे, मगर कभी जवाब में तो रहते नहीं हैं। अभी गंभीरता की बहुत सारी बातें हो रही थीं। मैं जब उस दिन बजट प्रस्तुत करने आया, तो मैं आकर पूरा अपना टेबलेट वगैरह सब रखा तो यहां पर कोई नहीं था। तो मैं 2 मिनट के लिए पानी पीने गया और मैं ढाई मिनट, दो मिनट सवा दो मिनट लेट हुआ तो उसको बहुत हास्यास्पद तरीके से गंभीरता का विषय बनाया गया। इस तरह की ओछी आलोचना और आज बजट चर्चा पर जवाब आ रहा है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं ही नहीं, तो मैं उसको कौन सी गंभीरता मानूं? और आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिये, हमारी लगभग 2 साल की सरकार हुई है। चाहे बजट चर्चा का जवाब आया हो, चाहे विनियोग पर जवाब आया हो, चाहे अनुपूरक में कोई भी जवाब आया हो, उसमें कितने बार माननीय भूपेश बघेल जी उपस्थित रहे हैं, उसको चेक करा लीजिये, पता चल जाएगा सदन में कौन कितना गंभीर है। (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, केपेक्स के संबंध में मैं कुछ बिंदु कुछ डेटा रखना चाहूंगा जो तथ्य हैं। वर्ष 2018-19 में सरकार कांग्रेस की बनी थी, जी.एस.डी.पी. की तुलना में केपेक्स था 2.7 प्रतिशत। वर्ष 2019-20 में केपेक्स था 2.5 प्रतिशत। वर्ष 2020-21 में केपेक्स था 2.6 प्रतिशत। वर्ष 2021-22 में केपेक्स था 2.9 प्रतिशत। वर्ष 2022-23 में इनका केपेक्स था 3 प्रतिशत। हमारी सरकार आने के बाद, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, वर्ष 2024-25 में जो केपेक्स है, वह 3.5 प्रतिशत है। तो इस तरह से केपेक्स में कमी नहीं होने दिया जाएगा, बेहतर से बेहतर लगातार करने का हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। सभापति महोदय, इसके अलावा राजस्व वृद्धि पर भी कई चर्चाएं हुईं, निश्चित रूप से बहुत सारे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से मैं जरूर रखना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हम जी.एस.टी. में देश में Highest growth वाले राज्य रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस बार कोयले में जो नियम परिवर्तित हुआ है, उसके कारण एक-डेढ़ साल तक हमको इनपुट क्रेडिट में एडजस्टमेंट के कारण हमारा टैक्स कम होगा और एक-डेढ़ साल बाद बहुत तेजी से उसका भी फायदा हमको छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है और जी.एस.टी. के रेट इतनी तेजी से आदरणीय मोदी जी ने कम किए हैं, जी.एस.टी. रिफॉर्म 2.0 के माध्यम से, उसके कारण भी जी.एस.टी. रेवेन्यू तात्कालिक रूप से थोड़ा कम होता है। स्वाभाविक रूप से जब टैक्स कम होता है तो जनता के जेब में ज्यादा पैसा जाता है। उससे इकोनॉमिक बायनसी आती है, जिसका लाभ long term में कर संग्रह के रूप में मिलता है और जरूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऋण पर भी बहुत सारी चर्चाएं की गईं। सभापति महोदय, मैं

आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी ऋण लिया जाता है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से Fiscal Responsibility and Budget Management Act (F.R.B.M.) के रूल्स हैं। उसके अंतर्गत उस एक्ट में प्रावधान हैं, आर.बी.आई. के, भारत सरकार के, सबके बनाए हुए नियम हैं, उस सीमा में ही हम रहकर ऋण लेते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि F.R.B.M. की सीमा के अंतर्गत ही 3% of GSDP के अंतर्गत ही हम लोन लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो टोटल लोन है, जिसमें 25% of GSDP के नीचे बने रहना चाहिए, उसको भी हम लोग बखूबी maintain करेंगे। वह amount में ज़्यादा ज़रूर दिखेगा क्योंकि GSDP का Size भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए वह amount में ज़्यादा दिखेगा। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में बताना चाहूँगा। मैं ज़्यादा डेटा नहीं रखूँगा, मैं विनियोग विधेयक के दिन रखूँगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का जो Fiscal deficit है, वह 5.8% पर गया है। उनका टोटल लोन है, जो GSDP के Comparison में 25% से नीचे maintain करना रहता है, वह हिमाचल प्रदेश का, It is well above that 29% of GSDP है। इनके इंडी गठबंधन के दोस्त आम आदमी पार्टी वाले पंजाब चला रहे हैं। वहां GSDP के Comparison में उनका लोन 37% तक पहुँच गया है। देश में सबसे ज़्यादा है। आप चाहे कोई भी गैर भा.ज.पा. शासित राज्य का Fiscal health उठा कर देख लीजिये, वह भा.ज.पा. शासित राज्यों की तुलना में कई गुना ज़्यादा ख़राब है। हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति उस तुलना में बहुत अच्छी है और हमेशा अच्छी बनी रहेगी। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, दूसरी ओर मैं फिर से अवगत कराना चाहूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस के लोग चर्चा करते हैं कि हमने इतना लोन लिया था। जब हम सरकार में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को वित्त विभाग की ज़िम्मेदारी दी। जब हमने Accounts को, सब चीज़ों को खंगालना चालू किया, तब सारी जगहों में बुरे हालात थे। जो स्थिति थी, उसको हमने झेला है। इनके Accounting का कोई माई-बाप ही नहीं था, जो सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूँ कि यह लोन लेने की बात कहते हैं। 39,000 करोड़ रूपये की देनदारी विभिन्न जगहों पर ये लोग छोड़ करके गए थे, जिसका Accounting लोन में कहीं नहीं होता है। जिस Account के Cleaning में हमने 39,000 करोड़ रूपये की देनदारी को Face किया, उसमें से हम 20,000 करोड़ रूपये से अधिक की देनदारी को अभी दो सालों में दे चुके हैं। ये सब भी जाकर के वहाँ Reflect होता है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, मार्कफ़ेड में 22,000 करोड़ रूपये की देनदारी बची थी, जो ये लोन में Count नहीं करते थे। नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) में लगभग 5,000 करोड़ रूपये की देनदारी बची थी। आयुष्मान योजना में 2,000 करोड़ रूपये की देनदारी बची थी। दवाइयों और री-एजेंट के पेमेंट में 1,000 करोड़ रूपये की देनदारी बची थी। 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करना, उसकी 2,000 करोड़ की देनदारी रूपये बची थी। ऑफ बजट लोन, जो रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन में लेकर बैठे थे, एन.आर.डी.ए. में लिया गया था, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में लिया गया था, पुलिस हाउसिंग बोर्ड में लिया गया था, इन सबका मिला कर 7,000 करोड़ रूपये बचा था। ये जो सारी देनदारियां बची थीं, उसका amount 39,000 करोड़ रूपये का था, जिस pressure को हमने झेलते हुए वित्तीय व्यवस्था को चलाया है और निश्चित रूप से हम कई लोन लेकर के इन भुगतानों को किए हैं, जो इनके समय का 39,000 करोड़ रूपये का भुगतान था। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 6,670 करोड़ रूपये के ऐसे ऋण थे, जिनमें उच्च ब्याज दर था। इसके लिए भी हमने लोन लिया और उस लोन को उन संस्थानों के लिए पटाया जो High interest rates वाले थे। उससे लगभग 1,350 करोड़ रूपये के ब्याज के राशि की बचत होने जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं इन देनदारियों के अलावा बताना चाहूँगा कि जब इन संस्थानों-मार्कफ़ेड, नागरिक आपूर्ति निगम, इस तरह की संस्थाओं को जब कोई वित्तीय संस्था जब लोन देती है, तब स्टेट की गारंटी माँगती है। इनके समय में स्टेट की गारंटी 30 हजार करोड़ की थी, हमने जिसको बेहतर वित्तीय प्रबंधन करते हुये, वित्तीय प्रबंधन केवल एकाऊंटिंग नहीं है कि मैं सारे एकाऊंट्स को कचरा करके रखा रहूँ, मैं बोलूं कि कितना ही लोन लिया गया है। अभी पिछले अनुपूरक बजट में हम लोग लाये थे तो लगभग 35 हजार करोड़ का था। वह क्यों था, हमने 32-33 हजार करोड़ रूपये तो राजस्व व्यय था। मार्कफेड की देनदारी, नागरिक आपूर्ति निगम की देनदारी, इन सब को हम क्लियर किया, वित्तीय प्रबंधन यह नहीं है कि मैं केवल दिखाने के लिये कम लोन दिखा दूँ । हमने लोन ज्यादा दिखाया और इन सब एकाऊंट को क्लिनिंग करने का काम किया है, ताकि आगे सरकार अच्छी तरह से चलती रहे। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जो राज्य की गारंटी थी, यह सब सरकार छोड़कर गये थे तो 30 हजार करोड़ से अधिक की शासकीय गारंटी स्टेट से दी हुई थी, हमने इसको 12 हजार करोड़ कम करके 18 हजार करोड़ पर लाये हैं, दिज आर फायनेंशियल मैनेजमेंट। यह वित्तीय प्रबंधन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। सभापति महोदय, यह केवल एकाऊंटिंग नहीं है। कांसोलिडेटेड सिंकिंग फण्ड, जो राज्य की वित्तीय स्थिरता को अच्छे तरह से बनाकर रखना होता है। उसके लिये हमारे सीएसएफ में 8875 करोड़ रूपये की राशि जमा है। जो राज्य कोई गारण्टी देता है स्टेट गारण्टी देता है, उस परिस्थिति के लिये आरबीआई व्यवस्था बनाकर रखा है कि उसमें हम 1033 करोड़ रूपये जमा करके रखे हैं । पिछले साल के बजट में हमने बड़े वित्तीय रिफार्म के रूप में पेंशन फण्ड का प्रावधान लेकर आये थे, जब मानसून सत्र आया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधान सभा ने एक्ट पारित कराया। हम पहले राज्य बने है, इन्होंने पेंशन फण्ड बनाया है, इसका उद्येश्य यही है कि आज ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे राज्य के कर्मचारियों के लिये लागू है। लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है । हमारे राज्य में लोग जी रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के कारण उसकी औसत आयु बढ़ रही है, यह प्रदेश के लिये गौरव की बात है। इससे पेंशन का बर्डन भी बढ़ता जायेगा। जिस वर्ष पेंशन बर्डन 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ेगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिये उस वर्ष पेंशन फण्ड में जो पैसा जमा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उस पैसे को राज्य उपयोग कर सकेगा । आज हम खाओ पीओ के लिये काम नहीं कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले वर्ष में और आने वाले दशकों में हमारे राज्य की वित्तीय स्थिरता कैसे बनी रहे, इसकी भी चिंता करके पेंशन फण्ड का प्रावधान किये हैं, पिछले साल भी हमने पेंशन फण्ड में 500 करोड़ रूपया का निवेश किया है। इस वर्ष के बजट में हमने पेंशन फण्ड के माध्यम से 500 करोड़ रूपये निवेश करने का बजटरी प्रावधान किया है। सभापति महोदय, वित्तीय रिफार्म के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी..।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- माननीय वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो कर्जा बचा था वह हमारे पांच साल का था कि आपके भी 15 साल का था । इसे अलग-अलग बता सकें तो बेहतर होगा ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो टोटल कर्ज का एमाऊंट है, राज्य के ऊपर जो लोन थे, उसका डाटा आप लोग भी प्रस्तुत करते रहते हैं, यह आता रहता है । 39 हजार करोड़ की देनदारी में कहना चाहता हूँ कि मैं उसका सेप्रेट डाटा दे दूँगा, लेकिन मैं आपको पूर्णत: सदन से कहना चाहता हूँ कि उसका 70-80 परशेंट आप ही के समय का है । मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूँगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- मोबाईल लेकर भाग गे रहिन हे । मोबाईल के पइसा हमन देन। चप्पल जूता के पइसा ला हमन दे रेहेन।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऊपर बैठकर पूरा देखे हो, चार्वाक दर्शन है उधार लो और कथरी ओढ़ के घी पीओ। लखमा जी को पर्यटन में भेजो। यही है और क्या है, लखमा जी पर्यटन से आ गये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- काय सूजी लगाय हे तेला बताओ।

श्री अनुज शर्मा :- तै पहली कैपेक्स के मतलब ला बता।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो कैपेक्स को बढ़ाने की बात है उसको मैं भी मानता हूँ कि हमको उसमें बहुत रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार इस कैपेक्स को बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेगी। वित्तीय रूप से भी कई डेलिगेशन किए हैं, आज मैं विधानसभा प्रश्नकाल में बता रहा था कि हमने वित्तीय रूप से पावर्स का कई डेलिगेशन किए हैं, ताकि विभाग स्वयं से कर सकें, वह भी हमने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने लगभग 1000 सब इंजीनियर्स की भर्ती की अनुमति वित्त विभाग के माध्यम से प्रदान की है। लगभग 1000 इंजीनियर्स की भर्ती हो रही है ताकि पूंजीगत व्यय जो सड़क बनाना है, डब्ल्यूआरडी के काम है, पीडब्ल्यूडी के काम है, इस तरह के काम तेजी से आगे बढ़ सकें। हमारी सरकार द्वारा लगभग 1000 इंजीनियर के भर्ती की अनुमति दी गई है।

सभापति महोदय, एक विषय एससीए का आ रहा था, मैं उसका विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। हमारे राघवेंद्र भाई बहुत अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, मुझे लगा उनको इस मामले में कोई कंफ्यूजन है। एससीए जिसको हम स्टेट स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस शासकीय बोलते हैं, उसके तहत आदरणीय मोदी जी ने प्रावधान किया कि राज्य भी पूंजीगत व्यय तेजी से आगे बढ़ाएं ताकि अर्थव्यवस्था तेज गति से चलती रहे। इसके लिए उन्होंने बड़ी उदारता के साथ ये निर्णय लिया, उन्होंने स्टेट को रिफॉर्म्स एजेंडा दिया। सबसे पहली बात उन्होंने रिफॉर्म्स एजेंडा दिए। आप लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज कीजिए, आप एसएनए स्पर्स लागू करिए, आप वित्तीय प्रबंधन में डिजिटाइज सिस्टम इफमिस लागू करिए, आप लैंड यूज चेंज करने में रिफॉर्म करिए, औद्योगिक नीति में रिफॉर्म करिए। उन्होंने राज्यों को ये सारे रिफॉर्म एजेंडा दिया और रिफॉर्म करने पर एससीए का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पैसा नरेंद्र मोदी जी की ओर से मिलता है। एससीए को एक लोन टेक्निकली जरूर माना जाता है, लोन है भी, उसे बोलने में मुझे कोई आशंका भी नहीं, लेकिन ये 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन है। 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन है। मैं आपके माध्यम से आज राघवेंद्र जी को ही कहना चाहूंगा, अगर कोई आपको आज एक करोड़ रुपया दे दे और कहे कि 2076 में एक करोड़ वापस कर देना या मैं पूरे सदन के सभी सदस्यों को पूछना चाहता हूं, एक करोड़ रुपया आपको कोई दे दे और बोले कि 2076 में वापस कर देना तो कौन उसको नहीं लेगा? मैं पूछना चाहता हूं कौन नहीं लेना चाहेगा?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, रत्ती भर का कंफ्यूजन नहीं है। मुझे ये पता है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है जो एक लंबे समय के बाद हमें वापस देना है। कंफ्यूजन शायद आपको मेरी बात समझने में हुई, मेरा सिर्फ ये कहना था कि हम एफआरबीएम एक्ट के तहत नीचे हैं। लेकिन आज जब हम वित्तीय प्रबंधन देखते हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि 50 साल बाद इंफ्लेशन को अगर आप जोड़ लें तो उस पैसे का महत्व बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं कि 1 लाख 80 हजार रुपये किसी को हमें देने हैं, 18 साल बाद देंगे तो उसका महत्व कम हो जाएगा। मैं वह बात बिल्कुल समझ रहा हूं, मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें सिर्फ मेरा पॉइंट ये था कि आज जब हम उसको अपना फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने में ऐड करते हैं तब हम 4 परसेंट के ऊपर जा रहे हैं और मैंने उस समय में भी ये बात कही थी कि मुझे बिल्कुल पता है कि वह एफआरबीएम में कवर नहीं होता है। प्लीज मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, आप इस मामले में निश्चिंत रहें।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, एससीए राज्यों को केंद्र की ओर से नरेंद्र मोदी जी की ओर से निर्मला सीतारमण जी की ओर से दिया गया एक वरदान है और इसके तहत रिफॉर्म करने पड़ते हैं, ऐसे ही वह पैसा नहीं मिल जाता है, रिफॉर्म करने पड़ते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमने चर्चा की कि भाई 50 साल बाद एक करोड़ वापस करना है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक बहुत सामान्य टर्म नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है । अगर किसी चीज को हमें 50 साल बाद बिना इंटरेस्ट के वापस करना है तो मैंने विभाग में इसका एक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलवाया था, यह करीब 8 परसेंट के लगभग पड़ रहा है। अगर हमको 50 साल बाद किसी को 1 करोड़ वापस करना हो तो उसकी वैल्यू आज 8 लाख है लेकिन हमको 8 लाख नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

1 करोड़ मिल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का राज्य के लिए दिया हुआ वरदान है जो रिफॉर्म आधारित है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस की सरकार चला रहे हैं और रिफॉर्म ओरिएंटेड सरकार चला रहे हैं। मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस में हमारी सरकार पूरी तरह से सवार होकर चल रही है, इसलिए हम एससीए में पैसा ले पा रहे हैं और देश के सबसे अग्रणी राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ है, जो ये पैसा ले पा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मैं जस्ट एक डेटा देना चाहूंगा, 2020-21 के आसपास तत्कालीन कांग्रेस की हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार एससीए में 286 करोड़ ले पाई थी। पिछले साल हम 6200 करोड़ ले पाने में सफल हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस साल हमको लगभग 7000 करोड़ मिल चुके हैं और प्रयास चल रहा है कि ये फिगर 8000 करोड़ तक पहुंचे। आने वाले वर्षों में भी रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नेंस के माध्यम से एससीए से हम जितना ज्यादा पैसा ला सकेंगे, राज्य का उतना ही भला होगा। सभी क्षेत्रों तथा 3 करोड़ जनता-जनार्दन का उतना ही भला होगा, इस माइंडसेट के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि कल जो कुछ विषय आए थे, उन पर भी मैं शॉर्ट में विषय रखना चाहूंगा। संगीता दीदी अभी चली गई हैं। लेकिन कल सम्माननीय सदस्य बोल रही थीं कि अलग-अलग एसोसिएशन के सब लोग मेरे पास ही आते हैं और मुझे बोलते हैं कि यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है तो मुझे तो लग रहा था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, संगीता जी कांग्रेस पक्ष की गीता गोपीनाथन हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। (हंसी)

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति जी, अब पीछा छोड़ो, बहुत हो गया। सब कुछ आ गया है। हमारा पीछा छोड़िये और जाने दीजिये। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जिस तरह से संगीता जी बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी की कुर्सी खतरे में है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, आप अंत में यह जरूर एक बार बता दीजिये। कल मीडिया और बाकी साथियों में इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी।

श्री अजय चंद्राकर :- आप गीता गोपीनाथन को जानते हो ना? संगीता जी हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जी। आप जो चंदन का टीका लगाए थे, वह छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया का था? काबर कि सब कहत रीहिन हे कि भारी सफेद-सफेद दिखत हे। कही मुल्तानी मिट्टी तो नहीं रीहिस हे, तेला बता देहो।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वह कुम्हार का माटी था। मैं कुम्हार का माटी मंगवाया था।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- भैया, कौन जगह के मंगाए रहेव, तेन ला बता दो?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब पूछवाओ कि कति ले आए रीहिस हे। वह कुम्हार का माटी था, कुम्हार वाला।

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने का माटी बहुत पवित्र है, जहां से भी लगा के आए थे। ठीक है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कहां का था?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, कुम्हार की मिट्टी थी। हमारे विपक्ष के साथियों ने SIR पर भी काफी चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं कि टीचर लोगों की SIR में ड्यूटी लगा दी गई करके यह आलोचना कर रहे थे। आपके माध्यम से मैं विपक्ष के उन साथियों को कहना चाहता हूं कि आप घुसपैठियों को क्यों घुसाते रहे? अगर आज उसको क्लीन करने, उसकी सफाई करने की कोशिश हमारी पार्टी की सोच कर रही है तो उससे आपत्ति क्यों होनी चाहिए? (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आपने 11 साल तक घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली में यह काम क्यों नहीं किया? 11 साल से आपकी सरकार है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी असम चुनाव में काम कर रहा हूं। मैं 10 विधानसभा सीटों का काम देखता हूं। एक सीट में एक समुदाय विशेष के 96 % लोग एक कांस्टीट्यूएंसी में हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, ऐसा तो नहीं है कि वह कांस्टीट्यूएंसी बनाई ही वैसी गई है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, तात्कालिक रूप से लाभ लेने के लिए कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, उससे भारत देश, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों को इसका बहुत लंबा नुकसान होने जा रहा है। (शेम-शेम की आवाज) इसको दूर करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे कई साथी बोल रहे थे कि ओ.पी. चौधरी अच्छा आदमी था, भगवा चोला पहन लिया है तो मैं कहना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- व्यक्तिगत रूप से हमर मुख्यमंत्री घलो बढ़िया आदमी हे, तुहु बढ़िया आदमी हो, लेकिन जब ओला पहिनथो ता गड़बड़ हो जाथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये। उनको बोलने तो दो। आप सुनिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, भगवा प्रतीक है त्याग का, भगवा प्रतीक है ऊर्जा का (मेजों की थपथपाहट) और मैं एक IAS की सुरक्षित नौकरी को छोड़ कर आया हूं और जो अवसर मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है, उससे मैं बहुत गौरवान्वित हूं, बहुत संतुष्ट हूं और बहुत खुश हूं कि हमारे 3 करोड़ छत्तीसगढ़ भाई-बहनों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। इस तरह का भगवा चोला हर व्यक्ति को ओढ़ना चाहिए। अटल जी गाइडलाइन रेट पर चर्चा कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि गाइडलाइन रेट कम होता है तो जो भूमि अधिग्रहण होता है, उसमें किसानों को उसका सीधा नुकसान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने उसको बैलेंस करने का प्रयास किया। मध्यम वर्ग के लोगों को कोई कच्चा-पक्का नहीं करना होता है, इसलिए उनको बैंक लोन लेकर घर बनाना रहता है, प्लॉट खरीदना रहता है, उसमें उनको कम लोन मिल पाता है इसलिए हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। हमने रजिस्ट्री में कई ऐसे रिफॉर्म किए हैं, जिसके कारण हमको कम रेवेन्यू आने जा रहा है। जो स्क्वेयर फीट रेट होता था, उसे हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में समाप्त कर दिया, उसके कारण हमको रेवेन्यू कम आएगा। रजिस्ट्री में हमने एक नहीं सैकड़ों रिफॉर्म्स किये हैं। 1908 के एक्ट में 93 सेक्संस में से करीब 33 सेक्संस को हमने बदल डाला। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हम राजस्व के लिए यह सब नहीं कर रहे हैं। लोगों को सुविधा हो, लोगों की बेहतरी हो, इसके लिए हम गाइडलाइन रेट में बेहतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान को भू-अर्जन में बेहतर मुआवजा मिले, इसके लिए हम कोशिश कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं। मध्यम वर्ग को बैंक से बेहतर लोन मिले, कोई उद्यमी अगर जमीन के आधार पर लोन लेना चाहता है तो उसको बेहतर लोन मिले, हम इसके लिए यह कर रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाईंट है। हम लोगों ने इसमें विरोध दर्ज किया है। मंत्री जी उसके बारे में जवाब दे रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय मंत्री जी, बहुत सारी सड़कों के डी.पी.आर. पुराने रेट के बने थे, जिसमें मेरे यहां की भी दो-तीन सड़कें हैं इसलिए मैं उस बात को जानता हूँ। वह यहां पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस आ गए हैं और कई बीच के ऑफिसों में रुके हुए हैं। आप इसमें यह संज्ञान लीजिए कि अगर जो गाइडलाइन बदली गई हैं, कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं वह एक चर्चा का विषय है, लेकिन अगर बदली गई हैं तो डी.पी.आर. में बदलाव होगा क्योंकि लैंड एक्विजिशन चेंज होगा। उन फाइलों का मूवमेंट जल्दी कराने के लिए आप हम लोगों को यहाँ पर कोई न कोई स्पष्ट निर्देश या आश्वासन दे दें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत स्पष्ट है कि किसानों को गाइडलाइन रेट कम होने के कारण कम मुआवजा मिले, ऐसी स्थिति न बने। इसके लिए हम पूर्णतः समर्पित हैं कि नई गाइडलाइन के आधार पर नया अवार्ड अगर पारित हो रहा है, उस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से भुगतान करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) अगर गाइडलाइन के बारे में अटल जी इतनी बातें कर रहे थे और वे स्वयं बिल्डर हैं। सभापति महोदय, मैं सम्मानीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से एक बिंदु रखना चाहता हूँ कि अगर गाइडलाइन रेट इतना बढ़ गया है तो वे स्वयं बिल्डर हैं, वे सभी सदस्यों को गाइडलाइन रेट में कम से कम दो-दो, चार-चार प्लॉट दे दें या कम से कम एक-एक प्लॉट दे दें। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, यदि वे बोल रह हैं कि गाइडलाइन रेट इतना बढ़ गया है तो हम बिल्कुल तैयार है कि वे बिलासपुर में गाइडलाइन रेट पर प्लाट दें, उनसे सब लोग एक-एक प्लॉट खरीद लेंगे। ये बात दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है।

सभापति महोदय, हर्षिता जी बोल रही थीं कि डोंगरगढ़ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पिछले वर्ष वहां पर वाय-शेप ब्रिज के लिए 31 करोड़ की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। डोंगरगढ़ के चारों ओर 55 करोड़ रुपये का परिक्रमा पथ, फोर-लेन सड़क के लिए सहमति प्रदान की गई है। वहां पर वर्ष 2024-25 में शामिल छः सड़कों के लिए 31 करोड़ की राशि स्वीकृत की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गई है। कहीं पर विषय ही नहीं है। आदरणीय निषाद जी बोल रहे थे कि फसल बीमा में क्या होता है क्या नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य के समक्ष तथ्य रखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कृषकों की ओर से लगभग 1,580 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि आज तक पेमेंट की गयी है। उसके एवज में हमारे छत्तीसगढ़ में 7,414 करोड़ का बीमा भुगतान हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि यह बजट टूटी स्क्रीन पर एच.डी. फिल्म दिखाने की कोशिश जैसा लग रहा था। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश को पता है, विपक्ष के सभी साथियों को भी पता है, नेता प्रतिपक्ष जी तो उस समय आसंदी पर थे और जो सब कुछ होता रहा, उसको वह भी मजबूरीवश धृतराष्ट्र की तरह देखते रहे और भीष्म पितामह जी की तरह भी देखते रहे। उस स्क्रीन को तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने ही किया था। (शेम-शेम की आवाज) हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गवर्नेंस लाकर उसमें एच.डी. फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसी कार्यकाल में सफल होंगे और पूरी एच.डी. फिल्म हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को दिखाएंगे।

सभापति महोदय, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जी ने निफ्ट पर विषय रखा है। मैं जानकारी के रूप में उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने पिछले बजट में निफ्ट का जिक्र किया था इसलिए मैंने इस बार उसका जिक्र नहीं किया। निफ़्ट के संबंध में जमीन का आवंटन हो चुका है। उसके लिए भारत सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी निरीक्षण करके जा चुके हैं। जो पुरानी विधान सभा भवन है, उसे अभी टेंपरेरी तय किया गया है। वहीं पर टेंपरेरी रूप से अगले शैक्षणिक सत्र में निफ्ट प्रारंभ कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, नवा रायपुर में हमारी सरकार आने के बाद NIFT (National Institute for Fashion Technology) की भी लाइन पूरी क्लियर हो चुकी है, NIELIT (National Institute of Electronics & IT) का भी पूरा प्रारंभ हो चुका है, NFSU (National Forensic Sciences University) का भी पूरा रास्ता क्लियर हो चुका है। NARSEE MONJEE कालेज जो प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्थान है, उसका भी रास्ता क्लीयर हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नई केपिटल सिटी में NARSEE MONJEE कालेज का भी के.जी. से पी.जी. तक का संस्थान आने जा रहा है। कही किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने नर्सिंग कालेज के संबंध में बात कही थी कि पिछले बार 12 का जिक्र हुआ था, इस बार 4 नर्सिंग कालेज की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सन् 2000 में बना। 2000 से 2024 तक 24 सालों में 8 शासकीय नर्सिंग कालेज बने थे। हमने पिछले

बजट में 12 नर्सिंग कालेज का प्रावधान किया था, उन 12 के अतिरिक्त 2 और नर्सिंग कालेज के प्रावधान हो रहे हैं। सब मिलाकर, इस साल के बजट, पिछले साल के बजट और पुराने 8, सबको मिलाकर 22 नर्सिंग कालेज होंगे और हमारे इसी कार्यकाल के 22 में से 14 शामिल हैं। इसके अलावा Pan iit के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एम.ओ.यू. हुआ है। वह लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सस्ते रेट पर 10 नर्सिंग कालेज संचालित करेंगे। उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ की बहनों को मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा काम हमारे छत्तीसगढ में हुआ है। सभापति महोदय, मेकाहारा में बहुत सारे बिन्दु आ रहे थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मेकाहारा के बारे में कुछ विषय रखे थे, मैं उनको तथ्यात्मक रूप से बताना चाहूंगा कि मेकाहारा में इनके समय में आई.पी.डी. 600-700 हुआ करती थी, वह अभी बढ़कर 1300 से ऊपर जा चुकी है। पहले ओ.पी.डी. 1800 के लगभग हुआ करती थी, वह 3000 से ऊपर जा चुकी है। बहुत तेजी से मेकाहारा की हालत में भी सुधार हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इन सब विषयों को रखने का मैंने प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ 3 करोड़ जनता-जनार्दन के लिये समर्पित होकर कार्य करती रहेगी। विभिन्न विषयों पर विभिन्न तरह के आक्षेप और भी लगाये गये हैं, उनका विस्तार में जवाब चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हो, महतारी वंदन योजना से संबंधित हो, इन सब विषयों पर हम विस्तार से जवाब विनियोग के समय निश्चित रूप से देंगे। आज समय की भी थोड़ी सी मर्यादा है। ऐसे समय में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा :-

सच है विपत्ति जब आती है,

कायर को ही दहलाती है

सुरमा नहीं विचलित होते,

क्षण एक नहीं धीरज खोते,

विघ्नों को गले लगाते हैं,

कांटों में राह बनाते हैं।

हमारी सरकार चाहे कितने भी कांटे भरे रास्ते हों, पिछली सरकार के लिगेसी के रूप में, उनकी विरासत के रूप में कितनी भी कठिनाईयां प्रस्तुत की गई हों, कितने भी स्क्रीन तोड़े गये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हों, उन सब पर बेहतर रास्ता बनाते हुए हम एच.डी. फिल्म जरूर छत्तीसगढ़ की जनता के लिये तैयार करेंगे। वह एच.डी. फिल्म रील में भी होगी, रीयल में भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- महोदय, विधायक मन के फंड ला बढ़ात हे का।

श्री ओ.पी. चौधरी :- प्राधिकरण के लिये बढ़ाबो, विधायक ला का बढ़ाबो।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, बैठिये। संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ बोल रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण आय-व्यय में प्रस्तुत किया है और बहुत लंबा समय हो चुका है। आज अशासकीय कार्य दिवस भी है और अभी बिजनेश भी शेष है। सभी हमारे माननीय सदस्यगण भी धके हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो अशासकीय कार्य है, उसको अगले अशासकीय दिवस के लिये रखा जाये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैं भी इनके प्रस्ताव से सहमत हूं।

<u>अशासकीय संकल्प</u>

सभापति महोदय :- सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में दर्ज अशासकीय संकल्प अगले अशासकीय कार्य दिवस में लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

कृषि विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, यह थके हुए शब्द को निकाल दीजिए।

सभापति महोदय :- सभी की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(सायं 7 बजकर 05 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही, सोमवार, दिनांक 09 मार्च 2026 (फाल्गुन 18 शक संवत 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गयी।)

दिनांक 27 फरवरी, 2026
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं